रजिस्ट्री सं. डी--(डी एन)--128/89 REGISTERED NO. D--(DN)--128/89

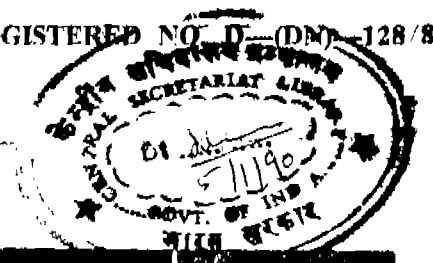

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
Dt. 5/11/90
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1989 (कार्तिक 6, 1911)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1989 (KARTIKA 6, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

कलकत्ता-700001, दिनांक 11 अक्तूबर 1989

भारत का राजपत्र अधिसूचना सं० डी० एफ० स० (सी० ओ० सी०) 56 दिनांक 28/3/89 आवश्यक सुधार का विवरण जो राजपत्र भाग III सेक्शन 4 दिनांक 15/7/89 को प्रकाशित किया गया

पैराग्राफ नं०	गजट का पेज नं०	सामग्री जो गजट में प्रकाशन हेतु भेजी गई अधिसूचना में है	सामग्री जो गजट में वास्तविक प्रकाशित की गई	आवश्यक सुधार जो करनी है
1	2	3	4	5
1. आरंभिक पंक्ति	661	अधिसूचना क्रमांक डी०एफ० सी० (सी० ओ० सी०) 56/(डी० जी० ओ)-89	क्रमांक डी०एफ० सी० (सी० ओ० सी०) 56/डी०जी० (ओ०)-89	क्रमांक के पहले अधिसूचना जोड़ना है
3 IV (I) ख)	662	चौबीस महीनों से अधिक अवधि के पश्चात् परन्तु साठ महीनों के अपश्चात	चौबीस महीनों से अधिक अवधि के पश्चात् परन्तु साठ महीनों के पश्चात्	पिछला पश्चात् की जगह अपश्चात् करना है

	2	3	4	5
	663	वर्तमान पैराग्राफ 10 अ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ 10 अ रखा जाएगा	वर्तमान पैराग्राफ 10अ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ 10अ रखा जाएगा	पैराग्राफ 10 क्ष की जगह पैराग्राफ 10अ लिखा जाएगा
5(I)	663	जहां ऋण या निवेश कंपनी छ: महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद	जहां ऋण या निवेश कंपनी छ: महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद	समाप्रित की जगह समाप्ति लिखना है।

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 14 अगस्त 1989

एस०बी०डी० क्र० 5/1989--इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नलिखित व्यक्तियों को स्टेट बैंक आफ इन्दौर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 22-8-1989 से 21-8-1992 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए सर्व श्री विजय सिंह तथा एस० के० खंडेलवाल के स्थान पर नामित किया है :--

(1) श्री अजीत सिंह बिशनार, 164/1, श्रीनगर कालोनी, इन्दौर-452002 (म० प्र०) एवं

(2) श्री टी० एस० अंकलेसरिया, "गुलिस्तान", डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, रतलाम-457 001 (म० प्र०)।

केन्द्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारिणी समिति के आदेशानुसार

ह०/- अपठनीय
उप प्रबंधक निदेशक (सहयोगी बैंक)

न्यू बैंक आफ इंडिया

कार्मिक विभाग

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 3 जुलाई 1989

संख्या 5007 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू बैंक आफ इंडिया के निदेशकमंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा न्यू बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी विनियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

2. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(I) यह विनियम न्यू बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी विनियम 1982 कहे जाएंगे।

(II) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. न्यू बैंक आफ इंडिया अधिकारी सेवा विनियम, 1982 के वर्तमान विनियम 23(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

"(1) 20-8-1988 को तथा इस तारीख से यदि वह नीचे सारणी के कालम 1 में दिए गए स्थान पर कार्यरत है, उस स्थान के सामने कालम 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकार भत्ता :--

सारणी

स्थान	दरें
क–क्षेत्र 1 में विभिन्न स्थान तथा गोवा राज्य	वेतन का 10% परन्तु अधिकतम रुपये 200/- प्रति माह
ख—5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों तथा राज्य, राजधानियों, एवं चण्डीगढ़ पाण्डेचेरी और पोर्ट ब्लेयर, जो उक्त "क" में शामिल नहीं हैं	वेतन का 6% परन्तु अधिकतम रुपये 120/- प्रतिमाह

खुशाल सिंह
सहायक महा प्रबन्धक (कार्मिक)

देना बैंक

कार्मिक विभाग प्रधान कार्यालय

बम्बई-400005, दिनांक 13 सितम्बर 1989

सं०एच०क्यू०पी०ई० आर० आई०आर० 5456/89---बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण)

अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देना बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :--

2. संक्षिप्त शार्षक और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का नाम देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियन 1989 होगा।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. विनियम 23(I) यथा संशोधित

दि० 20-8-1988 को और से यदि वह निम्नलिखित तालिका के कालम 1 में उल्लिखित स्थान पर कार्यरत हो तो नगर प्रतिपूरक भत्ता उनके कालम 2 में उस स्थान के सामने दर्शायी गयी दर पर होगा :--

तालिका

स्थान	दरें
(क) क्षेत्र 1 में स्थान और गोवा राज्य में	मूल वेतन का 10% बशर्ते कि अधिकतम रु० 200/- प्रतिमाह हो।
(ख) 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पांडीचेरी एवं पोर्ट ब्लेयर जो उपर्युक्त (क) में शामिल नही है।	मूल वेतन का 6% बशर्ते कि अधिकतम रु० 120/- प्रतिमाह हो।

आर०एन० बुच सहायक महा प्रबंधक (कार्मिक)

भारतीय चार्टेड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई-400 005, दिनांक 29 अगस्त, 1989

सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (5)/11/89-90--इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/9/88 दिनांक 1-2-1989, 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/11/88 दिनांक 5-1-1988, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	06158	श्री प्रतापराय जिवालाल गोरडीया, एफ० सी० ए०, मार्फत : सनराईस एजन्सी, 114, बैंक आफ बरोदा बिल्डिंग, (अब डेवलपमेंट को-आप० बैंक बिल्डिंग, 4था मंजला, पल्टन रोड, बम्बई-400 001.	12-6-89
2.	30618	श्री बाबूराव वासुदेव नीम, एसीए. 9/ए, शिवस्मारक गोल्ड फिल्ड, सोलापुर-413 007	11-7-89

स० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (5)/12/89-90--इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/5/85-86 दिनांक 30-9-85 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/11/87-88 दिनांक 5-1-88, 4 डब्ल्यू० सी० ए० (11)/80-81 दिनांक 31-3-81, 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/7/86-87 दिनांक 25-2-87, 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/8/83-84 दिनांक 26-3-84, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	30143	श्री प्रविणचंद्रा अमिदास मेहता, एफ० सी० ए० द्वारा-गोलवाला क्लासिस प्रा० लि०, 2रा माला, बम्बई म्यूचल बिल्डिंग, 293, डी० एन० रोड, फोर्ट, बम्बई-400 001.	21-6-89

1	2	3	4
2.	30693	श्री किरन जमनादास शाह, ए० सी० ए०, 1, सुरज सारस्वती रोड, सांताक्रुज (प) बम्बई-400 054.	3-8-89

एम० सी० नरसिम्हन
सचिव

कलकत्ता 700071, दिनांक 21 सितम्बर 1989

सं० 3-ई० सी० ए० (4)/4/89-90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 26 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्न-लिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	3624	श्री बाल कृष्ण थोफ, मैसर्स बी० के० थोफ एण्ड कं०, 23ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700 001	13-7-89
2.	2243	श्री अमल चन्द्र चक्रवर्ती, टैम्पल चैमबर्स, 6, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001	5-7-89
3.	4648	श्री जुगल किशोर लाहोटका, मैसर्स जे० लाहोटका एण्ड कं०, 16, मंगोइ लेन, कलकत्ता-700 001	2-8-89
4.	4830	श्री अमरचन्द भुटेरिया, मैसर्स ए० सी० भुटेरिया एण्ड कं०, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-700 001	9-7-89
5.	5144	श्री सोमनाथ बसु, 21/7, अश्विनी दत्त रोड़, कलकत्ता-700 029	19-2-89
6.	5446	श्री मोहन लाल सिंघी, मैसर्स सिंघी एण्ड कं०, 1बी, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-700 001	18-8-89
7.	14981	श्री समीर कुमार रुदा, 6बी, शंकर घोष लेन, कलकत्ता-700 006	1-8-89
8.	52058	श्री समीर कुमार मुखोपाध्याय, फ्लैट नं० 48/बी, ब्लॉक बी सी, सैक्टर-1, साल्ट लेक, कलकत्ता-700 064	24-9-88

एम० सी० नरसिम्हन
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 1989

सं० एन० 15/13/20/1/85-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-10-1989 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा जम्मू तथा काश्मीर कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1988 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ जम्मू तथा काश्मीर राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाति व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात्

काश्मीर क्षेत्र

क्र० सं०	क्षेत्र	हदबस्त संख्या
1	2	3
1.	श्रीनगर नगर की नगरपालिका सीमाएं	--
2.	श्रीनगर कैंट की नगरपालिका सीमाएं	--
3.	ग्राम कानमोह	246
4.	रत्नग्रेथ बुदगाम जिले में	284

1	2	3
5.	पम्पपोर	105
6.	काहन	98
7.	मिश्रपोरा	92
8.	बाग	15
9.	कतगाम	63
	जम्मू क्षेत्र	
	(1) जम्मू	
1.	जम्मू नगर की नगरपालिका सीमाएं	–
2.	जम्मू कैंट की नगरपालिका सीमाएं	– –
3.	ग्राम मिटान साहिब (बन मुलतान)	37
4.	मुट्ठी	190
5.	गंगयाल	155
	(2) बर्गी-अखनूर	
1.	बेगपुर	208
2.	मैन सरकार	206
3.	मैन सरकान	205
4.	मसी खुर्द	220
5.	रामीलपुर	201
6.	करथाली	203
7.	मिरानाह	230
	(3) कठुआ	
1.	चाक राजू	79
2.	चाक राम सिंह	70
3.	जगतपुर	62
4.	चाक खुर्नी	69

एन० बोस
निदेशक यो० एवं विकास

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

सीमा शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर, दिनांक 29 सितम्बर, 1989

संदर्भ: सी० नं० VIII/17/202/89 सी० शु० विधि सीमा शुल्क (नाम का प्रकाशन) नियम 1975 के नियम 3(1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) के अंतर्गत दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम और विवरण नीचे निर्दिष्टानुसार प्रकाशित करता हूं ।

दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम और पता	अपराध का स्वरूप	दंडादेश अधिनियम करने वाले न्यायालय का नाम	अपराधिक मामला संख्या	दोषसिद्धि की तारीख	अधिनिर्णित दंड के विवरण
1	2	3	4	5	6
कि० वत्सलन, के० कुंचप्पा के पुत्र "श्रीकला" अम्बिलाद, कूतुपरम्बा पोस्ट, तेलिचेरी तालुक, कन्नूर जिला, केरल राज्य ।	रु० 46,000/- मूल्य की विदेशी मूल की दो सोने के पेलेट्स की किसी भी अन्य प्रकार से व्यवहार अथवा रखने, ले जाने, छुपाने, खरीदने से संबंद्ध जिसे वह जानता था अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 की 52) की धारा III(डी) के अधीन जब्ती के योग्य है, यह विश्वास करने के कारण थे ।	III अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेलगांव ।	सी०सी०नं० 1474/88	7-2-1989	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135(1) (बी) (ii) के अधीन अपराध दंडनीयसिद्ध हुआ और 1,750/- रुपये और जुर्माना देने का दंडादेश हुआ और संदाय के अभाव में 20 दिनों का साधारण कारावास ।

जे० पी० कौशिक
समाहर्ता सीमा शुल्क, बंगलौर

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 1988-89 (जुलाई-मार्च)

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अधीन निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

अध्याय 1

परिचालन वातावरण और परिप्रेक्ष्य

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भाऔविनि) का निदेशक बोर्ड 31 मार्च 1989 को समाप्त हुई नौ माह की अवधि के लेखा परीक्षित लेखा विवरण सहित भाऔविनि के परिचालनों पर 41वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1.02 भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में एकरूपता लाने का निर्णय लिए जाने के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों ने भी वित्तीय वर्ष को जुलाई-जून से अप्रैल-मार्च आधार पर परिवर्तन करने का निर्णय लिया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भाऔविनि) के मामले में भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना सं० एफ०2(37) वीवि 1/88 दिनांक 26 दिसम्बर 1988 को जारी की गई, जिसके द्वारा औद्योगिक वित्त निगम नियम 1965 में संशोधन किया गया और भाऔविनि को जुलाई-जून के बजाय अप्रैल-मार्च के आधार पर लेखाकन वर्ष परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गयी। अतः भाऔविनि ने 30 जून के स्थान पर अपने खाते 31 मार्च, 1989 को बंद किए। प्रस्तुत की जा रही रिपोर्ट नौ माह की अवधि, अर्थात् पहली जुलाई, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की है। पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं दिए गए हैं, पूरे 12 माह के वित्तीय वर्ष (जुलाई-जून) के हैं, अतः यथातथ्य तुलनात्मक नहीं हैं।

1.03 यह उचित ही है कि 31 मार्च, 1989 को को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान भाऔविनि की परिचालन गतिविधियों, कार्य प्रगति और कार्य परिणामों की पृष्ठभूमि के रूप में 1988-89 (अप्रैल-मार्च) में देश की अर्थव्यवस्था, विद्यमान निवेश वातावरण, औद्योगिक परिदृश्य और भावी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त चर्चा की जाए।

(क) भारतीय अर्थव्यवस्था 1988-89

1.04 वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार तीन वर्षों के प्रतिकूल मानसून के पश्चात् अच्छे मानसून और व्यावहारिक वित्तीय प्रबन्ध के कारण वृद्धि-युक्त बहुमुखी सुधार परिलक्षित हुआ, और पुनः यह प्रदर्शित हो गया, कि अर्थ-व्यवस्था निरन्तर प्रगति के पथ पर ही थी।

1.05 उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि उत्पादन, 1987-88 के 2.1% की कमी की तुलना में, 1988-89 (अप्रैल-मार्च) में 18.9% तक बढ़ जाने की आशा है। 1988-89 में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि 170 मिलियन टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन होना है, जो कि 22.8% वृद्धि को द्योतक है। 1988-89 में अवस्थापना क्षेत्र के सर्वोत्तम निष्पादन के फलस्वरूप औद्योगिक विकास में 1987-88 के 7.4% की तुलना में लगभग 9% की वृद्धि होने की आशा है। औद्योगिक क्षेत्र में त्वरित उच्च विकास दर, 1980 के दशक के प्रारम्भ में सरकार द्वारा शुरू की गई उदारीकरण नीति और अनुवर्ती वर्षों में इसे और भी गतिशीलता प्रदान करने के फलस्वरूप अनुकूल प्रभाव की द्योतक है। इसके अतिरिक्त कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्र आपसी निवेश एवं निर्गत के पारस्परिक सम्बन्धों के कारण, एक दूसरे को शक्ति-प्रदायक सिद्ध हुए प्रतीत होते हैं।

1.06 माल और सेवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के कारण 1988-89 में मुद्रा-स्फीति दर प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रण में रही। अप्रैल, 1988-मार्च 1989 के बीच में थोक मूल्य सूचकांक में केवल 6.1% की वृद्धि बिन्दु से बिन्दु आधार पर हुई, जबकि 1987-88 में यह वृद्धि बिन्दु से बिन्दु आधार पर 10.5% थी। अर्थव्यवस्था में त्वरित आर्थिक विकास को समाहित करने, साथ आवश्यकताओं पर दुष्प्रभाव डाले बिना अधिक मांग दबाव को नियंत्रित करने, तथा प्रमुख अंशधारी के रूप में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करने की भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों से समर्थित सरकार की समग्र राजकोषीय नीति काफी प्रभावशील रही।

1.07 निर्यात में 29% तक की वृद्धि के बावजूद, आयात में 23.9% तक वृद्धि होने के कारण व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 6,624 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 7,512 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। आयात बिल में वृद्धि मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेलों और खाद्यान्नों जैसी थोक मदों के प्रवर्धित आयात और उत्पादन के लिए आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं जैसे, लोहा और इस्पात, अलौह धातुएं, धातु छीजन, रबड़, कागज आदि, के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में असामान्य रूप से वृद्धि तथा विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण हुई है।

1.08 यद्यपि भुगतान संतुलन स्थिति और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां अत्यधिक दबाव में रहीं, तथापि वर्ष 1988-89 में स्थिति काफी नियन्त्रण में रही। अप्रवासी भारतीयों से आवक धनराशियों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा (अप्रवासी) लेखा योजना के अधीन जमाराशियों पर ब्याज दरों में वृद्धि, और, अप्रवासी भारतीयों के लिए विशेष बांड निर्गम करने, और उच्चतर बाहरी सहायता के लिए लिए गए नीति प्रयासों से भुगतान स्थिति के संतुलन पर सार्थक प्रभाव पड़ा।

1.09 बाह्य स्थिति पर दबाव के बावजूद, समग्र घरेलू स्थिति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त रूप से सुदृढ़ हुई, और एक त्वरित मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की (1980-81 के मूल्यों पर) विकास दर में वर्ष 1986-87 में 3.8% और वर्ष 1987-88 में 3.6% की तुलना में 9% वृद्धि होने का अनुमान है। सारणी 1 1987-88 से 1988-89 में प्रतिशत परिवर्तन सहित दोनों वर्षों के भारतीय अर्थव्यवस्था के चुने हुए संकेतक 1987-88 के वास्तविक और 1988-89 के अनुमानित प्रस्तुत करती है।

(ख) निवेश वातावरण और पूंजी बाजार

1.10 स्टाक बाजार में स्फूर्ति, आर्थिक विकास में उत्थानशीलता, संतोषजनक निगमित परिणाम प्रभावी वित्तीय उपाय सक्षम प्रतिस्पर्धा और निवेश कर्ताओं में विश्वास पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से निरन्तर नीति सुधार, आदि, कारणों से वर्ष 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान देश में निवेश वातावरण उत्साहवर्धक रहा। वर्ष 1988-89 (अप्रैल-नवम्बर, 1988) में विदेशी सहयोग अनुमोदन में 1987-88 की उसी अवधि की तुलना में 15.1% वृद्धि हुई। इसी प्रकार आशय पत्रों में 11.3% की वृद्धि हुई। पूंजीगत माल निर्यातों में 45.7% की वृद्धि हुई।

सारणी 1 : भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट सूचक

आधारभूत आर्थिक सूचक	इकाई	1987-88 (अप्रैल-मार्च)	1988-89 (अप्रैल-मार्च)	1987-88 की तुलना में 1988-89 में प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनसंख्या	मिलियन	785.0	801.4	2.0
—सकल राष्ट्रीय उत्पाद (सराउ) (1980-81 मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	1,68,919	1,84,122	9.0
—निवल राष्ट्रीय उत्पाद (निराउ) (1980-81 मूल्यों के आधार पर)	रु० करोड़	1,50,573	1,64,125	9.0
—सराउ प्रति व्यक्ति (1980-81 मूल्यों के आधार पर)	रु०	2,151	2,297	6.8
—निराउ प्रति व्यक्ति (1980-81 मूल्यों के आधार पर)	रु०	1,918	2,048	6.8
—कृषि उत्पादन सूचकांक	1969-70=100	149.3	177.6	18.9
—खाद्यान्न उत्पादन	मिलि० टन	138.4	170.0	22.8
—उर्वरक उत्पादन (पोषकों के आधार पर नाइट्रोजन पोटाश खाद)	मिलि० टन	7.13	8.96	25.7
—बिजली उत्पादन	बिलियन किलोवाट	201.9	220.8	9.4
—कोयला उत्पादन	मिलि० टन	179.7	194.6	8.3
—तेल उत्पादन (कच्चा)	मिलि० टन	30.3	32.0	5.6
—सीमेंट उत्पादन	मिलि० टन	39.5	44.6	11.3
—बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	मिलि० टन	8.59	9.21	7.2
—रेलवे द्वारा राजस्व-अर्जक माल यातायात	मिलि० टन	290.2	302.1	4.1
—प्रमुख बंदरगाहों पर माल का लदान-उतार	मिलि० टन	133.8	149.9	12.0
—औद्योगिक उत्पादन (सामान्य सूचकांक)	1980-81=100	166.4	181.0	8.8
—निर्यात	रु० करोड़	15,719	20,281	29.0
—आयात	रु० करोड़	22,343	27,693	23.9

1	2	3	4	5
—व्यापार सन्तुलन	रु० करोड़	(—) 6,624	(—) 7,412	11.9
—विदेशी मुद्रा रिजर्व (स्वर्ण एवं विशिष्ट आहरण अधिकारों को छोड़कर)	रु० करोड़	7,287	6,605	(—) 9.4
—विदेशी सहायता (संवितरण वर्ष की समाप्ति पर)	रु० करोड़	5,032	5,369	6.7
—ऋण शोधन	रु० करोड़	2,623	2,770	5.6
—मुद्रा पूर्ति (मुद्रा)	रु० करोड़	1,61,503	1,88,474	16.7
—बैंक उधार	रु० करोड़	70,089	83,266	18.8
—वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा	रु० करोड़	1,17,574	1,38,855	18.1
—थोक मूल्य सूचक (औसत)	1970-71=100	405.1	435.0	7.3
—औद्योगिक कामगारों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचक (औसत)	1960=100	736	803	9.1
—मुद्रा स्फीति दर (उ०मू०सूची०-कामगार पर आधारित) (बिन्दु से बिन्दु आधार पर)	(प्रतिशत)	9.8	8.6	—

सारणी 2 में 1987-88 और 1988-89 में औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिंदा सूचकों के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 2 : औद्योगिक निवेश वातावरण के चुनिंदा सूचक

सूचक	इकाई	1987—88 (अप्रैल—मार्च)	1988—89 (अप्रैल—मार्च)	1987—88 की तुलना में 1988—89 में प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—विदेशी सहयोग	संख्या	385*	443*	15.1
—अनुमोदित विदेशी निवेश	रु० करोड़	110	240	118.2
—जारी किये गये आशय पत्र	संख्या	647*	720*	11.3
—प्रदान किये गये औद्योगिक लाइसेंस	संख्या	255*	201*	(—) 21.2
—तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण	संख्या	715*	450*	(—) 37.1
—लाइसेंस-मुक्त उद्योगों के लिए औद्योगिक विकास सचिवालय द्वारा अनुमोदन	संख्या	1,062*	836*	(—) 21.3
—पूंजी माल निर्बाधता	रु० करोड़	800 (680)@	991 (अप्रैल-फरवरी)	45.7
—पूंजी निर्गमों के लिए अनुमति (बोनस निर्गम सहित)	रु० करोड़	4,689 (4,238)@	5,352 (अप्रैल-फरवरी)	26.3
—पूंजी निर्गम	रु० करोड़	5,167	8,113	57.0

1.11 स्टाक और पूंजी बाजार के लिए, 1988-89, बाजार मूल्य और व्यापारवर्त को सुव्यवस्थित और न्यायसंगत रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने का एक वर्ष रहा। 1988-89, (अप्रैल-मार्च) के दौरान पूंजी निर्गम नियंत्रक ने सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा नवीन पूंजी जुटाने के लिए पूंजी निर्गम (अर्थात् सहमति और पावती) के लिए लगभग 8,113 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जो 1987-88 की इसी अवधि की तुलना में 57% अधिक थी। यह वृद्धि संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम के कारण हुई जिसकी राशि उक्त अवधि के दौरान 3,133 करोड़ रुपये थी। सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, अर्थात् भाऔविबैंक, भाऔविनि, भाऔसानिनि, भाऔपु बैंक, जाबीनि, भायू ट्रस्ट, साबीनि, राविनि और राविनि द्वारा मंजूर की गई सहायता में 1988-89 में 60% की

वृद्धि परिलक्षित हुई। इसी प्रकार उपर्युक्त वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए संवितरणों में भी पिछले वर्षों के संवितरणों से 36.2% की वृद्धि हुई।

1.12 पूंजी बाजार को गतिशील बनाने के लिए, वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में संशोधन करते हुए स्टाक एक्सचेंज की निगमित सदस्यता को प्रभावी करने और बहुसंख्यक सदस्यता की अनुमति देने के प्रयास किए गए। उपर्युक्तानुसार, भाप्रविनि को भी 8 मार्च, 1989 को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज का सदस्य दाखिल कर लिया गया। शेयर अन्तरण प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। कम्पनी के विद्यमान और नए शेयरों के मूल्यों में समता सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय इक्विटी सूची प्रस्तुत करने के उपाय किए गए, और निवेशकर्त्ताओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, दलालों को प्रशिक्षित करने और स्टाक एक्सचेंज को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी, 1989 को जयपुर स्टाक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने से देश के मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की संख्या 16 हो गई।

1.13 अन्य नीति संबंधी कदम, जिन से पूंजी बाजार अवस्थापना को सुदृढ़ करने में सहायता मिली, वे थे—चुने हुए उद्योगों के लिए निवेश भत्ता पुन आरम्भ करना तथा धारा 115 ञ के अधीन नियति पर अर्जित लाभ के संबन्ध में न्यूनतम पर लागू न करना, आदि। शेयरों और डिबेंचरों के सार्वजनिक/अधिकारिक निर्गमों के अति-अभिदान अवधारण के विद्यमान मार्गनिर्देशों में संशोधन किए गए, और उसे 15% के समान स्तर पर लाया गया। वित्तीय संस्थानों द्वारा अति-अभिदान की 11% सीमा हटाई गई। सरकार ने नई कम्पनियों द्वारा उनके आरंभिक पूंजी के निर्गम के समय प्रवर्तक कम्पनी/कम्पनियों के शेयरधारियों और आरंभिक पूंजी का निर्गम करने वाली कम्पनी के कर्मचारियों को अधिमानत आबंटित शेयरों के लिए तीन वर्षों की अवरोध अवधि को हटाने का निर्णय लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि वे कर्मचारियों को उनकी अपनी कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिए क्रय मूल्य के 90% तक ऋण प्रदान करें, बशर्ते कि यह राशि 20,000/- रुपये से अधिक न हो।

1.14 भारत सरकार ने दिनांक 13 फरवरी, 1989 से किसी कम्पनी के स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए न्यूनतम इक्विटी पूंजी की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये और जनता को अभिदान के लिए न्यूनतम राशि 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 180 लाख रुपये कर दी। इससे न केवल सूचीकरण के लिए पात्र निर्गमों के आकार में वृद्धि और स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के बाद उनकी द्रव्यता संभावनाओं में वृद्धि होगी, अपितु इससे गौण बाजार के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा। विद्यमान कम्पनियों को प्रदत्त शेयर पूंजी की 10 करोड़ रुपये या 40% की मद्रा सीमा सहित उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चयनात्मक आधार पर विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति दी गई। इसी प्रकार विदेशी कम्पनियों को भी भारत में नए उपक्रमों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई।

1.15 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भाप्रविबोई), डिस्काउंट एंड फाइनेन्स हाउस ऑफ इण्डिया (डीएफएचआई) और भारतीय स्टाक धारण निगम लिमिटेड (एम एचसीआईएल) द्वारा किए गए कार्यों से भी पूंजी बाजार के परिचालन सांविधिक रूप से प्रभावित हुए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मेरिल लिंच कैपीटल सर्विसिज इन्कारपोरेटिड के सहयोग से अमरीका में भारतीय विकास निधि चलानी आरंभ की। इस निधि ने अप्रवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकर्त्ताओं को भारतीय प्रतिभूति बाजार में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने के अवसर प्रदान किये। एनबीआई कैपिटल मार्किट्स लि० ने दूसरा मेगनम आरम्भ किया, जिसमें निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80एम के अधीन कर-लाभ प्राप्त होगा।

1.16 वर्ष के दौरान पूंजी बाजार के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना नवीन जोखिम पूंजी कम्पनियों या जोखिम पूंजी निधियों के प्रवर्तन के लिए ढांचा तैयार किया जाना था। नवीन प्रौद्योगिकी-उन्मुख उद्यमों को, जहां जोखिम बहुत अधिक हो, उद्यमी अर्हता प्राप्त हों परन्तु उनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव हो, उनको महत्वपूर्ण इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए एक मुख्य नीति प्रयास के रूप में जोखिम पूंजी मार्गनिर्देश जारी किए गए।

1.17 यद्यपि 1989-90 के बजट के समय स्टाक बाजार में सतर्कता की स्थिति व्याप्त थी, फिर भी अर्थव्यवस्था की मौलिक सुदृढ़ता के कारण स्टाक मूल्य अधिक ऊंचे चल रहे थे। बम्बई स्टाक एक्सचेंज सेन्सिटिव इक्विटी मूल्य सूचकांक (1978-79=100), जो स्टाक बाजार का बैरोमीटर है, 28 फरवरी, 1989 (बजट से पूर्व) को 663.84 था, जो 29 फरवरी, 1988 के 411.22 के बजट-पूर्व सूचकांक से 252.62 पाइंट (614.4% अधिक था। इकनोमिक टाइम्स (अखिल भारतीय) [सूचकांक (1984-85=100) 31 मार्च, 1989 को इक्विटी शेयरों के लिए 394.8 था, जो 31 मार्च, 1988 को एक वर्ष के सूचकांक से 75.5% वृद्धि-युक्त था।

(ग) औद्योगिक परिदृश्य

नीतिगत पहलू

1.18 सरकार की औद्योगिक नीति के पहलू बाजार माहौल की स्थापना में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, और औद्योगिक कार्य-निष्पादन को भी अनुप्राणित करते हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान आश्रयी औद्योगिक उपक्रमों के प्रवेश या विस्तार और उत्पादन के कुशल पैमाने की

मान्यता पर बल देने सहित औद्योगिक नीति में लगातार सुधारों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इन सुधारों को मुख्यत तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात (i) क्षमता सृजन को सुविधाजनक बनाने के उपाय, (ii) उत्पादन विस्तार को सुविधाजनक बनाने के उपाय, और (iii) प्रक्रियात्मक रुकावटें दूर करने के उपाय।

1.19 क्षमता सृजन को सुविधाजनक बनाने के उपायों के अधीन, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसमुक्ति के एक बड़े पैकेज की घोषणा की गई। गैर-एम०आर०टी०पी० और गैर-फेरा संस्थाओं की परियोजनाओं के सम्बन्ध में केवल कम विकसित रूप में घोषित क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये या गैर-अविकसित क्षेत्रों में स्थित 15 करोड़ रुपये से अधिक की अचल परिसम्पत्तियों में निवेश करने वाली परियोजनाओं को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने अपेक्षित रखे गये, अन्यथा लगभग सभी मामलों में लाइसेंसमुक्ति व्यवस्था लागू कर दी गई, बशर्ते कि नगरों और शहरों के मानक शहरी क्षेत्रों/नगर सीमाओं की सीमा से निर्दिष्ट दूरी, सीमाओं वाली परियोजनाओं की स्थापना के लिए कुछ प्रतिबन्ध एवं शर्तों का पालन हो। लाइसेंसमुक्त उद्योगों की स्थान-निर्धारण आवश्यकताओं की दूरी सीमाओं के अनुरूप बनाया गया। आयातित उत्पादनों की अपेक्षा सीमा, वार्षिक उत्पादन के फैक्टरी इतर मूल्य के 15% या अधिकतम 75 लाख रुपये से बढ़ाकर पहले वर्ष के उत्पादन के फैक्टरी इतर मूल्य के 30% कर दी गई, और, इसके साथ-साथ ऐसे आयातित उत्पादनों के लिए 75 लाख रुपये अधिकतम सीमा भी हटा दी गई। एकाधिकार प्रतिबन्ध एवं व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 20 ख के अधीन पंजीकृत प्रमुख उपक्रमों को भी उन मदों को छोड़कर, जिनमें औद्योगिक उपक्रम एक प्रमुख औद्योगिक उपक्रम के रूप में पंजीकृत हैं, सभी मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस से छूट दी गई।

1.20 वर्ष 1988–89 के दौरान 11 और उद्योगों के परिवर्धन से न्यूनतम आर्थिक पैमाना योजना के अधीन सम्बन्धित उद्योगों की कुल संख्या 84 हो गई। इसके अतिरिक्त 5 उद्योगों, अर्थात्, कार्बन ब्लैक, हाट रोल्ड स्ट्रिप यूनिट्स, स्टोरेज बैटरियां, छत के पंखे और इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों के सम्बन्ध में विद्यमान न्यूनतम आर्थिक क्षमताओं में भी संशोधित एवं परिवर्धन किया गया।

1.21 उत्पादन विस्तार की सुविधा के उपायों के अधीन, दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से लाइसेंसीकृत क्षमता की पुनर्पृष्ठांकन योजना नामक एक उदारीकृत योजना लागू की गई। इसके अतिरिक्त, जिन उद्योगों के लिए क्षमता का स्वत: पुनर्पृष्ठांकन उपलब्ध नहीं होता और जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है, उन उद्योगों की संख्या 77 से घटाकर 26 कर दी गई। अनेक उद्योगों को विस्तृत वर्गीकरण की सुविधा दी गई, जिससे विनिर्माण उद्यम, परिवर्तनशील बाजार स्थितियों के अनुरूप अपने उत्पाद मिश्र का समायोजन करने और बेहतर क्षमता उपयोगिता की सुविधा में समर्थ हो सकें। कुल मिला कर, दिसम्बर, 1988 तक 40 उद्योग विस्तृत वर्गीकरण के क्षेत्र में लाये गये। परिशिष्ट-1 उद्योग सूची, और कुछ निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अधीन गैर-परिशिष्ट-1 उद्योग सूची, के सम्बन्ध में एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को भी विस्तृत-वर्गीकरण-सुविधा प्रदान की गई। 33,000 टन, या इससे अधिक वार्षिक क्षमता वाली कागज मिलों को मुक्त रूप से अखबारी कागज में विशाखित करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि उनके पास 20,000 टन वार्षिक अखबारी कागज की रिक्त क्षमता हो। शीरे के अतिरिक्त कच्चे माल पर आधारित पेय अल्कोहल के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजन के प्रतिबन्ध में पूर्ण ढील दी गई। इस उपाय से विशेषत: औद्योगिक अल्कोहल के विनिर्माण के लिए शीरे की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने परिशिष्ट-1 के अधीन उद्योग सूची में दो नई मदें (i) खनन रसायन और (ii) सीमेंट रसायन, जैसे वाइंडर तीव्र सेट होने वाले और पतले रसायन, शामिल करने का निर्णय लिया। सभी प्रकार के फल और सब्जी उत्पाद, सिवाय घुल उद्योग के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर, विस्तृत-वर्गीकरण योजना के अधीन, संसाधित-भोजन की श्रेणी के अधीन लाये गये।

1.22 प्रशासकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, पहली जून, 1985 के बाद जारी किए गए आशय पत्रों की वैधता अवधि तीन वर्ष तक बढ़ा दी गई। इसी प्रकार तकनीकी विकास महानिदेशालय और अन्य तकनीकी प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त पंजीकरणों की वैधता पहली जून, 1985 से दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई। विदेशी कम्पनियों को भी औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग, और उन्हें अपने नाम से अन्य अनुमोदनों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई, और एक बार ऐसा अनुमोदन प्राप्त होने पर विदेशी कम्पनियों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत में कम्पनी निगमित करना अपेक्षित किया गया। 10 फरवरी, 1989 को सरकार ने उद्यम और संस्थानात्मक स्तरों पर अनुसंधान और विकास दोनों में विदेशी सहयोग को प्राप्त करने की अनुमति भी दे दी।

1.23 कम विकसित क्षेत्रों के उद्योगीकरण के लिए भारत सरकार ने लगभग अगले पांच वर्षों में सम्पूर्ण देश में 100 विकास केन्द्र स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। ये विकास केन्द्र, विकास केन्द्रों में अवस्थापना के पर्याप्त विकास की मार्फत, कम विकसित क्षेत्र के उद्योगों को को आकर्षित करने के लिए "गुरुत्व केन्द्र" के रूप में कार्य करेंगे। सबसे पहले, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 61 विकास केन्द्र विकसित किये जायेंगे, अर्थात् उत्तर प्रदेश में 6, मध्य प्रदेश और बिहार में पांच-पांच, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में चार-चार, कर्नाटक, उड़ीसा,

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तीन-तीन, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल और पंजाब में दो-दो और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी और त्रिपुरा में एक-एक विकास केन्द्र । इसके अतिरिक्त सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के मामले में उनकी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष उपचार की आवश्यकता पर बल दिया जायेगा, और भिन्न आधारों पर तत्सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

1.24 प्रत्येक विकास केन्द्र में 400 से लेकर 800 हेक्टेअर भूमि अधिग्रहण करके, मुख्यतः लघु और मध्यम आकार की इकाइयों को आबंटित करके उनका विकास करने की योजना है, प्रत्येक विकास केन्द्र की उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए 25 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक की निधि प्रदान की जानी है । सरकार ने दिनांक 14 फरवरी, 1989 से विकास केन्द्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लाइसेंसिंग नीति मानदण्डों में भी ढील दे दी है । एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति सामान्यतः विकास केन्द्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक फ्रेमवर्क और प्रक्रिया प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्नशील है ।

1.25 कुछ विशेष उद्योगों के मामले में भी, विभिन्न सरकारी उपायों की मदद से उन उद्योगों के निष्पादन में सहायता मिली । भारत सरकार ने खुले रूप में बिक्री योग्य चीनी का अधिकतम कोटा बढ़ा कर चीनी उद्योग के लिए एक नवीन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की । इसके अतिरिक्त 1250 टन प्रतिदिन गन्ना पेरने की कमजोर क्षमता वाली इकाइयों को 2,500 टन प्रतिदिन गन्ना पेरने तक, विस्तार करने की अनुमति प्रदान की । सीमेंट और अल्यूमीनियम के मूल्य और वितरण पर नियन्त्रण समाप्त कर दिया गया । दिनांक 1 मई, 1988 से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विनिर्मित माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए 50 प्रतिशत की दर से परिवहन उप-सहायता प्रदान की गई । 13 फरवरी, 1989 को जूट विनिर्माण निर्यातकों के लिए एक बाह्य बाजार सहायता की घोषणा की गई । उत्पादकों, उद्योग और सरकार के बीच अन्तर विचार आदान-प्रदान मंच उपलब्ध करने के लिए सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड के अनुरूप जूट सलाहकार बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई । जनवरी, 1989 में तिलहन उत्पादन, आयात, वितरण और मूल्य की एक समेकित नीति की भी घोषणा की गई । कुछ थोक औषधि विनिर्माण इकाइयों को औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1987 से छूट प्रदान करने के मार्गनिर्देशों की घोषणा हुई । पेट्रोरसायन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोरसायन क्षेत्र के प्रवर्तन के लिए एक पेट्रोरसायन प्रवर्तन और विकास एजेंसी की स्थापना की गई । अर्ध निर्मित अवस्था में परिष्कृत चमड़े के विनिर्माण की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना का प्रतिबन्ध हटाया गया, और नई इकाइयों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया और जूते और चमड़े का सामान बनाने वाली विद्यमान इकाइयों के महत्वपूर्ण विस्तार की सुविधा प्रदान की गई ।

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति

1.26 1988-89 के दौरान देश में उन्नत औद्योगिक सम्बन्ध वातावरण के कारण, जिसमें औद्योगिक अशांति की कोई मुख्य घटना न होना सम्मिलित है, और इसके साथ-साथ उपर्युक्त नीतिगत पहलुओं की सहायता से उद्योग ने पर्याप्त प्रगति अर्जित की । औद्योगिक उत्पादन का औसत सूचकांक (आधार 1980-81—100) जो 1985-86 में 142.1, 1986-87 में 155.1 और 1987-88 में 166.4 था, 1988-89 में बढ़कर अनुमानतः 181.1 हो गया, जिससे 8.8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर परिलक्षित हुई, जो कि सातवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत पर लक्ष्य की गई वार्षिक वृद्धि से भी कहीं अधिक थी ।

1.27 औद्योगिक उत्पादन के मासिक सरकारी सूचकांक में प्रवृत्तिवार निरन्तर वृद्धि हुई, और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बेहतर निष्पादन हुआ, जो कि सारणी 3 से स्पष्ट है ।

सारणी 3 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक

1980-81=100

मास	1987-88	1988-89	प्रतिशत अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल .	156.7	170.8	9.0
मई .	149.6	174.0	16.3
जून .	158.5	180.2	13.7
जुलाई .	164.9	170.7	3.5
अगस्त .	155.6	170.0	9.3
सितम्बर .	161.9	172.1	6.3
अक्तूबर .	158.0	175.1	10.8
नवम्बर .	166.4	180.3	8.3
दिसम्बर .	175.8	193.5	10.1
जनवरी .	175.1	191.8	9.5
फरवरी .	177.7	185.6	4.4
मार्च .	196.6	208.1(पी)	5.8
अप्रैल से मार्च के दौरान औसत .	166.4	181.0	8.8

(पी) अनन्तिम

1.28 1987-88 और 1988-89 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्रवार प्रवृत्तियां (क्रमशः वास्तविक और अनुमानित) सारणी 4 में दी गई हैं ।

सारणी 4 : औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति

1980-81=100

भार	क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
		1987-88 (अप्रैल-मार्च)	1988-89 (अप्रैल-मार्च)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.46	खान एवं खदान	3.8	7.8*
77.11	विनिर्माण	7.9	8.9*
11.43	बिजली	7.7	9.4
100.00	समस्त उद्योग	7.4	8.8

*अनन्तिम

1.29 1988-89 के दौरान अवस्थापना क्षेत्र का निष्पादन समग्रतः हर्षवर्धक रहा । छः अवस्थापना उद्योगों के संयुक्त सूचकांक, जिनमें बिजली, कोयला, बिक्री-योग्य स्टील, कच्चा पेट्रोलियम,, पेट्रोलियम परिष्कृत उत्पादन और सीमेंट शामिल हैं, और जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 28.8 प्रतिशत के भार का उत्तरदायी है, अप्रैल-जनवरी, 1988-89 में, पिछले वर्ष की इसी अवधि से 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1987-88 की 7.7 प्रतिशत की तुलना में 1988-89 के दौरान कुल बिजली उत्पादन में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1988-89 में कोयला उत्पादन, पिछले वर्ष के 179.7 मिलियन टन की तुलना में 194.6 मिलियन टन हुआ, जिसमें 8.3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । 1988-89 के दौरान सीमेंट उत्पादन 44 मिलियन टन हुआ, जबकि 1987-88 में यह 39.5 मिलियन टन था, और इस प्रकार इसके उत्पादन में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1985-86 के दौरान समेकित स्टील संयंत्रों द्वारा बिक्री-योग्य स्टील का उत्पादन, पिछले वर्ष के उत्पादन से 7.2 प्रतिशत अधिक किया गया । समीक्षाधीन वर्ष में समेकित स्टील संयंत्रों के समग्र क्षमता उपयोग में 66 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 57 प्रतिशत थी । 1988-89 के दौरान उर्वरक उत्पादन, पिछले वर्ष के 7.13 मिलियन टन की तुलना में, 8.96 मिलियन टन हुआ, जिसमें 25.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में, जो पिछले वर्ष 30.3 मिलियन टन था, 32 मिलियन टन तक की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 5.6 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है । रेलवे के माल वहन पर अर्जित राजस्व में 4.1 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1988-89 के दौरान प्रमुख बन्दरगाहों पर जहाजी माल का निपटान पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक रहा । वर्ष 1988-89 के दौरान दूर संचार के क्षेत्र के कार्य वस्तुतः काफी अच्छे रहे । अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान टेलीफोन व्यवस्था में 1.53 लाख लाइनों की अतिरिक्त स्विचिंग क्षमता का सृजन किया गया, जो अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान सृजित 1.27 लाख लाइनों की अतिरिक्त स्विचिंग क्षमता से 20.5 प्रतिशत अधिक था । उपलब्ध कराये गये कुल नए कनेक्शनों में 34.4 प्रतिशत कनेक्शन महानगरों में दिए गए, और अन्य क्षेत्रों में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

1.30 वर्ष 1988-89 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में समग्रतः वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत रही । इसकी खास विशेषता, इसकी पर्याप्त व्यापकता है । विभिन्न उद्योगों, विशेषतः इलेक्ट्रानिक्स, उर्वरक, एल्यूमिनियम आदि के क्षेत्र में 25 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक की विकास दर परिलक्षित हुई । अप्रैल, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि की सूचना और आंकड़ों के आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 44.9 प्रतिशत संयुक्त भार वाली दो अंक स्तर के 17 उद्योग समूहों में से 8 उद्योग समूहों की विकास दर 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के बीच रही । इसमें रसायन (18.8 प्रतिशत), गैर-धातु खनिज उत्पाद (17.1 प्रतिशत), रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद (15.5 प्रतिशत), मशीनरी और मशीन टूल्स (15 प्रतिशत), परिवहन उपस्कर (12.3 प्रतिशत), जूट वस्त्र (12 प्रतिशत), विविध उत्पाद उद्योग (10.4 प्रतिशत) और मूल धातु और अलौह उत्पाद (10.2 प्रतिशत) शामिल हैं । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 6.82 प्रतिशत भार वाले टैक्सटाइल उत्पादों में 55.6 प्रतिशत असाधारण वृद्धि हुई । सूचकांक में 13.1 प्रतिशत के भार वाले चार उद्योग समूहों की विकास दर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत रही । इन उद्योग समूहों में खाद्य उत्पाद (8.3 प्रतिशत), विद्युत मशीनरी (7.1 प्रतिशत), पेय तथा तम्बाकू (6.4 प्रतिशत), और लकड़ी और लकड़ी उत्पाद (5.2 प्रतिशत) शामिल हैं । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 5.5 प्रतिशत भार वाले धातु उत्पाद तथा कागज और कागज उत्पाद में विकास दर क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत धीमी रही । (12.8 प्रतिशत भार वाले) शेष समूहों में से सूती वस्त्र और चमड़ा उत्पाद में क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत नकारात्मक विकास दर परिलक्षित हुई ।

1.31 वर्ष 1987-88 के आंकड़ों के आधार पर, व्यापक उपयोग-आधारित उद्योग समूहों के विकास के विश्लेषण से यह पता चलता है, कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 16.4 प्रतिशत भार वाले पूंजीगत माल क्षेत्र में विकास 16 प्रतिशत रहा । इसके बाद 23.7 प्रतिशत

भार वाला उपभोक्ता माल क्षेत्र आता है, जिसमें 7.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । उपभोक्ता माल में तीव्र प्रगति की प्रोत्साहक विशेषता यह रही कि वर्ष 1987-88 में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता माल की विकास दर में 7.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 1986-87 के दौरान यह वृद्धि 4.9 प्रतिशत थी । फिर भी मूल उद्योगों की विकास गति जिनका सूचकांक में भार 39.4 प्रतिशत है, काफी धीमी रही । इस क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसके विपरीत वर्ष 1986-87 में यह वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी । 20.5 प्रतिशत भार वाले मध्यस्थ माल क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई, जो वर्ष 1986-87 के विकास कार्यों में न्यूनतम सुधार की द्योतक है । वर्ष 1988-89 में विकास दरों में महत्वपूर्ण सुधार सहित, कम या अधिक यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर प्रतीत हुई ।

1.32 जहां तक क्षमता उपयोग का सम्बन्ध है, 1988-89 के दौरान इसमें कुछ विशेष सुधार हुआ । परिशिष्ट-1 में वर्ष 1988-89 के लिए 60 चुनिंदा औद्योगिक उत्पादों की संस्थापित क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग प्रतिशत और उनके संदर्भ में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 521 वित्तपोषित संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर समकक्षी आंकड़े दिए गए हैं ।

उद्योगों की वित्तीय प्रगति

1.33 401 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के एक सेम्पल के (जिनके खाते 31 मार्च, 1988 को या उससे पूर्व बन्द हो गए थे) वित्तीय प्रगति के अध्ययन से पता चलता है, कि वर्ष 1987-88 के दौरान अचल परिसम्पत्ति निरूपण, बिक्रियों और उत्पादन मूल्य में सुधार परिलक्षित हुआ, यद्यपि उनके परिचालन परिणाम दबावपूर्ण स्थिति में रहे । 1987-88 में, इन सेम्पल कम्पनियों की कुल आय में 2,785 करोड़ रुपये की वृद्धि होने से कुल आय बढ़कर 29,571 करोड़ रुपये हो गई, जबकि ब्याज अदायगियों को छोड़ कर कुल व्यय में 2,673 करोड़ रुपये की वृद्धि होने से यह बढ़कर 26,762 करोड़ रुपये हो गया । यद्यपि सकल लाभ 112 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, परिचालन लाभ में 39 करोड़ रुपये का सीमान्त ह्रास हुआ । वित्त अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप संयंत्र और मशीनरी के मामले में सेम्पल कम्पनियों पर प्रभारित मूल्य ह्रास की उच्चतर दरें महत्वपूर्ण रूप से उनके लाभप्रदता अनुपात में सीमान्त ह्रास के लिए मुख्यतः उत्तरदायी रहीं । 398 करोड़ रुपये की लाभांश अदायगियां करने के बाद, जो पिछले वर्ष से 61 करोड़ रुपये अधिक थीं, 1987-88 में धारित लाभ की राशि 526 करोड़ रुपये रही, जबकि वर्ष 1986-87 में यह राशि 640 करोड़ रुपये थी । इन कम्पनियों द्वारा प्रवर्धित सकल मूल्य 1986-87 के 6,614 करोड़ रुपये से बढ़कर 1987-88 में 7,372 करोड़ रुपये हो गया, अर्थात् 11.5 % की वृद्धि हुई । 1987-88 के दौरान 23,129 करोड़ रुपये की सकल अचल परिसम्पत्तियों में 12 % की विकास दर परिलक्षित हुई, जो संयंत्र और मशीनरी के रूप में प्रवर्धित अचल परिसम्पत्ति निरूपण का लगभग 50 % थी । वर्ष 1987-88 के दौरान, कुल सामान सूची में 6.1% की कम दर से वृद्धि हुई, जबकि 1986-87 में यह वृद्धि 9 % थी । पूंजी पर प्रतिफल (कुल नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ, अर्थात् निवल मूल्य और कुल उधार), बिक्री पर मार्जिन (बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ) में शेयरधारियों की ईक्विटी पर आय में (निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात् लाभ) में पिछले वर्ष की तुलना में सीमान्त ह्रास हुआ ।

1.34 तथापि, 1988-89 के पहले अर्ध-वर्ष में, 140 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से लिए गए निगमित क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन के पुनरीक्षण से निष्पादन में बहुमुखी प्रगति परिलक्षित होती है । यह प्रगति 31 मार्च, 1988 के बाद समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान (अनेक्षा-परीक्षित अप्रकाशित वित्तीय परिणामों के आधार पर) बिक्री में वृद्धि, सकल लाभ और मार्जिन पर लाभ से परिलक्षित होती है । यद्यपि बिक्री और सकल लाभ में पिछले इसी अर्ध-वर्ष के आंकड़ों से क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 33.1 % वृद्धि हुई, बिक्री का मार्जिन भी 8.7 % से बढ़ कर 10 % हो गया ।

(घ) संभावनाएं और परिप्रेक्ष्य

1.35 उद्योग ने 1988-89 के दौरान पर्याप्त विकास दर अर्जित की है । वर्षों में किए गए अनेक प्रमुख सुधारों के परिणामस्वरूप उद्योग क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है । इसके अतिरिक्त, मूल्यों में उपयुक्त स्थिरता और मुद्रा-स्फीति नियंत्रण से, बेहतर निवेश वातावरण सृजित हुआ है और औद्योगिक परिप्रेक्ष्य और भी प्रतिस्पर्धात्मक और आशाजनक बना है ।

1.36 1988-89 में राजकोषीय उपायों विशेषतः, कृषि और कृषि-आधारित कार्याकलापों को रियायतें, निवेश भत्ते का पुनः प्रारम्भ और चुनिंदा उद्योगों को शुल्क राहतों से उत्पादन, कृषि और उद्योग क्षेत्र दोनों को आवश्यक प्रोत्साहन मिला है, साथ ही निर्यात कार्यों, निर्यातकों और निर्यात गृहों को राजकोषीय प्रोत्साहनों से निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है । आयकर अधिनियम की धारा 80 ज ज ग के अधीन निर्यात लाभ को आयकर से छूट प्रदान करना, जिसे बढ़ाकर 100 % तक कर दिया गया है, उससे निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण बनने की संभावना है 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को 5 वर्ष कर अवकाश देने से निर्यात को अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेगा; यह सुविधा अभी तक "मुक्त व्यापार जोन" को ही प्राप्त थी ।

1.37 प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अधीन प्रदत्त ढीलें, विशेषतः उत्पादन के लिए आवश्यक चुनिंदा कच्चे माल पर सीमा शुल्क 100-180 % घटा कर 55 % कर देना और तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन

प्रौद्योगिकी और पूंजीगत माल के आयात की विद्यमान सीमा को प्रति इकाई 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ाना जैसे उपाय क्षेत्र मे बृहत्तर आत्म-निभरता को बढ़ावा देने में पर्याप्त सहायक होंगे। अनेक अभिनिर्धारित निर्यात प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त मशीनरी पर आयात शुल्क से घटाने से निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा। प्रत्यक्ष कर-विधि (संशोधन) अधिनियम 1988, जो अनुमोदित होटलों, भ्रमण परिचालकों और यात्रा एजेंटों द्वारा अर्जित अपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 100% छूट, निर्यात लाभों और अनुमोदित होटलों द्वारा अर्जित लाभों को आयकर अधिनियम की धारा 115 ञ से छूट, तथा अप्रवासी भारतीय बांडों में निवेशकर्ताओं को कुछ कर रियायतों और भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई परियोजनाओं द्वारा की गई तकनीकी सेवाओं के लिये किसी विदेशी कम्पनी द्वारा अर्जित शुल्क में छूट के लिये प्राधिकृत करना है, उसने पर्यटन और पर्यटन से सम्बन्धित कार्य-कलापों और अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

1.38 1988-89 में साख नीति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में, साख प्राधिकरण योजना में समग्र परिवर्तन, बिल वित्तपोषण को प्रोत्साहन, समूह आधार पर नहीं, अपितु पद्धति में द्रव्यता की अनुचित वृद्धि के बिना निर्धारित दरों पर अल्पकालीन ब्याज-दर संरचना मे लचीलापन आदि कारणों से पर्याप्त बैंक उधार उपलब्ध कराना संभव हुआ। बैंकिंग पद्धति में अल्पकालीन द्रव्यता के समायोजन की सुविधा के लिए अन्तर-बैंक भागीदारी प्रमाण-पत्र नामक एक नवीन प्रलेख और डिस्काउंट हाउस आफ इण्डिया के परिचालनों से मुद्रा बाजार मे पर्याप्त नम्यता आई है।

1.39 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1989 को 1989 90 के अर्ध-वर्ष के लिये घोषित साख नीति द्वारा मुद्रा पद्धति मध्यम और दीर्घकालीन दोनों के कार्यों को सरलीकृत और सुधार करने के अनेक प्रयास किये गये हैं। इसका उद्देश्य मुद्रा नीति की कार्य विधि में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करना है, जिसका आरम्भ 1988–89 में किया गया था। 15–45 दिनों के अल्पावधि बैंक जमा, जिस पर 3% वार्षिक ब्याज लगता है, का पहला स्लेब दिनांक 28 मार्च, 1989 को समाप्त कर दिया गया है, 46 से 90 दिनों के दूसरे स्लेब के लिये, ब्याज दर 4% वार्षिक से बढ़ाकर 6% कर दी गई है। पहली मई, 1989 से अन्तर-बैंक मांग जमा बाजार पर लागू 10% वार्षिक ब्याज-दर सीमा हटा ली गई है। चयनात्मक साख नियंत्रण में परिशोधन किया गया है, और कुछ उद्योगों के मामले में बैंक अग्रिम पर न्यूनतम मार्जिन कम कर दिया गया है। विद्यमान मुद्रा बाजार प्रलेखों में दो नवीन मुद्रा बाजार प्रलेखों, अर्थात्, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्रों का समावेश किया गया है, जो स्वागत-योग्य है। जबकि जमा प्रमाण-पत्रों का उद्देश्य मुद्रा बाजार प्रलेखों की श्रेणी में विस्तार करना और निवेशकों को उनकी अल्पकालीन अधिशेष निधियों का निवेश करने का बेहतर लचीलापन प्राप्त होना है; वाणिज्यिक पत्रों से प्रतिष्ठित निगमित निकायों को उनके अल्पकालीन उधारों के स्त्रोत को विशाखित करने एवं निवेशकों को एक अतिरिक्त प्रलेख में निवेश करने का लाभ प्राप्त होगा। पहली जुलाई, 1989 से आरम्भ होने वाले पखवाड़े से नकद आरक्षित अनुपात से संबंधित बहुखण्ड निर्धारण को सम्पूर्ण मांग और बैंकों की समय देयताओं के 15% एकल निर्धारण से बदला जा रहा है।

1.40 1989-90 के केन्द्रीय बजट में पूंजी बाजार को उत्प्रेरित करने के लिये अनेक सकारात्मक विशेषतायें हैं। उदाहरणार्थ, 18,000-25,000/- रुपये के आय वर्ग के लिये कर दर 25% से घटा कर 20% कर दी गई है। बांडों और डिबेंचरों पर 2,500/- रुपये तक ब्याज अदायगियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती हटा दी गई है। जोखिम पूंजी के शेयरों की बिक्री प्राप्त पूंजीगत आय के सम्बन्ध में, जोखिम पूंजी कम्पनियों को, गैर-निगमित कर दाताओं को उपलब्ध समान दर पर कटौती करने की अनुमति दी गई है। अस्पतालों की स्थापना में लगी कम्पनियों के शेयरों में निवेश को भी धारा 80 ग ग के अधीन रियायतें प्रदान की गई है। इक्विटी में व्यक्तिगत बचत प्रवाह को उत्प्रेरित करने के लिये, 1989-90 के बजट में भारतीय यूनिट ट्रस्ट और मान्यताप्राप्त पारस्परिक निधियों द्वारा इक्विटी से सम्बद्ध बचत योजना चलाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अधीन ऐसी बचत में निवेश को निवल वार्षिक परिवर्द्धन के आधार पर कर कटौती के लिये उपयुक्त बनाया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने गृह निर्माण कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिये गृह ऋण खाता योजना की घोषणा की है। इस योजना के अधीन जमा राशियों पर कर रियायतें दी जायेंगी। परियोजनाओं के लिए आयात पर, और बहुत सी वस्तुओं पर आयात कर कम कर दिया गया, अथवा युक्तियुक्त बना दिया गया है। रुग्ण किन्तु आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों के लिये उत्पादन शुल्क में रियायतों से औद्योगिक विकास में काफी बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 1989-90 में सम्पूर्ण घाटा 7,337 करोड़ रुपये के न्यूनीकृत स्तर पर प्रक्षेपित किया गया है, जबकि 1988-89 में घाटे की यह राशि 7,940 करोड़ रुपये थी। 1989-90 के लिये केन्द्रीय योजना व्यय की राशि 28,715 करोड़ रूपये बढ़ाकर 34,446 करोड़ रूपये कर दी गई है, जिसमे लगभग 20% वृद्धि परिलक्षित होती है। इन सभी प्रयासों से 1989-90 में बचत और निवेश में पर्याप्त वृद्धि की संभावना है।

1.41 निःसन्देह, भुगतान सन्तुलन पर दबाव के कारण दुर्लभ विदेशी मुद्रा के सुविवेचित नियोजन पर बल दिया जाना है, और निर्यात कार्य को भी पर्याप्त बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सौभाग्य से, समाज के सभी वर्गों में निर्यात के प्रति जागरूकता आई है, इसने चालू वर्ष में समग्रतः विदेशी मोर्चे पर देश के आर्थिक निष्पादन को बेहतर बनाने में सहायता

मिलेगी। पावर की उपलब्धता में अवरोध सहित, पावर आपूर्ति की सम्पूर्ण कमियां आर्थिक उत्पादन की प्रमात्रा और गुणवत्ता पर निरन्तर कठोर सीमा लगाती रहती है। अतः भविष्य को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उच्चतर निवेश द्वारा बेहतर प्रौद्योगिकी और पावर क्षेत्र में परिचालन कार्यों के सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस सन्दर्भ में, गैस आधारित संयंत्रों में तत्काल निवेश, उर्जा संरक्षण उपायों और बृहत्तर उपाय से वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

1.42 विश्व अर्थ व्यवस्था में अप्रत्याशित परिस्थितियों और गतिविधियों को छोड़कर 1989-90 में एक अच्छी विकास दर की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार 1989–90 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 10% या इससे भी उच्चतर वृद्धि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अध्याय 2

परिचालन, संसाधन एवं कार्य परिणाम

(क) परिचालन

समग्र परिचालन

2.01 वर्ष 1988-89 की नौ माह की अवधि के दौरान, भा० औ०वि०नि० की समग्र मंजूरियां, इसकी विभिन्न सहायता योजनाओं के अधीनस्थ 604 परियोजनाओं के लिये 1,333.34 करोड़ रुपये की रहीं। ये मंजूरियां, पिछले वर्ष, अर्थात् 1987-88 की नौ माह की अवधि के वार्षिकीय आधार पर मंजूरियों की तुलना में 31.6% अधिक थीं।

2.02 वर्ष के दौरान, कुल संवितरण, पिछले वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में संवितरित 730.22 करोड़ रुपये के स्थान पर 739.92 करोड़ रुपये के रहे। ये संवितरण पिछले वर्ष के नौ माह की अवधि के वार्षिकीय आधार पर किये गये संवितरणों की तुलना में 35.1% अधिक थे।

2.03 संचयी रूप से मार्च, 1989 के अन्त तक भा०औ०वि०नि० द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त समग्र मंजूरियां, 3,159 परियोजनाओं के लिये 6,546.78 करोड़ रुपये की रहीं। 31 मार्च, 1989 तक समग्र संवितरण 4,352.08 करोड़ रुपये के रहे, जिसमें से नकद संवितरण, अर्थात् निर्गमित गारन्टी रहित संवितरणों की राशि 4,275.17 करोड़ रुपये की थी। 31 मार्च, 1989 तक कुल बकाया राशि, ऋणियों द्वारा पुनर्भुगतानों की निवल राशि छोड़कर 3,577.78 करोड़ रुपये थी।

सहायता का योजनावार वर्गीकरण

2.04 परियोजना वित्त के अतिरिक्त, भा०औ०वि०नि० अब औद्योगिक क्षेत्र की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अनेक योजनायें चला रहा है। ये हैं—(क) उपस्कर वित्तपोषण योजना, (ख) उपस्कर लीजिंग, (ग) उपस्कर उपार्जन, (घ) पूर्तिकार उधार, तथा (ङ) लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को वित्तीय सहायता योजना। 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान मंजूर और संवितरित सहायता का मुख्य योजनावार वर्गीकरण एवं 31 मार्च, 1989 को संचयी स्थिति सारणी 5 में दी गई है।

सारणी 5 मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजनावार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण योजना	1989-89			31 मार्च 1989 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परियोजना वित्त (उपस्कर वित्त सहित) .	535	1,210.00	671.32	3,055	6,339.91	4,265.31
उपस्कर लीजिंग . . .	29	75.38	50.83	31	90.45	65.90
उपस्कर उपार्जन . . .	8	4.61	0.62	8	4.61	0.62
पूर्तिकार उधार . . .	16	30.55	0.71	38	88.51	3.81
लीजिंग एवं किराया खरीद-संस्थाओं को सहायता	16	12.80	16.44	27	23.30	16.44
जोड़	604	1,333.34	739.92	3,159	6,546.78	4,352.08

परियोजना वित्त

2.05 वर्ष 1988-89 (जुलाई—मार्च) की अवधि के दौरान परियोजना वित्त मंजूरियों की राशि (उपस्कर वित्त सहित) 1987-88 के 1,267.34 करोड़ रुपये की तुलना में 1,210.00 करोड़ रुपये रही। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंजूरियां और संवितरण चार मुख्य शीर्षकों अर्थात् रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान और गारंटियों के अधीन दर्शाते हुए परियोजना वित्त का सुविधावार वर्गीकरण तथा 31 मार्च, 1989 तक संचयी और इसी तिथि को बकाया राशियों का वितरण सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6—परियोजना वित्त का सुविधावार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

सुविधा	1988-89 (जुलाई—मार्च)		31 मार्च 1989 तक संचयी		31 मार्च, 1989 को बकाया
	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजना वित्त					
—रुपया ऋण . .	784.36	547.40	4,537.93	3,397.39	2,739.16
—विदेशी मुद्रा ऋण . .	359.47	105.15	1,247.74	673.36	616.77
—हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान	64.96	13.04	421.57	117.65	111.75*
गारंटियां .					
—आस्थगित अदायगियां हेतु .	0.64	5.73	85.09	44.60	16.57
—विदेशी ऋणों हेतु .	0.57	—	47.58	32.31	15.94
जोड़ . .	1,210.00	671.32	6,339.91	4,265.31	3,500.19

*इसमें इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित बकाया ऋण राशि का भाग, जहां ऋण सहायता की मंजूरी के समय संपरिवर्तन के अधिकार की शर्त रखी गई थी, इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित संपरिवर्तनीय डिबेंचर और शेयरों/डिबेंचरों में संपरिवर्तित बकाया ऋणों (अतिदेय ब्याज आदि) के भाग भी शामिल हैं।

2.06 रुपया ऋण की मांग अत्यधिक रही, जिसके कारण रुपया ऋण का भाग परियोजना वित्त की कुल मंजूरियों का 64.8% रहा। इसके बाद विदेशी मुद्रा ऋणों का स्थान आता है, जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंजूर किये गये कुल परियोजना वित्त का 29.7% रहे। वार्षिकीय आधार पर पिछले वर्ष की नौ माह की अवधि की तुलना में रुपया वित्त मंजूरियों, (ऋणों, हामीदारियों और प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में) 10.4% और विदेशी मुद्रा ऋणों में 117.6% की वृद्धि परिलक्षित हुई।

निवेश परिचालन

2.07 भा० औ० वि० नि० ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 61 संस्थाओं को साधारण शेयरों की हामीदारी के रूप में 44.57 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, और एक संस्था को अधिमान शेयर निर्गम के लिये 0.69 करोड़ रुपये की हामीदारी की मंजूरी दी। इस प्रकार 1987-88 की वार्षिकीय आधार पर नौ माह की अवधि के दौरान अनुमोदित कुल हामीदारी सहायता की तुलना में 1988-89 में मंजूर की गई हामीदारी सहायता 2.4% अधिक रही।

2.08 अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में की गई मंजूरियों में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई। 1987-88 के दौरान शेयरों और डिबेंचरों के प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में जबकि 76 संस्थाओं को 15.16 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी, 1988-89 की 9 माह की अवधि के दौरान शेयरों और डिबेंचरों के प्रत्यक्ष अभिदान के लिये 82 संस्थाओं को 19.70 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जो पिछले वर्ष की नौ माह की इसी अवधि के लिये वास्तविक आधार पर 29.9% और वार्षिकीय आधार पर 73.3% अधिक थी।

2.09 इस अवधि के दौरान, भा० औ० वि० नि० ने जिन संस्थाओं के शेयरों की हामीदारी की थी, उनमें से 27.58 करोड़ रुपये के 49 निर्गम पूंजी बाजार में जारी किये गए। हामीदारी दायित्व के रूप में जो शेयर भा० औ० वि० नि० को लेने पड़े, उनकी राशि 5.28 करोड़ रुपये की रही। इसके अतिरिक्त भा० औ० वि० नि० ने प्रत्यक्ष अभिदान के सम्बन्ध में की गई मंजूरियों के लिये 48 कम्पनियों के 9.07 करोड़ रुपये के शेयरों और डिबेंचरों में अभिदान किया।

गारंटियां

2.10 इस अवधि के दौरान, मशीनरी और उपस्कर के विदेशी संभरकों को दो मामलों में 0.64 करोड़ रुपये

की आस्थगित अदायगी गारन्टी सहायता मंजूर की गई। ये इकाइयां थी—(i) आन्ध्र प्रदेश में एक सीमेंट इकाई और (ii) पश्चिम बंगाल में एक जूट मिल। उड़ीसा में अलौह धातु इकाई से संबंधित एक मामले में विदेशी मुद्रा ऋण के लिये 0.57 करोड़ रुपये की गारन्टी भी दी गई। तथापि, जहां तक गारण्टियों के निष्पादन का सम्बन्ध है, इस अवधि के दौरान समग्रतः 5.73 करोड़ रुपये की राशि के लिये आस्थगित अदायगी गारण्टियों का निष्पादन किया गया।

1988-89 में परियोजना वित्त के अधीन सहायता का प्रयोजन-वार वर्गीकरण

(क) नई परियोजनाओं को सहायता

2.11 1988-89 (जुलाई—मार्च) में भा०औ०वि०नि० द्वारा 1,210 करोड़ रुपये की कुल मंजूर परियोजना वित्त सहायता में से 66.5% (804.17 करोड़ रूपये) 166 नई परियोजनाओं को मिली। पिछले वर्ष की नौ माह की वार्षिकीय आधार पर मंजूरियों से इस वर्ष नई परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता 78.5% अधिक रही। इनमें से 5 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपये तक थी, 35 परियोजनायें अलग-अलग 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये की पूंजी लागत के बीच की थीं, 43 परियोजनाओं की, प्रत्येक की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच की थीं, 30 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रूपये के बीच थी, और 53 परियोजनायें ऐसी थी, जिनकी पूंजी लागत प्रति परियोजना 20 करोड़ रुपये से अधिक थीं।

(ख) विस्तार एवं विशाखन योजनाओं के लिये सहायता

2.12 1988-89 (जुलाई—मार्च) में विस्तार और विशाखन कार्यक्रमों के लिये 48 परियोजनाओं को 82.21 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई जो परियोजना वित्त के अधीन कुल मंजूर सहायता का 6.8% थी।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिये सहायता

2.13 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिये 132 परियोजाओं को 127.50 करोड़ रुपये की सहायता (परियोजना वित्त के अधीन कुल सहायता का 10.5%) मंजूर की गई, जबकि 1987-88 में 218 परियोजनाओं के लिये यह सहायता 246.68 करोड़ रुपये की थी।

2.14 इसी अवधि के दौरान, उदार ऋण योजना के अधीन 64 परियोजनाओं को 86.26 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई, जबकि वर्ष 1987-88 में यह सहायता 88 परियोजनाओं के लिये 127.50 करोड़ रुपये की थी।

(i) चीनी इकाइयों का आधुनिकीकरण

2.15 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 2,500 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता तक प्रासंगिक विस्तार करने के साथ-साथ आधुनिकीकरण करने वाली चीनी इकाइयों को, जो न्यूनतम 5 पेराई (परिचालन) मौसमों में परिचालनरत रही हों, उदार ऋण योजना के अधीन आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करने की भी सहमति हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी परियोजनाओं की प्रोत्साहन योजनाओं के वित्त-पोषण के लिये अन्तर मंत्रालय समूह की बैठक में हुई सहमति के अनुसार चीनी इकाइयों द्वारा 2,500 टन दैनिक गन्ना पेराई क्षमता तक आधुनिकीकरण/विस्तार योजनाओं के मामले में ऋण इक्विटी अनुपात 1:1 तक रखे जाने की भी सहमति हुई। वित्तीय संस्थान, उन चीनी इकाइयों के विषय में, जिनको प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऋण मोचन सीमा अनुपात, परिसम्पत्ति सीमा अनुपात और चालू अनुपात के अनुसार, मामले-वार आधार पर, 2,500 टन दैनिक गन्ना पेराई क्षमता से अधिक विस्तार करने वाली परियोजनाओं के गुणावगुण आधार पर, ऋण-इक्विटी अनुपात में ढील के औचित्य की जांच करेंगे। इस अवधि के अन्त में भा औ वि वि भा औ बैंक, भाऔ ना नि नि के संस्थानात्मक अधिकारियों की एक समिति का गठन भा औ वि नि के अग्रणी दायित्व में भी किया गया, जो चीनी इकाइयों की संख्या और स्वरूप (नई, विस्तार, आधुनिकीकरण आदि) से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करेगी और सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली प्रत्येक इकाई की जांच करेगी। यह समिति उद्योग के संसाधनों की कुल वित्तपोषण सम्बन्धी अपेक्षाओं, चरणबद्ध निवेश की संभावना, क्षेत्रीय संवितरण, गन्ने की उपलब्धता, चूक की स्थिति और अन्य उपयुक्त तथ्यों पर भी विचार करेगी।

(ii) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना

2.16 पहली अगस्त, 1986 से, प्रारम्भिक तौर पर दो वर्ष के लिये, आरम्भ की गई वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की इस अवधि में समीक्षा की गई, तथा योजना की अवधि में बढ़ोतरी इस प्रावधान के साथ की गई, कि सातवीं योजना के अंत में इसकी पुनः समीक्षा की जाए। साथ ही भा औ वि बैंक ने वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना की निकाय निधि बढ़ाने सम्बन्धी तथ्यों और आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसन्धान संस्था के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। अग्रणी संस्थान के रूप में भा औ वि बैंक ने वित्तपोषित इकाइयों के निष्पादन और कार्य परिणामों के निर्धारण के आधार पर वस्त्र उद्योग की हालत में सुधार लाने के लिये वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के प्रभाव का भी अध्ययन करने के लिये एक समिति का गठन किया। वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना से सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण निर्णय समीक्षाधीन अवधि के दौरान जो हुआ, वह था सहकारी क्षेत्र की कताई/संयुक्त इकाइयों को भी इस योजना के अधीन प्रवर्तक अंशदान के रूप में "विशेष ऋणों" के लाभ देना। इस योजना के अधीन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/औद्योगिक सहकारिताओं के रूप में निगमित बिजली करघा इकाइयों और स्वावलम्बी प्रक्रिया गृहों को भी सहायता

प्रदान करने की सहमति हुई। 1988-89 की जुलाई-मार्च अवधि के दौरान वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन भा औ वि नि ने 49 इकाइयों को लगभग 21.62 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, जबकि वर्ष 1987-88 में 84 इकाइयों को 59.60 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई थी।

(iii) जूट आधुनिकीकरण निधि योजना

2.17 जूट आधुनिकीकरण निधि योजना की भी जो 1 नवम्बर, 1986 से दो वर्ष के लिये आरम्भ की गई थी, समीक्षा करने पर इसकी अवधि 1 नवम्बर, 1988 से दो वर्ष के लिये बढ़ा दी गई। इस अवधि के दौरान जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के अधीन पांच परियोजनाओं को केवल 6.61 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। जूट आधुनिकीकरण निधि योजना की अनुवर्तन समिति सचिव (वस्त्र), भारत सरकार की अध्यक्षता में योजना का निरन्तर, अनुवर्तन और परिचालनों की समीक्षा करती रही। जूट मिलें जो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, प्रौद्योगिकी चुनाव, श्रम के यौक्तिकीकरण, आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप श्रम विस्थापन से उद्भूत समस्याओं और इन मामलों में सम्पूर्ण दृष्टि कोण के बारे में आशंकाओं, जैसे विभिन्न कारणों से यह निर्णय नहीं ले सकीं कि वे अपनी इकाइयों का आधुनिकीकरण करें या नहीं। इनके अतिरिक्त विद्यमान अधिकांश जूट इकाइयों के रुग्ण होने के कारण उन्हें तब तक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी, जब तक कि उन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड द्वारा इकाइयों के पुनरुद्धार के लिये पुनर्स्थापन पैकेज का अनुमोदन प्राप्त न हो जाये। फिर भी, केन्द्रीय सरकार/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान विभिन्न निवर्तमान मदों का निपटान करने के लिये निरन्तर प्रयास करते रहे।

(घ) पुनर्स्थापन सहायता सहित अधिव्यय सहायता

2.18 सामान्य अधिव्यय सहायता और पुनर्स्थापन सहायता आदि के रूप में 136 इकाइयों को 113.53 करोड़ रुपये (परियोजना वित्त के अधीन मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता का 9.4%) मंजूर किये गये, जबकि पिछले वर्ष 198 इकाइयों को 154.70 करोड़ रुपये की सहायता इस सन्दर्भ में मंजूर की गई थी।

परियोजना वित्त के अधीन भा औ वि नि की सहायता के विशेष पहलू (1988-89)

2.19 1988-89 में परियोजना वित्त के अधीन भा औ वि नि की सहायता की कुछ मुख्य विशेषतायें/पहलू इस प्रकार हैं—

—निगमित अस्पतालों और बहु आयामी स्वास्थ्य केन्द्रों को भा औ वि नि की सहायता योजना के अधीन 8 अस्पताल इकाइयों को 26.85 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

— महत्वपूर्ण निर्यात दायित्व वाली निर्यातोन्मुख 23 परियोजनाओं को 46.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

—166 नई परियोजनाओं में से 31 परियोजनायें ऐसी थी, जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई थी। इन्हें 54.51 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित बीस परियोजनाओं को 56.40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।

—समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 103 ऐसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई, जिनमें विदेशी सहयोग और/अथवा विदेशों से प्रौद्योगिकी अंतरण समाहित था। इन परियोजनाओं को 564.43 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

—आठ परियोजनायें ऐसी थी, जिन्होंने देश में पहली बार कुछ उत्पादों के विनिर्माण या देश में पहली बार बेहतर और उन्नत प्रौद्योगिकी आरम्भ करने पर विचार किया। ऐसी परियोजनाओं को 24.77 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में संबंधित योजनाओं के अधीन सहायता।

(i) उपस्कर वित्त

2.20 पूंजीगत उपस्कर की खरीद के लिए जो किसी विशिष्ट परियोजना से सम्बद्ध नहीं है, विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को रुपया और विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने के लिए, भाऔविनि 1984-85 से एक उपस्कर वित्त योजना चला रहा है, जिसके अधीन, समीक्षाधीन वर्ष में 53 इकाइयों को 82.59 करोड़ रु० की ऋण सहयता मंजूर की गई। पिछले वर्ष इस योजना के अधीन 65 इकाइयों को 67.03 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गई थी। संचयी रूप से भाऔविनि ने इस योजना के अधीन 162 इकाइयों को 186.19 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी।

(ii) उपस्कर लीजिंग

2.21 भाऔविनि, उपस्कर लीजिंग योजना के अधीन मास्टर लीज, सामूहिक लीज और बिक्री तथा लीज पुनखरीद व्यवस्था सहित वित्तीय लीज के रूपमें विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को देशीय और/अथवा आयातित उपस्कर उपलब्ध करवा रहा है। लीज पर उपलब्ध कराए गए उपस्कर सामान्यत. औद्योगिक उपस्कर/मशीनरी, ईपीएबीएक्स सिस्टम, कम्प्यूटर आदि हैं। प्रारम्भिक लीज अवधि पांच से आठ वर्ष और दूसरी लीज की अवधि पट्टा-धारी के विकल्प से नवीकृत की जा सकती है। 1 जून, 1988 से आरम्भ की गई इस योजना को पर्याप्त स्वीकार्यता प्राप्त हुई जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान एक माह में ही 15.07 करोड़ रुपए की लीज लागत पर उपस्कर प्रदान करने के दो लेनदेनों को अन्तिम रूप दिया गया, 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि

के दौरान 75.38 करोड़ रुपए की लीज लागत पर उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए 26 लेनदेनों को अन्तिम रूप दिया गया।

31 मार्च 1989 तक उपस्कर लीजिंग के अधीन संचयी रूप से 90.45 करोड़ रुपए की मंजूरियां दी गई थीं, जिनके अन्तर्गत 65.90 करोड़ रुपए का संवितरण किया जा चुका था।

(iii) उपस्कर उपार्जन

2.22 पहली नवम्बर, 1988 से लागू उपस्कर उपार्जन योजना के आरम्भ होने से भाऔविनि की विभिन्न वित्तीय सेवाओं में, वर्ष 1988-89 में, एक नया आयाम जुड़ गया। इस योजना के अधीन भाऔविनि उपस्कर उपार्जित करने की सहमति देता है और उसके बाद निगमित और/अथवा सहकारी क्षेत्र की पात्र विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को प्रलेखों के पृष्ठांकन द्वारा पुनिबिक्री करता है। स्थायी प्रभारों सहित उपस्कर का बीजक मूल्य क्रेता संस्था से 3 से 5 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है। इस योजना के अधीन हितोपभोगी संस्थाओं को मूल्य ह्रास और निवेश प्रभार का भी लाभ उपलब्ध है। 31 मार्च, 1989 को समाप्त पांच माह की अवधि में 8 विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं को 4.61 करोड़ रुपये की सहायता की मंजूरी दी गई। मार्च, 1989 के अन्त तक 0.62 करोड़ रुपये के संवितरण द्वारा एक शुरुआत की गई।

(iv) पूर्तिकार उधार

2.23 भाऔविनि द्वारा 1 जुलाई, 1987 से आरम्भ की गई पूर्तिकार उधार योजना की भी अच्छी स्वीकार्यता रही जिसमें आस्थगित आधार पर वास्तविक उपभोक्ता-क्रेता को अपने उपस्कर की बिक्री के लिए मशीनरी/उपस्कर तथा कम्प्यूटर विनिर्माता संस्थाओं को अनावर्ती ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अधीन 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान 16 उपस्कर विनिर्माता संस्थाओं को 30.55 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। संचयी आधार पर, 31 मार्च, 1989 तक पूर्तिकार उधार योजना के अधीन 38 उपस्कर विनिर्माता संस्थाओं को 88.51 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की जा चुकी थी। 31 मार्च, 1989 तक इस योजना के अधीन मंजूरियों के अन्तर्गत सम्पूर्ण संवितरण 3.81 करोड़ रुपये का रह. था।

(v) लीजिंग और किराया-खरीद संस्थाओं को वित्त

2.24 यद्यपि लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं के वित्तपोषण के लिए भाऔविनि की पहुंच चयनात्मक रही है, 1988-89 (जुलाई-मार्च) की नौ माह की अवधि के दौरान 16 लीजिंग संस्थाओं को 12.80 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। 31 मार्च 1989 तक भाऔविनि ने संचयी आधार पर 27 लीजिंग संस्थाओं को 23.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की थी, जिसके अन्तर्गत उक्त तारीख तक 16.44 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया था।

(vi) मर्चेन्ट बैंकिंग

2.25 31 मार्च 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान भाऔविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग और समवर्गीय कारोबार विभाग ने (बम्बई स्थित ब्यूरो कार्यालय सहित) 32 दत्तकार्य पूरे किए जिनमें से 25 सार्वजनिक निर्गम से संबंधित थे, और जिनसे ग्राहकों को 141.01 करोड़ रुपये की निधियां जुटाने में सहायता मिली संचयी रूप से भा औविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग एवं समवर्गीय कारोबार विभाग ने जुलाई, 1986 में अपने आरम्भ से और 31 मार्च, 1989 तक 77 दत्तकार्य पूरे किए थे, जिनमें 538.35 करोड़ रुपए की निधियां जुटाने के 59 सार्वजनिक निर्गम भी शामिल हैं। मर्चेन्ट बैंकिंग एवं समवर्गीय कारोबार विभाग अन्य वित्तीय सेवाओं विशेषतः परियोजना परामर्श, पूंजी पुनः संरचना, समामेलन, विलयन, न्यासिता दत्त कार्य आदि सम्मिलित करने के लिए अपने कार्यकलापों का धीरे धीरे विस्तार एवं विशाखन कर रहा है।

आवेदनों की प्राप्ति

2.26 भाऔविनि को परियोजना वित्त और इसके द्वारा प्राप्त वित्तीय सेवाओं से सम्बन्धित योजनाओं, दोनों के अधीन आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्थायी रूप से बनी रही।

2.27 परियोजना वित्त के अधीन, भाऔविनि ने 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान या तो स्वयं या संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर 602 पात्र संस्थाओं से 5,112.63 करोड़ रुपए के आवेदन (उपस्कर वित्त योजना के अधीन आवेदनों सहित प्राप्त किए। 64.50 करोड़ रुपए की सहायता के लिए 13 संस्थाओं के आवेदनों को, या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया, अथवा प्रगति के अभाव या प्रस्तावित परियोजना के व्यवहार्य न होने के कारण बन्द हुआ मान लिया गया। मार्च, 1989 के अन्त तक संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर कुल 251.68 करोड़ रुपए की सहायता के लिए भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 39 संस्थाओं (32 संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर) के आवेदन विचाराधीन थे। 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान 550 संस्थाओं के सभी आवेदनों पर वित्तीय सहायता मंजूर की गई; 97.3 प्रतिशत मामलों में निपटान पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से चार माह से भी कम की अवधि में सम्पन्न किया गया।

2.28 भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 29 संस्थाओं के आवेदनों के अतिरिक्त 1,278 करोड़ की समग्र सहायता के लिए 98 संस्थाओं के आवेदन भाऔविबैंक और भाऔसाविनि के अग्रणी दायित्व में, संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर 31 मार्च, 1989 की स्थित अनुसार विचाराधीन थे। इनमें भाऔविनि को सम्मिलित किए जाने और आगामी समय में भागीदार बनाए जाने की पूरी संभावना थी।

2.29 वित्तीय सेवाओं के अधीन अपनी योजनाओं सम्बन्ध में भाऔविनि ने 191.90 करोड रुपये की सहायता के लिए 98 संस्थाओं (उपस्कर वित्त योजना से भिन्न) से सहायता के आवेदनों पर विचार किया। इनमें से 66 संस्थाओं के आवेदनों के लिए भाऔविनि द्वारा उपलब्ध वित्तीय सेवाओं अर्थात् उपस्कर उपार्जन, उपस्कर लीजिंग, पूर्तिकार उधार, लीजिंग और किराया खरीद संस्थाओं को वित्तीय सहायता आदि के सम्बन्ध में सहा-

यता की मंजूरी दी गई। 24 संस्थाओं के आवेदन पात्रता के अभाव और/अथवा अन्य संबंधित तथ्यों के कारण वापस ले लिए माने गए, और 31 मार्च, 1989 को 11.20 करोड़ रुपये की सहायता के लिए 8 संस्थाओं के आवेदन भाओवित्त के विचाराधीन थे।

समग्र सहायता—उद्योग-वार

2.30 वर्ष 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान सहायता का उद्योग-वार प्रसार एवं 31 मार्च, 1988 तक संचयी आंकड़े सारणी 7 में दिए गए हैं।

सारणी 7 : सहायता का उद्योग-वार प्रसार

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1988-89 (जुलाई-मार्च)			31 मार्च, 1989 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी :						
—सहकारिताएं	17	41.73	3.1	215	283.30	4.3
—अन्य	15	21.06	1.6	85	121.49	1.9
वस्त्र	57	77.40	5.8	595	721.60	11.0
पटसन	7	8.85	0.7	38	46.79	0.7
रसायन :						
—मूल रसायन	21	31.98	2.4	138	352.71	5.4
—उर्वरक व कीटनाशक	18	235.72	17.7	71	506.61	7.7
—कृत्रिम रेशे	10	66.66	5.0	59	416.31	6.4
—कृत्रिम रेसिन्स, प्लास्टिक सामान व उत्पाद	26	128.97	9.7	100	243.89	3.7
—अन्य रसायन व रसायन उत्पाद	30	43.91	3.3	151	197.52	3.0
सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद	30	69.06	5.2	151	611.91	9.3
कागज व कागज उत्पाद	11	5.59	0.4	114	227.86	3.5
रबर उत्पाद	9	11.77	0.9	39	116.37	1.8
लोहा व इस्पात	52	117.65	8.8	205	487.48	7.4
मशीनरी तथा उपांग	36	66.83	5.0	194	287.38	4.4
परिवहन उपस्कर व पुर्जे	18	11.67	0.9	135	277.12	4.2
इलैक्ट्रानिक्स	35	91.26	6.9	137	307.07	4.7
बिजली मशीनरी व उपस्कर	15	17.84	1.3	98	148.58	2.3
धातु उत्पाद	20	29.96	2.2	107	144.10	2.2
अलौह धातुएं	10	14.45	1.1	40	93.61	1.4
विविध अधातु खनिज उत्पाद	18	27.14	2.0	86	155.37	2.4
गैस व बिजली	6	63.43	4.7	24	181.12	2.8
होटल	21	29.41	2.2	81	123.74	1.9
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं	8	26.85	2.0	17	44.61	0.7
विविध अन्य उद्योग	74	94.15	7.1	279	450.24	6.9
जोड़	604	1,333.34	100.0	3,159	6,546.78	100.0

2.31 1988–89 के दौरान भाऔविनि की सहायता में से जिन उद्योगों को उल्लेखनीय भाग प्राप्त हुआ वे थे—उर्वरक और कीटनाशक (17.7%) सिन्थेटिक रेसिन्स तथा प्लास्टिक का सामान/उत्पाद (9.7%), लोहा तथा इस्पात (8.8%) इलेक्ट्रानिक्स (6.9%) वस्त्र (5.8%) रसायन और रसायन उत्पाद (5.7%), सीमेंट (5.2%), सिन्थेटिक फाइबर्स (5.0%), मशीनरी व सहायक उपकरण (5.0%), गैस और बिजली (4.7%), चीनी (4.7%), धातु उत्पाद (2.2%), होटल (2.2%), विविध गैर धातु खनिज उत्पाद (2.0%), चिकित्सा, सेवायें (2.0%), और अन्य (12.4%)। कुल सहायता में से प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों, जैसे, उर्वरक, सिन्थेटिक रेसिन्स, लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रानिक्स, वस्त्र, रसायन और रसायन उत्पाद, सीमेंट, सिन्थेटिक फाइबर्स, मशीनरी और सहायक उपकरण, बिजली तथा गैस, चीनी, कागज, परिवहन उपस्कर अलौह धातु तथा विविध खाद्य उत्पाद, आदि, को 82.6% भाग प्राप्त हुआ।

2.32 संचयी आधार पर भाऔविनि के कुल निवेश में से वस्त्र, सीमेंट, उर्वरक, लोहा तथा इस्पात, लौह मिश्र धातु कृत्रिम रेशे तथा चीनी उद्योग सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में उभर कर आए, जिन्हें इस निवेश सहायता का 48 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ, इसके बाद मूल औद्योगिक आर्गनिक और गैर आर्गनिक रसायन (5.4 प्रतिशत), इलेक्ट्रानिक्स (4.7%), मशीनरी और उपकरण (4.4%), परिवहन उपस्कर (4.2%), आदि की स्थिति रही।

2.33 उत्पादों के उपयोग–आधारित वर्गीकरण के अनुसार वर्ष 1988–89 के दौरान एवं 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार संचयी मंजूर सहायता का उद्योग–वार वितरण सारणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8 : उत्पादों के उपयोग–आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग–वार वितरण

(करोड़ रुपए)

उद्योग	1988–89 (जुलाई–मार्च)			31 मार्च, 1989 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूल उद्योग	143	546.35	41.0	651	2,277.14	34.8
(अर्थात मूल धातु उद्योग, मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	(163)	(398.76)	(29.5)	(592)	(1,771.32)	(33.4)
पूंजी माल उद्योग	104	187.60	14.1	564	1,020.15	15.6
(अर्थात मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर आदि)	(158)	(245.67)	(18.2)	(507)	(849.53)	(16.0)
मध्यवर्ती माल उद्योग	125	331.55	24.9	614	1,433.80	21.9
(अर्थात रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब, आदि)	(153)	(387.69)	(28.7)	(541)	(1,123.79)	(21.2)
उपभोक्ता माल उद्योग	185	194.28	14.5	1,196	1,607.32	24.5
(अर्थात चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	(264)	(268.43)	(19.9)	(1,120)	(1,428.18)	(26.9)
सेवा उद्योग	47	73.56	5.5	134	208.37	3.2
(अर्थात होटल, चिकित्सा सेवायें, जहाजरानी, आदि)	(42)	(50.32)	(3.7)	(97)	(132.81)	(2.5)
जोड़	604	1,333.34	100.0	3,159	6,546.78	100.0
	(780)	(1,350.87)	(100.0)	(2,857)	(5,305.63)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से सम्बन्धित हैं तथा जून, 1988 की स्थिति अनुसार हैं।

समग्र सहायता—राज्य-वार

2.34 1988–89 (जुलाई–मार्च) के दौरान मंजूर की गई सहायता एवं 31 मार्च, 1989 तक संचयी आधार पर राज्य-वार प्रसार सारणी में दिया गया है।

सारणी 9 : सहायता का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रसार

(करोड़ रुपए)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1988-89 (जुलाई-जून)			31 मार्च, 1989 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आन्ध्र प्रदेश	65	106.50	8.0	297	666.96	10.2
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1	0.16	—
असम	8	7.40	0.6	34	45.12	0.7
बिहार	11	11.39	0.9	72	114.34	1.7
गोवा	5	13.78	1.0	23	38.90	0.6
गजरात	56	228.90	17.2	289	851.93	13.0
हरियाणा	28	35.97	2.7	142	206.45	3.2
हिमाचल प्रदेश	15	21.43	1.6	41	67.45	1.0
जम्मूकश्मीर	4	1.48	0.1	19	23.18	0.4
कर्नाटक	31	39.49	3.0	214	356.82	5.5
केरल	17	14.09	1.0	83	121.58	1.9
मध्य प्रदेश	30	49.24	3.7	136	317.02	4.8
महाराष्ट्र	91	171.44	12.9	554	926.51	14.2
मणिपुर	1	2.45	0.2	2	3.96	0.1
मेघालय	2	1.89	0.1	6	7.79	0.1
नागालैण्ड	—	—	—	4	2.97	0.1
उड़ीसा	13	38.40	2.9	67	213.17	3.3
पंजाब	36	60.73	4.6	145	341.08	5.2
राजस्थान	27	127.19	9.5	129	387.22	5.9
सिक्किम	—	—	—	3	2.90	—
तमिलनाडु	77	107.00	8.0	295	506.26	7.7
त्रिपुरा	—	—	—	2	2.63	—
उत्तर प्रदेश	48	189.59	14.2	338	930.10	14.2
पश्चिम बंगाल	21	37.91	2.8	192	264.32	4.0
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	1	0.98	—
चण्डीगढ़	—	—	—	3	2.05	—
दादरा व नगर हवेली	1	0.30	—	7	6.69	0.1
दमण व दीव	2	2.36	0.2	2	2.36	—
दिल्ली	8	53.67	4.0	35	102.00	1.6
पांडिचेरी	7	10.74	0.8	23	33.88	0.5
जोड़	604	1,333.34	100.0	3,159	6,546.78	100.0

2.35 इस अवधि के दौरान, मात्रा-वार आधार पर भाऔविनि की सहायता में प्रथम पांच स्थान, क्रमश: गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यों को प्राप्त हुए; क्रमश: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रहे।

2.36 पिछले वर्ष 1987-88 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सहायता के प्रतिशत भाग की तुलना में असम गोवा गुजरात-हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर केरल मणिपुर मेघालय राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश राज्यों और दिल्ली दमण तथा दीव और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान भाऔविनि की वित्तीय सहायता में अपनी स्थिति सुधारने में समर्थ रहे।

2.37 समीक्षाधीन अवधि में पहली बार दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को भी भाऔविनि की सहायता के दायरे में लाया गया संचयी आधार पर भाऔविनि ने पिछले 41 वर्षों के दौरान मिजोरम और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों में अपनी सहायता का प्रसार कर लिया है। विभिन्न प्रवर्तन उपायों के द्वारा संस्थान सामूहिक रूप से यह प्रयास कर रहे हैं, कि मिजोरम और लक्षद्वीपसमूह में भी औद्योगिक कार्यालय बढ़ सकें।

2.38 1988-89 की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि पंजाब में औद्योगिक कार्यकलाप निरन्तर पिछले वर्ष जैसे ही रहे। 31 मार्च 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान भाऔविनि द्वारा परियोजनाओं को मंजूर की गई सहायता की राशि लगभग उतनी ही थी जितनी कि वार्षिकीय आधार पर पिछले वर्ष के इन्हीं नौ माह में मंजूर की गई थी। वित्तीय संस्थानों ने पंजाब की इकाइयों को वरीयता प्रदान करने की नीति पिछड़े हुए क्षेत्रों के श्रेणी "ख" वर्गीकरण के अनुसार जारी रखी।

2.39 संचयी आधार पर 31 मार्च 1989 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि की कुल वित्तीय सहायता में प्रथम पांच स्थान क्रमश: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यों को प्राप्त हुए। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का स्थान रहा।

समग्र सहायता—क्षेत्र-वार

2.40 सारणी 10 में परियोजनाओं का क्षेत्र-वार वर्गीकरण एवं वर्ष 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान उन्हें मंजूर सहायता तथा 31 मार्च, 1989 तक संचयी आंकड़ों का विवरण दिया गया है।

सारणी 10 : मंजूर और संवितरित की गई सहायता का क्षेत्र-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	1988-89 (जुलाई-मार्च)			31 मार्च 1989 तक संचयी		
	मंजूरियां		संवितरण	मंजूरियां		संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	राशि रु०	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	राशि रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहकारी	23	52.40 (4.6%)	33.77 (3.9%)	327	463.43 (7.1%)	402.24 (9.2%)
निजी	501	1,053.40 (79.0%)	564.83 (76.3%)	2,291	4,583.57 (70.0%)	2,962.67 (68.1%)
संयुक्त	49	135.41 (10.2%)	71.08 (9.6%)	256	905.55 (13.8%)	543.27 (12.5%)
सरकारी	31	92.13 (6.9%)	70.24 (9.5%)	285	594.23 (9.1%)	443.90 (10.2%)
जोड़	604	1,333.34 (100.0%)	739.92 (100.0%)	3,159	6,546.78 (100.0%)	4,352.08 (100.0%)

टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

(क) सहकारी क्षेत्र को सहायता

2.41 वर्ष 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान भाऔविनि ने सहकारी क्षेत्र की 23 परियोजनाओं को 52.40 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की। मात्रा-वार आधार पर पिछले पूर्ण वर्ष में औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई 32.52 करोड़ रुपए की सहायता की तुलना में वर्ष 1988-89 की नौ माह की अवधि के दौरान मंजूर की गई सहायता 61.1 प्रतिशत अधिक थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई सहायता में से 17 चीनी सहकारिताओं को 41.73 करोड़ रुपए, वस्त्र सहकारिताओं को 3.71 करोड़ रुपए और 2 अन्य सहकारिताओं को 6.96 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

2.42 संचयी आधार पर, 31 मार्च, 1989 तक भाऔविनि ने सहकारी क्षेत्र की 327 परियोजनाओं को 463.43 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी, जिसके अंतर्गत 402.24 करोड़ रुपए की सहायता संवितरित की जा चुकी थी। भाऔविनि की वित्तीय सहायता में सहकारी क्षेत्र में परियोजनाओं की संख्या तथा मंजूर की गई राशि, दोनों की ही दृष्टि से महाराष्ट्र का स्थान सर्वोपरि रहा।

भाऔविनि द्वारा औद्योगिक सहकारिताओं को मंजूर की गई संचयी सहायता में महाराष्ट्र का भाग लगभग 34.1 प्रतिशत था। महाराष्ट्र के बाद, संचयी आधार पर भाऔविनि की वित्तीय सहायता में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान रहा, जिन्हें क्रमशः 11.3 प्रतिशत, 17.8 प्रतिशत, 7.0 प्रतिशत 6.2% और 5.9 प्रतिशत सहायता प्राप्त हुई।

(ख) निगमित क्षेत्र को सहायता

2.43 वर्ष 1888-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान निगमित क्षेत्र की 581 परियोजनाओं को 1,280.94 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। निजी निगमित क्षेत्र, जो आरम्भ से ही भाऔविनि की सहायता का सबसे बड़ा लाभ भोगी रहा है, की 501 परियोजनाओं को 1,053.40 करोड़ रुपए की सहायता (कुल सहायता का 79.0 प्रतिशत) प्राप्त हुई, जो कि पिछले वर्ष के पूरे 12 माह के दौरान निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूर की गई 937.56 करोड़ रुपए की सहायता से 6.7 प्रतिशत अधिक थी।

2.44 संयुक्त और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को क्रमशः 135.41 करोड़ रुपए और 92.13 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई, जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंजूर कुल सहायता का क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत भाग रही। यह सहायता संयुक्त क्षेत्र की 49 परियोजनाओं और सरकारी क्षेत्र की 31 परियोजनाओं से संबंधित थी।

2.45 31 मार्च, 1989 तक निगमित क्षेत्र की 2,832 परियोजनाओं को मंजूर संचयी सहायता 6083.35 करोड़ रुपए हो गई थी, और 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के कुल निवेश में इनका भाग 92.9 प्रतिशत था। निजी, संयुक्त और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का भाग, क्रमशः 70 प्रतिशत, 13.8 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत था। निगमित क्षेत्र की परियोजनाओं को संचयी संवितरण 3,949.84 करोड़ रुपए के रहे।

2.46 निगमित क्षेत्र में, 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार मात्रा-वार अनुसार भाऔविनि की संचयी निवेश सहायता में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान सर्वप्रथम रहा, जिसे 847.44 करोड़ रुपए की सहायता (13.9 प्रतिशत) प्राप्त हुई। इसके बाद क्रमशः गुजरात 799.41 करोड़ रुपए (13.1 प्रतिशत), महाराष्ट्र 768.23 करोड़ रुपए (12.6 प्रतिशत), आन्ध्रप्रदेश 645.67 करोड़ रुपए (10.6 प्रतिशत), तमिलनाडु 478.72 करोड़ रुपए (7.9 प्रतिशत) और राजस्थान 382.50 करोड़ रुपए (6.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। संख्या-वार अनुसार महाराष्ट्र के निगमित क्षेत्र को सर्वाधिक इकाइयों (439) को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, और इसके बाद उत्तर प्रदेश (296), आन्ध्र प्रदेश (273), तमिलनाडु (272), गुजरात (265) और पश्चिम बंगाल (192), का स्थान रहा।

पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योग-रहित जिलों को वित्तीय सहायता

2.47 अभिनिर्धारित विकास केन्द्रों के विकास की संशोधित योजना बनने तक, भाऔविनि सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों की उभरती हुई परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त की विद्यमान योजना का निरन्तर अनुवर्तन करते रहे। वर्ष 1988-89 (जुलाई-मार्च) के दौरान भाऔविनि द्वारा केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों की 307 परियोजनाओं को 614.92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2.48 पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों को श्रेणी "क" "ख" और "ग" के अन्तर्गत वर्गीकरण करने की विद्यमान योजना के अनुसार श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले) में स्थित 71 परियोजनाओं को 109.03 करोड़ रुपए, श्रेणी "ख" जिलों/क्षेत्रों में स्थित 105 परियोजनाओं को 187.78 करोड़ रुपए और श्रेणी "ग" जिलों/क्षेत्रों की 131 परियोजनाओं को 318.11 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। पिछड़े हुए जिलों की प्रत्येक श्रेणी अर्थात श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र जिले), "ख" और "ग" को केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई कुल सहायता का क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 51.8 प्रतिशत, 30.5 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ।

2.49 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से भाऔविनि ने अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों/जिलों में स्थित 1,480 परियोजनाओं को 3,311.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जो भाऔविनि की समग्र निवल संचयी मंजूरियों का 50.6 प्रतिशत थी। इसके अन्तर्गत 31 मार्च, 1989 तक 2,186.44 करोड़ रुपए का संवितरण किया जा चुका था।

भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का निधिक स्वरूप (1988-89)

2.50 445 परियोजनाओं के निधिक स्वरूप पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार (जिसमें परियोजनाओं की लागत में अधिव्यय के वित्तपोषण के लिए 1988-89 के दौरान अतिरिक्त सहायता की मंजूरियों के 90 मामले शामिल नहीं हैं) 1988-89 (जुलाई-मार्च) के परिचालनों से यह पता चलता है कि भाऔविनि की सहायता सारणी 11 में दिए गए विवरण के अनुसार 7,560.90 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने में समर्थ रही है।

सारणी 11: भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1988-89 जुलाई-मार्च)

(करोड़ रुपए)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनायें	विस्तार/विशाखन परियोजनायें	आधुनिकीकरण परियोजनायें	पुनर्स्थापन, सन्तुलन उपस्कर आदि के लिए सहायता	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परियोजनाओं की संख्या	166	48	132	99	445
I. प्रवर्तक योगदान					
—शेयर पूंजी	794.88 (13.9%)	20.09 (2.8%)	43.51 (5.5%)	15.78 (4.1%)	874.26 (11.6%)
—अप्रतिभूत गौण ऋण	27.23 (0.5%)	5.56 (0.8%)	16.76 (2.1%)	16.67 (4.7%)	66.22 (0.9%)
—आन्तरिक प्रोद्भूत, आदि	156.00 (2.7%)	96.44 (13.7%)	145.63 (18.4%)	51.54 (14.5%)	469.61 (5.9%)
II. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात भाऔविनि, भाऔविबैंक, भाऔसानिनि, एवं भाऔपुबैंक द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	2,580.69 (45.2%)	272.10 (38.5%)	486.26 (61.3%)	229.22 (64.4%)	3,568.27 (47.2%)
—इक्विटी सहायता	204.27 (3.6%)	2.10 (0.3%)	1.00 (0.1%)	0.56 (0.2%)	207.93 (2.8%)
III. निवेश संस्थानों अर्थात् जीबीनि; यूबीनि और भायूट्र द्वारा सहायता					
—ऋण तथा अग्रिम	226.40 (4.0%)	29.38 (4.2%)	45.29 (5.7%)	15.13 (4.3%)	316.20 (4.2%)
—इक्विटी सहायता	48.38 (0.9%)	0.70 (0.1%)	-- (--)	-- (--)	49.08 (0.6%)
IV. (क) बैंकों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	890.48 (15.6%)	55.71 (7.9%)	13.22 (1.7%)	22.16 (6.2%)	981.57 (13.0%)
(ख) बैंकों आदि द्वारा इक्विटी सहायता	98.56 (1.7%)	12.60 (1.8%)	12.00 (1.5%)	1.65 (0.5%)	124.81 (1.7%)
V. (क) राज्य-स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	8.16 (0.1%)	1.45 (0.2%)	0.92 (0.1%)	-- (--)	10.53 (0.1%)
(ख) इक्विटी सहायता	36.48 (0.7%)	1.20 (0.2%)	-- --	0.02 (Negl.)	37.70 (0.5%)
VI. अधिकारिक निर्गम	332.13 (5.8%)	176.72 (25.0%)	6.65 (0.8%)	1.10 (0.3%)	516.60 (6.8%)
VII. आस्थगित अदायगियां	0.26 (Negl.)	-- --	0.76 (0.1%)	0.86 (0.2%)	1.88 (Negl.)
VIII. विदेशी संस्थानों से ऋण	3.39 (0.1%)	30.00 (4.2%)	-- (--)	-- (--)	33.39 (0.4%)
IX. अन्य	298.85 (5.2%)	2.03 (0.3%)	20.88 (2.7%)	1.09 (0.3%)	322.85 4.3%)
जोड़	5,706.16 (100.0%)	706.08 (100.0%)	792.88 (100.0%)	355.78 (100.0%)	7,560.90 (100.0%)

टिप्पणियां : 1. इक्विटी सहायता में हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान सम्मिलित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

3. उपरोक्त में परियोजना लागत आदि में अधिव्यय को पूरा करने के लिए सहायता की मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं।

नई, विस्तार और विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक अभिदान (1988-89)

2.51 1988-89 (जुलाई-मार्च) में भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित 214 नई और विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से यह सूचित होता है, कि इस अवधि के दौरान भाऔविनि की सहायता विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण क्षमता सृजित करने में समर्थ रही है। उपर्युक्त परियोजनाओं से लगभग 51,442 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो सकेगा। इन परियोजनाओं का वार्षिक अनुमानित उत्पादन मूल्य 5,348.40 करोड़ रुपए है। प्रवर्धित सकल मूल्य लगभग 2,491.30 करोड़ रुपए होने की संभावना है, जो इन परियोजनाओं द्वारा देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंशदान का द्योतक है। इस से संबंधित एक विस्तृत विवरण परिशिष्ट-II के रूप में दिया गया है।

जन-हित में प्रदान की गई मंजूरियां

2.52 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 26 (2) की व्यवस्थाओं के अनुसार निदेशकों के हितबद्ध होने के कारण भाऔविनि को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अधीन जन-हित में सहायता मंजूर करनी पड़ी हो।

(ख) परिचालन गतिविधियां

औ० वि० नि० अधिनियम, 1948 के अधीन प्राधिकार

2.53 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ग) के उप-खंड (xvi) द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 से अपनी अधिसूचना द्वारा, "मनोरंजन उद्यानों, सांस्कृतिक केंद्रों, सम्मेलन केंद्रों, रेस्टोरेंट, यात्रा और परिवहन (हवाई अड्डों पर परिवहन सहित) पर्यटक सेवा एजेंसियों और पर्यटकों को परामर्श सेवाओं सहित पर्यटन विकास या स्थापना से संबंधित सुविधाओं" के कार्य में लगी या लगने के लिए प्रस्तावित, भारत में निगमित और पंजीकृत किसी लिमिटेड कम्पनी या सहकारी समिति को भाऔविनि से वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए पात्र "औद्योगिक संस्थाओं" के रूप में विनिर्दिष्ट किया।

अन्तर-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के समान कार्यविधि

2.54 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यह सहमति हुई, कि वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे, कि 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक के मूल्य वाले संयंत्र और मशीनरी का आयात करने वाली बड़े आकार की सभी औद्योगिक परियोजनाएं अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली जैसी कार्य-विधि के सदृश प्रक्रिया अपनाएंगे। यह भी सहमति हुई, कि सभी मामलों में, जहां अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली जैसी कार्य विधि आवश्यक है, वित्तपोषित संस्थाएं एक परियोजना कार्यान्वयन समिति गठित करेंगी, जिसमें वित्तीय संस्थानों के सांसदों को भी समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम व्यवस्था योजना

2.55 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम निधि नामक निधि के अभिकरण के द्वारा विनिमय जोखिम से विदेशी मुद्रा के उप-ऋणियों को हित रक्षा करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम व्यवस्था योजना को अन्तिम रूप दे दिया। एक अप्रैल 1989 से, इस योजना के लाभ दिनांक 1 अप्रैल, 1989 को या उसके बाद होने वाली सभी विदेशी मुद्रा संविदाओं को उपलब्ध होंगे। इस योजना के अंतर्गत ऋणियों का मूल पुनर्भुगतान दायित्व संवितरण की तारीखों को लागू विनिमय दरों पर रुपये में होगा। ऐसे रुपये से सहबद्ध ऋण दायित्व पर ऋणी, ऋणों का पूरा लाभ उठाते हुए अदायगी करेगा, जिसमें संयुक्त लागत के तीन तत्व, अर्थात् (क) मुद्रा राशि के विभिन्न संघटकों की भारित औसत ब्याज लागत के आधार पर निकाली गई ब्याज राशि (ख) वित्तीय संस्थानों का विदेशी मुद्रा प्रसार और (ग), विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम प्रीमियम शामिल हों। संयुक्त लागत की दर भिन्न-भिन्न होगी जो "न्यूनतम" और "अधिकतम" सीमा सहित छः माह के अंतरालों पर निर्धारित की जायेगी। समय-समय पर "न्यूनतम" और "अधिकतम" सीमा और अवधि पर लागू ब्याज दर की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी, इस समिति में वित्तीय संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विनिमय जोखिम प्रबंध निधि भाऔविबैंक में स्थापित की जाएगी, जिसकी आरंभिक पूंजी 15 करोड़ रुपये होगी, जो भाऔविबैंक, भाऔविनि और भाऔसानिनि द्वारा बराबर अभिदत्त की जाएगी। सभी तीनों संस्थानों, अर्थात्, भाऔविबैंक, भाऔविनि और भाऔसानिनि द्वारा तिमाही आधार पर संयुक्त लागत का विनिमय प्रीमियम तत्व का अंतरण विनिमय जोखिम व्यवस्था निधि को किया जाएगा।

2.56 विदेशी मुद्रा ऋणों के उप-ऋणियों को या तो विनिमय जोखिम व्यवस्था योजना का लाभ लेने या नहीं लेने का विकल्प प्राप्त होगा। जो ऋण विनिमय जोखिम व्यवस्था निधि का विकल्प नहीं लेते हैं, उन्हें विद्यमान व्यवस्थाओं के अधीन विदेशी मुद्रा ऋण उपलब्ध होते रहेंगे। जो ऋणी स्वयं अपने विदेशी मुद्रा हानि और जोखिम उठाने में समर्थ हैं, उन ऋणियों पर यह योजना लागू नहीं होगी।

2.57 1 अप्रैल, 1989 से 30 जून, 1989 की अवधि के दौरान हस्ताक्षरित ऋण करारों के संबंध में आरम्भ से ही संयुक्त लागत 15% वार्षिक होगी, जो 'न्यूनतम सीमा' 15% वार्षिक और 'अधिकतम सीमा' 18% वार्षिक पर परिवर्ती होगी।

ऋण की शर्तों आदि में परिवर्तन

2.58 साधन जुटाने की लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ते रहने के बावजूद, भाऔविनि की ऋण प्रदान करने की मूल शर्तों, अर्थात् ब्याज दर, बचतबद्धता प्रभार और अन्य प्रभारों आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

2.59 तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान समीप रूप से धारित और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में लागू

ब्याज दर से अधिक 1% वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज लगाने की संस्थानात्मक प्रक्रिया की अन्तर संस्थानात्मक स्तर पर समीक्षा की गई, जिसके अनुसार निम्नलिखित सहमति हुई :

(i) सूचिबद्ध कम्पनियों की सहायक और सहयोगी कम्पनियों पर लागू ब्याज दर 1% वार्षिक अतिरिक्त ब्याज न लगाने की छूट समाप्त कर दी गई।

(ii) जिन कम्पनियों के शेयर 51% या इससे अधिक संस्थानात्मक धारित के परिणामस्वरूप या सरकार और सरकारी एजेंसियों की सम्पूर्ण या अधिकांश शेयर धारिता-स्वरूप सूचीबद्ध नहीं होते थे, उन कम्पनियों को छूट देने की नीति समाप्त कर दी गई। तथापि जहां संस्थानों ने मध्यम आकार की कम्पनियों को सार्वजनिक निर्गम के व्यय से बचाने के लिए उनमें सीधे ही शेयर पूंजी का अभिदान करने का निर्णय लिया था, उन कम्पनियों पर लागू ब्याज दर से 1% वार्षिक अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाने की नीति जारी रहेगी।

2.6 यद्यपि सरकार द्वारा संपरिवर्तनीयता मार्ग-निर्देशों के सम्बन्ध में कोई नए अनुदेश जारी नहीं किए गए, तथापि वित्तीय संस्थानों ने संपरिवर्तन मार्गनिर्देशों की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में निम्नानुसार सहमति दी:—

(i) संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों से छूट प्राप्त प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा सहायता भी, संपरिवर्तनीयता खंड की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए कुल सहायता के परिकलन के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं की जायेगी।

(ii) चूंकि कम्पनियों द्वारा अधिकारिक रूप में प्रस्तुत की गई पेशकश के परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिकारिक डिबेंजर में अभिदान को सहायता नहीं माना जा सकता ; संस्थानों द्वारा अभिदत्त अधिकारिक डिबेंचर या शेयरों की बाजार खरीद से उद्भूत अधिकारिक रूप में संस्थानों द्वारा अभिदत्त डिबेंजर न तो कुल सहायता के गणन हेतु लिए जायेंगे, और न ही उन पर संपरिवर्तनीयता विकल्प लागू होगा।

2.61 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंजूर की गई सहायता के संबंध में विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 119 मामलों में संपरिवर्तन विकल्प लागू किया गया। इस अवधि में संपरिवर्तनीयता अधिकार का उपयोग 5 मामलों में किया गया और 30 मामलों में इसे छोड़ दिया गया। संचयी रूप से संपरिवर्तनीयता मार्गनिर्देशों के प्रारम्भ होने से अब तक भाऔवित्तनि ने 1,402 मामलों में संपरिवर्तनीयता खंड की शर्त लगाई, और 126 मामलों में इसका उपयोग किया तथा 514 मामलों में सभी सम्बद्ध पहलूओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प के उपयोग से छूट दी गई।

विद्यमान प्रक्रियाओं को सरल बनाना

2.62 विद्यमान प्रक्रियाओं को, चाहे वे मूल्यांकन, प्रलेखन या अनुवर्तन किसी से भी संबंधित हों, यथासंभव पुनरावृत्ति को कम करके निरंतर सरल बनाया गया। यह सहमति हुई कि वित्तीय संस्थान शेयरों के सार्वजनिक निगम के लिए पूरक ऋण प्रदान करने हेतु अपने पक्ष में प्रवर्तकों द्वारा शेयरों के गिरवी रखे जाने की शर्त समाप्त कर देंगे। यह भी सहमति हुई कि संस्थान प्रवर्तक कम्पनियों/प्रवर्तकों को इस शर्त पर कि शेयरों को नियंत्रित करने वाले मताधिकार बैंकों का ही होगा और इन अधिकारों का प्रयोग संस्थानों के परामर्श से किया जाएगा, गैर निपटान वचनपत्रों द्वारा समाहित शेयरों को बैंक के पास गिरवी रखने की अनुमति दे सकेंगे। अग्रणी वित्तीय संस्थान डिबेंचरधारियों के रूप में निवेश संस्थानों की ओर से पक्ष मंजूरी अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत कर दिये गये, बशर्ते कि वित्तपोषित कम्पनियां 1.5:1 परिसम्पत्ति आवृत्त सीमा अनुपात की अपेक्षा का अनुपालन करें।

अनुवर्तन प्रक्रिया

2.63 अनुवर्तन व्यवस्था की मूल विधाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिसमें (क) वित्तपोषित संस्थाओं द्वारा संबंधित सांविधिक/प्रशासनिक/नियामक प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक उत्पादन रिपोर्टें प्राप्त करना, (ख) आवधिक प्रगति रिपोर्टें और संस्थाओं द्वारा अपने बैंकरों को प्रस्तुत किए गए विवरणों की प्रतियां प्राप्त करना, (ग) खातों, कार्य परिणामों और वित्तीय स्थिति के अर्ध-वार्षिक/वार्षिक विश्लेषण मंगाना, (घ) वित्तपोषित संस्थाओं की परिचालन योजनाओं की तुलना में सहायता और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की अंतिम जांच करने की दृष्टि से सावधिक स्थल दौरे करना, (ङ) फैक्टरी स्थल पर आकस्मिक दौरा करना या संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रवर्तकों/वरिष्ठ कार्यपालकों को बुलाना, (च) आवश्यकता आधारित प्रबन्ध सूचना पद्धति पर बल देना और (छ) नामित निदेशकों/समवर्ती लेखा परीक्षकों/सलाहकारों से, जहां कहीं नियुक्त हैं, रिपोर्ट प्राप्त करना, शामिल है। वर्ष के दौरान अग्रणी मामलों में अनुवर्तन उपायों में तीव्रता लाई गई, और सामूहिक वित्तपोषण आधार पर अन्य वित्तपोषित संस्थाओं की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों के मंच का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।

2.64 31 मार्च, 1989 तक, भाऔवित्तनि ने 793 वित्तपोषित संस्थाओं के निदेशक बोर्डों में 348 नामित निदेशक नियुक्त किए हुए थे, जिनमें 152 शासकीय और 196 गैर-शासकीय थे।

2.65 नामित निदेशकों की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सभी वित्तपोषित संस्थाओं को सलाह दी गई, कि वे बोर्ड/समिति बैठक के आयोजन का नोटिस और कार्य-सूची नामित निदेशकों को काफी पहले भेजें और बोर्ड की कम से कम दो माह में एक बैठक अवश्य करें। भाऔविनि और इसका निदेशक बोर्ड, नामित निदेशकों की पद्धति और उनके कार्यों की अर्धवार्षिक रूप से निरन्तर समीक्षा करता रहा है।

2.66 नामित निदेशकों के कार्यों को पुष्टिकारक एवं प्रभावी बनाने तथा वित्तपोषित संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करने तथा नियंत्रण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भाऔविनि ने 21 जनवरी, 1989 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "नामित निदेशकों (उत्तरी क्षेत्र) के हित के लिए कार्यशाला" का आयोजन किया। इस कार्यशाला में भाऔविनि, भाऔविबैंक, भाऔसानिनि के 120 गैर-शासकीय नामित निदेशकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, जैसे नामित निदेशकों की विधिक देयताएं और उत्तरदायित्व, नामित निदेशक व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन का पालन, लेखा-परीक्षा उप समिति की भूमिका, नामित निदेशकों की प्रत्याशा और अनुभव, आदि। इस कार्यशाला का उद्घाटन कम्पनी कार्य विभाग के तत्कालीन अपर सचिव (अब सचिव, खाद्य संसाधान मंत्रालय) श्री अशोक चन्द्र ने किया।

नियमों और सामान्य विनियमों में संशोधन

2.67 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्व कथनानुसार, सरकार द्वारा औद्योगिक वित्त निगम नियम, 1965 में संशोधन करके भाऔविनि के कारोबार वर्ष की समाप्ति 30 जून के स्थान पर 31 मार्च करने का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप भाऔविनि के सामान्य विनियम, 1982 में कुछ प्रासंगिक संशोधन किए गए, ताकि अप्रैल-मार्च आधार पर भाऔविनि के नवीन लेखांकन वर्ष के अनुरूप विभिन्न प्रावधान किए जा सकें।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय

2.68 अग्रणी संस्थान अवधारणा को गहन बनाने से वित्तपोषित संस्थाओं की परियोजनाओं के मूल्यांकन, प्रलेखन, अनुवर्तन आदि संस्थाओं में वित्तीयज संस्थानों और बैंकों में अब और भी अधिक समन्वय गहरा हुआ है। परियोजनाओं की आवश्यकता आधारित अपेक्षाओं और लागत अधिव्यय के वित्त पोषण को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं की मंजूरी और निधियों के निर्मोचन पर अब सही-समय पर बल दिया जा रहा है। एक ऐसी पद्धति का भी विकास किया गया है, जिसके द्वारा परियोजनाओं के कार्यों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच नियमित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। जहां कहीं अग्रणी वित्तीय संस्थान द्वारा किसी नई परियोजना की प्रगति के अनुवर्तन के लिए किसी परियोजना कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया हो, वहां अग्रणी बैंक का एक प्रतिनिधि ऐसी समितियों से अवश्य सहबद्ध किया जा रहा है।

उद्योग व्यवहार्यता/बाजार अध्ययन

2.69 वित्तीय संस्थानों से अपेक्षा की जाती है, कि वे उद्योगों में ऐसी नई इकाइयां लगाए जाने को प्रोत्साहित करें जिनमें, मांग और आपूर्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता सृजित किए जाने की गुंजाइश हो। इस सम्बन्ध में, योजना की प्राथमिकता एवं लक्ष्यों पर भी समुचित बल दिया जाना अपेक्षित है। वित्तीय संस्थानों से यह भी आशा है, कि वे कार्यकुशलता एवं उत्पादकता के मापदण्डों के अनुरूप आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों के विस्तार अथवा विशाखन को प्रोत्साहित करें। इसको ध्यान में रखते हुए, संस्थान समय-समय पर विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित उद्योग व्यवहार्यता/बाजार अध्ययन करते रहे हैं, ताकि सम्बन्धित क्षेत्रों में नई इकाइयां लगाने के लिए वित्तपोषण अथवा विद्यमान इकाइयों के विस्तार एवं विशाखन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करते समय समुचित नीतियां निर्धारित की जा सकें।

2.70 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान संस्थाओं ने फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्पस, शीट ग्लास, नाश्ते के अन्न, वीडियो मेग्नैटिक टेप, रेक्टिफायर डिओड्स, एक्रेलिक स्टेपल फाइबर, पोलिमर कन्क्रीट/रेजिन बांडिड मार्बल/एग्लोमरेटिड मार्बल, पीवीसी विन्डो और डोर प्रोफाइल्स, एल्यूमिनियम एक्सट्रजन्स, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, सीमलेस ट्यूबस, इलक्ट्रोलिक केपेसिटर्स, रेड मड कोरूगेटिड शीट्स, हार्ड जेलेटिन केप्सूल्स, आदि, जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए। संस्थानों द्वारा इनमें से कुछ अध्ययन भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में किए गए।

सरकार के अंतरसम्पर्क

2.71 भाऔविनि ने सरकार के सभी संबंधित विभागों, योजना आयोग और भारिबैंक, भाऔविबैंक आदि, द्वारा गठित सभी महत्वपूर्ण समितियों/कार्यकारी समूहों से समय-समय पर निरंतर सम्पर्क और विचारों का आदान-प्रदान जारी रखा। भाऔविनि चीनी, वस्त्र, जूट, पर्यटन और पर्यटन के आधुनिकीकरण और विकास से संबंधित सभी मामलों में भी शामिल रहा। यद्यपि भाऔविनि इस अवधि के दौरान जूट आधुनिकीकरण निधि योजना के लिए एक केंद्रीय एजेंसी और चीनी विकास निधि के अधीन चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सहायता के संवितरण के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता रहा; इस को पर्यटन और पर्यटन से संबंधित कार्यकलापों के लिए भी एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में घोषित किया गया।

2.72 हाल ही में, भाऔविनि को आठवीं योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की प्राथमिकताओं के निरुपण के लिए भी सहयोजित किया गया है। भाऔविनि विभिन्न उद्योगों की आर्थिक क्षमताओं के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा गठित कुछ समितियों में और राष्ट्रीय वित्त एवं साख परिषद में भी अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है।

(ग) संसाधन

संसाधन जुटाना एवं वित्तीय प्रबंध

2.73 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुई नौ मास की अवधि के लिए भाऔविनि द्वारा कुल 846.33 करोड़ रुपये (193.8 करोड़ रुपये के प्रारंभिक नकद शेष को छोड़कर, के संसाधन जुटाए गए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान संसाधनों के क्षेत्र में निम्नलिखित उल्लेखनीय बातें हुई :

-- 2 मार्च, 1989 को 12.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी का निर्गम।

-- आन्तरिक प्रोद्भूत, जिससे भाऔविनि की आरक्षित निधियों में 45.32 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

-- दो सार्वजनिक निर्गम बांडों (13 दिसंबर, 1988 एवं 28 फरवरी, 1989 को जारी की गई 51 वीं तथा 52 वीं सीरीज) के द्वारा 248.02 करोड़ रुपय के रुपया संसाधन में वृद्धि।

-- (क) ऋणों की पुनर्अदायगी, और (ख) निवेशों की बिक्री/विमोचन के द्वारा 116.94 करोड़ रुपये की प्राप्ति।

-- (क) स्विस बैंक कारपोरेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लि० (एस बी सी आई) से प्राप्त 50 मिलियन अमरीकी डालर के दो भागों में 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण, जिसमें से 50 मिलियन अमरीकी डालर कि दूसरा भाग व्यवस्थापक, अर्थात् एसबीसीआई के विकल्प से दो वर्षों के पश्चात् स्विस फ्रांक में संपरिवर्तनीय है, (ख) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोआपरेशन लि०, हेलसिंकी, फिनलैंड के माध्यम से दो भागों में फिम 30 मिलियन का ऋण जिसमें से 20 मिलियन फिम का भाग (1) ईंडो-फिनिश संयुक्त उद्यमों तथा 10 मिलियन फिम का भाग (2) अन्य परियोजनाओं के लिए होगा, (ग) एजेंट के रूप में कार्य कर रहे सिक्योरिटी पेसिफिक होरे गोवेट एशिया लि० के साथ विदेशी बैंकों के समूह से अमरीकी डालर में ब्याज निधि सहित 20 मिलियन जापानी येन का ऋण, जिसकी व्यवस्था मेरिल लिन्च कैपिटल सर्विसेज इन्कारपोरेटिड के माध्यम से की गई, द्वारा विदेशी मुद्रा संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि।

2.74 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक) अथवा केंद्रीय सरकार से कोई ऋण नहीं लिये गये किन इस अवधि के दौरान भाऔविबैंक और केंद्रीय सरकार को क्रमशः 4.20 करोड़ रुपये तथा 0.44 करोड़ रुपये की राशि पुनर्अदा की गई, जिससे 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भाऔविबैंक और केंद्रीय सरकार से लिए गए ऋणों की राशि घटकर क्रमशः 61.85 करोड़ रुपये से 57.65 करोड़ रुपये एवं 1.40 करोड़ रुपये से 0.96 करोड़ रुपये रह गई।

2.75 जहां तक ब्याज अंतर अन्य निधियों के ऋण भाग का संबंध है, रिपोर्ट की अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार से 2.28 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई, तथा 0.51 करोड़ रुपये की राशि पुनर्अदा की गई। इस प्रकार, 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सरकार को देय ब्याज अंतर अन्य निधियों के ऋण भाग की कुल राशि 9.25 करोड़ रुपये रही, जबकि 30 जून, 1983 की स्थिति के अनुसार यह देय राशि 7.48 करोड़ रुपये थी।

2.76 मार्च, 1989 की समाप्ति के समय भाऔविनि की विदेशी मुद्रा संसाधनों को जुटाने के संबंध में एशियाई विकास बैंक से 100/150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण जुटाने हेतु बातचीत चल रही थी।

2.77 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के समग्र संसाधनों में निहित थे--(क) इसकी प्रदत्त पूंजी (82.50 करोड़ रुपये), (ख) आरक्षित निधियां (270.94 करोड़ रुपये), (ग) 31 मार्च, 1989 तक विमोच्य राशियों को छोड़कर बांडों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा रुपया उधार (2,314.70 करोड़ रुपये), (घ) अन्य रुपया उधार (67.85 करोड़ रुपये), (ङ) जर्मन मार्क में 25 ऋण व्यवस्थाओं के अधीन जर्मन संघीय गणराज्य के क्रेडितांस्तल्त-फरवाइ डरफब्रुक से उधार (जर्मन मार्क 408 मिलियन), तथा (च) अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से विदेशी मुद्राओं में जुटाए गए अमरीकी डालर 320 मिलियन, जापानी येन 40 बिलियन और जर्मन मार्क 15 मिलियन तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपरेशन लि०, फिनलैंड के माध्यम से फिनिश निधि से ऋण व्यवस्था फिम 30 मिलियन।

निधियों के स्रोत और प्रयोग

2.78 वर्ष 1988-89 के दौरान भाऔविनि द्वारा जुटाए गए कुल संसाधन (193.38 करोड़ रुपये के प्रारंभिक नकद शेष को छोड़कर), 846.33 करोड़ रुपये रहे। इनमें सम्मिलित हैं (क) 12.50 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रदत्त शेयरपूंजी वृद्धि, (ख) कर से पूर्व 60.55 करोड़ रुपये का लाभ जनन, (ग) ऋणियों से ऋणों की वसूली और निवेशों आदि की बिक्री से प्राप्त 116.94

करोड़ रुपये की राशि, (घ) बांडों के माध्यम से 248.02 करोड़ रुपये के बाजार उधार, (ङ) विदेशी मुद्राओं में 399.09 करोड़ रुपये के उधार तथा सरकार से ब्याज अन्तरजन्य निधियों के रूप में 9.23 करोड़ रुपये की प्राप्त राशि। इन संसाधनों का उपयोग वित्तीय सहायता के संवितरण (734.19 करोड़ रुपये), बांडों का विमोचन (35.02 करोड़ रुपये) रुपया तथा विदेशी मुद्रा ऋणों की पुनर्अदायगी (72.85 करोड़ रुपये) लाभांश की अदायगी (7.21 करोड़ रुपये), कराधान (10.02 करोड़ रुपये) और अन्य उपयोगों (39.49 करोड़ रुपये), हेतु किया गया। अवधि के अन्त में नकद शेष 140.93 करोड़ रुपये का था।

बकाया और अतिदेय

2.79 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार 2,150 संस्थाओं से 3,373.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता बकाया थी। वित्तपोषित कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में भाऔविनि की धारिता 111.75 करोड़ रुपये थीं, और 32.51 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए गारंटियां दी गई थीं।

2.80 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण सहायता में से, कुल अतिदेय राशि (मूलधन के रूप में 81.25 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 44.96 करोड़ रुपये) 126.21 करोड़ रुपये थी। ये अतिदेय राशियां 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भाऔविनि के कुल बकाया ऋणों का लगभग 37% थीं।

2.81 रिपोर्ट की अवधि के दौरान वसूली अनुपात 87.90% ब्याज के संबंध में 88.5% और मूलधन के संबंध में 86. 8% रहा, यह पिछले वर्ष 1987-88 के स्तर पर ही था।

2.82 दीर्घकाल से समस्याओं का सामना करती आ रही इकाइयों के मामलों में परियोजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित सभी भागीदार संस्थानों की संयुक्त बैठकें आयोजित की गई, ताकि इनके पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार के लिए संभव एक मुश्त सुविधाओं को निर्धारित करने हेतु सहमति प्राप्त की जा सके। वसूली अभियान एवं वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों को भी इस कार्य में सक्रिय रूप से सम्मिलित किया गया।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.83 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए भा औविनि के प्रयास रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो पिछले दो वर्षों से कार्यरत है, के साथ संबद्ध रहे।

2.84 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुई नौ मास की अवधि के दौरान, भाऔविनि के 46 अग्रणी मामलों के संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की 63 सुनवाइयां हुईं। प्रत्येक मामले में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उल्लिखित विशिष्ट मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने एवं पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाने के लिए 20 मामलों (3 गैर अग्रणी मामलों सहित) के संबंध में भाऔविनि को परिचालन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया। इनमें से भाऔविनि ने परिचालन एजेन्सी के रूप में 11 मामलों के संबंध में मसौदा पुनर्स्थापन योजनाएं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के तत्वावधान में भाऔविनि ने 4 अग्रणी मामलों में व्यवहार्यता अध्ययन और/अथवा पुनर्स्थापन कार्यक्रम बनाने का दायित्व निभाया, यद्यपि इन मामलों में यह परिचालन एजेन्सी नहीं था। कुछ गैर-वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए योजनाओं की जांच करने/पुनः संरचित करने के लिए भाऔविनि की दक्षता बीआईएफआर को उपलब्ध कराई गई।

2.85 बीआईएफआर की परिधि में न आने वाले मामलों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों की पृष्ठ-भूमि में पुनर्स्थापन पैकेज बनाए गए। ऐसे 6 मामलों में वर्ष के दौरान पुनर्स्थापन योजनाएं बनाई गईं। सिफ़ारिश किए गए/प्रत्याशित पुनर्स्थापन उपायों में जो विस्तृत पहलू निहित थे, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण इकाइयों के आधुनिकीकरण, विस्तार, विशाखन आदि भी सम्मिलित थे। चार मामलों में बकाया देय राशियों के निपटान की एक मुश्त व्यवस्था की गई। एक मामले में गारंटरों के साथ सहमति से निपटान किया गया। भाऔविनि के एक अग्रणी मामले में बकाया देय राशियों को वसूल करने के लिए ऋण वापस मांगा गया, और इस अवधि के दौरान वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनकी भागीदारी में किए जा रहे पुनर्स्थापन प्रयासों के साथ भी भाऔविनि को सक्रिय रूप से सहयोजित किया जाना जारी रहा।

2.86 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु प्रदान की जाने वाली राहतों/रियायतों के संबंध में अपने निजी प्रयोग के लिए आंतरिक मार्गनिर्देश निर्धारित किये।

2.87 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भाऔविनि के कार्यक्रम से उपचारित की गई कुछ इकाइयों ने उल्लेखनीय प्रगति की। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1989 की समाप्ति पर समामेलन/अधिग्रहण के कुछ प्रस्ताव संस्थानों के विचाराधीन थे।

(घ) कार्य परिणाम

लाभ

2.88 नौ मास की अवधि के लिए लाभ-हानि लेखों के लेखा परीक्षित लेखों तथा 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र से जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ लगाया गया है, पता चलता है, कि इस अवधि के दौरान भाऔविनि का कर-पूर्व लाभ 60.55 करोड़ रुपये रहा, जबकि 1986-88 (जुलाई-जून) के वर्ष के दौरान यह 68.88 करोड़ रुपये था। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना करने पर वार्षिकीय आधार पर 17.2% की वृद्धि परिलक्षित है। नौ मास की रिपोर्ट अवधि के दौरान, 10.02 करोड़ रुपये के लिए कराधान की व्यवस्था करने के पश्चात् 50.53 करोड़ रुपये का निवल लाभ रहा, जबकि 1987-88 में यह 52.66 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष में नौ मास की अवधि की वार्षिकीय आधार पर यह निवल लाभ 28% अधिक था।

समायोजन

2.89 भाऔविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किए गए समायोजन का विवरण सारणी 12 में दिया गया है।

रिज़र्व में अभिवृद्धि

2.90 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान भाऔविनि ने अपने रिज़र्व में 42.82 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की, जिसमें सामान्य आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित निधि शामिल है।

लाभांश

2.91 संतोषजनक कार्य-परिणाम को ध्यान में रखते हुए भाऔविनि के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर पिछले वर्ष घोषित 12% की तुलना में 13% वार्षिक का लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया है।

सारणी 12 : निवल लाभ का विनियोजन

(करोड़ रुपये)

	इस वर्ष (1988-89) (जुलाई-मार्च)	पिछला वर्ष (1987-88) (जुलाई-जून)
(1)	(2)	(3)
नौ माह का निवल लाभ	50.53	52.66
विनियोजन		
निम्नलिखित को अन्तरित—		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	27.53	17.93
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	1.00	2.00
(ग) विशेष रिज़र्व [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (1) (viii) के अधीन]	14.29	25.01
कर्मचारी कल्याण निधि को आबंटन	0.50	0.25
लाभांश की अदायगी (13% वार्षिक)	7.21	7.47
जोड़	50.53	52.66

कार्य-परिणामों की प्रवृत्ति

2.92 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुई नौ मास की अवधि सहित भाऔविनि के पिछले पांच वर्षों के कार्य-परिणामों का संक्षेप सारणी 13 में दिया गया है।

2.93 तुलनात्मक आधार पर पिछले वर्ष की समरूप नौ मास की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट है—

— 1988-89 (जुलाई मार्च) में ऋण परिचालनों से ब्याज आय में 29.8% की वृद्धि हुई।

— 1988-89 (जुलाई मार्च) में "उधार लागत" में 34.3% की वृद्धि हुई।

— निवल आय, कार्य पूर्व लाभ एवं निवल लाभ में क्रमशः 21.8%, 17.2% तथा 28% की वृद्धि हुई

सारणी 13 : पांच वर्षों के दौरान भाग्रौविनि के कार्य-परिणाम

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष				31 मार्च, 1989 को समाप्त 9 माह की अवधि
	1985 रु०	1986 रु०	1987 रु०	1988 रु०	1989 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिए गए उधारों पर ब्याज	129.78	167.74	225.48	285.30	277.77
घटाइए : लिए गए उधारों की लागत	85.62	119.92	160.78	212.10	213.62
निवल ब्याज राजस्व	44.16	47.82	64.70	73.20	64.15
अन्य आय	5.22	9.40	8.00	9.36	11.26
निवल आय	49.38	57.22	72.70	82.56	75.41
व्यय					
—कार्मिक व्यय	4.44	4.85	6.55	6.12	5.02
—निवेशों पर हानि	0.19	0.37	0.18	0.02	0.31
—निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02
—अन्य व्यय व अनुदान	2.29	2.67	3.14	4.51	3.70
—मूल्य ह्रास	0.34	0.50	1.18	3.00	5.81
कर-पूर्व लाभ	42.09	48.81	61.62	68.88	60.55
कराधान	12.78	14.63	18.14	16.22	10.02
निवल लाभ	29.31	34.18	43.48	52.66	50.53
लाभांश (दर)	9.0%	10.0%	11.0%	12.0%	13.0%

-- 1987-88 में "लिए गए ऋणों पर 74.3% की ब्याज आय" की तुलना में 1988-89 (जुलाई-मार्च) में ब्याज आय 76.9% रही।

-- 1988-89 (जुलाई-मार्च) में निवल आय में प्रतिशत के रूप में कर पूर्व लाभ 80.3% रहा।

-- 1988-89 (जुलाई-मार्च) में निवल आय में प्रतिशत के रूप में निवल लाभ 67% रहा, यह पिछले वर्ष 63.8% था।

(वित्तीय स्थिति)

2.94 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार भाग्रौविनि की परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति सहित पिछले पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति, जैसा कि भाग्रौविनि के तुलन-पत्र से स्पष्ट है, सारणी 14 में दी गई है।

सारणी 14 पांच वर्षों के दौरान भाग्रौविनि की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं की स्थिति (करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त				31 मार्च, 1989 को समाप्त 9 माह की अवधि
	1985	1986	1987	1988	1989
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	142.13	208.88	137.00	193.38	140.93
निवेश					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
—सहायता प्राप्त संस्थाओं में	57.16	58.68	72.83	96.53	111.75
—अन्य संस्थानों में	0.21	0.21	2.81	6.50	20.10
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	1,307.31	1,649.11	2,117.10	2,733.21	3,372.53
स्थिर तथा अन्य परिसम्पत्तियां	65.68	93.25	132.73	221.45	309.61
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	7.87	17.88	21.93	22.92	32.51
	1,580.36	2,028.01	2,484.40	3,273.99	3,987.43
देयताएं और शेयरधारी निधि					
शेयर पूंजी	35.00	45.00	57.50	70.00	82.50
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	114.32	144.88	182.17	225.62	270.94
उधार					
(क) बांड	1,107.00	1,452.88	1,729.40	2,083.80	2,314.70
(ख) सरकार तथा भा०औ०वि० बैंक से	130.73	87.13	79.30	70.73	67.85
(ग) विदेशी मुद्राओं से	88.22	163.25	285.78	611.15	988.60
चालू देयताएं और प्रावधान	92.36	110.74	120.29	179.87	216.88
निर्धारित निधियां	4.86	6.25	8.03	9.90	13.45
स्वीकृतियों पर देयता	4.87	17.88	21.93	22.92	32.51
	1,580.36	2,028.01	2,484.46	3,273.99	3,987.43
ऋण इक्विटी	8.9:1	8.9:1	8.7:1	9.3:1	9.5:1
निवल मूल्य : निवल लाभ	5.1:1	5.6:1	5.5:1	5.6:1	7.0:1

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

2.95 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1984 की धारा 34(1) की व्यवस्थाओं के अधीन भाऔविबैंक द्वारा रिपोर्ट की अवधि के लिए मैसर्स गुप्ता एण्ड कं., सनदी लेखापाल ल ता को सांविधिक लेखा-परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया। भाऔविबैंक से भिन्न भाऔविनि के शेयरधारियों ने मैसर्स टी. आर. चड्ढा एंड कं., सनदी लेखापाल, नई दिल्ली को इसी अवधि के लिए लेखा परिक्षा चुना।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1984 की धारा 34(3) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुई नौ मास की अवधि के लेखा-परीक्षाओं रिपोर्ट इस वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है आयकर अधिनियम, 196 की धारा 44 कख के अनुसार 31 मार्च 1989 की समाप्त अवधि के लिए भाऔविनि की कर लेखा-परीक्षा करने के लिए ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड , सनदी लेखापाल, नई दिल्ली कर लेखा-परीक्षा के रूप में नियुक्त हैं।

प्रवर्तन सेवाएं

प्रवर्तन सेवाएं—समीक्षा

3.01 अपनी प्रवर्तनात्मक और विकासात्मक भूमिका में भाऔविनि का यह प्रयास रहा है कि वह संस्थ नात्म अवस्थापना या विस्तार सेवाओं में प्रत्यक्ष क निरि अपने संसाधनों और क्षमता के अनुरूप संभव सीमा तक गैर-वित्तीय निवेशों को उपलब्ध करवाएं, और साथ ही उसके उपबन्धों को प्रोत्साहित करें। भाऔविनि की प्रवर्तनात्मक सेवाओं में व्याप्त दर्शन का लक्ष्य ऐसे सहायक उपायों से, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों एवं उद्यमियों को मदद और प्रोत्साहन प्रदान करना है, जो उन्हें 'स्थिरता सहित प्रगति प्रदान कर सकें।

3.02 भाऔविनि द्वारा प्रवर्तित की जा रही कुछ प्रवर्तन सेवाएं निम्नानुसार हैं :—

— विशेष रूप से निर्मित की गई प्रवर्तन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता।
— समग्र देश में स्थापित तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से सलाहकारी सेवाओं हेतु सहायता।
— उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में भागीदारी के माध्यम से उद्यमीयता विकास के लिए सहायता और शीर्ष और राज्य स्तर पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित विशेषज्ञ संस्थानों की सहायता करना।
— प्रबन्ध व्यवस्था के व्यावसायीकरण और प्रबंधकीय दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सहायता।
— प्रौद्योगिकी-उन्मुख परियोजनाओं को जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए सहायता।
— पर्यटन और पर्यटन सबंधी कार्यों, इत्यादि और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए सहायता

— प्रतिभूति बाजार के विकास एवं निवेशक संरक्षण के लिए सहायता।

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमीयता पार्कों के लिए सहायता।

— विभिन्न विषयों और अनुसंधान-उन्मुख कार्यों के लिए सहायता।

3.03 समीक्षाधीन नौ माह की अवधि के दौरान विभिन्न प्रवर्तन कार्यों पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई कुल राशि 572.93 लाख रुपए रही जो वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष इसी अवधि में उपयोग की गई राशि से 41.4% अधिक है। संचयी रूप से 31 मार्च, 1989 तक भाऔविनि अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के लिए 3,262.51 लाख रुपए का उपयोग किया। सारणी 15 और 16 में भाऔविनि द्वारा इसकी प्रवर्तन सेवाओं के लिए उपयोग की गई राशि, और जिन स्रोतों से इसे जुटाया गया, का ब्यौरा दिया गया है।

प्रवर्तन योजनाएं।

3.04 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाऔविनि ने निम्नानुसार दो नई प्रवर्तन योजनाओं को प्रारम्भ किया :

— पर्यटन तथा पर्यटन संबंधी कार्यों में उद्यमीयता विकास को प्रोत्साहित करने की योजना।

सारणी 15 : प्रवर्तन सेवाओं पर भाऔविनि द्वारा उपयोग की गई राशि (लाख रुपये)

भाऔविनि द्वारा सहायता प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप	1988–89 (जुलाई-मार्च)			31 मार्च, 1989 तक संचयी
	1988-89 राशि रुपये			राशि रुपये
(1)	2			(3)
(i) प्रवर्तन योजनाएं				
उप सहायता			306.76	
—ऋण सहायता	35.00	35.00	23.50	330.26
(ii) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण	—			
उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए		0.04	35.00	9.63
(iii) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए सहायता			68.75	
—तकनीकी सलाहकारी संगठन	6.22	6.22	0.43	69.18
—औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका	—		—	
(iv) उद्यमीयता विकास के लिए सहायता	—			
—उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी	8.71		55.70	
—भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता	8.75		93.00	
—उद्यमीयता विकास संस्थानों को सहायता	2.81	20.27	15.06	163.76
(v) प्रबन्ध विकास संस्थान को प्रबन्ध विकास गतिविधियों के लिए मदद		48.25		845.24
(vi) जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता के लिए मदद		325.31		1,575.23
(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिए सहायता		125.00		125.00
(viii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्कों को सहायता		—		15.91
(ix) अनुसंधान आदि का प्रवर्तन				
—भाऔविनि पीठें	1.79		29.15	
—विशेष अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट आदि	—		10.63	
—इण्डियन इकनामिक जर्नल को सहायता	0.05	1.84	0.15	39.93

1	2		3	
(x) अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के लिए सहायता				
--ग्रामीण विकास पर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपादन	---		1.00	
--गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुसंधान और सूचना व्यवस्था	3.00		11.00	
--विश्व आर्थिक कांग्रेस	--		4.00	
--इण्डियन इकोनोमैट्रिक सोसायटी	--	3.00	0.50	16.50
(xi) विशेष संगठनों को सहायता				
--गहरा कुआं परियोजना के लिए मुनगुडा, उड़ीसा के 'नई आशा ग्रामीण कुष्ठ कुष्ठ रोग न्यास'	---		0.21	
--धारवाड़ (कर्नाटक) के बहु आयामी विकास अनुसंधान केन्द्र	5.00		5.00	
--नई दिल्ली का पालिसी ग्रुप (गैर-लाभ अर्जक अनुसंधान संगठन)	3.00	8.00	3.00	8.21
(xii) पुनर्स्थापना कार्यक्रम और राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता		---		4.30
(xiii) अन्य (परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिए प्रयुक्त)		---		59.36
जोड़		572.93		3,262.51

सारणी 16 : भाऔविनि की प्रवर्तन सेवाओं के लिए वित्तीय स्रोत

(लाख रुपये)

निधि	1988-89 (जुलाई-मार्च) राशि रु०	31 मार्च, 1989 तक संचयी राशि रु०
1	2	3
हितकारी आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1984 की धारा 32ख के अधीन भाऔविनि के लाभों में से बनाई गई)	160.73	829.80
ब्याज अन्तर-जन्य निधियां (भाऔविनि, क्रेदितांस्तल्त फर वाइडरफवाऊ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के० एफ० डब्ल्यू० ऋणों के लिए, भाऔविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त धन की द्योतक हैं)	412.20	2,432.71
जोड़	572.93	3,262.51

--- पुनर्स्थापन/पुनर्जीवन की प्रक्रिया से गुजरने वाली संगठित क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में छंटनी या यौक्तिकीकरण के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों में स्वनियोजन को प्रोत्साहित करने की योजना।

आरम्भ करने के उद्देश्य से पहली योजना गोवा राज्य में लागू की गई और दूसरी योजना प्रायोगिक तौर पर केवल मध्य प्रदेश राज्य में लागू की गई। इसके अतिरिक्त कुछ वर्तमान प्रवर्तन योजनाओं को पहुंच और योजनाओं के अंतर्गत अनुमत्य उप सहायता की प्रमात्रा में एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से व्यापक रूप से उदार बनाया गया।

3.05 वर्तमान स्थिति यह है, कि भाऔविनि की इस समय निम्नलिखित चौदह प्रवर्तन योजनाएं हैं, जिनमे से आठ सलाहकारी शुल्क उप सहायता योजनाए, चार ब्याज उप-सहायता योजनाएं और दो उद्यमीयता विकास योजनाएं हैं।

सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाएं

— व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के लघु उद्यमियों को उप-सहायता योजना।

— पशु पालन, डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन और मछली पकड़ने से संबंधित उद्योगों को सलाहकारी उप सहायता योजना।
— कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग और मत्स्य पालन पर आधारित या उनसे संबंधित उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना।
— सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना।
— बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण आदि की लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप सहायता योजना।
— लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए उप-सहायता योजना।
— गैर-परम्परागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के प्रयोग तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों हेतु सलाहकारी उप सहायता योजना।
— ग्रामीण और लघु उद्योग के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-सहायत योजना।

ब्याज उप-सहायता योजनाएं

— बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए ब्याज उप-सहायता।
— महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।
— लघु क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।
— स्वदेशी प्रौद्योगिकी के ग्रहण करने को प्रोत्साहित के लिए ब्याज उप-सहायता योजना।

उद्यमीयता विकास योजनाएं

— पर्यटन तथा पर्यटन संबंधी कार्यों में उद्यमीयता विकास को करने की योजना।
- पुनर्स्थापन/पुनर्जीवन की प्रक्रिया से गुजरने वाली संगठित क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में छाँटनी या

प्रौद्योगिकी रग एके कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों में स्व-नियोजन को प्रोत्साहित करने की योजना।

3.06 सलाहकारी शुल्क उप सहायता योजनाओं का उद्देश्य तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र में व्यापक रूप से औद्योगिक इकाइयों को कम दर पर सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना है। ब्याज उप सहायता योजनाओं का लक्ष्य बेरोजगार युवाओं तथा महिला उद्यमियों को स्व विकास एवं स्व रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियन्त्रण उपायों को ग्रहण करना, उपलब्ध स्वदेशी प्रौद्योगिकी को काम में लाना, आदि है। उद्यमीयता विकास योजनाएं लघु उद्योग क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कार्यों में स्व नियोजन पर जोर देती हैं, और पुनर्प्रशिक्षण की प्रक्रिया द्वारा स्व नियोजन एवं उद्यमीयता विकास के माध्यम से उन लोगों की तकलीफों को कम करने में सहायक होती हैं जिनको किसी कार्य रुग्ण इकाइयों के मामले में आधुनिकीकरण पुनर्स्थापन और पुनर्जीवन योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण छंटनी का सामना करना पड़ा हो।

प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप सहायता तथा ऋण सहायता

3.07 समीक्षाधीन नौ माह की अवधि में अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अंतर्गत भाऔविनि ने कुल 35 लाख रुपये की उप सहायता 1,224 परियोजनाओं, जिनमें से अधिकांश परियोजनाएं ग्रामीण एवं लघु उद्योग (सहायक उद्योगों सहित) क्षेत्र में थीं, को संवितरित की। सारणी 17 में समीक्षाधीन नौ माह की अवधि के दौरान और 31 मार्च, 1989 तक, भाऔविनि, द्वारा संचयी रूप से अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप सहायता के विवरण दिए गए हैं।

सारणी : 17 : भाऔविनि द्वारा इसकी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के अधीन संवितरित उप-सहायता :

(लाख रुपये)

प्रवर्तन योजनाओं के नाम	1988-89 (जुलाई-मार्च) राशि रु०	31 मार्च, 1989 तक संचयी राशि रु०
(1)	(2)	(3)
— व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत को पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र, छोटे उद्यमियों को उप-सहायता योजना	23.40	207.61
— पशु-पालन, डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मछली पकड़ने से सम्बद्ध उद्योगों को सलाहकारी उप-सहायता योजना	0.65	0.65
— में कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन तथा मत्स्य पालन में लगे हुए या इससे सम्बद्ध उद्योगों को सलाहकारी सहायता योजना	1.64	1.64
— सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन के लिए उप-सहायता योजना	0.14	16.95
— बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण की लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना	3.07	12.60
— ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-सहायता योजना	0.15	0.15

		(लाख रु०)
1	2	3
—लघु क्षेत्र की इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उप-सहायता योजना	0.29	0.73
—अति लघु और लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए उप-सहायता योजना	2.87	13.59
—अति लघु, लघु और सहायक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उप-सहायता योजना	1.71	4.75
—बेरोजगार युवा व्यक्तियों के लिए स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए उप-सहायता योजना	0.10	0.42
—महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप सहायता योजना	0.98	2.32
—देशी तकनीक को ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना	—	45.35
—इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास के लिए सहायता योजना	—	23.50
जोड़	35.00	330.26

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए सहायता

(क) तकनीकी सलाहकारी संगठन

3.08 भाऔविबैं सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठन प्रवर्तक संस्थानों की ओर से, प्रवर्तन सेवाएं उपलब्ध करवाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस समय 18 तकनीकी सलाहकारी संगठन—भाऔविबैंक के अग्रणी दायित्व में 9, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 5, भाऔसाविनि के अग्रणी दायित्व में 3 और कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवर्तित 1,—उद्यम स्थापित करने में विशेषकर ग्रामीण, अति लघु, लघु और मध्यम क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में, व्यापक सलाहकारी और विस्तार सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा समीक्षाधीन नौ माह की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 2,985 दत्तकार्य निष्पादित किए गए और संचयी रूप से 31 मार्च, 1989 तक 30,415 दत्त कार्य निष्पादित किए जा चुके थे, जिनका विवरण सारणी 18 में दिया गया है।

3.09 भाऔविबैं का वर्ष के दौरान (क) तकनीकी सहलाहकारी सेवाओं के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करने, (ख) उनके कारोबार मिश्र के विशाखन के विकास के लिए वरीयता क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने, (ग) उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में जहां कहीं उनके द्वारा आयोजित किए गए हों प्रशिक्षण और धारण के बीच संबंध स्थापित करने, और (घ) विशेषतः ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों में उद्योगों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने पर लगातार जोर रहा। अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन भाऔविबैं की सलाहकारी शुल्क उपसहायता योजनाओं से भी उन क्षेत्रों के तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा अपेक्षित आयाम बनाए रखने और सृजित करने में सहायता मिली, जिनमें विशेषतः ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों में, परामर्श सेवाएं अत्यन्त आवश्यक समझी गई।

सारणी 18. सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों की गति का सार

दत्तकार्यों की प्रकृति	पूरे किये गये दत्तकार्यों की संख्या: 1988-89 (जुलाई-मार्च)	पूरे किये गये दत्तकार्यों की संख्या: प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के आरम्भ से 31 मार्च, 1989 तक
(1)	(2)	(3)
I. निवेश पूर्व सलाहकारी दत्तकार्य		
—व्यवहार्यता, व्यवहार्यता-पूर्व-अध्ययन/परियोजना रिपोर्टें, आदि	1,691	13,953
—औद्योगिक सम्भावना/क्षेत्र		
—विकास सर्वेक्षण	19	484
—बाजार सर्वेक्षण	62	611
—परियोजना रूपरेखा	551	8,701
—प्रारम्भिक तथ्य निरूपण		
—अध्ययन	26	121
—मूल्यांकन	23	1,029
—अन्य	243	2,130
उप-जोड़ (I)	2,615	27,029
II. निवेश-पश्चात् सलाहकारी दत्तकार्य		
—निदानात्मक अध्ययन	79	925
—रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	42	484
—अन्य	83	987
उप-जोड़ (II)	204	2,396
III. टर्नकी दत्तकार्य/कार्यात्मक औद्योगिक काम्पलैक्स, आदि	3	63
IV. उद्यमीयता विकास कार्यक्रम	163	927
कुल जोड़ (I+II+III+IV)	2,985	30,415

(ख) औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

3.10 भाऔविबैंक के अग्रणी दायित्व में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारों की एक नामिका बनाए रखी, और इसे औद्योगिक परामर्शदाता निर्देशिका में सूचीबद्ध करते रहे । वर्ष के दौरान 69 नए परामर्शदाताओं को इस सूची में शामिल किया गया, और पहले से सूचीबद्ध 10 परामर्शदाताओं को अतिरिक्त क्षेत्रों में शामिल किया गया। इससे 31 मार्च, 1989 तक संस्थानों द्वारा सूची में शामिल किए गए परामर्शदाताओं की कुल संख्या 817 हो गई ।

उद्यमीयता विकास के लिए सहायता

3.11 संस्थानों ने अनुभव किया है कि केवल वित्त कच्चे माल और अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाओं की सरल उपलब्धि से ही कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब तक कि मानव संसाधन को स्व विकास और स्व नियोजन की ओर पुनः उन्मुख न किए जायें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, भाऔविनि द्वारा अन्य भागीदार संस्थानों के सहयोग से निधियां देकर उद्यमीयता विकास गति पर उचित जोर दिया जा रहा है।

3.12 समीक्षाधीन नौ माह की अवधि के दौरान भाऔविनि ने भाऔवि बैंक और भाऔसावित्रि के सहयोग से 276 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों हेतु सहायता दी, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए 64 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम शामिल थे । उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित करने वाली एजेंसियों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठनों, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, राज्य स्तरीय उद्यमीयता विकास संस्थानों, उद्यमीयता और प्रबन्ध विकास संगठनों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों, प्रौद्योगिकी संस्थानों और विभिन्न अन्य प्रौद्योगिकी उन्मुख संगठनों जैसी एजेंसियां शामिल थीं । सम्प्रति मार्च, 1989 के अंत तक भाऔविनि ने भाऔवि बैंक और भाऔसावित्रि सहित 1206 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की थी/करने की सहमति प्रदान की थी, जिससे 24,880 संभावित उद्यमियों को लाभान्वित होना था ।

3.13 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में भागीदारी करते हुए 31 मार्च, 1989 तक भाऔविनि ने 55.70 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें से 8.71 लाख रुपये की राशि समीक्षाधीन नौ माह की अवधि से संबंधित थी ।

उद्यमीयता विकास हेतु संस्थानात्मक अवस्थापना के लिए सहायता

3.14 उद्यमीयता विकास के लिये संस्थानात्मक नवस्थापना के सृजन के क्षेत्र में भाऔविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का पहला कार्य राष्ट्रीय स्तर पर स्रोत संगठन के रूप में अहमदाबाद में मार्च, 1983 में भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान (भांउविसं) की स्थापना करना था। केन्द्रीय सरकार ने भी वर्ष 1983 में उद्यमीयता और लघु कारोबार विकास से संबंधित कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय उद्यमीयता और लघु कारोबार विकास संस्थान की स्थापना की। ये दोनों संगठन उद्यमीयता विकास आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये बराबर मिल कर कार्य कर रहे हैं।

3.15 राज्य स्तर पर उद्यमीयता विकास कार्यों को संस्थागत करने के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में उद्यमीयता विकास संस्थान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों संबंधित राज्य सरकारों और बैंकों की सहायता से पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं, और पूरी तरह से अपने कार्यों को कर रहे हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 17 नवम्बर 1988 को मध्य प्रदेश में उद्यमीयता विकास केन्द्र पंजीकृत किया गया, जिसका कि अग्रणी दायित्व अब भाऔविनि द्वारा ले लिया गया है। भाऔवि बैंक के अग्रणी दायित्व में गोवा में एक उद्यमीयता विकास संस्थान, अन्य उद्यमीयता विकास संस्थानों के मामले में अपनाई गई पद्धति के अनुसार स्थापित किये जाने की सहमति हो चुकी है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी एक उद्यमीयता विकास संस्थान के स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव उत्तर पूर्वी परिषद के विचाराधीन है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान सरकार, आदि जैसी कुछ एक राज्य सरकारों ने भी अपने संबंधित राज्यों में उद्यमीयता विकास केन्द्रों को स्थापित करने के लिये इच्छा व्यक्त की है। इन राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर यथा समय वित्तीय संस्थानों द्वारा उन गुणावगुणों के आधार पर विचार किये जाने की संभावना है।

3.16 मार्च, 1989 की समाप्ति तक भाऔविनि ने भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को 93 लाख रु० की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी, जिसमें से 8.75 लाख रुपये 1988-89 में उपलब्ध करवाये गये थे। मार्च 1989 की समाप्ति तक राज्य स्तरीय उद्यमीयता विकास संस्थानों को 15.06 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी, जिसमें से 2.81 लाख रुपये समीक्षाधीन वर्ष में उपलब्ध करवाये गये थे। इसके अतिरिक्त उद्यमीयता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के मामले में भाऔविनि पूंजी लागत और 5 वर्ष की अवधि तक आवर्ती व्यय में अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी, कैम्पस निर्माण और समूह निधि के सृजन के लिये 54.50 लाख रुपये आदान के रूप में अंशदान करने को सहमत हो चुका था । भाऔविनि, उद्यमीयता विकास के लिये, अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों केन्द्रों की, विशेषकर जहां किये तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्यों में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित किये जा रहे हैं, स्थापना में हिस्सेदारी आधार पर भागीदारी करने के लिए भी सहमत हो गया है।

3.17 यद्यपि भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमीयता और लघु कारोबार विकास संस्थान, आदि जैसे

राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का जोर (क) उद्यमीयता कार्यों को संस्थागत करने, (ख) अनुसन्धान प्रलेखीकरण और प्रकाशन, के द्वारा उद्यमीयता जानकारी बढ़ाने, सुधारने और बांटने, (ग) उद्यमीयता ज्ञान-तंत्र में व्यावसायिकों के एक संवर्ग को सृजित और विकसित करने (जिसे कि अब सही रूप से एक विद्या-विशेष के रूप में जाना जा सकता है), (घ) उद्यीयमान होने और फलने-फूलने के लिये उद्यमीयता वातावरण को सुग्राही बनाने और सुधार करने और (ङ) अग्रत क्षेत्रों में उद्यमीयता विकास आन्दोलन को आगे बढ़ाने और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिये नये उत्पादों, बाजार खण्डों को विकसित करने पर रहा, उद्यमीयता विकास के लिये राज्य स्तरीय संस्थानों,केन्द्रों ने आधारभूत स्तर पर उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को करने और उद्यमीयता विकास कार्य में लगे हुए विभिन्न राज्य और जिला स्तर के संगठनों को मानव संसाधन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किये। राज्य स्तरीय संगठन भी औद्योगिक विस्तार प्रेरणा सेवायें, कारोबार अवसर मार्गदर्शन, परियोजना परामर्श, आदि पूर्ववत् उपलब्ध करवाते रहे और देश के युवकों में उद्यम वृत्ति को जीवन-वृत्ति में ढालने हेतु विद्यालय स्तर पर उद्यमीयता शिक्षा प्रारम्भ करने में सहायता की। अपनी सहायता और पुष्टिकारक भूमिका को पूरा करने में इन संगठनों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कई कार्यशालायें, संगोष्ठियां, सम्मेलन आयोजित किये, और उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिये सहायक सामग्री के रूप में अनुसन्धान पर आधारित प्रकाशन निकाले। संगठनों ने सशक्त और अच्छी पण्डितयों पर उद्योग को स्थापित करने और उनका परिचालन करने के लिये उद्यमियों को प्रशिक्षित करने और उनको प्रेरित करने के लिये श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री के रूप में कई वीडियो फिल्में भी तैयार कीं।

प्रबन्ध व्यवस्था के व्यासायीकरण और प्रबन्धकीय दक्षताओं के उन्नयन के लिये सहायता

3.18 दिन-प्रतिदिन प्रबन्ध-व्यवस्था की गुणवत्ता को विकसित करने, उसमें सुधार करने और प्रबन्ध-व्यवस्था में व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से, जो किसी भी औद्योगिक उद्यम के लिये अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है, भाऔविनि ने दिल्ली के निकट गुड़गांव (हरियाणा) में प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना 1973 में की थी। प्रबन्ध विकास संस्थान अब प्रबन्ध प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श का परिपूर्ण अंग है, इसका मुख्य लक्ष्य अर्थ-व्यवस्था के 'उद्योग', 'सरकारी' और 'बैंकिंग' क्षेत्रों में प्रबन्धकीय प्रभावशीलता को उन्नत करना है। प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा किये गये अनुसन्धान अध्ययन, अर्थ-व्यवस्था और औद्योगिक विकास के बृहद् एवं सूक्ष्म दोनों ही क्षेत्रों में है, और साथ ही विशिष्ट उद्योग या आर्थिक कार्य से सम्बन्ध क्षेत्रों में भी है।

3.19 प्रबंध विकास संस्थान के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था, कि इस संस्थान का उच्च-पद स्थितियों को ग्रहण करने की संभावना रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा/ग्रुप "क" सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संगठनों के कार्यपालकों के लिये पहला सघन 15 माह का राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम आयोजित करने के लिये एक एजेंसी के रूप में भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा चयनित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पहला राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ और जेवियर लेबर रिलेशन्स संस्थान, जमशेदपुर के सहयोग से पहली जुलाई, 1988 से प्रारम्भ किया गया।

3.20 कैलेण्डर वर्ष 1988 के दौरान और उसके बाद 31 मार्च, 1989 को समाप्त तीन माह की अवधि के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान ने विभिन्न विषयों में 103 प्रबन्ध विकास कार्यक्रम आयोजित किये, जिससे कुल 1,857 भागीदार लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भारत एल्युमीनियम कं० लि०, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन आफ इण्डिया भारतीय मानक ब्यूरो, हिन्दुस्तान जिंक लि०, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, मध्य प्रदेश वित्तीय निगम, आदि जैसे सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बहुत से कार्यपालकों के लिये कार्यक्रम सम्मिलित थे।

3.21 प्रबंध विकास संथान ने कर्नाटक में जिला उद्योग केन्द्रों और राज्य स्तरीय प्रवर्तन और वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों, आदि के अधिकारियों की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए 'औद्योगिक परियोजनाओं का निरूपण, प्रवर्तन और कार्यान्वयन' पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध विकास संस्थान तथा इसके विकास बैंकिंग केन्द्र ने कई कार्यक्रम विशेषकर कुशल सामरिक योजना, नए उत्पादों का विपणन, सहकारी अल्पावधि साख प्रणाली को सशक्त करने, विपणन और बिक्री, प्रबन्ध परामर्श, विकास बैंकिंग, श्रमिक प्रबन्धक वर्ग सम्बन्ध, मानव संसाधन विकास, लघु उद्योग वित्तपोषण, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, निदेशकों की भूमिका, मर्चेन्ट बैंकिंग, लीजिंग, कार्यरत पूंजी का वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अन्तरण, प्रबन्धन, विकास वित्तपोषण संस्थानों के प्रलेखीकरण और वसूली पद्धतियों, आदि के क्षेत्र में आयोजित किये। योजना आयोग/अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन-हाउस मैनेजमेंट कन्सलटेंसी डेवलपमेंट परियोजना (फेज-II), के अन्तर्गत प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा 23 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 31 मार्च, 1989 तक संचयी रूप से प्रबन्ध विकास संस्थान ने 928 प्रबन्ध विकास कार्यक्रम आयोजित किये थे, जिससे 21,944 भागीदार लाभान्वित हुए थे, और जिसमें से 539 अन्य विकासशील देशों के थे।

3.22 समीक्षाधीन अवधि के दौरान परामर्श औरअनुसन्धान के क्षेत्र में प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम सेन केवल विकासशील प्रबन्ध परामर्श पर जोर दिया गया, अपितु बड़े मिश्रित संगठनों में प्रत्यय परामर्श दत्त कार्यों को करने,

और जन उपयोगिताओं में इन हाउस मैनेजमेंट सलाहकारी दलों को विकसित करने के प्रयासों को दिशा देने पर रहा। प्रबन्ध विकास संस्थान के परामर्श और अनुसन्धान कक्षों ने निर्गमित योजना, मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन, व्यवहार्यता अध्ययन, कार्य संरचना, प्रबन्ध सूचना व्यवस्था, मानव शक्ति योजना, बाजार मूल्यांकन, पूंजी बाजार, अपसटीय बैंकिंग, अन्तर फर्म तुलना, बीज पूंजी, प्रौद्योगिकी इसकी सम्बद्धता, मूल्यांकन और प्रभार, आदि जैसे क्षेत्रों में सघन कार्य किया

3.23 प्रबन्ध विकास संस्थान ने "सरकारी क्षेत्र प्रबन्ध व्यवस्था" विषय पर 10 नवम्बर, 1988 को माननीय श्री बसन्त साठे, ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार, द्वारा अपना स्थापना दिवस व्याख्यान करवाया।

3.24 1988-89 में प्रबन्ध विकास संस्थान को भाऔविनि द्वारा 48.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायत दी गई, जिसमें कि भाऔविनि की सामान्य निधियों से, 5 लाख रुपये का वार्षिक अंशदान सम्मिलित था। 31 मार्च 1989 तक संचयी रूप से भाऔविनि द्वारा प्रबन्ध विकास संस्थान को हितकारी आरक्षित निधि और ब्याज अन्तर जन्य निधियों में से 845.24 लाख रुपये और अपनी सामान्य निधियों में से 80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिये सहायता

3.25 यद्यपि जोखिम पूंजी सहायता का देश में उद्यमिता आधार को विस्तृत करने में अपना महत्व है, उद्यम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के रूप में सहायता से भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकी आधार को सुधारने में अपना महान योगदान है। भाऔविनि द्वारा प्रवर्तित जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि०, शायद अपने प्रकार का पहला संस्थान है जो कि उभरते हुए उद्यमियों और उनके प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्यमों को जोखिम पूंजी सहायता और प्रौद्योगिकी वित्त, दोनों एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाता है।

3.26 जोखिम पूंजी सहायता के क्षेत्र में जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम ने, जो कि पहले के जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान का उत्तराधिकारी है, जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 तक 15 माह की अवधि के दौरान अपनी 43 मध्यम प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं के लिये 70 प्रवर्तकों को 641.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की। संचयी रूप से, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के रूप में अपने प्रारम्भिक वर्ष 1976 से लेकर 31 मार्च, 1989 तक, जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि०, 177 परियोजनाओं के लिये 297 उद्यमियों को 2,188.98 लाख रुपये की जोखिम पूंजी सहायता मंजूर कर चुका था। इन मंजूरियों के समकक्ष 148 परियोजनाओं के 247 प्रवर्तकों के लिये 1,735.73 लाख रुपये का संवितरण किया गया।

3.27 प्रौद्योगिकी वित्त के क्षेत्र में पांच नवोन्मेष प्रौद्योगिकी उन्मुख परियोजनाओं को कुल 124.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर करके समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक अच्छी शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं में, शैक्षिक रोबोटों के विकास और निर्माण, होटल/पर्यटन/चिकित्सीय उपयोग के लिये दक्ष प्रणालियों के लिये एल० ए० एन० डब्ल्यू० ए० एन० सिस्टम साफ्टवेयर, विशेषो/कृत-साफ्टवेयर का विकास, विभिन्न भारतीय/एशियन निधियों से संबंधित अंकीकृत फान्टों के विकास और उत्पाद नई डिजाईन अवधारणा पर आधारित प्रत्यक्ष, काम्पैक्शन ईंधन बनाने वाली मशीनों का उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूर्ण रूप से नये रूप से डिजाइन किये गये हथकरघों का विकास जैसी बहुत सी प्रौद्योगिकी उन्मुख परियोजनायें सम्मिलित थीं।

3.28 जोखिम पूंजी सहायता और प्रौद्योगिकी वित्त दोनों ही क्षेत्रों में, जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि०, का जोर पथ-प्रदर्शक/टेक्नोक्रेटों, व्यावसायिकों की योजनाओं अर्थात् नई प्रौद्योगिकी (विशेषत: आन्तरिक रूप से विकसित), नये उत्पादों, नये बाजारों, नये उपयोगों और नई विशेष सेवाओं, आदि, जैसी स्पष्ट योजनाओं के विशिष्ट पहलुओं के सम्बन्ध में उच्च जोखिम और उच्चतर आय वाले उद्यमों को सहायता करने पर है। विशेष जोर नवीनतम उपायों को प्रारम्भ करने सहित, (जिससे कि ग्राहकों की स्वीकार्यता में वृद्धि हो), इन-हाउस अनुसन्धान एवं विकास अवस्थापना की स्थापना, इन-हाउस अनुसन्धान एवं विकास को बढ़ाना, उर्जा संरक्षण के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण आदि, जैसी देशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण पर है।

3.29 यह समझा जाता है, कि अपनी नई उदीयमान भूमिका में जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० न केवल देश में उद्यमीयता आधार को नियमित रूप से विस्तृत करने में सहायता करता रहे, अपितु प्रौद्योगिकी के विकास और इसके वाणिज्यिक उपयोग के बीच व्याप अन्तराल को भी भरने में सहायक सिद्ध होगा।

3.30 अब तक जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० को वित्तीय सहायता पूरी तरह से भाऔविनि द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। 31 मार्च 1989 तक जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम लि० को भाऔविनि 100 लाख रुपये शेयर पूंजी में अभिदान करने के अतिरिक्त 1,575.23 लाख रुपये की राशि संवितरित कर चुका था। भाऔविनि वर्ष 1989-90 के दौरान 400 लाख रुपये की सीमा तक जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि० की अतिरिक्त इक्विटी में अभिदान करने, और कुल मिलाकर 325 लाख रुपये के ब्याज मुक्त और ब्याज वहन करने वाले ऋणों को प्रदान करने के लिये भी वचन-बद्ध है।

पर्यटन और पर्यटन सम्बन्धी कार्यों, सुविधाओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिये सहायता

3.31 समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, भारत सरकार द्वारा भाऔविनि को देश के भीतर पर्यटन और पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के वित्तपोषण के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय वित्तीय एजेंसी के रूप में घोषित करना। इस कार्य को पूरा करने के लिये और यथासंभव व्यापक स्तर पर परिचालन हेतु भाऔविनि ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग से एक नया संगठन, अर्थात् भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि०, प्रवर्तित किया। भारतीय पर्यटन वित्त निगम, जो कि 27 जनवरी, 1989 को एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया गया, पहली फरवरी, 1989 से परिचालनरत हो गया।

3.32 भारतीय पर्यटन वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य निगमित निकायों, भागीदार फर्मों, न्यासों, व्यक्तियों, अन्य कम्पनियों को, चाहे जैसे भी उनका गठन किया गया हो, जो पर्यटन स्थापित करने और/अथवा विकास करने और पर्यटन सम्बन्धी कार्यों, सुविधाओं और सेवाओं में लगी हों या उनका लगाने का प्रयास हो, सहायता करने के कारोबार को करना है, जैसे होटल, रेस्तरां, काफी हाऊस हवाई स्टेशन पर, आकाश आरामगाह, लांजिंग गृह, होस्टल, कैंपिंग स्थल मनोरंजन पार्क, सिनेरमा, आडिटोरियम, म्यूजियम, पर्यटन परिवहन के सभी साधन, यात्रा एजेंसियां पर्यटन एम्पोरिया, जल क्रीड़ा सुविधाएं और पर्यटकों के लिये अन्य क्रीड़ाएं आदि। ऐसी इकाइयां अपने सृजन, परिचालन, विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु सहायता तथा निजी और सरकारी स्वामित्व और पूंजी की भागीदारी को प्रोत्साहित एवं प्रवर्तित कर सकती हैं।

3.33 भारतीय पर्यटन वित्त निगम से सहायता रुपया और विदेशी मुद्रा ऋणों, हामीदारी और/या शेयरों डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अभिदान, आस्थगित अदायगी के लिये गारन्टी, उपस्कर, वित्त, उपस्कर लीजिंग पूर्तिकार उधार, आदि के रूप में होगी। भारतीय पर्यटन वित्त निगम से यह भी अपेक्षित है कि वह मर्चेन्ट बैंकिंग और सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करवाए और पर्यटन उद्योग में सभी परियोजनाओं और पर्यटन सम्बन्धी कार्यों, सुविधाओं और सेवाओं के वित्तपोषण से संबंधित मार्गनिर्देशों और नीतियों के समन्वय और सूचीकरण के कार्यों को आगे बढ़ाये। लेकिन भारतीय पर्यटन वित्त निगम के क्षेत्र में यह अपेक्षित नहीं है, कि वह पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाये, जो कि यथापूर्व भाऔवि बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय संस्थानों/बैंकों को उपलब्ध करवायी जाती रहेगी।

3.34 प्रारम्भ में, भारतीय पर्यटन वित्त निगम एक करोड़ रुपये और अधिक की पूंजी लागत वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। लेकिन विशिष्ट परियोजनाओं पर, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से अनुपम एवं महत्वपूर्ण हों, और जिनके लिये राज्य स्तरीय संस्थानों/बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती हो, उनकी पूंजी लागत के एक करोड़ रुपये से कम होने पर भी अपवादात्मक आधार पर विचार किया जा सकता है। तीन करोड़ रुपये तक की पूंजी लागत वाली परियोजनाएं राज्य स्तरीय संस्थानों/बैंकों के साथ भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित की जाएंगी। लेकिन 3 करोड़ रुपये और इससे ऊपर की पूंजी लागत वाली परियोजनाएं विभाऔवि, भाऔवि बैंक और भाऔसानिनि जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों सहित सामूहिक संघ आधार पर भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा वित्तपोषित की जाएंगी।

3.35 भारतीय पर्यटन वित्त निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये है जिसमें से 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्रदत्त शेयर पूंजी भाऔविनि, भाऔवि-बैंक, भाऔसानिनि, भा०यू०ट्र०, जी०बी०नि०, सा०बी०नि० भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक आफ इण्डिया द्वारा अभिदत्त की गई है। भारतीय पर्यटन वित्त निगम को बांडों के निर्गम के लिये भी प्राधिकृत किया गया है और अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिये भारत सरकार गारंटी के लिये बद्ध है। भारतीय पर्यटन वित्त निगम की इक्विटी पूंजी में अब तक भाऔविनि का अंशदान 12.50 करोड़ रुपये हो चुका है।

प्रतिभूति बाजार के विकास और निदेशक हित के संरक्षण के लिये सहायता

3.36 प्रतिभूति बाजार के स्वस्थ्य विकास को समुचित रूप से बढ़ावा देने और पर्याप्त निवेशक हित संरक्षण कराने के लिये, भारत सरकार ने सांविधिक शीर्ष बोर्ड स्थापित करने तक, दिनांक 12 अप्रैल, 1988 को वित्त मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में एक अन्तरिम उपाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन किया। 30 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक निधि को पूरा करने के लिये भाऔविनि ने जी० बी० नि०, सा० बी० नि०, भा० यू० ट्र०, भाऔवि बैंक, भाऔसानिनि, भारतीय स्टेट बैंक और निवेश बैंकिंग कार्य करने वाले अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ मिलकर समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 2.50 करोड़ रुपये के अपने हिस्से में से 1.25 करोड़ रुपये का अंशदान कर दिया है।

3.37 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति बाजारों के विनियमन और विकास हेतु व्यापक संविधि तैयार करने सहित प्रतिभूति बाजार के समुचित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिये एक एजन्सी के रूप में कार्य करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता

3.38 विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों और उद्योग के बीच बढ़ते हुए प्रभाव को विकसित करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमियों के नये वर्ग को प्रवर्तित करने और उद्योग में प्रौद्योगिकी संस्कृति को सृजित करने के दृष्टिकोण से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सुस्थापित इंजीनियरिंग कालेजों और

तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों की सहायता कर रहे हैं। भाप्रौविनि ने पहले ही चार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों, अर्थात, बिड़ला इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी स्टेप (बी० आई० टी० स्टेप), रांची, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज स्टेप (आर० ई० सी० स्टेप), तिरूचिरापल्ली, राष्ट्रीय उद्यमी रसायन पार्क स्टेप (एन० ई० सी० पी स्टेप), बम्बई और हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान स्टेप (एच० बी० टी आई स्टेप), कानपुर के निधिकरण में भागीदारी की है।

3.39 बिड़ला इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी स्टेप (बिट स्टेप) ने औद्योगिक उपयोग के लिये अन्य प्रौद्योगिकियों के अतिरिक्त आटोमेटिक वायर लेग्थ मेजरमेंट स्टिम और आयात प्रतिस्थापन स्टेनलेस स्टील वेज वायर स्क्रीन के लिये एक विलक्षण प्रौद्योगिकी का विकास किया है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज स्टेप (आर० आई० सी० स्टेप), अन्य हाई स्टेक और आयात प्रतिस्थापन उत्पादों के अतिरिक्त आणविक उपयोग के लिये हाई-टेक पेन्टस हेतु प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। सात आर० ई० सी० स्टेप उद्यमियों ने पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय उद्यमी रसायन पार्क चुनिंदा आयातित औषधियों की परियोजना रूपरेखा तैयार करने में लगा हुआ है। हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान स्टेप के विद्यार्थी-उद्यमी उन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, जिनमें फाइबर रिन्फोर्पड कैंकरीट और प्लास्टिक कम्पोनेन्टस शामिल है।

3.40 समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाऔविनि दो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों के निधिकरण के लिए सहमत हो गया है, एक श्री जयचामाराजेन्द्र कॉलिज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर (एस०जे०सी०ई०-स्टेप) द्वारा प्रवर्तित और दूसरा गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलिज, लुधियाना (जी०एन०ई०सी०-स्टेप) द्वारा प्रवर्तित। एस० जे० सी०ई०-स्टेप उसके पास उपलब्ध दक्षता के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में मुख्यतः विशेष ध्यान करेगा। जी०एन०ई०सी०-स्टेप मशीन टूल उप-साधनों और मैक्नो-इलेक्ट्रानिक नियंत्रणों में विशेष अध्ययन करेगा।

3.41 मार्च, 1980 की समाप्ति तक, तीन और अनुरोध, यथा रुड़की विश्वविद्यालय, मौलाना आज़ाद कॉलिज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल, और जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता, प्रत्येक से एक-एक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के विचाराधीन थे। 31 मार्च, 1989 तक मंजूरियों के रूप में स्टेप्स की भाऔविनि द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधि सहायता 15.91 लाख रुपये रही थी।

औद्योगिक प्रबंध एवं विकास बैंकिंग के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सहायता

(क) भाऔविनि पीठें

3.42 औद्योगिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, औद्योगिक वित्त, क्षेत्रीय अर्थशास्त्र और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भाऔविनि ने छः पीठों को सृजित किया है--भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों प्रत्येक में एक-एक।

3.43 समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपर्युक्त पीठों के तत्वाधान में निम्नलिखित वार्षिक सार्वजनिक व्याख्यान दिए गए :--

-- निगमित पूंजी की प्रबन्ध उत्पादकता

-- प्रो० एस०सी० कुच्छल, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद

-- भारत में विकास बैंकिंग और नीति के कुछ पहलू

-- डा० आर० एस० सबनीस, बम्बई विश्वविद्यालय

-- भारत में विकास बैंकिंग-उत्तर-पूर्वी भारत में कार्य निष्पादन और प्रत्याशाएं

-- डा० पी०सी० गोस्वामी गुवाहाटी विश्वविद्यालय

3.44 पीठों के कार्य की 18 मार्च, 1989 को भाऔविनि के निदेशक बोर्ड की एक समिति की बैठक में समीक्षा की गई, जहां पर कि समिति के सदस्यों को भाऔविनि पीठ प्राध्यापकों से, जो कि विशेषतः इस प्रयोजन के लिए आमंत्रित किए गए थे, परस्पर विचार-विनिमय का अवसर भी मिला। उसके पश्चात समिति की सिफारिशों पर भाऔविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा विचार किया गया, जिसके परिणाम-स्वरूप निम्नानुसार सहमति हुई :--

(i) पीठें अपेक्षाकृत अनुसंधान के उन क्षेत्रों के लिए ही हों, जो कि उद्योग, वित्त, बैंकिंग और अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हों। भाऔविनि के परामर्श से पीठ प्राध्यापकों द्वारा अनुसधान परियोजनाओं में कुछ अग्रता का निर्धारण आवश्यक है।

(ii) पीठें एक स्थायी समीक्षा-तंत्र के अधीन होनी चाहिएं, जिसके आधार पर पीठ की निरन्तरता और वृत्तिदान के रूप में प्रदान की गई राशि को प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जा सके।

(iii) एक-मुश्त वृत्तिदान आधार पर पीठों की निधिकरण पद्धति रखना उचित होगा।

(iv) पीठों का और नवीन सृजन सुस्वस्थ चयनता पर आधारित होना चाहिए, और विशिष्टता पीठ पर आसीन होने वाले या आसीन होने को निरूपित व्यक्ति के चारों ओर बनायी जानी चाहिए।

(v) जहां पीठ के अंतर्गत किया जाने वाला अनुसंधान कार्य उत्कृष्ट प्रकृति का हो, भाऔविनि

को या तो कुछ अतिरिक्त मंजूरी देकर या प्रकाशन की लागत को पूरा करके अनुसंधान कार्य को प्रकाशित करवाना चाहिए।

समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में वृत्तिदान की राशि में और समझौता ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तन करके, जहां आवश्यक हो, सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए उपाय किए जा रहे थे।

3.45 31 मार्च, 1989 तक वर्तमान पीठों को वृत्तिदान मंजूरी/वार्षिक मंजूरी के रूप में भाऔविनि की निधि सहायता कुल मिलाकर 29.15 लाख रुपये हो चुकी थी।

(ख) अन्य अनुसंधान परियोजनाएं

3.46 अनुसंधान-उन्मुख कार्यों के प्रवर्तन के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाऔविनि ने गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना पद्धति, नई दिल्ली को 3 लाख रुपये का और अंश दान दिया। भाऔविनि ने "दि पॉलिसी ग्रुप" नामक एक अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, द्वारा किए गए "ए मैक्रो-इकोनामीट्रिक मॉडल ऑफ दि इण्डियन इकोनॉमी" शीर्षक अनुसंधान परियोजना के लिए सहमत आठ लाख रुपये में से 3 लाख रुपये का अंशदान भी किया।

3.47 "प्रोफेशनल एसिस्टेंस फॉर डवलपमेंट एक्शन" (प्रदान) के रूप में विख्यात एक स्वयंसेवी संगठन को स्वयं-संपोषित आर्थिक उद्यमों को स्थापित करने में निम्न आय समूहों की सहायता करने के लिए निरन्तर आधार पर आधारभूत व्यावसायिकों के समूह को तैयार करने के लिए भाऔविबैंक, भाऔविनि और भाऔसानिनि (भाऔविनि की हिस्सेदारी 10 लाख रुपये) द्वारा इसकी निकाय निधि में निधि सहायता प्रदान की। "प्रदान" द्वारा दो कार्यक्रम, एक मानव संसाधन विकास से संबंधित जिसमें 25 और 10 स्नातकों को क्रमशः तीन माह की एसोसिएटशिप और एक वर्ष की प्रशिक्षता, शामिल है और एक पाइलट परियोजना, जिससे कि गैर-परम्परागत ग्रामीण रोजगार का संवर्द्धन हो, उपर्युक्त निकाय निधि से प्रोद्भूत होने वाली आय से, वार्षिक आधार पर, किए जाने का प्रस्ताव है।

3.48 अपनी प्रवर्तन भूमिका के भाग के रूप में देश में उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करने के दृष्टिकोण से समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाऔविनि भी उपभोक्ता सूचना, अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करवाने में लगी हुई एक गैर-लाभ अर्जक और गैर-राजनीतिक स्वयंसेवी एजेंसी, "उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र" (सी०ई०आर०सी०) को अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ हिस्सेदारी आधार पर पूंजी लागत के लिए 73 लाख रुपये और आवर्ती व्ययों के लिए पांच वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को सहमत हुआ। सी०ई०आर०सी० द्वारा खाद्य, औषधि और फार्मास्युटिकल्स, एवं घरेलू बिजली उपकरणों के क्षेत्र में बाजार से लिए गए उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षण के लिए उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि निरन्तर आधार पर उत्तम प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपनी वचनबद्धता के बारे में उपभोक्ता-उत्पादों के उत्पादकों के बीच बेहतर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। उपभोक्ताओं के संरक्षण और सुरक्षा के व्यापक हित में उत्पाद परीक्षण और मूल्यांकन संगठनों की स्थापना में संस्थानात्मक सहायता, वित्तीय संस्थानों के प्रवर्तन कार्यों की नानाविध प्रकृति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाना चाहिए।

आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड की बैठकें

4.01 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड की नौ बैठकें हुईं, जिनमें से सात नई दिल्ली में और एक-एक बैठक कलकत्ता और मद्रास में हुई।

निदेशक बोर्ड में परिवर्तन

4.02 निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने कार्यपालक निदेशक, श्री एस० एच० खान को दिनांक 9 जनवरी, 1989 से श्री एस० एम० पालिया के स्थान पर नामित किया। इस के अतिरिक्त अवधि के अंत में बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और अन्य ऐसे वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निर्वाचित निदेशक, श्री एस० के० सेठ ने भी भाऔविनि के निदेशक बोर्ड से त्याग-पत्र दे दिया, और उनके स्थान की पूर्ति 30 जून, 1989 को निर्धारित आगामी 41वीं वार्षिक महासभा में चुनाव द्वारा की जानी सम्भावित है।

4.03 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड श्री एस० एम० पालिया और श्री एस० के० सेठ द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने की अवधि के दौरान किए गए उपयोगी और बहुमूल्य योगदान की अति प्रशंसा करता है।

सलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें

4.04 अवधि के दौरान, होटलों, अस्पतालों, रसायन प्रक्रिया एवं सम्बद्ध उद्योगों, इंजीनियरिंग तथा चीनी उद्योगों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विशिष्ट परामर्श प्राप्त करने हेतु सलाहकारों के तदर्थ समूह की बारह बैठकें हुईं।

राज्य सलाहकार समितियों की बैठकें

4.05 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अनुसार पहली बार गोवा और हरियाणा राज्यों में राज्य सलाहकार समितियों का गठन किया गया। इस अवधि के दौरान राज्य सलाहकार समितियों की तीन

बैठकें—एक गोवा में, एक हरियाणा में और एक मध्य प्रदेश में हुई। इस समय विभिन्न राज्यों में भाऔविनि की 18 राज्य सलाहकार समितियां कार्यरत हैं।

अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय

4.06 अन्तर-संस्थानात्मक बैठकों, अन्तर संस्थानात्मक पुनर्स्थापन बैठकों, वरिष्ठ कार्यपालक बैठकों और क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थात्मक समन्वय बनाए रखा गया। 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान आठ अन्तर-संस्थानात्मक बैठकें, दो अन्तर-संस्थानात्मक पुनर्स्थापन बैठकें, उन्नीस वरिष्ठ कार्यपालक बैठकें, और सोलह क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकें आयोजित की गईं।

4.07 राज्य स्तर पर, भाऔविनि द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य स्तरीय मार्गदर्शन और अनुवर्तन समितियों तथा राज्य स्तरीय अन्य मंचों आदि की बैठकों में अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों के माध्यम से भाग लेकर समन्वय बनाए रखा गया।

विदेश यात्राएं और अन्तरराष्ट्रीय मंच पर भागीदारी।

4.08 भाऔविनि ने विदेशों के अन्य विकास वित्तीय संस्थानों और विश्व पूंजी बाजार में कार्यशील अन्तरराष्ट्रीय बैंकों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाए रखा।

4.09 भाऔविनि के अध्यक्ष, श्री धर्मेन्द्र नाथ डावर ने, उप-महाप्रबन्धक, श्री वी० पी० कामथ के साथ, "औद्योगिक विकास कोआपरेशन लिमिटेड के लिए फिनिश निधि" के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करने और क्रिदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) के साथ ऋणों पर बातचीत करने और जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख बैंकों के साथ परस्पर हित के मामलों पर विचार करने हेतु फिनलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, स्विट्-जरलैंड और यूनाइटिड किंगडम का दौरा किया।

4.10 भाऔविनि के कार्यपालक निदेशक, श्री सुदर्शन कुमार ऋषि ने मेरिल लिंच से हांगकांग में 20 बिलियन येन के करार पर हस्ताक्षर करने और सिंगापुर के बैंकरों से विचार-विमर्श करने हेतु हांगकांग और सिंगापुर का दौरा किया। इसी प्रकार, भाऔविनि के महाप्रबन्धक, श्री एफ० एम० पटनायक ने, श्री के० पी० मुखर्जी, प्रबन्धक के साथ, 100 मिलियन अमरीकी डालर ऋण के लिए स्विस बैंक कारपोरेशन इंवेस्टमेंट बैंकिंग लिमिटेड से ऋण करार पर हस्ताक्षर करने और के० एफ० डब्ल्यू० के अधिकारियों से विचार-विमर्श करने हेतु स्विट्जरलैंड और जर्मन संघीय गणराज्य का दौरा किया। इसी भाँति, महाप्रबन्धक, श्री वी० एस० आर० के० शास्त्री ने भारतीय प्रतिनिधि दल के सदस्य के रूप में दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अधीन व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग हेतु विशेषज्ञ समूह अध्ययन की इस्लाबाद, पाकिस्तान में आयोजित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

4.11 अवधि के दौरान, अनेक विदेशी उच्चाधिकारियों/विशिष्ट व्यक्तियों ने भी भाऔविनि का दौरा किया, और भारतीय वित्तीय पद्धति, भारत में निवेश सुयोगों, और पारस्परिक हित के अन्य मामलों पर परामर्श हेतु विचार-विमर्श किया।

11वां भाऔविनि रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान

4.12 "परिवर्तन के युग में केन्द्रीय बैंकिंग" विषय पर तान श्री दातो जाफ़र हुसैन, गवर्नर, बैंक नेगारा, मलेशिया (सेन्ट्रल बैंक आफ मलेशिया) द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 1988 को भाऔविनि का 11वां रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान दिया गया। इस बहु-उपस्थितीय व्याख्यान की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री आर० एन० मल्होत्रा ने की। तान श्री दातो जाफ़र हुसैन के व्याख्यान का सार-तत्व यह था, कि प्रबन्ध विकास में किसी भी विकासशील देश की सफलता, मूलतः उसके सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय संस्थानों की प्रभावोत्पादकता तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में उनकी प्रतिक्रियाशिलता पर निर्भर करती है। केन्द्रीय बैंकों को भी विकास बैंकों के समान समय के अनुसार अपने को परिवर्तित करना होगा अन्यथा वे अप्रयुक्तप्राय होकर रह जायेंगे। तान श्री दातो जाफ़र हुसैन का विचार था, कि एक विकासशील देश में, जहां विदेशी व्यापार दक्षताएं अपेक्षित है, केन्द्रीय बैंक का यह दायित्व है, कि वह बाजार में दक्ष मानवशक्ति को उपलब्ध करवाने वाले, तकनीकी कुशलताओं के जानकार तथा बैंकिंग और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले की भूमिका निभाए। श्री जाफ़र हुसैन ने यह भी कहा कि बैंक नेगारा, मलेशिया ने माडर्न डीलिंग रूम टेक्नोलाजी और मानवशक्ति दक्षता पर अत्यधिक निवेश किया है क्योंकि उसका पूर्ण विश्वास है कि "मानवीय पूंजी ही सबसे अधिक आय-प्रदायक होती है"।

4.13 11वें रजत जयन्ती स्मारक व्याख्यान के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री आर० एन० मल्होत्रा ने, भाऔविनि को देश में एक राष्ट्रीय गौरव वाले संस्थान के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने हेतु प्रदत्त महान सेवाओं के लिए भाऔविनि के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालकों/अध्यक्षों को भाऔविनि की ओर से रजत-फलक भी प्रदान किए।

जवाहरलाल नेहरू जन्मशती समारोह

4.14 पहली जुलाई, 1989 को भाऔविनि भारतीय उद्योग के प्रति सेवा के अपने 42वें वर्ष में कदम रखेगा। यह वर्ष जवाहरलाल नेहरू जन्मशती वर्ष भी है। अतः भाऔविनि ने इस अवसर को उचित रूप से मनाने का निर्णय किया है। श्री नेहरू के लेखों और अभिभाषणों से लिए गए उद्धरण पत्र-शीर्षों तथा भाऔविनि द्वारा निकाले गए अन्य प्रकाशनों पर अंकित किए गए है। नेहरू जन्मशतीवर्ष के दौरान सात केन्द्रों, यतः अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कानपुर और मद्रास में आधुनिक भारत

के निर्माण में विभिन्न रूपों में नेहरू की भूमिका से संबंधित विषयों पर विचार-गोष्ठियां आयोजित करने की भी योजनाएं बनायी गई है ।

4.15 नेहरू जन्मशती समारोह के भाग के रूप में भाऔविनि ने पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित अपनी स्टाफ कालोनी में 25 फरवरी, 1989 को एक नेहरू बाल मेला का आयोजन किया । जिसमें "विविधता में एकता" के प्रतीक रूप में भारतीय राज्यों की विभिन्न वेशभूषाओं में कर्मचारियों के लगभग 160 बच्चों द्वारा एक प्रभावशाली मार्च पास्ट किए जाने के अतिरिक्त, चित्रकला और रंग-भरने की प्रतियोगिताएं तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और कार्यों से सम्बन्धित विषयों पर भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । भागीदारों को उचित पुरस्कार दिए गए । श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और कृतित्व को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया ।

संगठनात्मक गतिविधियां

4.16 अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि के समाप्त होने पर, श्री आर० विश्वनाथन, कार्यपालक निदेशक, 19 अगस्त, 1988 से अपने मूल संस्थान, अर्थात्, भारतीय स्टेट बैंक में वापस चले गये । श्री एस० पी० बैनर्जी, महाप्रबन्धक को पहली मार्च, 1989 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया ।

4.17 अनुवर्तन अवधि के लिए कार्यान्वयन योजना बनाने सहित कार्य-समीक्षा, माहौल की सूक्ष्म जांच करने, नीतियां समष्टि तथा सामरिक बनाने और कार्यक्रम तैयार करने की लगातार प्रक्रिया के रूप में, भाऔविनि के वरिष्ठ अधिकारियों के दो सम्मेलन अप्रैल और दिसम्बर, 1988 में आयोजित किए गए ।

इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग तथा सम्प्रेषण प्रणाली

4.18 भाऔविनि की पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय में अपेक्षित अनुषंगी सामान सहित एक आधुनिक आई० सी० आई० एम०-6040 मेन फ्रेम कम्प्यूटर स्थापित और परिचालित करने एवं भाऔविनि के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक आई० सी० आई० एम० क्वाटरो पर्सनल कम्प्यूटर लगाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था । इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान आई० सी० आई० एम० क्वाटरों पर्सनल कम्प्यूटर के स्थान पर मिनी/सुपर माइक्रो रेंज आई० सी० आई० एम० की नवीनतम मशीन अर्थात् यू० एन० आई० एक्स० परिचालन पद्धति सहित डी०आर०एस०-300 प्रतिस्थापित की गई, और इसे आई० सी० आई० एम० मेन फ्रेम कम्प्यूटर और यू० एन० आई० एक्स० एन्वायरमेंट, जो सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में स्थापित किए जाने हैं, कार्यरत ई०एस०पी०एल० मिनी सिस्टम्स के बीच नेटवर्किंग/सम्प्रेषण की सुविधा के लिए प्रधान कार्यालय में स्थापित किया गया ।

4.19 मुख्य परिचालन क्षेत्रों में आई० सी० आई० एम०-6040 मेन फ्रेम कम्प्यूटर पर विकसित/कार्यान्वित साफ्टवेयर से भाऔविनि की लेखा और प्रबन्ध सूचना पद्धति संतोषजनक रूप से कार्य करती रही । मार्च, 1989 के अंत में, वित्तीय संस्थाओं के संक्षिप्त विवरणों के लिए वित्तीय अनुपात विश्लेषण की संशोधित पद्धति, आंकड़ों के भंडारण, रख-रखाव, अद्यतन बनाने और पुनः प्राप्त करने, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के निष्पादन आंकड़ों के संकलन तथा विदेशी मुद्रा संसाधन और परिचालन विभाग में कम्प्यूटरीकरण के लिए ई०एस०पी०एल० पर मिनी पद्धतियों पर फ्रेश यूअर फ्रैंडली सिस्टम का विकास किया जा रहा था । इसके अतिरिक्त, ईलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयोक्ता विभागों/प्रभागों के अधिकारियों और स्टाफ को कम्प्यूटर मूल्यांकन, आंकड़ा प्रलेखन और कम्प्यूटर डिसीप्लिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा ।

4.20 समान धारणा विकसित करने, प्रणालियों के विकास प्रयासों में द्विरावृत्ति को रोकने, और भविष्य में प्रणालियों में एकीकरण करने की दृष्टि से औवि बैंक के तत्वाधान में संस्थानों द्वारा एक अन्तर-संस्थानात्मक इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समन्वय समिति का गठन किया गया । समिति से यह अपेक्षा है, कि वह प्रपत्रों का मानकीकरण करने और उन प्रणालियों का, जिनमें वित्तपोषित संस्थाओं और परियोजना रूप-रेखा के विवरणों के रख-रखाव के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकता है, कार्य देखेगी ।

कार्मिक

4.21 मार्च, 1989 की समाप्ति तक भाऔविनि में (इसके क्षेत्रीय, शाखा और अन्य कार्यालयों सहित) 1,136 कर्मचारी कार्यरत थे । इनमें 392 अधिकारी, 530 सहायक कर्मचारी और 214 अधीनस्थ कर्मचारी थे । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या, क्रमशः 160,37 और 17 थी । मार्च, 1989 के अंत तक भाऔविनि में महिला कर्मचारियों की संख्या 181 थी ।

मानव संसाधन विकास

4.22 कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने, उचित दृष्टिकोण का वातावरण सृजित करने और संगठन में प्रेरक विकास के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा मानव संसाधन विकास पर अतीत की भांति ही समुचित महत्व दिया जाता रहा । भाऔविनि में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी, आवश्यक दक्षताओं सहित, मानव संसाधनों को सज्जित करने और उनमें बदलते हुए कारोबार, परिवेश और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख कार्यों को गहराई से समझने पर प्रमुख बल दिया गया । आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम्प्यूटर की जानकारी, मर्चेन्ट बैंकिंग, लीजिंग, विदेशी मुद्रा ऋण

परिचालन, औद्योगिक परियोजनाओं का आर्थिक विश्लेषण आदि जैसे कुछ विशेष क्षेत्र अन्य कार्यक्रमों के साथ सम्मिलित रहे ।

4.23 31 मार्च, 1989 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान भाआवित्रि के अधिकारियों और स्टाफ के लाभ के लिए विभिन्न अवधि के 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो प्रधान कार्यालय के प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली और पटना, हैदराबाद और बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किए गए । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न कार्यालयों और विभिन्न स्तरों के 405 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया ।

4.24 इन-हाऊस प्रशिक्षण, में संपूरक के रूप में देश के अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी 50 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त, प्रबन्ध विकास के लिए भाआवित्रि द्वारा प्रवर्तित, प्रबन्ध विकास संस्थान (प्रविसं) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी 15 स्टाफ सदस्यों को भेजा गया । विश्व बैंक के आर्थिक विकास संस्थान और एशियाई विकास बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भी दो अधिकारियों को भेजा गया । भाआवित्रि के परिचालनों से सम्बन्धित उपयुक्त विषयों पर, कर्मचारियों और स्टाफ के लाभ के लिए विशेषज्ञों द्वारा विशेष भाषणों का भी प्रबन्ध किया गया ।

4.25 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन हेतु वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की योजना के अधीन, भाआवित्रि ने, वर्ष के दौरान, वाणिज्यिक बैंकों के चार अधिकारियों को अपने पुनर्स्थापन वित्त विभाग में कार्य-प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराईं ।

4.26 भाआवित्रि ने अपनी सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कर्मचारियों हेतु आरक्षण/रियायतों के सम्बन्ध में सरकारी मार्गनिर्देशों को कार्यान्वित करना जारी रखा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध प्रत्याशियों को बेहतर परिणाम दर्शाने के लिए तैयार करने हेतु 33 भर्ती पूर्व बोध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाआवित्रि में विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार देने से पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 234 प्रत्याशियों ने भाग लिया ।

4.27 गहन आन्तरिक तथा कार्य-दौरान प्रशिक्षण के अतिरिक्त संगठन की समग्र उत्पादकता में सुधार लाने के लिए स्टाफ सुझाव योजना के अन्तर्गत स्टाफ को निरन्तर सुझाव देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया । स्टाफ़ सुझाव समिति द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव का भली भांति मूल्यांकन किया गया और यदि कोई सुझाव कार्यान्वयन हेतु स्वीकार किया गया तो सम्बन्धित स्टाफ सदस्यों को नकद पुरस्कार/प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये ।

कल्याण कार्य

4.28 भाआवित्रि के कर्मचारियों का कल्याण कार्य सभी केन्द्रों और सभी स्तरों पर जारी रहा और पहले की भांति ही इसको कार्मिक प्रबन्ध के क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई । भाआवित्रि के कल्याण कार्यों में सामाजिक सुरक्षा आवास और चिकित्सा सुविधाएं मुख्य बनी रहीं । स्टाफ कल्याण निधि विविध प्रकार की स्टाफ कल्याण गतिविधियों का मूलाधार बनी रही ।

खेल कूद

4.29 भाआवित्रि ने लगातार चौथे वर्ष भी भाआवित्रि के कर्मचारियों में खेल और खेल भावना विकसित करना निरन्तर जारी रखा । चौथी अखिल भारतीय भाआवित्रि खेल कूद प्रतियोगिता 1989, इस वर्ष दिनांक 19 फरवरी 1989 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक समारोह के साथ सम्पन्न हुई । इस वर्ष के खेल कूद के मुख्य पहलू थे —(क) अधिक प्रकार की खेल कूद क्रीड़ाएं प्रारम्भ करना (ख) भाआवित्रि के अनेक पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेना तथा (ग) सभी स्तरों पर भाआवित्रि के कर्मचारियों के बच्चों द्वारा अधिकाधिक भाग लेना ।

राहत कोषों में अंशदान

4.30 भाआवित्रि ने वर्ष 1988 के परवर्ती भाग के दौरान पंजाब के विभिन्न भागों में आई बाढ़ और वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत और सहायता देने के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष में एक लाख रुपये का अंशदान दिया । झंडा दिवस निधि और बधिरों की अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् नई दिल्ली के लिए भी स्वल्प अंशदान दिये गये ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4.31 भाआवित्रि ने अतीत की भांति अपने निजी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया । 31 मार्च 1989 को समाप्त अवधि के दौरान हिन्दी में एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार दिए गए । प्रधान कार्यालय और क्षेत्र "क" और "ख" में स्थित क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए कुछ प्रभागों/विभागों को भी अभिनिर्धारित किया गया और इन प्रभागों/विभागों का शासकीय कार्य 100% आधार पर हिन्दी माध्यम में किया जाना आरम्भ करना निश्चित किया गया ।

4.32 प्रधान कार्यालय सहित भाआवित्रि के प्रत्येक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखी, तथा अपने सम्बन्धित कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव दिए । इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह का अंतिम शुक्रवार हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा । पुनः हिन्दी में अधिकतम मूल पत्र व्यवहार बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के पहले और तीसरे बुधवार को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाना बढ़ाया गया ।

4.33 सभी प्रशासन परिपत्र और परिचालन परिपत्र अधिसूचनाएं विज्ञापन और सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किए गए। भाऔविनि कार्यालयों में उपयोग हो रहे अधिकांश रजिस्टर द्विभाषिक रूप में बनाए गए। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले स्टाफ सदस्यों को भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के लिए भेजा गया। भाऔविनि के आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को प्रधान कार्यालय के विभिन्न प्रभागों/विभागों और सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुवर्तन करने का कार्य भी सौंपा गया।

प्रकाशन

4.34 रिपोर्ट की अवधि के दौरान भाऔविनि के जनसम्पर्क विभाग द्वारा अनेक प्रकाशन निकाले गए। इस वर्ष का एक गौरवमय प्रकाशन "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम—प्रगति और विकास" शीर्षक के अन्तर्गत भाऔविनि की वार्षिक महासभाओं में अध्यक्षों के अभिभाषणों का संग्रह रहा। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन—"भाऔविनि—उद्योग की सेवा के चालीस वर्ष" था।

आभार प्रदर्शन

4.35 निदेशक बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैंक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔविबैंक) अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर के वित्तीय एवं विकास संस्थानों और मर्चेन्ट बैंकिंग संस्थाओं से प्राप्त हुई सहायता सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

4.36 निदेशक बोर्ड भाऔविनि द्वारा विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहयोग विशेष रूप से विश्व बैंक आर्थिक विकास संस्थान एशियाई विकास बैंक एशिया और प्रशान्त के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ और जर्मन संघीय गणराज्य के क्रेडितान्स्टाल्ट-फर-वाइडरफबाऊ और अनेकों विदेशी समवर्ती बैंकों, और अन्य अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय के सदस्यों से प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है।

4.37 निदेशक बोर्ड को निगम के सभी स्तर पर समस्त कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट की अवधि के दौरान की गई एकनिष्ठ और समर्पित सेवा के लिए उनकी अत्यंत सराहना करते हुए भी अत्यधिक प्रसन्नता है।

डी० एन० डावर
अध्यक्ष

परिशिष्ट—1

1988-89 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण।

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1988-89 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन					
			सम्पूर्ण देश के संबंध में			निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध में		
			विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1988-89 (अप्रैल-मार्च में) उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1988-89 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	चीनी	लाख टन	82.69 (392)	84.20*	101.8	12.40 (79)	16.90	136.3
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)		28.09 मिलियन तकुए (1054)**	1296.90 मिलियन कि०ग्राम	—	5.81 मिलियन तकुए	375.64 मिलियन कि०ग्राम	—

* उत्पादन अक्तूबर 1988 से 7 मई 1989 की अवधि का है।
**23 संयुक्त मिल सम्मिलित है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)		1.99 लाख खडिडयां	2911 मिलियन मीटर	—	0.51 लाख खडिडयां	904.33 मिलियन मीटर	—
4.	पटसन वस्त्र	लाख टन	16.86 (72)	13.88	82.3	0.77 (3)	0.62	80.5
5.	कागज और गत्ता	लाख टन	29.85 (303)	17.20	57.6	8.71 (25)	6.74	77.3
6.	रेयन पल्प	लाख टन	1.96 (5)	1.60	81.6	0.96 (3)	1.01	105.2
7.	अखबारी कागज	लाख टन	3.00 (5)	3.10	103.3	0.75 (1)	0.87	116.0
8.	प्लाईवुड	मिलियन वर्ग मी०	122.44 (61)	70.00	57.2	3.25 (2)	0.46	14.1
9.	सीमेन्ट	मिलियन टन	62.07	42.92	69.1	28.34 (61)	23.03	81.3
10.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	81.4 (47)	64.55	79.2	22.84 (17)	20.14	88.2
11.	फास्फेटिक उर्वरक	लाख टन	26.50 (19)	22.69	85.6	15.64 (10)	21.79	139.3
12.	कास्टिक सोडा	लाख टन	11.03 (39)	8.60	77.9	3.24 (7)	2.69	83.0
13.	सोडा एश	लाख टन	14.60 (7)	11.00	75.3	0.66 (1)	0.57	86.4
14.	केल्सियम कार्बाइड	लाख टन	2.19 (7)	0.80	36.5	0.84 (3)	0.38	45.2
15.	एसिटिक एनहाइड्राइड	हजार टन	35.00 (11)	20.00	57.1	5.10 (1)	2.90	56.9
16.	एसिटिक एसिड	लाख टन	1.05 (21)	0.80	76.2	0.07 (2)	0.07	100.0
17.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.75 (7)	1.20	68.6	0.17 (1)	0.12	70.6
18.	तरल क्लोरीन	लाख टन	7.70 (29)	3.29	42.7	2.23 (6)	1.72	77.1
19.	नायलोनफिलामेंट धागा	हजार टन	158.09 (22)	34.88	22.1	13.61 (3)	13.92	102.3
20.	नायलोन टायर कार्ड	हजार टन	एन०ए०	एन०ए०	—	8.00 (2)	8.89	111.1
21.	पालिएस्टर फिलामैंट यार्न	हजार टन	158.09 (22)	140.67	89.0	29.40 (8)	42.04	143.0
22.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	176.06 (9)	100.28	56.9	103.00 (4)	73.65	71.5
23.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	हजार टन	89.00 (2)	125.03	140.5 (1)	78.00 (1)	89.92	115.3

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24. आटोटायर	लाख संख्या	182.28 (24)	160.00	87.7	45.60 (5)	30.30	64.4
25. आटो ट्यूब्स	लाख संख्या	193.73 (26)	145.00	74.8	43.35 (5)	32.08	74.0
26. रबर गर्भरोधक	मिलियन संख्या	1033.00 (3)	890.00	86.2	808.00 (2)	544.33	67.4
27. पुर्नप्रयोगकी गई रबर	हजार टन	36.58 (11)	24.00	65.6	4.80 (1)	2.36	49.2
28. खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	120.37 (46)	62.00	51.5	3.70 (2)	2.62	70.8
29. त्वचा से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	614.94 (67)	330.00	53.7	19.40 (2)	3.89	20.00
30. कांच की शीटे	मिलियन वर्ग मी०	40.79 (9)	42.00	102.9	14.70 (2)	17.10	116.3
31. फाइबर ग्लास	हजार टन	5.29 (3)	4.65	87.9	2.00 (1)	1.91	95.5
32. कांच की बोतलें और विविध कांच का सामान	लाख टन	6.53 (31)	5.95	91.1	0.24 (1)	0.12	50.0
33. कृत्रिम डिटर्जेन्ट	हजार टन	323.46 (21)	258.52	87.3	20.00 (2)	9.17	45.8
34. साबुन	हजार टन	365.40 (48)	368.00	100.7	33.50 (3)	6.29	18.8
35. फैटी एसिड	हजार टन	150.00 (18)	110.00	73.3	17.96 (3)	7.78	43.3
36. ग्लिसरीन	हजार टन	22.58 (19)	12.65	56.0	2.34 (2)	0.40	17.1
37. रिफ्रेक्ट्रीज	लाख संख्या	17.20 (71)	9.34	54.3	1.55 (5)	1.04	67.1
38. सिरेमि कटाइल्स	लाख टन	2.13 (16)	1.30	61.0	0.36 (3)	0.21	58.3
39. विस्फोटक	हजार टन	199.00 (15)	144.20	72.5	26.50 (3)	11.46	43.2
40. आक्सीजन	एम०सी०एम०	205.38 (177)	129.00	62.8	26.50 (8)	14.05	64.9
41. घड़ियां	मिलियन संख्या	14.20 (13)	7.71	54.3	5.97 (2)	5.37	88.9
42. बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	92.52 (6)	92.10	99.5	21.00 (1)	19.20	91.4
43. स्टील इंगोटस/ बिल्लेट्स	लाख टन	52.40 (166)	33.00	63.00	6.81 (15)	4.35	63.9
44. स्टील गढ़ाई	लाख टन	3.30 (75)	1.60	57.6	0.25 (3)	0.10	40.0
45. स्टील ढलाई	लाख टन	2.05 (85)	1.00	48.8	1.05 (5)	0.62	59.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46.	शीतकृत इस्पात पत्तियां	लाख टन	15.00 (57)	3.88	25.9	0.90 (5)	0.58	64.4
47.	स्पांज आयरन	लाख टन	3.00 (3)	1.94	64.7	1.35 (1)	0.89	65.9
48.	दुपहिये	लाख संख्या	24.00 (24)	16.00	66.7	5.20 (5)	3.19	61.3
49.	वाणिज्यिक वाहन	लाख संख्या	2.65 (13)	1.90	71.7	0.99 (5)	0.81	81.8
50.	कारें	लाख संख्या	1.71 (5)	1.60	93.6	0.35 (2)	0.20	57.1
51.	वी० बेल्ट	लाख संख्या	183.71 (16)	300.00	163.3	12.00 (1)	11.90	99.2
52.	कन्वेयर बेल्ट्स	हजार टन	8.91 (8)	11.45	128.5	2.38 (1)	2.54	106.7
53.	जी०एल०एस० लैम्प	मिलियन संख्या	343.00 (20)	250.00	72.9	76.10 (3)	53.57	70.4
54.	फ्लोरेसेन्ट ट्यूबैल	मिलियन संख्या	46.20 (16)	50.00	108.2	9.50 (2)	10.15	106.8
55.	पावर एवं वितरण ट्रांसफार्मर्स	मिलियन किलोवाट्स	33.7 (33)	25.00	74.2	1.80 (1)	1.61	89.4
56.	इलेक्ट्रीकल पंखे	लाख संख्या	76.00 (17)	55.00	72.4	0.60 (1)	0.60	100.00
57.	डीजल इंजिन	हजार संख्या	336.00 (34)	198.00	58.9	4.80 (2)	3.51	73.1
58.	ट्रैक्टर	हजार संख्या	122.30 (19)	101.00	82.6	37.00 (2)	27.00	73.0
59.	पावर टिलर	हजार संख्या	16.00 (5)	4.00	25.0	2.50 (1)	1.74	69.6
60.	होटल	लाख संख्या@	135.05 (600)	91.56	67.8	7.51 (14)	4.92	65.5

@कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराए के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है।

परिशिष्ट–II

1988–89 (जुलाई–मार्च) के दौरान भा०औ०वि०नि० द्वारा वित्त पोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(रु० करोड़)

उद्योग	परियोजनाएं	कुल पूंजी लागत	संभावित प्रत्यक्ष रोजगार	उत्पाद मूल्य	सकल मूल्य वृद्धि	क्षमता प्रतिवर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
खनन	3	37.89	1,021	32.94	28.08	80,620 टन निम्न श्रेणी कोम अयस्क की प्रोसेसिंग, 4 कुएं खोदने वाले चलते-फिरते बरमों

1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						का अधिग्रहण, तेल की खोज के लिए 3,200 किलोमीटर तेल क्षेत्र में भूकम्प सर्वेक्षण।
चीनी	12	282.09	8,315	251.22	99.18	5.18 लाख टन चीनी
खाद्य पदार्थों का संसाधन (प्रोसेसिंग)	8	91.00	1,137	162.69	58.57	33,000 टन गेंहू तथा 6,000 टन चावल, 4,680 टन संभाधित खाद्य, 131,80 लाख लिटर फलों के रस, 2 लाख लिटर खनिज जल, 120 लाख लीटर मीठे पेय, 106.42 लाख लिटर शीतल पेय, 4,100 टन संसाधित चाकलेट तथा 20,000 टन माल्ट का संसाधन (प्रोसेसिंग)।
वस्त्र	16	153.53	4,721	176.96	55.49	1.66 लाख तकुए, 10 लाख किलोग्राम धागे की गांठें एवं लच्छियां तथा 66 लाख मीटर कृतिम धागा मिश्र कपड़े का संसाधन (प्रोसेसिंग)।
कागज	2	18.87	135	28.55	4.45	19,800 टन अखबारी कागज तथा 750 टन खोई पर आधारित कागज
उर्वरक/कीटनाशक	6	1,902.44	2,664	985.98	614.93	15.00 लाख टन यूरिया खाद, 1.32 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट (एस० एस० पी०) 1.00 लाख टन मेथानॉल, 2.5 लाख टन अमोनिया नाईट्रोफास्फेट, 1,200 टन राइस हस्कीसाइड।
रसायन एवं रसायन उत्पाद	24	372.13	3,504	446.40	173.63	10,560 टन कार्बोनेयेन, 12,500 टन आक्सो अल्कोहल, 7,000 टन मैलिक एन्हाइड्राइड, 7,200 टन मिथाइल ईथाइल कीटोन (कार्बनिक यौगिक), 1,800 टन बटा नेफथाल, 1,800 टन क्लोरनोबेंजिन, 1,500 टन ग्लाइक्सॉल, 1,300 टन एथिलएसिटेड, 200 टन मैथेन/ईथाइलएक्रीलेट, 550 टन ईथाइल हेक्सीएक्रीलेट, 1,500 टन सोडियम थियोसल्फेट, 900 टन रेड आक्साइड, 9,900 टन डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेड, 2,775 टन डेक्सट्रोज

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						इनीड्रेट, 1,650 टन मेल्ट्रोडेक्सट्रीन, 58 टन इंजक्टीबल सोडियम एन० पी०सिलीन, 8,350 टन रिफाइंड बेल्ड ल्यूबस्टाक, 250 टन फिनाइल ग्लीसीन क्लोराइड, 60 टन डेनेसाल्ट, 345 टन ट्रीमेथॉक्सीबेंजाडिहाइड, 70 टन एम्पीसीलिन ट्रीहाइड्राइज, 30 टन एमोक्सीलिन ट्रीहाइड्राइड, 30 टन सफेक्सीलिन, मोनोहाइड्राइड, 10 टन डिलेक्सीलीन सोडियम, 200 टन मैगनेटिक आक्साइड, 3,500 टन एल्फोलीफीन्स, 184 टन स्टार्च पाउडर, 1,28,750 टन ग्लूकोस सिरप, 6,600 टन फ्रक्टोज सिरप, 1,000 टन पाउडर पेंट, 441 टन टैबलेट और कैप्सूल के नरम और कठोर खोल, 22,400 टन पशु खाद्य, 6 लाख मिलियन क्यूबिक हीलियम गैस का वितरण ।
ऑटोमोबाइल टायर और ट्यूबें	3	14.80	573	26.83	7.38	दुपहियों और तिपहियों के 11.65 लाख टायर तथा 6.39 लाख ट्यूबें ।
कृत्रिम रेशे	4	507.33	1,863	256.38	169.17	34,500 टन पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न तथा 12,000 टन एक्रीलिक स्टेपल फाइबर यार्न ।
कृत्रिम रेसिन्स एवं प्लास्टिर उत्पाद	21	1,075.95	3,890	741.12	401.78	20000 टन पोलियोल्स, 13,250 टन प्रोपीलीन ग्लाईकोल, 1,000 टन पोली बुटेंस, 12,000 टन प्रोपीलीन आक्साइड, 2000 टन पोलीविनाइल अल्कोहल, 10,000 टन एथिलीन प्रोपीलीन कोपेलिमर्स तथा एथीलीन प्रोपीलीन, डायन टरपोलीमर्स, 6,000 टन ट्रिक्लोरो एथीलीन, 9,000 टन एक्रीलोनोट्राइट बुटाडाइन स्ट्रीन, 60,000 टन उच्च घनत्व पोलीथीलिन, 60,000 टन मोनोथीलीन ग्लाइकोल, 1,00,000 टन पोलीविनाइल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						क्लोराइड, 2,000 टन बी० ओ० पी०पी० फिल्में, 100 मिलियन डिस्पोजेबल सुइयां, 30 मिलियन डिस्पोजेबल सीरींज, 6,600 टन पी० वी० सी० रीजिड फिल्में/ शीटें, 760 टन थर्मोफार्म्ड कंटेनर तथा पी०वी०सी शीटें, 1.080 टन पी०वी०सी० दरवाजे/ खिड़कियां पल्ले, 3.96 लाख एच० एम०-एच० डी० पी० ई० (एल०-रिंग बरल), 1,120 टन एडेसिव टेपें, 750 टन फेरोलिक फोम, तथा 2,850 टन वाल कवरिंग मेटेरियल ।
सीमेंट	9	208.06	1,403	114.16	39.26	13.14 लाख टन पोर्टलैंड सीमेंट, 50,000 टन सफेद एवं रंगीन सीमेंट तथा 75,000 स्पन कास्ट कंक्रीट पोल ।
कांच व कांच उत्पाद	4	78.75	1,150	56.55	32.34	2.65 मिलियन मीटर शीट ग्लास, 32,700 टन हाई वेट ग्लास की बोतलें, 48,000 टन अम्बर ग्लास की बोतलें तथा 600 टन लेबोरेटरी कांच के उपकरण तथा बोरोसिलिकेट ग्लास की ट्यूबें ।
विविध अधातु खनिज उत्पाद	7	46.23	917	51.60	23.22	86 मिलियन सैंड लाइम ईंट, 4.01 मिलियन वर्ग फुट एग्लोमेरेटिड मारबल तथा ग्रेनाइट, स्लैबें एवं टाइलें, 4 लाख वर्ग मीटर दीवार और फर्श की टाइलें, 12, 000 टन चमक रहित (अनग्लेज्ड) टाइलें, 9,000 टन सिन्थेटिक मारबल, 24,000 वर्ग मीटर ग्रेनाइट स्तम्भ एवं स्लैबें, 1,000 टन बोंडिड अब्रेसिव तथा 6,000 टन खनिज वूल ।
लोहा एवं इस्पात	10	365.06	2,570	471.87	141.09	92,500 टन कोल्ड रॉल्ड स्टील क्वाइल/ स्ट्रीप्स, 61,250 टन कार्बन एवं एलॉय सीमलेस ट्यूबें, 64,000 टन प्री/कोटेड कोल्ड रॉल्ड जस्तीकृत शीटें 25,000 टन जस्तीकृत शीटें, 1600 टन स्टैनलेस स्टील कंडेन-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						सर ट्यूबें, 3,750 टन हाई स्पीड स्टील, 90,000 टन स्टील बिल्लट्स तथा 2.2 लाख टन डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन ।
मशीनरी एवं उपांग	10	154.46	2,827	226.92	94.18	1.05 लाख पोर्टेबल पावर टूल्स, 12,000 इंडस्ट्रियल ग्रेड सोकेट्स, 1,780 हाई प्रीसीजन स्पिंडल्स ग्राइंडिंग एवं टूल कटिंग के लिए, सिंगल एवं ट्वीन स्क्रू एक्सट्रूड के लिए 280 बैरल 1,875 डीजल इंजिन तथा 25 वेब आफसेट प्रिंटिंग मशीनें, 89 रंगीन आफसेट प्रिंटिंग मशीनें, 2 लाख माइक्रो प्रोफोसेसर आधारित वाशिंग मशीनें, 7,000 लाउंड्री सिस्टम्स, 15,000 वाशिंग सिस्टम्स, 10,000 डिस्पेंसिंग सिस्टम्स, 120 एयर एवं गैस-कम्प्रैशर्स, 90 सेंटीफ्यूज्स, 30 लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट, 25 इंडस्ट्रियल-रेफ्रीजरेटर्स, 300 मिक्सिंग प्रोसेस उपस्कर 15 फ्लूइड- बेड ड्रायर्स ।
बिजली मशीनरी एवं उपकरण	6	49.12	917	132.94	28.07	25,000 मोल्डिड केस सरकट ब्रेकर्स, 1,100 बुशलेस अल्टरनेटर्स 6 लाख हीट श्रिंक/स्लीव्स टाइप केबल ज्वाइंटिंग किट्स, पोलीएथीलीन जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, 6.25 लांख कंडक्टर्स किलोमीटर्स 500 पावर सिस्टम्स 10 चार्ज रेक्टीफायर्स 200 सालिड स्टेटलाइन वोल्टेज रेगुलेटर्स, 1,000 स्विच मोड रेक्टीफायर्स ।
इलैक्ट्रानिक उपस्कर	17	196.67	4,308	442.49	154.57	2.0 मिलियन श्वेत व श्याम पिक्चर ट्यूबें 112.5 मिलियन रेक्टीफाइड डायड 1.5 मिलियन श्वेत व श्याम तथा 3.7 लाख रंगीन टेलीविजन सेट 140 लाख इलैक्ट्रानिक कनेक्टर्स 4,100 मिलियन रनिंग मीटर्स वीडियो एवं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						आडियों टेपें, 10 लाख आडियो टेप डेक मैकेनिज्म, ट्रांसफार्मर्स के 6 लाख टर्नर्स 25 लाख अन्य इलैक्ट्रानिक कम्पोनेटस 3,000 प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स 72 मिलियन अल्युमीनियम इलैक्ट्रोलेटिक कैपेसिटर्स 23,400 वर्ग मीटर प्रिंटिड सरकट बोर्ड, 650 टन प्रोफेसनल/कंज्यूमर ग्रेड सोफ्ट फैरिट्स 15,000 लाइनों वाले एनालॉग सब्स-सक्राइबर तथा डिजिटल सब्स-क्राइबर कैरियर सिस्टम्स तथा 23 कम्प्यूटर मेन फ्रेम्स ।
परिवहन उपस्कर	3	8.31	137	18.25	6.00	दुपहियों और चार पहियों के 2.75 लाख स्विच तथा ताले 300 डीलक्स बस के ढांचे 10,0,000 फैन ब्लोयर मोटर्स 34,000 वेंटीलेटर मोटर्स 17,300 मेगनेटिक सी०डी० आई० तथा मेगनेटिक क्वायल्स ।
धातु उत्पाद	9	58.73	1,467	188.13	36.89	2.10 लाख प्रैशर कुकर, 1.05 लाख प्रेशर पैन 2.00 लाख वैक्यूम फ्लास्क, 250 टन निकिल तथा कोबाल्ट बेस्ड कास्ट अलॉय रॉडस; 65,000 टन प्लेन तथा कोरूगेटिड जस्तीकृत शीटें, 1,500 टन पोलीले-मिनेटिड अल्युमिनियम फॉयल टेपें, 54,000 हाई प्रैशर सीमलैस सिलिन्डर्स, 2,400 टन इंडस्ट्रियल फास्टनर्स तथा 11,250 टन अल्युमीनियम एक्सट्रूडिड प्रोडक्टस ।
लकड़ी उत्पाद	4	61.03	604	41.41	22.23	26,390 टन मीडियम डेंसिटी पार्टिकल बोर्ड तथा 30,000 टन सीमेंट बांडिड पार्टिकल बोर्ड ।
होटल	10	121.15	21,331	65.22	46.45	1,289 कमरें
हास्पीटल	6	133.05	3,096	83.46	51.32	1,732 बिस्तर
बिजली एवं गैस	6	416.82	504	204.62	127.79	289 मेगावाट विद्युत का उत्-पादन तथा 595 लाख प्राकृतिक गैस एन० एम० 3 का संवितरण ।
अन्य	14	58.87	1,388	141.62	45.23	
जोड़	214	6,412.34	51,442	5,348.40	2,491.30	

लेखे 1988-89 (जुलाई-मार्च)
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट
सेवा में
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हमने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 31 मार्च, 1989 तक के संलग्न तुलन-पत्र और जुलाई, 1988 से 31 मार्च, 1989 की अवधि के निगम के लेखों का लेखा-परीक्षण किया है, और शेयरधारियों के निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं ।

2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं ।

3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां पूर्ण और स्पष्ट हैं, इनमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है, तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है, और इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है ।

गुप्ता एण्ड कम्पनी — टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 1989

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988 को लाख रुपये
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	14,092.53	19,337.83
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश	2	11,175.28	9,653.38
अन्य संस्थानों में निवेश	--	2,010.02	650.00
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण	3	3,37,253.47	2,73,320.77
स्थिर परिसम्पत्तियां	4	4,809.80	3,902.88
अन्य परिसम्पत्तियां	5	26,151.87	18,242.42
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता	--	3,250.64	2,292.01
जोड़		3,98,743.61	3,27,399.29
देयताएं और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	8,250.00	7,000.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	27,094.32	22,561.85
दीर्घकालीन ऋण	8	3,37,115.35	2,76,568.24
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	9	21,688.10	17,987.54
स्वीकृतियों पर देयताएं	--- --	3,250.64	2,292.01
निर्दिष्ट निधियां	10	1,345.20	989.65
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां	17	--	--
जोड़		3,98,743.61	3,27,399.29

हरिश्चंद्र शर्मा, महाप्रबन्धक — एस० के० ऋषि, कार्यपालक निदेशक — डी०एन० डावर, अध्यक्ष — ए०वी० गणेशन, एम०सी० सत्यवादी, निदेशक — एस०एच० खान, वी०आर० पंचमुखी, निदेशक — एस०एस० कदम, डी०एम० पटेल, निदेशक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
गुप्ता एण्ड कम्पनी — टी०आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

नई दिल्ली : 19 मई, 1989

1 जुलाई, 1988 से 31 मार्च, 1989 की अवधि के लिए लाभ हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये	30 जून 1988 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर)	11	27,777.34	28,529.67
ऋणों की लागत	12	2,361.84	21,209.70
निवल ब्याज राजस्व		6,415.50	7,319.97
अन्य परिचालनों से आय	13	1,125.58	936.38
जोड़		7,541.08	8,256.35
कार्मिक व्यय	14	501.85	612.23
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस, आदि	--	2.09	3.30
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास	15	762.65	533.49
अन्य व्यय	16	213.95	214.26
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान	--	5.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था	--	1,002.19	1,621.85
जोड़		2,487.73	2,990.13
समायोजन :			
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि		2,753.54	1,792.52
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि		1,429.11	2,500.83
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि		100.00	200.00
कर्मचारी कल्याण निधि		50.00	25.00
लाभांश		720.70	747.87
		5,053.35	5,266.22
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां	17		

हरिश्चंद शर्मा महाप्रबन्धक — एस० के० ऋषि कार्यपालक निदेशक — डी०एन० डावर अध्यक्ष — ए० वी० गणेशन, एस०एच० खान, एम०एन० कल्म, एस०सी० सत्यवादी, वी०आर० पंचमुखी, डी०एम० पटेल निदेशक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

गुप्ता एण्ड कम्पनी — टी०आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

नई दिल्ली : 19 मई, 1989

8—309GI/89

अनुसूची 1

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988 को लाख रुपये
रोकड़ और बैंक शेष		
हाथ में नकदी	1.12	1.14
हाथ में चैक/ड्राफ्ट एवं वसूली हेतु प्रस्तुत	460.69	1,142.31
भारत में बैंकों में शेष		
चालू खातों में (टिप्पणी सं० 7 देखें)	11,255.93	7,992.65
अल्पावधि जमा में	1,453.25	9,848.00
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
चालू खातों में	722.43	283.70
अल्पावधि जमा में	199.11	70.03
जोड़	14,092.53	19,337.83

अनुसूची 2

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश (लागत पर)

विवरण	धारा के अन्तर्गत*			31 मार्च 1989 को	30 जून, 1988 को
	23(घ)	23(ज)	23(झ)	लाख रुपये	लाख रुपये
1	2	3	4	5	6
(i) इक्विटी शेयर	5,184.13	2,691.90	1,985.89	9,861.92	8,807.15
(ii) अधिमान शेयर	305.30	91.00	0.01	396.31	384.76
(iii) डिबेन्चर	32.92	439.30	218.67	690.89	425.68
(iv) शेयरों और डिबेन्चरों पर आवेदन राशि	94.37	131.79	—	226.16	35.79
31 मार्च, 1989 का जोड़	5,616.72	3,353.99	2,204.57	11,175.28	9,653.38
30 जून, 1988 का जोड़	5,226.11	2,410.38	2,016.89	9,653.38	

कथित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-- बही मूल्य				5,818.13	5,069.05
-- बाजार मूल्य				16,298.83	10,288.39
निवेश जिनके लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं					
-- बही मूल्य				5,130.99	4,548.54
-- विश्लेषित मूल्य				3,104.83	3,328.64

*औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से सम्बंधित है।

अनुसूची 3

31 मार्च 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था को घटाकर)

विवरण	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988 को लाख रुपये
(i) भारतीय रुपयों में	2,75,576.76	2,25,840.72
(ii) विदेशी मुद्राओं में	61,676.71	47,480.05
जोड़	3,37,253.47	2,73,320.77

टिप्पणियां :

(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध है।	शून्य	शून्य
(ii) वर्ष के दौरान संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से सितबद्ध है।	शून्य	शून्य
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज किस्तों की कुल अतिदेय राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य

अनुसूची 4

31 मार्च 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

स्थिर परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च 1989 को		निवल मूल्य	
	मूल लागत लाख रुपये	संचित मूल्यह्रास लाख रुपये	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988 को लाख रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भवन				
--जब्ती होल्ड भूमि तथा भवन	775.18	141.07	634.11	562.85
--पट्टे पर भूमि तथा भवन	810.73	143.20	667.53	388.30
उपस्कर				
--फर्नीचर तथा फिटिंग	129.22	51.11	78.11	58.20
-- कार्यालय उपस्कर	282.01	157.64	124.37	68.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
--बिजली के संस्थापन	26.32	20.06	6.26	5.00
--वाहन	18.29	12.48	5.81	7.17
पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां--संयंत्र एवं मशीनरी	2,268.77	640.99	1,627.78	1,310.98
उपजोड़	4,310.52	1,166.55	3,143.97	2,401.11
पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम	1,665.83	--	1,665.83	1,501.77
जोड़	5,976.35	1,166.55	4,809.80	3,902.88
30 जून 1988 को	4,476.92	574.04		

अनुसूची 5

31 मार्च 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988 को लाख रुपये
प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	5,264.52	6,746.83
उपस्कर लीजिंग योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	4,409.33	--
उपस्कर उपार्जन योजना के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	61.66	--
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम	660.60	587.69
कर्मचारियों को अग्रिम	212.58	179.63
जमा राशियां	59.86	100.65
विनिमय अन्तर उचन्त खाता	3,814.47	2,465.0
कर्मचारी कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां	14.00	14.00
भुगतान किया गया अग्रिम कर	6,612.06	4,943.44
अन्य परिसम्पत्तियां	5,042.79	3,204.28
जोड़	26,151.87	18,242.42

अनुसूची 6

31 मार्च 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988के को लाख रूपय
(1)	(2)	(3)
अधिकृत		
प्रत्येक पांच हजार रुपये के 2,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 2,00,000)	10,000.00	10,000.00
जारी और अभिदत्त		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1,75,0 शेयर (पिछले वर्ष 1 50,000)	8,750.00	7,500.00

(1)	(2)	(3)
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)		
प्रदत्त		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रयेत्क पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवीं सीरीज)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आंठवीं सीरीज)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज)	500.00	500.00
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (बारहवीं सीरीज)	1,250.00	1;250.00
(xiii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (तेरहवीं सीरीज)	1,250.00	750.00 (आंशिक रूप से प्रदत्त)
(xiv) प्रत्येक पांच-पांच हजार रूपये के 25,000 शेयर (चौदहवीं सीरीज) (रुपये 3,000 प्रतिशेयर राशि मांगी गई और प्रदत्त)	750.00	--
	8,250.00	7,000.00

अनुसूची 7

31 मार्च 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि . .	10,622.31	7,868.77
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि . . .	232.20	292.93
आयकर धिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) अधीन विशेष आरक्षित निधि	15,429.11	14,000.00
क्रदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	710.70	300.15
जोड़	27,094.32	22,561.85

अनुसूची 8
दीर्घकालीन ऋण

31 मार्च 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च 1989 को लाख रुपये	30 जून 1988 को लाख रुपये
बांड (अप्रतिभूत—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त)		
(a) 6¼% बांड	--	3 501.54
(b) 6½% बांड	7 500.00	7 500.00
(c) 6¾% बांड	7 810.00	7 810.00
(d) 7¼% बांड	10 050.22	10,050.22
(e) 7½% बांड	10,995.00	10,995.00
(f) 8¼% बांड	7,975.00	7,975.00
(g) 8¾% बांड	8,004.80	8,004.80
(h) 9% बांड	19,701.00	19,701.00
(i) 9.75% बांड	32,269.13	32,269.13
(j) 11% बांड	69,548.00	69,548.00
(k) 11.5% बांड	39,802.00	15,000.00
(l) 7.6% बांड (येन मुद्रा)	5,938.24	5,341.88
(m) 6.9% बांड (येन मुद्रा)	5,938.24	5,341.88
(n) 6.3% बांड येन मुद्रा)	5,938.24	5,341.88
	2,31,469.87	2,08,380.33
उधार		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	5,765.00	6,185.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारत सरकार से	95.68	140.04
(ग) ऋदितास्तल्त-फर-याइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	924.66	747.67
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गये विदेशी बांडों में से विदेशी मुद्रा में	1,247.66	1,159.87
(ङ) विदेशी ऋण संस्थानों से विदेशी मुद्राओं— में (रु० शून्य के अल्पावधि पूरक ऋण सहित) पिछले वर्ष 14,194. 46 लाख रुपये)	97,612.48	59,955.33
जोड़	3,37 ,115.35	2,76,568.24

अनुसूची 9
चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये	30 जून, 1988 को लाख रुपये
(1)	(2)	(3)
(क) चालू देयताएं		
फुटकर लेनदार	4,168.21	5,884.81
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) बांडों पर	6,177.21	1,802.85
(ख) सरकार से उधार	4.38	17.75

(1)	(2)	(3)
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार	1,788.75	764.06
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार	457.47	262.36
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि	500.00	500.00
अग्रिम पावतियां	38.30	24.58
दावा न किया गया लाभांश	0.49	0.39
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि/भारत सरकार को देय राशि	1,287.94	1,154.28
(ख) व्यवस्थायें		
उपबंध में डाली गई राशियां		
(क) ब्याज	295.00	305.79
(ख) वचनबद्धता प्रभार	0.05	0.05
(ग) प्रासंगिक प्रभार	23.38	2.38
करोधान के लिए व्यवस्था	6,247.22	6,520.37
लाभांश के लिए व्यवस्था	720.70	747.87
जोड़ (ख)	7,265.35	7,576.46
जोड़ (क)+(ख)	21,688.10	17,987.54

अनुसूची 10

विशेष कार्य के लिए निर्धारित निधि

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च, 1989 को लाख रुपये	30 जून, 1988 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	1,028.71	904.48
विशेष जूट विकास निधि	180.10	--
कर्मचारी कल्याण निधि	136.39	85.17
जोड़	1,345.20	989.65

अनुसूची 11

ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों सहित ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये	30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय (पिछली अवधि के 0.81 लाख रुपये सहित)	25,158.98	26,830.25
अल्पावधि जमा आदि पर ब्याज	1,838.70	1,250.40
वचनबद्धता प्रभार	460.81	429.84
पट्टा किराया	318.05	19.18
स्थायी खर्चे	0.80	--
जोड़	27,777.34	28,529.67

अनुसूची 12

ऋणों की लागत

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये	30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
बांडों और उधारों पर ब्याज	21,055.97	20,943.87
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	15.70	3.76
बांड जारी करने की लागत (पिछली अवधि के 2.52 लाख रुपये उधार को निकाल कर निवल)	290.17	262.07
जोड़:	21,361.84	21,209.70

अनुसूची 13

अन्य स्रोतों से आय

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये	30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क	180.46	192.46
लाभांश	280.97	289.23
निवेशों की बिक्री से लाभ	605.60	333.26
अन्य विविध आय	58.55	121.43
जोड़:	1,125.58	936.38

अनुसूची 14

कार्मिक व्यय

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये	30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते	468.83	572.45
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	2.38	4.08
अन्य कार्मिक व्यय	30.64	35.70
जोड़:	501.85	612.23

अनुसूची 15

किराया, रखरखाव तथा मूल्य ह्रास

31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	31 मार्च 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये	30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
	2	3
किराया, कर, बीमा और रोशनी (पिछली अवधि के 1.94 लाख रुपये सहित)	153.69	193.65

(1)	(2)	(3)
मरम्मत एवं रखरखाव (पिछली अवधि के 1.40 लाख रुपये सहित)	27.99	39.83
मूल्यह्रास (पिछली अवधि के 5.07 लाख रुपये सहित)	581.07	300.01
जोड़	762.65	533.49

अनुसूची 16

31 मार्च, 1988 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 1989 को समाप्त अवधि लाख रुपये	30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क	1.25	1.25
यात्रा व विराम व्यय	25.99	33.30
संचार व्यय	44.90	44.37
मुद्रण, लेखन-सामग्री और विज्ञापन	41.67	46.94
निवेशों पर हानि	30.69	2.22
अन्य व्यय (प्रधान मंत्री राहत कोष में अंशदान सहित—रु० शून्य) (पिछले वर्ष 25 लाख रुपये)	69.45	86.18
जोड़	213.95	214.26

अनुसूची 17
31 मार्च, 1989 के तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां (लेखों का भाग)

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. राजस्व मान्यता

(क) जिन मामलों में ब्याज, वचनबद्धता प्रभार एवं कमीशन, आदि की वसूली संदिग्ध समझी जाती है उनमें निगम इन्हें आय के रूप में गणन नहीं करता। ऋण करारों का निष्कर्ष होने के पश्चात् ही वचनबद्धता प्रभारों को आय के रूप में गणन किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में निगम न्यायालय आदेश प्राप्त किए हैं उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज का गणन इस के प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

2. निवेश

2.1 मूल्यांकन :
निवेशों का सकल बाजार मूल्य/विभाज्य मूल्य के संदर्भ में बही-मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

2.2 लेन-देन :

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप बेचे गए निवेशों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

(ख) परिसमापन अथवा रुग्ण कम्पनियों के शेयर के मूल्य में, यदि कोई हानि हो, जिनका विलीनीकरण अन्य स्वस्थ कम्पनियों के साथ किया जाना है, उनका गणन विलीनीकरण पूरा होने पर अन्तिम अदायगी प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) निम्नलिखित के शेष—

(i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण,
(ii) उनमें से ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण
(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष, और
(iv) विदेशी मुद्रा में दी गई गारन्टियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक देयताओं

की अभिव्यक्ति तुलन-पत्र की तिथि को तार अन्तरण विक्रय दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में की जाती है।

(ख) विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुआ लाभ, यदि कोई हो, प्रत्येक ऋण के संबंध में तभी गणन किया जाता है जब निवेशी साख संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर

दी गई हो और उन ऋणों में से वित्तपोषित संस्थाओं को दिए गए ऋण पूर्ण रुप से वसूल कर दिए गए हों। इस प्रकार के उतार–चढ़ाव से हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है जब उस ऋण का भुगतान कर दिया गया हो। इस दौरान :

(i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान
(ii) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन और
(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उचित खाते में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से अन्तिम रुप में प्राप्त अंशदान विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भी उक्त खाते में जमा किया जाता।

4. स्थिर परिसंपत्तियां

(क) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का परिसंपतियों के पट्टे की मूल अवधि पर या इन परिसपतियों से संबंधित आय कर मुल्य ह्रास दरों के संबध में निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर जो भी कम हो, सरल विधि से मुल्य ह्रास किया जाता है।

(ख) अन्य परिसपत्तियों का मूल्य ह्रास आयकर अधिनियम, 1961 और इसके अधीन बनाए गए नियमों पद्धति द्वारा किया जाता है।

(ग) परिसपत्तियों का उल्लेख लागत में से मुल्य ह्रास घटा कर किया गया है।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन–पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रासंगिक रुप से उत्तरदायी है:

(क) बकाया हामीदारी संविदा (औद्योगिकी वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23 (घ) के अधीन) 305,00 लाख रुपए (739.00 लाख रुपए),

(ख) विवेश के रुप में औशत प्रदत्त शेयरों के लिए अयाचित राशि (औद्योगिकी वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 20, धारा 23 (घ) तथा धारा 23 (च) के अधीन 216,32 लाख रुपए (13.73 लाख रुपए) और

(ग) लगभग, 975.83 लाख रुपए (1,117.50 लाख रुपए) (प्रदत्त निवल अग्रिम) के पूंजी लेखे पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित की जानी है।

2. निगम के पक्ष में/विरुद्ध कुछ मामलों के संबंध में आयकर विभाग/निगम ने अपील/संदर्भ किया है। इस संबध में विवादास्पद देयता 55.39 लाख रुपए (55.39 लाख रुपये) है। जिसके लिए लेखों में पर्याप्त प्रावधान है।

3. फुटकर लेनदारों में 1,365.61 लाख रुपए (2,505.56 लाख रुपए) की राशि उन बांडो से संबधित है जो परिपक्व हो गए हैं किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं दिए गए हैं।

4. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 23 (घ) और 13 (च) के अधीन निवेशों में 127.27 लाख रुपए की राशि (131.69 लाख रुपए) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पुंजी में निवेश की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा 'रुग्ण' हैं और उनका स्वस्थ कंपनियों के साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है।

5. हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 41 मार्च, 1989 तक 56.55 लाख रुपए (50.36 लाख रुपए) का आंशिका उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रुप में कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पुंजी में अभिदान कर के किया गया है। अत: इस राशि का निगम के 'निवेशों' में गणन नहीं किया गया है।

6. तुलन–पत्र की तारीख की कुछ कंपनियों से 1,626.78 लाख रुपए (1,849.65 लाख रु०) की राशि बकाया थी जिनको कि केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। अभी यह तथा नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारंटी कर्ताओं से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा। इसके लिए अतिरिक्त तुलन–पत्र की तारीख को 35.11 लाख रुपए (35.11 लाख रू० की राशि कुछ कंपनियों पर बकाया है जिनकी देयताए उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई।

7. भारत के बैंकों के चालु खातों में (क) निगम की सहमति से केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में/भारतीय यूनिट ट्रस्ट की युनिटों में बैंकरों द्वारा निवेश किए गए लगभग 6,800.00 लाख रुपए (7,900.00 लाख रुपए) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत बिलों के रुप में 2,100.00 लाख रुपए (शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

8. निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कुछ परिसरों के संबंध में हस्तान्तरण की औपचारिकताएं पूरी किए जानी की प्रक्रिया जारी है ।

9. वर्ष के लिए 1,002.19 लाख रुपए के कराधान का प्रावधान, आयकर अनिधिनिम 1961 की धारा 32 कख के अधीन कटौती की पात्रता को ध्यान में रखते हुए तथा पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में 291.18 लाख रुपए, के प्रावधान, जिसकी अब आवश्यकता नहीं है को ध्यान में रखकर किया गया है । आयकर अधिनियम, 1961 यथा संशोधित, के अनुसार 1989–90 के निर्धारिण वर्ष के संदर्भ में निगम का पिछला वर्ष 1 जुलाई 1987 से 31 मार्च 1989 की अवधि से संबंधित है ।

10. आयकर अधिनिमय, 1961 में संशोधन के तदुपरान्त निगम का लेखांकन वर्ष 30 जून से 31 मार्च हो गया है । तदनुसार, ये लेखे 1 जुलाई, 1988 से 31 मार्च 1989 तक की अवधि के लिए हैं, और इसलिए ये आँकडे पिछले वर्ष के आकडों से तुलनीय नहीं हैं । पिछले वर्ष के आंकडों को, जहा कहीं आवश्यक हो, पुन: व्यवस्थित किया है ।

RESERVE BANK OF INDIA

Calcutta-700001, the 11th October 1989

Particulars of corrections necessary in the Notification No. 56 dated 28th March 1989 as it appeared in the Gazette of India, Part III—Section 4, dated 15th July 1989.

Paragraph No.	Page No. of the Gazette	Particulars as appearing in the copy of our Notification sent for Publication	Particulars as published in the Gazette	Nature of corrections necessary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(iii)	666	For clause (iv), the following clause shall be substituted,	For clause (iv), the following clause shall be rubstituted.	Rubstituted should be changed to substituted
3(iii)(b)	666	namely— Provided that the deposits accepted by a housing finance....	Proided that the deposits accepted by a housing....	Proided should be changed to provided
3(iv)(b)	667	Unless such deposit is repayable after a period of more than twenty-four months but not later than sixty months....	Unless such deposit is repayable after a period of more than twenty-four months out not later than sixty months.	Out should be changed to but
Do.	Do.	Provided that the deposits accepted by an equipment leasing company or a hire purchase finance company. before the 1st April, 1989....	Provided that the deposits accepted by an equipment leasing company or a hire purchase finance company. befoe the 1st April 1989,....	befoe to be changed to before.
Do. (iii)a	Do.	on and from 1st April 1989, no housing finance company shall have deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, which are referred to in clauses (ii),....	on and from 1st April 1989, no housing flnance shall have deposits the aggregate amount of which together with the amounts, if any, which are reforred to in clause (ii),....	clause to be changed clauses.
Do.	Do.	Provided that the refinance obtained by a housing finance company from the National Housing Bank shall be excluded for the purposes.	Provided that the refinance obtained by a housing finance company from the National Housing Bank shall be excluded for the purpose.	Purpose to be changed to purposes.
4(b)(i)	667	where a deposit is for a period not exceeding one year : one per cent (not per annum) of such deposits	where a deposit is for a period not exceeding one year one per cent (not per annum) of such deposit	: mark should appear between two columns
4(b)(ii)	Do.	where a deposit is for a period exceeding one year but not exceeding two years. : one and a half per cent (not per annum) of such deposits	where a deposit is for a period excluding one year but not exceeding two years one and a half per cent (not per annum) of such deposit	Do.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(b)(iii)	667	Where a deposit is for a period exceeding two years :	Two per cent (not per annum) of such deposits"	Where a deposit is for a period exceeding two years : mark should appear between two columns "(inverted comma) should appear after the words such deposits	Two per cent (not per annum) of such deposits
5	Do.	General provisions regarding repayment of deposits.	General Provision regarding repayment of deposits.	Provision should be changed to Provisions
5(ii)	Do.	Where an equipment leasing company.. ..after a period of more than twenty-four months,	where an equipment leasing company....after a period of more than twenty-four months.	,(comma) should appear after the word months.

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 14th August 1989

SBD. No. 6/1989.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Central Government and Reserve Bank of India, nominated the undernoted persons :—

(1) Shri Ajit Singh Vishnar, 164/1, Shrinagar Colony, Indore-452 002 (M.P.) and

(2) Shri T. S. Anklesaria, "Gulistan", Dr. Rajendra Prasad Marg. Ratlam-457 001 (M.P.)

as directers on the Board of Directors of the State Bank of Indore for a period of three years each with effect from 22nd August 1989 to 21st August 1992 (both days inclusive) in place of Sarvashri Vijay Singh and S. K. Khandelwal respectively.

By Orders of the Executive Committee of the Central Board

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Managing Director
(Associate Banks)

NEW BANK OF INDIA

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

New Delhi, the 3rd July 1989

1. Notification No. 5007 : In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfers of Undertakings) Act 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of New Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of Central Government hereby makes the following regulations further to amend New Bank of India Officers' Service Regulations 1982.

2. Short Title & Commencement : (i) These regulations may be called New Bank of India Officers' Service Regulations, 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

3. The existing Regulation 23 (i) of New Bank of India Officers' Service Regulations, 1982 shall be substituted by following :

"(i) On and from 20-8-88, if he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place :

Places	Rates
a. Places in Area I and in the State of Goa.	10% of basic pay subject to a maximum of Rs. 200/- p.m.
b. Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above	6% of basic pay subject to a maximum of Rs. 120/- p.m.

A.R. LAMBA
Asstt. Gen. Manager (Pers.

DENA BANK

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Bombay-400 005, the 13th September 1989

No. HQ-PER-IR.5456/89.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of directors of DENA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the DENA BANK (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the DENA BANK (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. *REGULATION* 23(i) *AS AMENDED* :

On and from 20-8-1988, if he is serving in a place mentioned in the Column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in the Column 2 thereof against that place :

Places	Rates
(a) Places in Area I and in the State of Goa.	10% of Basic Pay subject to a maximum of Rs. 200/- per month.
(b) Places with population of 5lacs and over and States Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	6% of Basic Pay subject to a maximum of Rs. 120/- per month

R. N. BUCH
Asstt. General Manager (P)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400 005, the 29th August 1989

No. 3WCA(5)/11/89.90.—With reference to the Institute's Notification No. 3WCA(4)/9/88-89 dated 1-2-1989, 3WCA (4)/11/87-88 dated 5-1-1988. it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations. the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	06158	Shri Prataprai Jivalal Goradia, FCA, C/o Sunrise Agencies, 114, Bank of Baroda Building, (Now Development Co-op. Bank Bldg.) 4th Floor, Palton Road, Bombay-400 001.	12-6-89
2.	30618	Shri Baburao Vasudeo Neel, ACA, 9/A, Shivsmark Gold Finch, Solapur-413 007.	11-7-89

No. 3WCA(5)/12/89-90.—With reference to the Institute's Notification No. 3WCA(4)/10/88-89 dated 15-2-1989, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	30143	Shri Pravinchandra Amidas Mehta, FCA, C/o. Golwalla Classes Pvt. Ltd., 2nd Floor, Bombay Mutual Building, 293, D.N. Road, Fort, Bombay-400 001.	21-6-89
2.	30693	Shri Kiran Jamnadas Shah, ACA 1, Suraj-Saraswati Road, Santacruz (W), Bombay-400 054.	3-8-89

M.C. NARASIMHAN
Secretary

Calcutta-700 071, the 21st September 1989

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/4/4/89-90.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(i)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names :

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	3624	Shri Bal Krishna Shroff, M/s. B.K. Shroff & Co., 23A, Nataji Subhas Road, Calcutta-700 001.	13-7-89
2.	2243	Shri Amal Chandra Chakravarty, Temple Chambers, 6, Old Post Office Street, Calcutta-700 001.	5-7-89
3.	4648	Shri Jugal Kishore Loyalka, M/s. J. Loyalka & Co., 16, Mangoe Lane, Calcutta-700 001.	2-8-89
4.	4830	Shri Amarchand Bhuteria, M/s. A.C. Bhuteria & Co., 2, India Exchange Place, Calcutta-700 001.	9-7-89
5.	5144	Shri Somnath Basu, 21/7, Aswini Dutta Road Calcutta-700 029.	19-2-89
6.	5446	Shri Mohan Lal Singhi, M/s. Singhi & Co., 1B, Old Post Office Street, Calcutta-700 001.	18-8-89
7.	14981	Shri Samir Kumar Rudra, 6B, Shanker Ghosh Lane, Calcutta-700 006.	1-8-89
8.	52058	Shri Samir Kr. Mukhopadhyay, Flat No. 48/8, Block BC, Sector-I, Salt Lake, Calcutta-700 064.	24-9-88

M.C.NARASIMHAN
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 12th October 1989

No. N-15/13/20/1/85 P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-10-89 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the *"Jammu and Kashmir"* Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1988 shall

be extended to the families of insured persons in the following area in the State of *Jammu and Kashmir* namely :—

I. **KASHMIR DIVISION**

Sl. No.	Area	HAD BAST NO.
1	2	3
1	Municipal limits of Srinagar City	—
2.	Municipal limits of Srinagar Cantt.	—
3.	Village Khanmoh	246
4.	Rangreth in Budgam District	284
5.	Pampor	105
6.	Wuyan	98
7.	Lethpora	92
8.	Khrew	15
9.	Badgam	63

II. **JAMMU DIVISIONS**

(1) **JAMMU**

1.	Municipal limits of Jammu City	—
2.	Cantonment limits of Jammu Cantt.	—
3.	Village Miten Sahib (Ban Sultan)	37
4.	Muthi	190
5.	Gangyal	155

1	2	3
	(2) **BARI-BRAHMANA**	
1.	Berpur	208
2.	Main Sarkar	206
3.	Main Cherkan	205
4.	Besi Khurd	220
5.	Samailpur	201
6.	Kartholi	203
7.	Bishnah	230
	(3) **KATHUA**	
1.	Chak Raju	79
2.	Chak Ram Singh	70
3.	Jagat Pur	62
4.	Chak Khuni	69

S. GHOSH
Director (P&D)

MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS

Bangalore, the 29th September 1989

Ref. C. No. VIII/17/202/89 Cus. Legal—In pursuance of rule 3(1) of the Customs (Publication of Names) Rules, 1975, I, hereby publish the name and particulars of the person convicted under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) as specified below :

Name and Address of the person convicted.	Nature of Offence	Name of the Court awarding the sentence.	Criminal Case No.	Date of conviction	Particulars of punishment awarded.
1	2	3	4	5	6
K. Valasalan, S/o K. Kunchappa, 'SHREEKALA' Ambilad, Kuthuparamba Post, Tellicherry Taluk, Cannanore District, Kerala State.	Concerned in possessing, carrying, concealing, purchasing or in any other manner dealing with the two gold pellets of foreign origin valued at Rs. 46,000/- which he knew or had reason to believe were liable to confiscation under section 111(d) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).	III Additional Chief Judicial Magistrate, Belgaum.	C.C. No. 1474/88	7-2-89	Convicted of the offences punishable under section 135(1)(b)(ii) of Customs Act, 1962 and sentenced to pay a fine of Rs. 1,750/- and in default to undergo simple imprisonment for 20 days.

J.P. KAUSHIK
Collector of Customs

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
41ST ANNUAL REPORT 1988-89

(JULY—MARCH)

Report of the Board of Directors

Under Section 35 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948

CHAPTER 1

OPERATIONAL ENVIRONMENT AND OUTLOOK

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 41st Annual Report on the operations of IFCI together with the audited Statement of Accounts for the nine months' period ended the 31st March, 1989.

1.02 Arising out of the decision of the Government of India to have a uniform financial year, the Public Financial Institutions decided to change the financial year from July-June to April-March basis. In the case of IFCI, a Notification No. F.2(37)IF.1/88 dated the 26th December, 1988 was issued by the Government of India making amendment in the Industrial Finance Corporation Rules, 1965, and permitting the accounting year of IFCI to be changed from July-June to April-March. As such, IFCI closed its accounts on the 31st March, 1989 instead of the 30th June. The report presented hereunder is for nine months' period, i.e., from the 1st July, 1988 to the 31st March, 1989. The previous year's figures, wherever given, are for full 12-months financial year (July-June) and are not, therefore, strictly comparable.

1.03 As a backdrop to the operations, performance and working results of IFCI during the nine months' period ended the 31st March, 1989, it is considered appropriate to have an overview of the country's economy in the year 1988-89 (April-March), the prevailing investment climate, the industrial scenario and the future outlook.

(A) *Indian Economy*—1988-89

1.04 After the three successive years of unfavourable monsoons, the Indian Economy in 1988-89, thanks to good monsoon and pragmatic economic management, showed an impressive all-round recovery, and redemonstrated, that it continued to be on the path of growth.

1.05 According to the information available, the agricultural output in 1988-89 (April-March) is expected to grow by 18.9% as against the decline of 2.1% in 1987-88. The significant achievement in the agricultural sector in 1988-89 is the record foodgrains production of 170 million tonnes, registering a 22.8% growth. Aided by an excellent performance of the infrastructural sector, industrial growth in 1988-89 is also expected to be around 9% as against 7.4% in 1987-88. The sustained high growth in the industrial sector is a reflection of the favourable impact of the policy of liberalisation initiated by Government in the early eighties and given further momentum in the subsequent years. Further, the agricultural and industrial sectors seem to have reinforced each other through their network of input-output relationships.

1.06 The remarkable expansion in the supply of goods and services had a powerful influence in moderating the rate of inflation in 1988-89. The wholesale price index on a point to point basis as at end of March, 1989 showed only 6.1% increase compared to 10.5% on point to point basis in the previous year. The overall fiscal policy stance of Government supported by the Reserve Bank of India's policy of keeping growth in money supply commensurate with growth in real output were major contributory factors in keeping the excessive demand pressures under check, without jeopardising the credit needs for accommodating the robust economic growth in the economy.

1.07. On the foreign trade front, despite exports rising by 29%, the trade deficit is expected to be Rs. 7,412 crores as aginst last year's Rs 6,624 crores, because of increase in imports by 23.9%. The substantial rise in the imports in rupee terms is mainly attributable to larger/bulk imports, such as petroleum products, edible oils and foodgrains (largely to replenish food stocks) coupled with unusually high international prices for certain commodities, like, iron and steel, non-ferrous metals, metal scraps, rubber, paper, etc., and exchange rate variations.

1.08. Though the balance of payments position and foreign exchange reserves continued to be under severe pressure, the situation remained well under control in 1988.89. Policy measures taken for promoting inward remittances from non-resident Indians, increase in the interest rates on deposits under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts Scheme and floatation of special bond issues for Non-Resident Indians coupled with higher external assistance had a relieving influence on the balance of payments situation.

1.09. Despite stresses and strains on the external front, overall, the Indian economy on the domestic front emerged considerably strong, and according to a quick assessment, the growth rate in Gross Domestic Product (GDP) during 1988-89 (at 1980-81 prices) is expected to be 9% as against 3.6% in 1987-88 and 3.8% in 1986-87. Table 1 presents some selected indicators of Indian economy—actuals for 1987-88 and estimates for 1988-89 alongwith percentage change in 1988-89 over 1987-88.

(B) *Investment Climate and Capital Market*

1.10. With the upswing in the Stock Market, resurgence in economic growth, satisfactory corporate results, effective economic measures, continuation of policy reforms aimed at promoting efficient competition and the restoration of confidence among investors, the investment climate in the country remained during 1988-89 (April-March) quite buoyant. The foreign collaboration approvals in 1988-89 (April-November, 1988) recorded an increase of 15.1%, compared to the same period of 1987-88. So also, the Letters of Intent showed an increase of 11.3%. The Capital Goods Clearances registered an increase of 45.7%. Table 2 below gives data about selected indicators of industrial investment climate for the year 1987-88 and 1988-89.

Table 1 : Selected Indicators of Inbian Economy

Basic Economic Indicators	Units	1987-88 (April-March)	1988-89 (April-March)	Percentage variation in 1988-89 over 1987-88
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Population	Million	785.0	890.4	2.0
Gross National Product (GNP) (At 1980-81 prices)	Rs. Crores	₹1,68,919	₹1,84,122	9.0
Net National Product (NNP) (At 1980-81 prices)	Rs. Crores	₹1,50,573	₹1,64,125	9.0
GNP per capita (At 1980-81 prices)	Rs.	₹2,151	₹2,297	6.8
NNP per capita (At 1980-81 prices)	Rs.	₹1,918	₹2,048	6.8
Agricultural Production Index	1969-70—100	149.3	177.6	18.9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Foodgrains Production	Mill. tonnes	138.4	170.0	22.8
Fertiliser Production (NPK in terms of nutrients)	Mill. tonnes	7.13	8.96	25.7
Power Generation	Billion Kwh	201.9	220.8	9.4
Coal Production	Mill. tonnes	179.7	194.6	8.3
Oil Production (Crude)	Mill. tonnes	30.3	32.0	5.6
Cement Production	Mill. tonnes	39.5	44.0	11.3
Saleable Steel (Main Plants)	Mill. tonnes	8.59	9.21	7.2
Revenue Earning Goods Traffic on Railways	Mill. tonnes	290.2	302.1	4.1
Cargo handled at major ports	Mill. tonnes	133.8	149.9	12.0
Industrial Production (General Index)	1980-81=100	166.4	181.0	8.8
Exports	Rs. Crores	15,719	20,281	29.0
Imports	Rs. Crores	22,343	27,693	23.9
Trade Balance	Rs. Crores	(—)6,624	(—)7,412	11.9
Foreign Exchange Reserves (Excluding gold and SDRs)	Rs. Crores	7,287	6 605	(—)9.4
External Assistance (Disbursements at the close of year)	Rs. Crores	5,032	5,369	6.7
Debt Servicing	Rs. Crores	2,623	2,770	5.6
Money Supply (M_3)	Rs. Crores	1,61,503	1 88,474	16.7
Bank Credit	Rs. Crores	70,089	83,266	18.8
Aggregate Deposits of Commercial Banks	Rs. Crores	1,17,574	1,38,855	18.1
Wholesale Price Index (Average)	1970-71=100	405.4	435.0	7.3
Consumer Price Index for Industrial workers (Average)	1960—100	736	803	9.1
Rate of Inflation (Based on CPI-W) (on point to point basis)	(In percentage terms)	9.8	8.6	—

Table 2 : Selected Indicators of Industrial climate

Indicators	Units	1987-88 (April-March)	1988-89 (April-March)	Percentage variation in 1988-89 over 1987-88
Foreign Collaborations	Nos.	385*	443*	15.1
Foreign Investments approved	Rs. Crores	110	240	118.2
Letters of Intent issued	Nos.	647*	720*	11.3
Industrial Licences granted	Nos.	255*	201*	(—)21.2
DGTD Registrations	Nos.	715*	450*	(—)37.1
Approvals by SIA under the de-licensed industries	Nos.	1,062*	836*	(—)21.3
Capital Goods Clearances	Rs. Crores	800 680)@	991 (April-February)	45.7
Consents for Capital Issues (including Bonus issues)	Rs. Crores	4,689 (4,238)@	5,352 (April-February)	26.3
Capital Issues	Rs. Crores	5,167	8,113	57.0

*Date on April-November basis.

@Figures within brackets indicate data for corresponding period of 1987-88.

1.11. For the Stock and Capital Market, 1988-89 was a year of smart and well justified restoration of market price and turnover trends. Approvals for capital issues (i.e., consents and acknowledgements) granted by the Controller of Capital Issues during 1988-89 (April-March) for raising fresh capital by Government and non-Government companies aggregated Rs. 8,113 crores, showing a sharp increase of 57% over that of the corresponding period of 1987-88. The increase was largely accounted for by issue of convertible debentures, which amounted to Rs. 3,133 crores during the aforesaid period.

The financial assistance sanctioned by the all-India Financial Institutions, viz., IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, LIC, UTI, GIC, SFCs and SIDCs, rose by 60% in 1988-89. So also, disbursements by the aforesaid Financial Institutions recorded an increase of 36.2% over the disbursements made last year.

1.12 With a view to making the capital market dynamic, a number of important initiatives were taken during the year. Steps were initiated to give effect to corporate membership and to permit multiple membership on Stock Exchanges by amending the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. Pursuant to these, IFCI was also admitted a member of Delhi Stock Exchange with effect from the 8th March, 1989. Share transfer procedures were simplified. Measures were taken for ensuring parity in prices of existing and new shares of a company; the introduction of a National Equity Index and various steps for promoting investors' education, training of brokers and computerisation in Stock Exchanges, etc. The number of recognised Stock Exchanges in the

country increased to 16 with the grant of recognition to Jaipur Stock Exchange by the Government of India on the 9th January, 1989.

1.13. Other policy measures, that strengthened the capital market trends, included reintroduction of investment Allowance for selected industries and the minimum tax under Section 115 J not being made applicable in respect of profits earned on exports. Existing guidelines for retention of over-subscription in public/rights issues of shares and debentures were modified and brought to a uniform level of 15%. Ceiling of 11% on oversubsriptions by Financial Institutions was removed. The Government decided to remove the three years lock-in period for preferentially allotted shares by new companies at the time of their initial issue to the shareholders of the promoting company/campanies and the employees of the company issuing the initial capital. The Reserve Bank of India allowed commercial banks to provide loans to employees for purchasing shares of their own companies upto 90% of purchase price, subject to a ceiling of Rs. 20,000/-.

1.14 The Government raised, with effect from the 13th February, 1989, the minimum equity capital limit of a company for listing on the Stock Exchanges from Rs. 1 crore to Rs. 3 crores and the minimum offer to public for subscription from Rs. 60 lakhs to Rs. 180 lakhs. This is expected not only to increase the size of the issues eligible for listing and improve their liquidity prospects after listing on the Stock Exchanges, but also pave the way for a second tier market. Foreign equity investment in existing companies was allowed on a selective basis in high-tech areas with a ceiling of Rs. 10 crores or 40% of paid up share capital. So also, foreign companies were allowed to apply for the grant of Industrial Licences for establishing new undertakings in India.

1.15 The operations commenced by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Discount and Finance House of India Ltd., (DFHI) and Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) also had a salutary effect on the operations in the capital market. The Unit Trust of India (UTI) floated the India Growth Fund in USA in association with Merrill Lynch Capital Services Inc. The Fund provided an opportunity for non-resident Indians (NRIs) and other foreign investors to participate indirectly in the Indian securities market. SBI Capital Markets Ltd., launched a second Magnum entitling investors tax benefits under Section 80-CC of the Income Tax Act.

1.16 Another important event in the field of capital market during the year was the establishment of a framework for launching new ventur capital companies or venture capital funds. Venture Capital Guidelines were issued as a major policy initiative to provide vital equity support to new technology intensive enterprises, where the risk element was high and the entrepreneurs were qualified but lacked the necessary resources to proceed on their own.

1.17 Even though Stock market on the eve of the Budget for 1989-90 was in a cautious mood, the stock prices were ruling high because of the fundamental strength of the economy. The Bombay Stock Exchange Sensitive Index of Equity Prices (1978-79=100), which is the barometer of the stock market, was at 663.84 on the 28th February, 1989 (pre-Budget) which was higher by 252.62 points (61.4%) from the pre-Budget Index of 411.22 in the previous year, i.e., as on the 29th February, 1988. The Economic Times (All India) Index (1984-85—100) for equity shares on the 31st March, 1989 was 394.8 which showed a change of 75.5% over the index a year back on the 31st March, 1988.

(C) Industrial Scenario

Policy Initiatives

1.18 The Industrial policy initiatives of the Government have a major role in setting the market environment, which governs industrial performance. During the year 1988-89, major advances were made as a result of on-going process of industrial policy reforms with emphasis on easing entry or expansions of incumbent industrial enterprises and the recognition of efficient scales of production. These reforms could be grouped broadly into three categories, viz., (i) measures to facilitate capacity creation, (ii) measures to facilitate output expansion, and (iii) measures to remove procedural impediments.

1.19 Under measures to facilitate capacity creation, a major package of industrial delicensing was announced to attract investment and promote industrial growth. In the case of projects of non-MRTP and non-FERA concerns, only those involving an investment in fixed assets of more than Rs. 5 crores, if located in centrally declared backward areas, or more than Rs. 15 crores, if located in non-backward areas, were required to obtain Industrial Licences; otherwise, delicensing was brought about in all the cases, subject to certain restrictions with regard to the establishment of projects within the specified distance limits from the boundaries of standard urban areas/municipal limits of cities, and towns, etc. Location requirements of industries delicensed were brought in line with the distance limits. The limit on requirement of imported inputs was increased from the earlier 15% of the ex-factory value of the annual production, subject to a ceiling of Rs. 75 lakhs to 30% of ex-factory value of production for the first year and simultaneously, the ceiling of Rs. 75 lakhs for such imports was removed. The exemption from industrial licensing was also extended to dominant undertakings registered under Section 20B of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969 for items other than those in which the industrial undertaking was registered as dominant industrial undertaking.

1.20 With the addition of 11 more industries during 1988-89, the total number of industries covered under the Scheme of Minimum Economic Capacities (MEC) stood at 84. Besides, the existing minimum economic capacities in respect of 5 industries, viz., carbon black, hot rolled strip units, storage batteries, ceiling fans and electronic typewriters were revised and increased during the year.

1.21 Under the measures to facilitate output expansion, a new liberalised Scheme of Re-endorsement of Licensed Capacity was introduced with effect from the 1st April, 1988. Furthermore, the number of industries for which automatic re-endorsement of capacity was not available and which required compulsory licencing was reduced from 77 to 26. The facility of broad-banding, which enables manufacturing enterprises to adjust their product mix in line with changing market conditions and also facilitates better capacity utilisation was extended to a large number of industries. Altogether, upto December, 1988, 40 items were brought under the purview of broad-banding. Broad-banding facility was also allowed to MRTP/FERA companies in case of Appendix-I industry list and subject to certain prescribed guidelines, in respect of non-Appendix-I industry list. Paper mills with an annual capacity of 33,000 tonnes or more were allowed to freely diversify into newsprint, provided they had spare capacity of at least 20,000 tonnes per annum of newsprint. The total ban on creation of additional capacity for manufacture of potable alcohol based on non-molasses raw material was relaxed. This measure particularly helped in augmenting the supply of molasses for the manufacture of industrial alcohol. The Government decided to include three new items (i) mining chemicals, (ii) cement chemicals such as binders, quick setting and grouting chemicals and, (iii) food processing industry in the list of industries under Appendix-I. All fruit and vegetable products, excluding those items reserved for the small scale sector, were brought under the category of processed foods under the broad-banding scheme.

1.22 In order to simplify administrative procedures and allow sufficient time for implementation of investment projects, the period of validity of Letters of Intent issued after the 1st June, 1985 was increased to three years. Also, the validity of registrations granted by the Directorate General of Technical Development (DGTD) and other technical authorities was increased from two years to three years after the 1st June, 1985. Foreign companies were allowed to submit applications for Industrial Licences, foreign collaborations and other approvals in their own names and once the approval was granted, the foreign companies were expected to incorporate a company in India for implementing the projects. From the 10th February, 1989, Government also allowed foreign collaborations in research and development

(R&D) both at the enterprise and institutional levels, as well.

1.23 For industrialisation of backward areas, the Government of India announced its decision to set up 100 growth centres throughout the country over the next five years or so. These growth centres would be expected to serve as 'gravity centres' for attracting industries to backward areas through adequate development of infrastructure in these growth centres. In the first place, it was decided during the year to launch 61 growth centres allocated to different State/Union Territories, viz., six in Utar Pradesh, five each in Madhya Pradesh and Bihar, four each in Andhra Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, three each in Karnataka Orissa, Tamil Nadu and West Bengal, two each in Assam, Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala and Punjab, and one each in Arunachal Pradesh, Goa, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizorm, Nagaland, Pondicherry and Tripura. Besides, in case of Sikkim, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep, the need for special traeatment in view of their geographical features was emphasised and proposals were to be considered on a different footing.

1.24. Each growth ceitre is expected to acquire and develop 400 to 800 hectares of land for allocation primarily to small and medium-sized units and is to be provided funds of the order of Rs. 25 crores to Rs. 30 crores with a view to creating infrastructural facilities of a high order. Effective from the 14th February, 1989, the Government have relaxed licencing policy norms for establishment of Industrial units in the growth centres. A High Power Committee is currently engaged in evolving a framework and mechanics for implementing the Growth Centre Programme.

1.25. In respect of certain specific industries too, various Governmental measures helped those industries to improve their performance. The Government of India announced a new incentive scheme for the sugar industry by way of a higher free sale quota. Further, units with a sub-optimal capacity of 1,250 tonnes of cane crushed per day, were permitted expension to 2,500 TCD. Control on price and distribution of cement and aluminium was abolished. Transport subsidy was allowed on inter-State movement of finished goods within the North-Eastern Region @ 50% with effect from the 1st May, 1988. An External Market Assistance Scheme was announced on the 13th February, 1989 to exporters of jute manufacturers. The constitution of a jute Advisary Board was also announced on the lines of the Cotton Advisory Board to provide a forum for interaction amongst growers, industry and the Government. An integrated policy on oilseeds production, import, distribution and pricing was announced in January, 1989. Guidelines were announced for granting exemption to certain bulk drug manufacturing units from the Drugs Price Control Order, 1987. A Petrochemicals promotion and Development Agency (PPDA) was set up for the promotion of the petrochemicals sector in view of its growing impotance. Restiction on setting up of additional capacity in the manufactue of finished leather from semi-final stage was removed and licensing procedure for new units and substantial expansion of existing units for manufacture of leather footwear and leather goods was eased.

Trends in Industrial Production

1.26 The aforesaid policy initiatives coupled with an improved industrial relations climate in the country with no major instances of prolonged industrial unrest, helped the industry achieve good growth performance during 1988-89. The Average General Index of Industrial Production (base 1980-81=100) which was 142.1 for 1985-86, 155.1 for 1986-87 and 166.4 for 1987-88 went up to an estimated 181.0 showing an overall growth of 8.8%, exceeding the targetted annual growth of 8% during the Seventh Plan.

1.27 Trend-wise, the monthly official Index of Industrial Production showed a continuous rise and comparatively better performance than in the corresponding period of the previous month, as is evident from Table 3 below,

Table 3 : Index Numbers of Industrial Production

Month	1980-81=100		
	1987-88	1988-89	%age Variation
(1)	(2)	(3)	(4)
April	156.7	170.38	9.0
May	149.6	174.0	16.3
June	158.5	180.2	13.7
July	164.9	170.7	3.5
August	155.6	170.0	9.3
September	161.9	172.1	6.3
October	158.0	175.1	10.8
November	166.4	180.3	8.3
December	175.8	193.5	10.1
January	175.1	191.8	9.5
February	177.7	185.6	4.4
March	196.6	208.1(P)	5.8
Average during April to March	166.4	181.0	8.8

(P) Provisional.

1.28 The sectoral trends in industrial production during 1987-88 (actual) and 1988-89 (estimated) are given in Table 4.

Table 4 : Sectoral Trends in Industrial Production

Weight	Sector	1980-81=100 %age increase over the previous year	
		1987-88 (April-March)	1988-89 (April-March)
(1)	(2)	(3)	(4)
11.46	Mining and Quarrying	3.8	7.8*
77.11	Manufacturing	7.9	8.9*
11.43	Electricity	7.7	9.4
100.00	All industries	7.4	8.8

*Provisional.

1.29 The performance of the infrastructure sector during 1988-89 remained buoyant, on the whole. The composite index of six infrastructure industries comprising electricity, coal, saleable steel, crude petroleum, petroleum refinery products and cement, accounting for a weight of 28.8% in he Index of Industrial Production, recorded a rise of 7.9% during April-January 1988-89 over the corresponding period a year ago. Total generation of electricity during 1988-89 registered a growth of 9.4 per cent as compared to 7.7 per cent in 1987-88. The coal production in 1988-89 is expected to be 194.6 million tonnes, as against 179.7 million tonnes in the preceding year showing an increase of 8.3%. The production of cement is expected to be 44 million tonnes in 1988-89, as against 39.5 million tonnes in 1987-88, showing an increase of 11.3%. Production of saleable steel by the integrated steel plants during 1988-89 is expected to be 7.2% more than the production in the previous year. The overall capacity utilisation of the integrated steel plants is reported to have been improved to 66% in the year under review, as against 57% last year. The fertiliser production in 1988-89 is expected to be 8.96 million tonnes, as against 7.13 million tonnes in the previous year, showing an increase of 25.7%. The production of crude petroleum, which was 30.3 million tonnes in 1987-88, is expected to have gone up to 32 million tonnes showing an increase of 5.6%. The revenue earning goods traffic on railways has shown an increase of 4.1% while the cargo handled at major ports has been 12% higher in 1988-89 compared to the previous year. In the telecommunications sector, the performance in 1988-89 has indeed been very good. An additional switching capacity of 1.53 lakh lines was created in the telephone system during April-December, 1988, which was 20.5% more than the additional switching capacity of 1.27 lakh lines created during April-December, 1987. Of the total new connections provided, 34.4% have been in the metro cities and there has been an increase of 18.7% in the telephone connections provided in other regions.

1.30 In the manufacturing sector, growth has been around 9% as a whole during the year 1988-89; the distinctive feature being, that it has been considerably broad-based. Several industries particularly electronics, fertilisers, aluminium, etc., have registered growth rates ranging from 25% to 38%. On the basis of information and data for the period from April, 1988 to December, 1988, eight out of 17 industry groups at the two digit level with a combined weight of 44.9% in the Index of Industrial Production have grown at rates ranging between 10 and 20%. These include chemicals (18.8%), non-metallic mineral products (17.1%), rubber, plastic and petroleum products (15.5%), machinery and machine tools (15%), transport equipment (12.3%), jute textiles (12%), miscellaneous manufacturing industries (10.4%) and basic metal and alloy products (10.2%). Textile products which account for a weight of 0.82% in the Index of Industrial Production have shown a phenomenal increase of 55.6%. Four industry groups, accounting for a weight of 13.1% in the index have grown at rates ranging from 5 to 10%. These are food products (8.3%), electrical machinery (7.1%), beverages and tobacco (6.4%) and wood and wood products (5.2%). Metal products and paper and paper products with a weight of 5.5% in the Index of Industrial Production have shown low growth rates of 4.7% and 1.9% respectively. Of the remaining groups, cotton textiles and leather products (accounting for a weight of 12.8%) have shown negative growth rates of the order of 7.7% and 3.7% respectively.

1.31 Based on the data for the year 1987-88, an analysis of growth by broad use-based group of industries reveals that the capital goods sector with a weight of 16.4% in the Index of Industrial Production grew at 16%. This was followed by the consumer goods sector with a weight of 23.7% in the index, which recorded an increase of 7.4%. A significant feature in the growth performance of consumer goods was the acceleration in growth of consumer non-durables from 4.9% in 1986-87 to 7.4% in 1987-88. However, there was considerable deceleration in the growth of basic industries which have a weight of 39.4% in the index. This sector recorded an increase of 5.6% in constrast to a growth of 9.2% in 1986-87. The intermediate goods sector with a weight of 20.5% recorded a growth of 4.7% which represented a marginal improvement in growth performance in the year 1986-87. For the year 1988-89, more or less, the same trend with significant improvement in growth rates seemed to be visible.

1.32 Insofar as capacity utilisation is concerned, 1988-89 showed some distinct improvement. *Appendix-I* to this Report gives the installed capacity, production and capacity utilisation percentage of 60 selected industrial products for the year 1988-89 and, in relation thereto, the corresponding data relating to 521 assisted concerns of IFCI, based on the performance reports received from them.

Financial Performance of Industries

1.33 A study of the financial performance of a sample of 401 public limited companies (whose accounts had been closed on or before the 31st March, 1988) showed an improvement in fixed assets formation, sales and value of output during 1987-88, though their operating results continued to be under pressure. The total income of these sample companies rose by Rs. 2,785 crores to Rs. 29,571 crores in 1987-88, whereas total expenditure, excluding interest payments, increased by Rs. 2,673 crores to Rs. 26,762 crores. While the gross profits increased by Rs. 112 crores, operating profits declined marginally by Rs. 39 crores. Significantly, higher rates of depreciation charged by the sample companies in respect of plant and machinery, consequent to amendments to the Finance Act, were mainly responsible for the marginal decline in their profitability ratios. After meeting dividend payments amounting to Rs. 398 crores, which was higher by Rs. 61 crores over the previous year, retained profits amounted to Rs. 526 crores in 1987-88, as compared to Rs. 640 crores in 1986-87. The gross value added by these companies increased to Rs. 7,372 crores in 1987-88 from Rs. 6,614 crores in 1986-87, i.e., by 11.5%. Gross fixed assets at Rs. 23,129 crores in 1987-88 recorded a growth rate of 12%, with nearly 50% of the incremental fixed assets formation being in the form of plant and machinery. During 1987-88, total inventories increased by a lower rate of 6.1% as compared to a 9% increase in 1986-87. The return on capital (gross profit as percentage of total capital employed, i.e., net worth plus total borrowings), margin on sales (gross profit as percentage of sales), return on shareholders' equity (profit after tax as percentage of net growth) registered marginal decline as compared to the previous year.

1.34 In the first half of the year 1988-89, a review of financial performance of corporate sector drawn from a sample of 140 public limited companies indicates, however, an all-round improvement in performance. This is reflected by the upsurge in sales, gross profit and margin on sales during the half-year ended subsequent to the 31st March, 1988 (based on the unaudited published financial results). While sales and gross profit have registered increase of 16.8% and 33.1% respectively, over the figures of the previous corresponding half-year, margin on sales has registered a rise from 8.7% to 10%.

(D) *Prospects and Outlook*

1.35 Industry has already recorded good growth performance in the year 1988-89. A number of major reforms introduced over the years have resulted in greater investment in the industries sector. Further, the relative stability in prices and the control of inflation have created a better investment climate and made the industrial scene more competitive and promising.

1.36 The fiscal measures in 1988-89, notably, concession to agricultural and agro-based activities, re-introduction of investment allowance and duty reliefs to selected industries have provided necessary fillip to production, both in agricultural and industrial sectors. At the same time, fiscal incentives for export production, exporters and export houses are expected to give a further boost to exports. The tax concession under Section-80 HHC of Income Tax Act for export profits which has been enhanced so as to exempt 100% of export profits from income tax is likely to create a highly favourable environment for exports. Extension of 5-year tax holiday to 100% export-oriented units which was hitherto available to Free Trade Zones is also expected to create the desired stimulus for exports.

1.37 To foster the growth of capital goods industry and to promote greater self-reliance in this critical sector, the

relaxations, accorded under the Technology Upgradation Scheme (TUS), particularly, the reduction of customs duty on selected raw materials needed for the production from 100—180% to 55%, and enhancement of the ceiling for import of technology and capital goods from existing Rs. 2 crores to Rs. 3 crores, per unit, per financial year under the Technical Development Fund (TDF) Scheme, are likely to be considerably helpful. The reduction of customs duty on machinery used in a number of identified export thrust industries is also expected to make exports more competitive. The Direct Tax Laws (Amendment) Act, 1988, which envisages 100% deduction in respect of profits earned by approved hotels, tour operators and travel agents in convertible foreign exchange, exclusion of the export profits and the profits earned by approved hotels, etc., from the purview of Section 115J of the Income Tax Act relating to levy of minimum tax on companies, certain tax concessions to the investors in NRI bonds and complete exemption in respect of fees earned by a foreign company for technical services rendered from projects connected with the security of India are likely to give a boost to the tourism and tourism related activities and other industries.

1.38 The developments in the credit policy effected during 1988-89 envisaging a major overhaul of the Credit Authorisation Scheme, encouraging bill financing and allowing flexibility in short term interest rate structure based on a band rather than on the basis of prescribed rates made it possible to have adequate availability of credit, without allowing undue growth of liquidity in the system.

The instrument known as Inter-Bank Participation Certificate introduced with a view to facilitating the adjustment of short-term liquidity within the banking system and operations of Discount and Finance House of India have provided considerable flexibility in the money market.

1.39 The Credit Policy for the first-half of 1989-90 announced by the Reserve Bank of India (RBI) on the 27th March, 1989 envisages a number of steps to simplify and improve the functioning of the monetary system, both in the medium as well as long run. It aims at bringing about certain structural changes in the monetary policy, a process which had already been started in 1989. The first slab for term bank deposits of 15—45 days fetching an interest rate of 3% per annum has been abolished with effect from the 28th March, 1989. For second slab—46 days to 90 days, the rate of interest has been raised from 4% per annum to 6% per annum. The 10% per annum interest rate applicable to the inter-bank call money market stands withdrawn with effect from the 1st May, 1989. Selective Credit Controls have been modified and minimum margin on bank advances in respect of certain industries has been reduced. Two new money market instruments, viz., Certificates of Deposits (CDs) and Commercial Papers (CPs) are welcome additions to the existing money market instruments. While CDs are intended to widen the range of money market instruments and provide investors with greater flexibility in deployment of their short-term surplus funs, CPs would enable well-rate corporate entities to diversify their sources of short-term borrowings and provide an additional instrument to investors. From the fortnight beginning the 1st July, 1989, the multiple prescriptions with regard to Cash Reserve Ratio (CRR) are going to be replaced by a single prescription of 15% of the entire demand and time liabilities of the banks.

1.40 The Union Budget for 1989-90 also has a number of positive features to provide impetus to capital markets. For instance, rate of tax for income slab Rs. 18,000—25,000 has been reduced from 25% to 20%. Tax deduction at source for interest payments upto Rs. 2,500/- on bonds and debentures has been withrawn. Venture capital companies have been allowed in respect of capital aim arising on sale of shares of venture capital undertaking a deduction on the same lines as applicable to non-corporate tax-payers. 80CC concessions have been extended to investment in shares of companies which are incorporated for setting up hospitals. To stimulate flow of personal savings into equity, the Budget for 1989-90 envisages introduction of an Equity-linked Savings Scheme to be operated through the Unit Trust of India (UTI) and recognised mutual funds. Investments under this have been made eligible for tax deduction on the basis of net annual additions to such savings. Home Loan Account Scheme of the National Housing Bank has been announced to promote house building activity. Deposits under the scheme have been given tax concessions. Import duty on project imports and several goods has either been reduced or rationalised. Excise duty relief for weak but potentially viable sick units is expected to give a major fillip to industrial growth. The overall deficit for 1989-90 has been projected at a reduced level of Rs. 7,337 crores from Rs. 7,940 crores in 1988-89. The Central Plan Outlay for 1989-90 stands stepped up by nearly 20% to Rs. 34,446 crores from Rs. 28,715 crores. All these measures are expected to lead and promote considerable savings and investment in 1989-90.

1.41 Undoubtedly, the pressure on the balance of payments calls for wise deployment of the scarce forein exchange and the need to step up substantially our export performance. Fortunately, there is awareness in all sections of the society and this factor is likely to help in improving the country's performance on the external front, as a whole, in the current year. Overall deficiencies in power supply together with interruptions in its availability continue to pose a severe constraint on the quantity and quality of economic production. Looking ahead, it is clear that higher investments, better technologies and improvements in operating performance of the power sector have to command high priority. In this context, quick investments in gas based power plants, energy conservation measures and use of alternate and renewable energy sources in greater measure deserve immediate attention.

1.42 The outlook, otherwise, for 1989-90 is one of high growth rate, barring unforeseen circumstances, and, developments in the world economy. According to an assessment, a 10% or even higher growth in the Gross National Product (GNP) may not be ruled out for 1989-90.

CHAPTER 2

OPERATIONS, RESOURCES AND WORKING RESULTS

(A) Operations

Overall Operations

2.01 During the nine months' period of the year 1988-89 overall sanctions of IFCI under its various schemes of assistance aggregated Rs. 1,333.34 crores in respect of 604 projects. Compared to the sanctions on annualised basis for nine months' period in the previous year, viz., 1987-88, these were higher by 31.6%.

2.02 Total disbursements during the period aggegated Rs. 739.92 crores as against Rs. 730.22 crores disbursed during the whole of the previous year. These were 35.1% higher than the disbursements taken on annualised basis for none months' period in the previous year.

2.03 Cumulatively, overall sanctions accorded by IFCI under its various schemes upto the end of March, 1989, amounted to Rs. 6,516.78 crores to 3,159 projects. The overall disbursements upto the 31st March, 1989 were of the order of Rs. 4,352.08 crores, of which cash disbursements, i.e., disbursements excluding guarantees issued, were of the order of Rs. 4,275.17 crores. The total outstanding as on the 31st March, 1989, net of repayments by the borrowers amounted to Rs. 3,577.78 crores.

Scheme-wise Classification of Assistance

2.04 Apart from project finance, IFCI now operates a number of schemes in the area of financial services in response to the emerging needs in the industrial arena. These are : (a) equipment financing, (b) equipment leasing, (c) equipment procurement, (d) suppliers' credit, and (e) finance to leasing and hire purchase concerns. Broad scheme-wise classification of assistance sanctioned and disbursed in 1988-89 (July-March) and comulatively upto the 31st March, 1989 is given in Table 5.

Table 5 : Scheme wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Scheme of Financing	1988-89 (July-March)			Cumulatives upto the 31st March 1989		
	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	No. of projects	Sanction (Rs.j	Disburse-ments (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Project Finance (including Equipment Finance) .	535	1,210.00	671.32	3,055	6,339.91	4,265.31
Equipment Leasing	29	75.38	50.83	31	90.45	65.90
Equipment Procurement	8	4.61	0.62	8	4.61	0.62
Suppliers, Credit	16	30.55	0.71	38	88.51	3.81
Assistanceto Leasing & Hire Purchase concerns .	16	12.80	16.44	27	23.30	16.44
Total	604	1,333.34	739.92	3,159	6,546.78	4,352.08

Project Finance

2.05 Project finance sanctions (inclusive of equipment finance) during the period 1988-89 (July–March) amounted to Rs. 1,210.00 crores as against Rs. 1,267.34 crores in 1987-88. Facility-wise classification of project finance under four distinct heads, viz., Rupee Loans, Foreign Currency Loans, Underwritings & Direct Subscriptions and Guarantees showing sanctions and disbursements during the period under review and cumulatively upto the 31st March, 1989 alongwith outstanding is as on that date are given in Table 6.

Table 6 : Facility-wise Classification of Project Finance

(Rs. Crores)

Facility	1988-89 (July-March)		Cumulative upto the 31st March 1989		Outstanding as on the 31st March 1989 (Rs.)
	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	Sanctions (Rs.)	Disburse-ments (Rs.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Project Finance					
Rupee Loans	784.36	547.40	4,537.93	3,397.39	2,739.16
Foreign Currency Loans . . .	359.47	105.15	1,247.74	673.36	616.77
Underwriting & DirecM Subscription .	64.96	13.04	421.57	117.65	111.75.
Guarantees					
For Deferred Payments . . .	0.64	5.73	85.09	44.60	16.57
For foreign loans	0.57	-	47.58	32.31	15.94
Total	1,210.00	671.32	6,339.91	4,265.31	3,500.19

Includes part of outstanding loan amount converted into equity shares where the condition of right of conversion was stipulated at the time of sanction of loan assistance, convertible debentures converted into equity shares and also includes part of outstanding loans (overdue interest etc.), converted into shares/debentures.

2.06 There was an increased demand for rupee loans which formed 64.8% of total sanctions for project finance. This was followed by foreign currency loans which formed 29.7% of the total poject finance sanctioned during the period under review. Compared with the nine months' period of the previous year on annualised basis, rupee finance sanctions (in the form of loans, underwritings and direct subscriptions) showed an increased of 10.4% and foreign currency loans 117.6%.

Investment Operations

2.07 IFCI sanctioned during the period under review the facility of underwriting of equity shares to 61 concerns for an aggregate amount of Rs. 44.57 crores and preference share issue of one concern to the extent of Rs. 0.69 crore The aggregate underwriting facility, sanctioned during the period was, thus 2.4% higher than the underwriting facility approved during the nine months' period on annualised basis in 1987-88.

2.08 The sanctions relating to direct subscriptions during the period, however, showed a significant increase. While sanctions relating to direct subscriptions of shares/debentures during 1987-88 amounted to Rs. 15.16 crores for 76 concerns, during the nine months' period of 1989-89 these amounted to Rs. 19.70 crores towards shares and debentures of 82 concerns, indicating a rise of 29.9% on absolute basis and 73.3% on the annualised for the corresponding nine months period in the previous year.

2.09 During the period, 49 issues of concerns whose shares had been underwritten by IFCI for Rs. 27.58 crores in aggregate were placed on the market. The shares devolved on FCI pursuant to underwriting obligations amounted to Rs. 5.28 crores. In addition, IFCI actually subscribed to shares and debentures of 48 companies amounting to Rs. 9.07 crores against the sanctions relating to direct subscriptions.

Guarantees

2.10 During the period, the facility of guaranteeing deferred payments to the extent of Rs. 0.64 crore to foreign suppliers of machinery and equipment was sanctioned in two cases pertaining to (i) a cement unit in Andhra Pradesh, and (ii) a jute mill in West Bengal. Guarantee was also agreed to be given for a foreign loan in one case relating to non-ferrous metal unit in Orissa for an amount of Rs. 0.57 crore. However, insofar as the execution of guarantees is concerned, guarantees for deferred payments were executed during the period under review for an amount aggregating Rs. 5.73 crores.

Purpose-wise Classification of Assistance under Project Finance in 1988-89

(a) *Assistance to New Projects*

2.11 Out of the total project finance assistance of the orer of Rs. 1,210 crores sanctioned by IFCI in 1988-89 (July–March), 66.5% (Rs. 804.17 crores) was claimed by 166 new projects. On the basis of annualised sanctions for the nine months' period in the pevious year, the assistance sanctioned to new projects during the period under review was higher by 78.5%. Of these, 5 projects had a capital outlay upto Rs. 3 crores each; 35 projects individually had a capital outlay between Rs. 3 crores to Rs. 5 crores; 43 projects were in capital outlay ranging from Rs. 5 crores to Rs. 10 crores; 30 projects had capital outlay between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores; and 53 projects were those whose capital outlay per project was above Rs. 20 crores.

(b) *Assistance for Expansion and Diversification Schemes*

2.12 Assistance of the order of Rs. 82.21 crores (6.8% of the total assistance sanctioned under project finance) went to 48 projects for their expansion and diversification programmes in 1988-1989 (July—March).

(c) *Assistance for Modernisation Programmes*

2.13 Assistance for midernisation purposes during the period under review amounting to Rs. 127.50 crores (10.5% of the total assistance sanctioned under project finance) went to 132 projects as against Rs. 246.68 crores to 218 projects in 1987-88.

2.14 Assistance under the Soft Loans Scheme during the period was Rs. 86.26 crores to 64 projects as against Rs. 127.50 crores to 88 projects in 1987-88.

(i) *Modernisation of Sugar Units*

2.15 During the period under review, it was agreed to extend the modernisation assistance under the Soft Loans Scheme to sugar units going in for modernisation and incidental expansion upto 2,500 TCD, which had been in operation for a minimum of five crushing (operating) seasons. It was also agreed that in case of modernisation/expansion schemes upto 2,500 TCD by sugar units, debt-equity ratio could be maintained at 1 : 1 as agreed to in the meeting of Inter-ministerial Group for financing of incentive schemes for sugar projects during the Seventh Five Year Plan. Institutions could examine the justification for relaxation of debt-equity ratio on merits for expansion projects beyond 2,500 TCD where incentives were not available, on a case to case basis, subject to adequate debt service coverage ratio, assets coverage ratio and current ratio. As at the close of the period, a Committee of institutional officials of IFCI, IDBI and ICICI (under the lead of IFCI) was constituted to go into all aspects relating to the number and type (new, expansion, modernisation, etc.) of sugar units as also individual units that could be taken up for financing by the Institutions during the remaining period of the Seventh Five Year Plan. The Committee was expected to take into consideration the aggregate requirement of resources for financing further projects in the industry, possibility of phasing out investments, regional distribution, availability of sugarcane, position of default and other relevant factors.

(ii) *Textile Modernisation Fund Scheme*

2.16 The Textile Modernisation Fund Scheme (TMFS) introduced with effect from the 1st August, 1986, initially for a period of two years, was reviewed during the period under review and was extended subject to a further review being made after the expiry of the Seventh Plan period. Meanwhile IDBI had constituted an Expert Group under the aegis of Ahmedabad Textile Industries Research Association (ATIRA) to look into the aspects relating to the augmenting of the corpus fund of TMFS and consider the recommendations made by Abid Hussain Committee. A study on the impact of the TMFS in bringing about improvement in the health of the textile industry based on an assessment of the performance and working results of the assisted units was also commissioned by IDBI as the lead institution. A significant development under TMFS was to extend the benefits of the "special loans" to be treated as the promoters' contribution under the scheme to spinning/composite units in the co-operative sector. Assistance under the scheme was also agreed to be extended to powerloom units and independent process houses incorporated as public limited companies/ industrial co-operatives. The share of assistance sanctioned by IFCI under TMFS during the period (July—March of 1988-89) aggregated Rs. 21.62 crores to 49 units, as against Rs. 59.60 crores to 84 units sanctioned assistance in 1987-88.

(iii) *Jute Modernisation Fund Scheme*

2.17 The Jute Modernisation Fund Scheme (JMFS) introduced with effect from the 1st November, 1986 also for a period of two years was reviewed, and, was extended for a further period of two years with effect from the 1st November, 1988. The assistance sanctioned under JMFS during the period was only Rs. 6.61 crores to five projects. The Monitoring Committee for JMFS headed by the Secretary (Textiles), Government of India, continued to monitor and review the operation of the scheme. The jute mills, which are predominantly in the State of West Bengal, were not able to decide whether to go in, or, not, for modernisation of their units for several reasons like choice of technology, rationalisation of labour, problems arising out of displacement of labour as a result of modernisation and the apprehension about the overall approach in these matters. Further, as most of the existing jute mills were sick, assistance could not be availed of by them on their own, unless a rehabilitation package for revival of the units was approved by the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) under Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. Efforts, however, continued to be made by the Central Government/ all-India Financial Institutions to sort out the various outstanding matters.

(d) *Overrun Assistance, inclusive of Rehabilitation Assistance etc.*

2.18 The general overrun assistance and the rehabilitation assistance aggregated Rs. 113.53 crores (9.4% of the total assistance sanctioned under project finance) to as many as 136 units as against the assistance of Rs. 154.70 crores to 198 units last year.

Special Features of IFCI's Assistance under Project Finance (1988-89)

2.19 Some of the specific characteristics/special features of IFCI's assistance under project finance in 1988-89 could be mentioned as under :

— Assistance of the order of Rs. 26.85 crores was provided to 8 hospital units under IFCI's Scheme of Assistance to Corporate Hospitals and Multi-disciplinary Health Centres.

— Export-oriented projects with substantial export obligations totalled 23; the financial assistance sanctioned being of the order of Rs. 46.56 crores.

— Out of 166 new projects assisted, 31 projects were those, which were promoted by first-generation entrepreneurs. These claimed assistance of the order of Rs. 54.51 crores. Twenty projects promoted by Non-resident Indians claimed assistance of Rs. 56.40 crores.

— 103 project sanctioned assistance during the period under review were those, which involved foreign collaboration and/or technology transfer from abroad. These claimed assistance of the order of Rs. 564.43 crores.

— Eight projects were such, which envisaged manufacturing some of the products for the first time in the country, or, introducing for the first time a better and improved technology in the country. The assistance to such projects aggregated Rs. 24.77 crores.

Assistance under the Scheme Pertaining to the Areas of Financial Services

(i) *Equipment Finance*

2.20. With a view to making available rupee and foreign currency loans to existing industrial concerns for purchase

of capital equipment not related to any specific project as such, IFCI has been operating from 1984-45 a Scheme of Equipment Finance, under which, during the period under review, loan assistance of the order of Rs. 82.59 crores was sanctioned to 53 units. Last year, the loan assistance sanctioned under this Scheme was Rs. 67.03 crores to 65 units. Cumulatively, under the Scheme, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 186.19 crores to 162 units under this scheme.

(ii) *Equipment Leasing*

2.21. Under the Equipment Leasing Scheme, IFCI has been providing equipment—indigenous and/or imported—to the existing industrial concerns by way of financial lease including master lease, syndicated lease and sale and lease back arrangement.

The equipment provided on lease are generally industrial equipment/machinery, EPABX systems, computers, etc. Primary lease period is fixed for five to eight years and the secondary lease period is allowed to be renewed at the option of the lessee. The scheme which was introduced on the 1st June, 1988, has evoked considerable response thereafter. While two transactions for providing equipment on lease costing Rs. 15.07 crores were finalised within one month's time during the year 1987-88, in another nine months' period ended the 31st March, 1989, as many as 26 transactions for providing equipment on lease costing Rs. 75.38 crores were finalised. Cumulatively, the overall sanctions under the equipment leasing upto the 31st March, 1989 amounted to Rs. 90.45 crores against which disbursements made were of the order of Rs. 65.90 crores.

(iii) *Equipment Procurement*

2.22. A new dimension to IFCI's variegated financial services was added in 1988-89 with the introduction of Equipment Procurement Scheme effective from the 1st November, 1988. Under this scheme, IFCI agrees to procure the equipment and then resell the same by endorsement of documents to the eligible existing industrial concerns in the corparate and/or co-operative sectors. The invoice value of the equipment with standing charges is recovered from the buyer concern in monthly instalments spread over a period of 3 to 5 years. The Scheme attractively affords the benefit of depreciation and investment allowance to the beneficiary concerns. In five months' period ended the 31st March, 1989, assistance of the order of Rs. 4.61 crores was sanctioned to 8 existing industrial concerns. A beginning in disbursement was made with Rs. 0.62 crore upto the end of March, 1989.

(iv) *Supplier's Credit*

2.23. The Suppliers' Credit Scheme introduced by IFCI with effect from the 1st July, 1987 envisaging the grant of a non-revolving line of credit to machinery/equipment and computer manufacturing concerns for the sale of their equipment to actual-user-purchaser concerns on deferred payment basis, gained further response, and, during the nine months' period ended the 31st March, 1989, assistance of the order of Rs. 30.55 crores was sanctioned to 16 equipment manufacturnig concerns. Cumulatively, upto the 31st March, 1989, assistance under the Suppliers' Credit Scheme had been sanctioned to the extent of Rs. 88.51 crores to 38 equipment manufacturing concerns. The overall disbursements against the sanctions under the scheme upto the 31st March, 1989 were of the order of Rs. 3.81 crores.

(v) *Finance to Leasing and Hire Purchase Concerns*

2.24. Despite IFCI's approach in assisting leasing and hire purchase concerns being selective, assistance of the order of Rs. 12.80 crores was sanctioned under the scheme to 16 leasing concerns during nine months' period of 1988-89 (July-March). Cumulatively, upto the 31st March, 1989, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 23.30 crores to 27 leasing concerns, against which disbursements of the order of Rs. 16.44 crores had been effected until the said date.

(vi) *Merchant Banking*

2.25. During the nine months' period ended the 31st March, 1989, the Merchant Banking Department of IFCI (with its Bureau Office at Bombay) handled 32 assignments, of which 25 related to public issues. These helped the clients to mobilise funds of the order of Rs. 141.01 crores. Cumulatively, IFCI's Merchant Banking Department had handled, since its inception in July, 1986, and upto the 31st March, 1989, as many as 77 assignments, which included 59 public issues mobilising funds of the order of Rs. 538.35 crores. The Merchant Banking Department is gradually diversifying its activities to encompass other financial services, particularly, project counselling, capital restructuring, amalgamations and mergers, trusteeship assignments, etc.

Flow of Applications

2.26. IFCI had a steady flow of applications both under project finance and schemes pertaining to the financial services extended by it.

2.27. Under project finance, IFCI processed during 1988-89 (July-March) applications (inclusive of applicatlons under Equipment Finance Scheme) from 602 eligble concerns for an aggregate assistance of Rs. 5,112.63 crores, either, on its own, or on joint financing basis. Applications from 13 concerns for an aggregate assistance of Rs. 64.50 crores were either withdrawn by the applicants or treated as closed for want of progress or lack of viability of the propsed projects. As at the close of March, 1989, applications from 39 concerns (32 on joint financing basis) under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 251.68 crores were pending for consideration. All other applications from 550 concerns were sanctioned assistance during the nine months' period ended the 31st March, 1989; the disposal in 97.3% cases having been made in less than four months' time from the date of receipt of complete information and data.

2.28. Apart from applications from 39 concerns pending under IFCI's lead as on the 31st March, 1989, applications from 98 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1,578 crores on joint financing basis were pending consideration under the lead of IDBI and ICICI, in which also IFCI's involvement and particpation was expected in the succeeding period.

2.29. In respect of its schemes under the financial services, IFCI processed applications for assistance (other than Equipment Finance Scheme) from 98 concerns for aggregate assistance of Rs. 191.90 crores. Out of these applications from 66 concerns were sanctioned assistance under variegated schemes related to the financial services provided by IFCI, viz., equipment procurement, equipment leasing, suppliers' credit, finance to leasing and hire purchase concerns, etc.

Applications from 24 concerns were treated as withdrawn because of the lack of eligibility and/or other related factors, and, as at the end of March, 1989, applications from 8 concerns for aggregate assistance of Rs. 11.20 crores were pending consideration of IFCI.

Overall Assistance—Industry-wise

2.30. Industry-wise coverage of overall assistance sanctioned during the year 1988-89 (July-March) and cumulatively upto the 31st March, 1989 is given in Table 7.

Table 7 : Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. Crores)

Industry	1988-89 (July-March)			Cumulative up to the 31st March, 1989		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar :						
Co-operatives	17	41.73	3.1	215	283.30	4.3
Others	15	21.06	1.6	85	121.49	1.9
Textiles	97	77.40	5.8	595	721.60	11.0
Jute	7	8.85	0.7	38	46.79	0.7
Chemicals :						
Basic chemicals	21	31.98	2.4	138	352.71	5.4
Fertilisers & pesticides	18	235.72	17.7	71	506.61	7.7
Synthetic fibres	10	66.66	50	59	416.31	6.4
Synthetic resins, plastic materials and products	26	128.97	9.7	100	243.89	3.7
Other chemicals & chemical products	30	43.91	3.3	151	197.52	3.0
Cement & Cement Products	30	69.06	5.2	151	611.91	9.3
Paper & Paper products	11	5.59	0.4	114	227.86	3.5
Rubber products	9	11.77	0.9	39	116.37	1.8
Iron & steel	52	117.65	8.8	205	487.48	7.4
Machine & Accessories	36	66.83	5.0	194	287.38	4.4
Transport equipment & Parts	18	11.67	0.9	135	277.12	4.2
Electronics	35	91.26	6.9	137	307.07	4.7
Electrical machinery & appliances	15	17.84	1.3	98	148.58	2.3
Metal Products	20	29.96	2.2	107	144.10	2.2
Non-ferrous metals	10	14.45	1.1	40	93.61	1.4
Misc. Non-metallic mineral products	18	27.14	2.0	86	155.37	2.4
Gas & Electricity	6	63.43	4.7	24	181.12	2.8
Hotels	21	29.41	2.2	81	123.74	1.9
Medical & Health Services	8	26.85	2.0	17	44.61	0.7
Misc. other Industries	74	94.15	7.1	279	450.24	6.9
Total	604	1,333.34	100.0	3,159	6,546.78	100.0

2.31 Industries which claimed a significant share in IFCI's assistance portfolio during 1988-89 were fertilisers and pesticides (17.7%), synthetic resins and plastic material/products (9.7%), iron and steel (8.8%), electronics (6.9%), textiles (5.8%), chemicals and chemical products (5.7%), cement (5.2%), synthetic fibres (5.0%), machinery and accessories (5.0%), gas and electricity (4.7%), sugar (4.7%), metal products (2.2%), hotels (2.2%), miscellaneous non-metallic mineral products (2.0%), medical services (2.0%) and others (12.4%). Priority industries like fertilisers, synthetic resins, iron and steel, electronics, textiles, chemicals and chemical products, cement, synthetic fibres, machinery and accessories, electricity and gas, sugar, paper, transport equipment, non-ferrous metals and miscellaneous food products accounted for 82.6% of the total assistance.

2.32 In the cumulative picture, textiles, cement, fertilisers, iron and steel and ferro alloys, synthetic and man-made fibres and sugar, emerged as largest beneficiaries of IFCI's assistance having claimed together 48% of assistance in IFCI's assistance portfolio, followed by basic industrial organic and inorganic chemicals (5.4%), electronics (4.7%), machinery and accessories (4.4%), transport equipment (4.2%), etc.

2.33 Industry-wise distribution of assistance sanctioned during 1988-89 (July-March) as also cumulative assistance as on the 31st March, 1989, according to the use-based classification of products is given in Table 8.

Table 8: Industry-wise Distribution of Assistance According to Use based Classification Products

(Rs. Crores)

Industry	1988-89 (July-March)			Cumulative up to the 31 stMarch, 1989		
	No of Projects	Amount Sanctioned Rs.	%to the total	No. of Projects	Amount Sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic Industries (viz, basic metal industries, basic industrial chemicals, fertilizers, cament, mining, power generation, etc.)	143 (163)	546.35 (398.76)	41.0 (29.5)	651 (592)	2,277.14 (1,771.32)	34.8 (33.4)
Capital goods Industries	104	187.60	14.1	564	1,020.15	15.6
(viz, machinery and accessories, electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.)	(158)	(245.67)	(18.2)	(507)	(849.53)	(16.0)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Intermediate goods industries	125	331.55	24.9	614	1,433.80	21.9
(viz, chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes, etc.)	(153)	(387.69)	(28.7)	(541)	(1,123.79)	(21.2)
Consumer goods industries (viz, sugar, other food products, cotton/woolen textiles, paper and other miscellaneous industries	185	194.28	14.5	1,196	1,607.32	24.5
	(264)	(268.43)	(19.9)	(1,120)	(1,428.18)	(26.9)
Service industries	47	73.56	5.5	134	208.37	3.2
(viz hotels, medical services, shipping, etc.)	(42)	(50.32)	(3.7)	(97)	(132.81)	(2.5)
Total	604	1,333.34	100.0	3,159	6,546.78	100.0
	(780)	(1,350.87)	(100.0)	(2,857)	(5,305.63)	(100.0)

Note: Figures in brackets relate to the previous year, and are as on 30th June, 1988.

Overall Assistance—State-wise

2.34 State-wise spread of IFCI's assistance in 1988-89 (July-March) and cumulatively upto the 31st March, 1989 is set out in Table 9.

Table 9 : State/Territory-wise Spread of Assistance (Rs. Crores)

State/Territory	1988-89 (July-March)			Cumulative up to the 31st March, 1989		
	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	65	106.50	8.0	297	666.96	10.2
Arunachal Pradesh	--	—	--	1	0.16	—
Assam	8	7.40	0.6	34	45.12	0.7
Bihar	11	11.39	0.9	72	114.34	1.7
Goa	5	13.78	1.0	23	38.90	0.6
Gujarat	56	228.90	17.2	289	851.93	13.0
Haryana	28	35.97	2.7	142	206.45	3.2
Himachal Pradesh	15	21.43	1.6	41	67.45	1.0
Jammu & Kashmir	4	1.48	0.1	19	23.18	0.4
Karnataka	31	39.49	3.0	214	356.82	5.5
Kerala	17	14.09	1.0	83	121.58	1.9
Madhya Pradesh	30	49.24	3.7	136	317.02	4.8
Maharashtra	91	171.44	12.9	554	926.51	14.2
Manipur	1	2.45	0.2	2	3.96	0.1
Meghalaya	2	1.89	0.1	6	7.79	0.1
Nagaland	—	—	—	4	2.97	0.1
Orissa	13	38.40	2.9	67	213.17	3.3
Punjab	36	60.73	4.6	145	341.08	5.2
Rajasthan	27	127.19	9.5	129	387.22	5.9
Sikkim	—	—	—	3	2.90	—
Tamil Nadu	77	107.00	8.0	295	506.26	7.7
Tripura	—	—	—	2	2.63	—
Uttar Pradesh	48	189.59	14.2	338	930.10	14.2
West Bengal	21	37.91	2.8	192	264.32	4.0
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	0.98	—
Chandigarh	—	—	—	3	2.05	—
Dadra & Nagar Haveli	1	0.30	—	7	6.69	0.1
Daman & Diu	2	2.36	0.2	2	2.36	—
Delhi	8	53.67	4.0	35	102.00	1.6
Pondichery	7	10.74	0.8	23	33.88	0.5
Total:	604	1,333.34	100.0	3,159	6,546.78	100.0

2.35 During the period, quantumwise, the States of Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu claimed first five positions in IFCI's portfolio, though, project number-wise, the first five positions were taken by Maharashtra, Tamil Nadu, ndhra Pradesh, Gujarat and Uttar Pradesh.

2.36 Compared to the percentage share of assistance during the whole of the preceding year 1987-88, the States of Assam, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Manipur, Meghalaya, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Union Territories of Delhi, Daman & Diu and Pondicherry were able to improve their position in IFCI's assistance portfolio during 1988-89 (July-March).

2.37 For the first time, the Union Territory of Daman & Diu was covered in IFCI's assistance during the period under review. In the cumulative sense, IFCI's assistance has reached almost all parts of the country during the past 41 years, except the State of Mizoram and the Union Territory of Lakshadweep. It is the collective endeavour of the Institutions through various promotional measures to see that industrial activity picks up in Mizoram as well as in Lakshadweep Islands.

2.38 A feature of considerable significance in 1988-89 was that in Punjab, the industrial activity continued to be on the same pattern as in the previous year. The assistance sanctioned to projects during nine months' period ended the 31st March, 1989 by IFCI was almost the same as for the corresponding nine months in the previous year on annualised basis. The Institutions continued their policy of according preferential treatment as also concessional assistance to new industrial units in Punjab as per 'B' category classification of backward areas.

2.39 Cumulatively, the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, continued to occupy the first five positions in IFCI's total cumulative assistance portfolio as on the 31st March, 1989. The next in order were Rajasthan, Karnataka, Punjab, Madhya Pradesh, West Bengal and Orissa.

Overall Assistance—Sector-wise

2.40 Table 10 gives the sector-wise classification of projects and assistance sanctioned to them both during 1988-89 (July-March) and cumulatively upto the 31st March, 1989.

Table 10 : Sector wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed (Rs. Crores)

Sector	1988-89 (July-March)			Cumulative up to the 31st March, 1989		
	Sanctions	Disbursements		Sanctions	Disbursements	
	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.	No. of projects	Amount Rs.	Amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Co-operative	23	52.40 (3.9%)	33.77 (4.6%)	327	463.43 (7.1%)	402.24 (9.2%)
Private	501	1,053.40 (79.0%)	564.83 (76.3%)	2,291	4,583.57 (70.0%)	2,962.67 (68.1%)
Joint	49	135.41 (10.2%)	71.08 (9.6%)	256	905.55 (13.8%)	543.27 (12.5%)
Public	31	92.13 (6.9%)	70.24 (9.5%)	285	594.23 (9.1%)	443.90 (10.2%)
Total	604	1,333.34 (100.0%)	739.92 (100.0%)	3,159	6,546.78 (100.0%)	4,352.08 (100.0%)

Note: Figures in brackets denote percentage to total.

(a) *Assistance to Co-operative Sector*

2.41 During 1988-89 (July-March), IFCI sanctioned assistance of the order of Rs. 52.40 crores to 23 projects in the co-operative sector. Quantum-wise, assistance sanctioned during the nine months' period of 1988-89 was higher by 61.1% compared with the assistance of the order of Rs. 32.52 crores sanctioned to industrial co-operatives in the preceding full year. The assistance to industrial co-operatives during the period under review included 17 sugar co-operatives with assistance of the order of Rs. 41.73 crores, 4 textile co-operatives with assistance to the extent of Rs. 3.71 crores and 2 other co-operatives with assistance of the value of Rs. 6.96 crores.

2.42 Cumulatively, upto the 31st March, 1989, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 463.43 crores to 327 projects in the co-operative sector against which Rs. 402.24 crores had already been disbursed. Maharashtra was on the top, both from the view point of number of co-operatives and amount sanctioned to them in IFCI's assistance portfolio. It had nearly 34.1% share in the cumulative assistance sanctioned by IFCI to industrial co-operatives. After Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, Karnataka and Tamil Nadu had the share in IFCIs cumulative assistance portfolio in respect of industrial co-operatives to the extent of 17.8%, 11.3%, 7.0%, 6.2% and 5.9% respectively.

(b) *Assistance to Corporate Sector*

2.43 Assistance to the corporate sector during 1988-89 (July-March) aggregated Rs. 1,280.94 crores for 581 projects. The private sector which has always been the largest beneficiary of the financial assistance from IFCI right from its inception, claimed assistance of the order of Rs. 1,053.40 crores (79.0% of the total) for 501 projects, which was higher by 6.7% over the assistance of Rs. 987.56 crores sanctioned to private sector projects in full 12 months period last year.

2.44 Assistance to projects in joint public sector amounted to Rs. 135.41 crores and Rs. 92.13 crores and formed 10.2% and 6.9% respectively during the period under review. This related to 49 joint sector projects and 31 public sector projects.

2.45 The assistance sanctioned cumulatively upto the 31st March, 1989, to the corporate sector projects amounted to Rs. 6,083.35 crores for 2,832 projects and their share in IFCI's portfolio as on the 31st March, 1989 was 92.9%, the share of private, joint and public sector projects *inter-se* being 70%, 13.8% and 9.1% respectively. The cumulative disbursements to projects in the corporate sector aggregated Rs. 3,949.84 crores.

2.46 In the corporate sector, in the cumulative assistance portfolio of IFCI as on the 31st March, 1989, quantumwise the State of Uttar Pradesh occupied the first position with assistance of the order of Rs. 847.44 crores (13.9%). The next in order were Gujarat Rs. 799.41 crores (13.1%), Maharashtra Rs. 768.23 crores (12.6%), Andhra Pradesh Rs. 645.67 crores (10.6%), Tamil Nadu Rs. 478.72 crores (7.9%) and Rajasthan Rs. 382.50 crores (6.3%). Numberwise, the largest number of projects assisted in the corporate sector were from Maharashtra (439) followed by Uttar Pradesh (296), Andhra Pradesh (273), Tamil Nadu (272), Gujarat (265) and West Bengal (192).

Assistance to Backward Areas and No-Industry Districts

2.47 Pending formulation of a revised scheme for development of identified Growth Centres, the all-India Financial Institutions including IFCI continued to follow the existing scheme of concessional finance for projects coming up in centrally notified backward districts/areas. IFCI's assistance to projects in centrally notified backward districts/areas during 1988-89 (July-March) amounted to Rs. 614.92 crores in respect of 307 projects.

2.48 As per the existing scheme of classification of backward districts/areas under category 'A', 'B' and 'C', 71 projects located in category 'A' (No-Industry/Special Region Districts) secured assistance of the order of Rs. 109.03 crores. 105 projects located in category 'B' districts/areas claimed assistance of the order of Rs. 187.78 crores, and, 131 projects in category 'C' districts/areas had assistance aggregating Rs. 318.11 crores. The percentage share of each category of notified backward districts, i.e., category 'A' (no-Industry/Special Region Districts), 'B' and 'C' in the total assistance sanctioned to projects in centrally notified backward districts/areas worked out 17.7%, 30.5% and 51.8% respectively.

2.49 Cumulatively, upto the 31st March, 1989, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 3,311.39 crores to 1,480 projects located in notified backward districts/areas, which constituted 50.6% of IFCI's overall net cumulative sanctions. The disbursements against these upto the 31st March, 1989 had been of the order of Rs. 2,186.44 crores.

Funding Pattern and Projects Assisted by IFCI (1988-89)

2.50 IFCI's operations in 1988-89 (July-March), according to a study made of the funding pattern of 445 projects (excluding 90 cases of sanctions of additional assistance during 1988-89 for financing purely the overrun in the cost of projects, etc.,) reveal that IFCI's assistance has been able to catalyse an investment of the order of Rs. 7,560.90 crores as per details given in Table 11.

Table 11 : Funding Pattern of Projects Assisted by IFCI 1988-89 (July–March) (Rs. crores)

Financing Pattern	New Projects	Expansion/ diversification projects	Modernisation projects	Assistance for rehabilitation, balancing equipment, etc.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of Projects	166	48	132	99	445
I. Promoters' contribution					
—Share Capital	794.88 (13.9%)	20.09 (2.8%)	43.51 (5.5%)	15.78 (4.4%)	[874.26 (11.6%)
—Unsecured subordinated loans	27.23 (0.5%)	5.56 (0.8%)	16.76 (2.1%)	16.67 (4.7%)	66.22 (0.9%)
—Internal accruals, etc.	156.00 (2.7%)	96.44 (13.7%)	145.63 (18.4%)	51.54 (14.5%)	449.61 (5.9%)
II. Assistance by term lending institutions viz., IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
—Loans & Advances	2,580.69 (45.2%)	272.10 (38.5%)	486.26 (61.3%)	229.22 (64.4%)	3,568.27 (47.2%)
—Equity Support	204.27 (3.6%)	2.10 (0.3%)	1.00 (0.1%)	0.56 (0.2%)	207.93 (2.8%)
III. Assistance by investment Institutions, viz., LIC, GIC & UTI					
Loans & Advances	226.40 (4.0%)	29.38 (4.2%)	45.29 (5.7%)	15.13 (4.3%)	316.20 (4.2%)
Equity support	48.38 (0.9%)	0.70 (0.1%)	— (—)	— (—)	49.08 (0.6%)
IV. (a) Assistance by Banks (term finance)	890.48 (15.6%)	55.71 (7.9%)	13.22 (1.7%)	22.16 (6.2%)	981.57 (13.0%)
(b) Equity support by Banks etc.	98.56 (1.7%)	12.60 (1.8%)	12.00 (1.5%)	1.65 (0.5%)	124.81 (1.7%)
V. (a) Assistance by State-level Institutions (Term Finance)	8.16 (0.1%)	1.45 (0.2%)	0.92 (0.1%)	— (—)	10.53 (0.1%)
(b) Equity Support	36.48 (0.7%)	1.20 (0.2%)	— —	0.02 (Negl.)	37.70 (0.5%)
VI. Rights Issues	332.13 (5.8%)	176.72 (25.0%)	6.65 (0.8%)	1.10 (0.3%)	516.60 (6.8%)
VII. Deferred Payments	0.26 (Negl.)	— —	0.76 (0.1%)	0.86 (0.2%)	1.88 (Negl.)
VIII. Loans from Foreign Institutions	3.39 (0.1%)	30.00 (4.2%)	— (—)	— (—)	33.39 (0.4%)
IX. Others	298.85 (5.2%)	2.03 (0.3%)	20.88 (2.7%)	1.09 (0.3%)	322.85 (4.3%)
Total:	5,706.16 (100.0%)	706.08 (100.0%)	792.88 (100.0%)	355.78 (100.0%)	7,560.90 (100.0%)

Notes: 1. Equity support includes underwriting assistance as also direct subscriptions.
2. Figures in brackets denote percentages to the total.
3 The above exclude the cases of sanction of assistance for meeting the over-run in the cost of projects, etc.

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects (1988-89)

2.51 A study of 214 new and expansion/diversification projects assisted by IFCI in 1988-89 (July-March) indicates that IFCI's assistance during the period has been able to create substantial capacities in a wide variety of industries. The aforesaid projects are expected to create direct employment for about 51,442 persons. The value of annual output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 5,348.40 crores. The gross value added is likely to be of the order of Rs. 2,491.30 crores which also accounts for the contribution of these projects to the Gross National Product (GNP) of the country. A detailed statement in this regard is annexed vide *Appendix II.*

Sanctions accorded in the Public Interest

2.52 During the period under review, there was no case where because of Director(s) of IFCI being interested in terms of Section 26(2) of the IFC Act, 1948 (as amended from time to time), IFCI had to sanction assistance in public interest in terms of Industrial Finance Corporation (Transaction of Business with Specific Industrial Concerns) Regulations, 1982.

(B) *Operational Developments*

Authorisation under IFC Act, 1948

2.53 During the period under review, the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by sub-clause (xvi) of clause (c) of Section 2 of the IFC Act, 1948, specified vide its Notification dated the 20th December, 1988, any limited company or co-operative society incorporated and registered in India, engaged or proposing to engage in 'the setting up or development of tourism related facilities including amusement parks, cultural centres, convention centres, restaurants, travel and transport (including those at Airports) tourist service agencies, and guidance and counselling services to tourists', as eligible "industrial concern" for the purpose of financial assistance from IFCI.

International Competitive Bidding (ICB) like procedure

2.54 During the period under review, it was agreed that Financial Institutions would ensure that all large-sized industrial projects involving import of plant and equipment of the value of Rs. 25 crores or more, would adopt a procedure very much akin to the International Competitive Bidding (ICB) procedure. It was further agreed that in all cases, where ICB like procedure was considered to be essential, the assisted concerns would be required to set up a Project Implementation Committee, on which the nominees of the Financial Institutions would be duly represented.

Exchange Risk Administration Scheme (ERAS)

2.55 The all-India Financial Institutions finalised during the period under review, the modalities of the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS), with a view to protecting the sub-borrowers of foreign currency loans against exchange risk through the instrumentality of a fund to be known as the Exchange Risk Administration Fund (ERAF). The benefits under the Scheme would be available from the 1st April, 1989 to all foreign currency loans contracted on or after the 1st April, 1989. Under the Scheme, the principal repayment obligation of the borrowers would be 'rupee tied' at the rate(s) of exchange prevailing on the dates of disbursement. On such 'rupee tied' loan liability, the borrower would pay by way of servicing of loans a composite cost consisting of three elements, viz., (a) the interest portion arrived at on the basis of the weighted average interest cost of the various components of the currency pool, (b) spread of the Financial Institutions, and, (c) the exchange risk premium. The composite cost would be a variable rate to be determined at six-monthly intervals with a'floor' and a 'cap'. Both the 'floor' and the 'cap' as well as the rate of interest applicable to the period shall be subject to review, from time to time, by a Committee consisting of the representatives of Financial Institutions, Reserve Bank of India (RBI) and the Government of India. The Exchange Risk Administration Fund (ERAF) would be set up in IDBI with an initial contribution of Rs. 15 crores to be made by IDBI, IFCI and ICICI equally. The exchange premium element of the composite cost would be transferred to ERAF by all the three Institutions, viz., IDBI, IFCI and ICICI on a quarterly basis.

2.56 The eligible sub-borrowers of foreign currency loans shall have the option either to join the ERAS or to stay out of ERAS. Those, who opt to stay out of ERAS, shall continue to get foreign currency loans under the existing arrangements. The Scheme shall also not apply to those borrowers who themselves are in a position to hedge their foreign exchange exposure and risks.

2.57 The composite cost, to start with, in respect of loan agreements signed during the periord from the 1st April, 1989 to the 30th June, 1989, would be 15% per annum, variable with a band having the 'floor' at 15% per annum and 'cap' at 18% per annum.

Changes in Lending Terms, etc.

2.58 Despite the cost of raising funds constantly going up, there was no change in the basic lending terms of IFCI, e.g., the rate of interest, commitment charge, and other charges, etc.

2.59 The institutional practice of *charging of additional interest* of 1% per annum over and above the applicable rate of interest in respect of closely-held and non-listed companies was, however, reviewed at the inter-institutional level, during the period under review, in terms of which it was agreed as under :

(i) Practice of exempting subsidiary and associate companies of the listed companies from the levy of the additional interest of 1% per annum over and above the applicable lending rate of interest was given up.

(ii) The policy of exempting companies whose shares were not listed as a result of institutional holdings in the companies being 51% or more or the Government(s) and Government agencies holding the entire or majority of shareholdings was dispensed with. However, where the Institutions themselves had taken a decision to directly subscribe to the share capital in medium-sized companies with a view to avoiding them the expenses on public issue, no additional interest of 1% per annum over and above the applicable lending rate of interest was made chargeable.

2.60 In respect of *convertibility guidelines,* while no new instructions were issued by the Government, the Financial Institutions agreed as under with regard to the applicability of conversion guidelines :

(i) Foreign exchange assistance under Technology Upgradation Scheme (TUS) exempted from convertibility guidelines, was also not to be included for the purpose of computation of aggregate assistance for determining the applicability of the convertibility clause.

(ii) Since subscriptions to rights debentures by the Financial Institutions consequent upon offer of rights made by the companies, could not be construed as assistance, rights debentures subscribed by Institutions or debentures subscribed by Investment Institutions by way of rights arising out of market purchase of shares were neither to be taken into account for aggregate assistance nor were to be made subject to conversion stipulation.

2.61 In respect of sanctions accorded during the period under review, convertibility clause was stipulated as per extant guidelines in 119 cases. The convertibility right was exercised duriug the period under review in 5 cases and waived in 30 cases. Cumulatively, since the introduction of convertibility guidelines, IFCI had stipulated the convertibility clause in 1,402 cases, exercised the convertibility option in 126 cases and waived the same after taking into account all the relevant factors in 514 cases.

Streamlining of Existing Procedures

2.62 The existing procedures, whether relating to appraisal, documentation, or follow-up, continued to be streamlined by removing redundancy, wherever possible. It was agreed that Financial Institutions would discontinue the practice of stipuation of pledge of shares by the promoters in their favour as a condition for grant of bridging loans against public issue of shares. It was also agreed that Institutions could allow the promoter companies/promoters to pledge with banks the shares covered by non-disposal undertakings, subject to the condition that the voting rights governing shares would be with the banks and those rights would be exercised in consulation with the Institutions. The lead

Financial Institution was authorised to accord post-sanction approvals on behalf of Investment Institutions as debenture holders, subject to the compliance with the requirement of assets coverage ratio of 1.5:1 by the assisted companies.

Follow-up Mechanism

2.63 There was no change in the basic components of the follow-up mechanism, which consisted of (a) obtaining monthly production reports which the assisted concerns are required to submit to the concerned statutory/administrative/regulatory authorities, (b) obtaining of periodical progress reports and copies of statements submitted by concerns to their bankers, etc., (c) calling of half-yearly/yearly statement of accounts, working results and financial position, (d) carrying out periodical site visits with a view to verifying the end-use of assistance and evaluating the performance of assisted concerns vis-a-vis their operational plans, (e) having snap visits at factory sites or calling promoters/senior executives for having discussions on related issues, (f) insisting upon a need-based Management Information System (MIS), and, (g) having reports from nominee directors/concurrent auditors/consultants, wherever appointed. During the year, the follow-up measures were intensified in lead cases and the fora of the 'Regional Executives' Meetings' (REMs) was effectively used for discussing the problems of other concerns assisted on consortium financing basis.

2.64 As on the 31st March, 1989, IFCI had appointed 348 nominee directors on the Board of Directors of 793 assisted concerns, of which 152 were officials and 196 were non-officials.

2.65 To make the *institution of nominee directors* more effective, all the assisted concerns were advised to send notices for convening Board/Committee Meetings and agenda papers to nominees well in advance and for holding the Board meetings at least once in two months. IFCI also continued to make half-yearly reviews of the system of nominee directors and its functioning at the level of Board of Directors as well.

2.66 With a view to invigorating the functioning of the nominee directors as also for improving the monitoring and control mechanism for overseeing the affirs of the assisted concerns, IFCI organised a "Workshop for the benefit of Nominee Directors (Northern Region)" on the 21st January, 1989 at Vigyan Bhavan, New Delhi. The Workshop was attended by about 120 nominee directors representing non-official nominees of IFCI, IDBI and ICICI as also the officials of the all-India Financial Institutions. The discussions in the Workshop centred around certain vital issues like, Role and Responsibilities of Nominee Directors, Legal Obligations and Liabilities of Directors, Institution of Nominee Directors and Observance of Financial Discipline, Role of Audit Sub-Committees, Expectations and Experiences of Nominee Directors, etc. The Workshop was inaugurated by Sri Ashok Chandra, then Additional Secretary, in the Department of Company Affairs (now Secretary, Ministry for Food Processing).

Amendments to the Rules and General Regulations

2.67 During the year under review, as stated earlier, the Government amended Industrial Finance Corporation Rules, 1965, providing for closing of the business year of IFCI as on the 31st March in place of the 30th June. As a sequel to the above, certain consequential amendments were made to IFCI General Regulations, 1982 so as to bring the various provisions in conformity with the new accounting year of IFCI on April-March basis.

Co-ordination between Banks and Financial Institutions

2.68 Greater co-ordination now exists between Financial Institutions and banks, at the stages of project appraisal, documentation, follow-up, etc., of assisted concerns with the deepening of lead institution concept. There is timely stress on sanction of working capital facilities and release of funds for meeting need-based requirements as also financing the cost overrun in projects. A system has also been developed, whereby regular information is being exchanged between the Financial Institutions and banks with regard to the affairs of the projects. Wherever a Project implementation Committee has been constituted by the lead Financial Institution to monitor the progress of a new project, a representative of the lead bank is also being associated with such Committees.

Industry Viability/Market Studies

2.69 Financial Institutions are expected to encourage the establishment of new units in industries where there is scope for further creation of capacity having regard to the demand and supply position, due weightage being given in this regard to Plan priorities and objectives. Financial Institutions are also expected to encourage expansion or diversification of units to economically viable levels, consistent with the norms of efficiency and productivity. In the light of these parameters, the Institutions have been making their own assessment from the view point of viability/market of various industries, from time to time, so that strategies for financing new units or supportiny expansion and diversification programmes of the existing units in related areas could be evolved.

2.70 During the nine months' period ended the 31st March 1989, the Institutions undertook several market evaluation studies on various industrial products like flourescent tube lamps, sheet glass, breakfast cereals, video-magnetic tapes, rectifiers diodes, acrylic staple fibre, polymer concrete/resin bonded marble/agglomerated marble, PVC window and door profiles, aluminium extrusions, polyester filament yard, seamless tubes, electrolytic capacitors, red mud corrugated sheets, hard gelatine capsules, etc. Some of the aforesaid studies were carried out by the Institutions, with IFCI in the lead.

Interface with Government

2.71 IFCI continued to have interface with all the concerned Departments of the Government, the Planning Commission, and also with all important Committees/Working Groups constituted by RBI, IDBI, etc., from time to time. IFCI was also involved with all matters relating the the modernisation and development of sugar, textiles, jute, tourism and tourism related activities. While IFCI continued to act as nodal agency for Jute Modernisation Fund Scheme and agent of Government for disbursement of assistance for modernisation of sugar industry under the Sugar Development Fund, during the course of the period under review, IFCI was also declared as the nodal agency for tourism and tourism related activities.

2.72 *Currently*, IFCI has also been involved with the formulation of the priorities for industrial development during the Eighth Plan period. IFCI is also represented on some of the Committees constituted by the Government for determining the economic capacities for various industries as also on the National Finance and Credit Council.

(C) *RESOURCES*

Resource Mobilisation and Financial Management

2.73 During the nine months' period ended the 31st March, 1989, the total resource mobilisation by IFCI was of Rs. 846.33 crores (excluding its opening cash balance of Rs. 193.38 crores). Major highlights on the resources front during the period under report, were as under :

— Issue of additional share capital to the extent of Rs. 12.50 crores made on the 2nd March, 1989.

— Internal generations leading to the accretion of reserves of IFCI by Rs. 45.32 crores.

— Augmentation of rupee resources by two public issue of bonds (51st and 52nd series made on the 13th December, 1988 and 28th February, 1989) to the extent of Rs. 248.02 crores.

— Increased receipts on account of (a) repayment of loans by the borrowers, and (b) sale/redemption of investments, aggregating Rs. 116.94 crores.

— Substantial step up in mobilisation of foreign currency resources by contracting (a) a loan of US $ 100 million through Swiss Bank Corporation Investment Banking Ltd. (SBCI) in two Tranches of US $ 50 million each,

the second Tranches of US $ 50 million, convertible after two years in Swiss Francs at the option of the Arranger, i.e., SBCI, (b) FIM 30 million in two Tranches—Tranche (1) for FIM 20 million meant for Indo-Finnish joint ventures and tranche (2) for FIM 10 million for other projects out of Finnish Fund through the Industrial Development Co-operation Ltd., Helsinki, Finland, (c) Japanese Yen 20 billion with interest swap in US$ from a syndicate of foreign banks with Security Pacific Hoare Govett Asia Ltd., acting as agent; the interest swap having been arranged through Merrill Lynch Capital Services Inc.

2.74 No loans were raised either from the Industrial Development Bank of India (IDBI) or from the Central Government, during the period under report. However, Rs. 4.20 crores and Rs. 0.44 crores were repaid to IDBI and the Central Government respectively, during the period, with the result that net outstanding borrowings from IDBI and Central Government came down from Rs. 61.85 crores and Rs. 1.40 crores to Rs. 57.65 crores and Rs. 0.96 crores respectively as on the 31st March, 1989.

2.75 Insofar as the loans portion under the Interest Differential Funds is concerned, during the period under report, a sum of Rs. 2.28 crores was obtained from the Central Government and a sum of Rs. 0.51 crore was repaid on this account. Thus, the total loans portion of IDFs repayable to the Central Government aggregated Rs. 9.25 crores as on the 31st March, 1989 as against Rs. 7.48 crores as on the 30th June, 1988.

2.76 With regard to the foreign currency resources as at the close of March, 1989, IFCI was actively involved in negotiating a credit line of US$ 100/150 million from the Asian Development Bank (ADB).

2.77. As at the 31st March, 1989, the overall resources of IFCI consisted of (a) its paid up capital (Rs. 82.50 crores), (b) reserves (Rs. 270.94 crores), (c) rupee borrowings by way of public issue of bonds net of the amount redeemed upto the 31st March, 1989 (Rs. 2314.70 crores), (d) other rupee borrowing (Rs. 67.85 crores), (e) borrowing from Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of Federal Republic of Germany against 25 Lines of DM Credit (DM 408 million), (f) cumulative commercial borrowings in foreign currencies raised from the international capital market of the order of US$ 320 million, Japanese Yen 40 billion and DM 15 million and credit line from Finnish Fund through Industrial Development Co-operation Ltd., Finland of the order of FIM 30 million.

Sources and Uses of Funds

2.78 The total resources raised by IFCI during 1988-89 (excluding opening cash balance of Rs. 193.38 crores) aggregated Rs. 846.33 crores. This comprised (a) increase in paid-up share capital to the extent of Rs. 12.50 crores, (b) generation of profit before tax of Rs. 60.55 crores, (c) recoveries of loans from borrowers and sale of investment, etc. to the extent of Rs. 116.94 crores, (d) borrowing from market by way of bonds (Rs. 248.02 crores) and (e) borrowings in foreign currency equivalent to Rs. 399.09 crores and the receipt of Rs. 9.23 crores under Interest Differential Funds from Government. These resources were utilised for effecting cash disbursement assistance (Rs. 734.19 crores), redemption of bonds (Rs. 35.02 crores), repayment of rupee and foreign currency borrowings (Rs. 72.85 crores), payment of dividend (Rs. 7.21 crores) and tax (Rs. 110.02 and other uses (Rs. 39.49 crores). The cash balance as at the close was Rs. 140.93 crores.

Outstandings and Overdues

2.79 As at the end of 31st March, 1989, loan assistance of Rs. 3,373.15 crore was outstanding from 2,150 concerns. The holdings of IFCI in shares and debentures of assisted companies were of the order of Rs. 111.75 crores and guarantees for an aggregate amount of Rs. 32.51 crores were in force.

2.80 Against the outstanding loan assistance as on the 31st March, 1989, the total overdues (comprising principal Rs. 81.25 crores and interest Rs. 44.96 crores) aggregated Rs. 126.21 crores. These overdues formed about 3.7% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 31st March, 1989.

2.81 The recovery ratio against dues during the period under report stood at 87.9% (88.5% in respect of interest and 86.8% in respect of principal), which was at the same level as that for the previous year 1987-88.

2.82 In the case of units facing long term problems, joint meetings of all the participating institutions/banks involved in the financing of the projects were held for arriving at a consensus for evolving possible rehabilitation/revival packages. Regional and Branch Offices were actively involved in the matter of recovery drive and achieveing the recovery targets.

Rehabilitation Programmes

2.83 The efforts of IFCI towards rehabilitation of sick units were dovetailed with those of Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) under Sick Industrial Companies. (Special Provisions) Act, 1985, which had been in operation for the last two years.

2.84 During the nine months' period ended the 31st March, 1989, 63 BIFR hearings were held in respect of 46 IFCI lead cases. IFCI was appointed as the Operating Agency in respect of 20 cases (including 33 non-lead cases) for detailed viability studies and formulation of rehabilitation programmes in the light of specific guidelines set by BIFR in each case. Of these, IFCI, as Operating Agency submitted its draft rehabilitation scheme in respect of 11 cases for further consideration of BIFR. In addition, though not in the role of Operating Agency, IFCI carried out viability studies and/or worked out rehabilitation programmes in four lead cases under the aegis of BIFR. The expertise of IFCI was also made available to BIFR in scrutinising/reshaping the schemes for revival of certain non-assisted sick units.

2.85 Formulation and designing of rehabilitation packages was done in the background of RBI Guidelines in respect of cases not falling under the purview of BIFR. In six of such cases, rehabilitation schemes were formulated during the course of the year. Rehabilitation measures recommended/contemplated covered a wide spectrum, comprising, *inter alia*, modernisation, expansion, diversification, etc., of sick units. In four cases, one-time arrangement was reached for settlement of outstanding dues, besides arriving at settlement with the guarantors in one case. In one IFCI lead case, loan was recalled and legal steps were initiated for recovery of dues during the course of the period. IFCI also continued to be closely involved with rehabilitation efforts made by other Financial Institutions in respect of their lead cases.

2.86 In the light of the experience gained, the all-India Financial Institutions formulated, during the period under review, their internal guidelines in regard to reliefs/concessions that could be extended to such units for their revival.

2.87 The period under report witnessed turn-around of a few units which were under nursing programme of IFCI. In addition, certain proposals for merger/take-over were also under consideration of the Institutions as at the end of March, 1989.

(D) *WORKING RESULTS*

Profit

2.88 From the audited accounts comprising Profit & Loss Account for the period of nine months and the Balance Sheet as at the 31st March, 1989, which are annexed to this Report, it would be observed that the pre-tax profit of IFCI for the period amounted to Rs. 60.55 crores as against Rs. 68.88 crores for the year 1987-88 (July-June) which shows an increase of 17.2% compared with the profit for the corresponding period in the previous year on annualised basis. The net profit for the period of nine months under report, after providing Rs. 10.02 crores for taxation, amounted to Rs. 50.53 crores as against Rs. 52.66 crores for 1987-88. This was 28% higher than the previous year's net profit for the corresponding period in the previous year on annualised basis.

Appropriations

2.89 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in Table 12.

Accretions to the Reserves

2.90 During the nine months' period ended the 31st March, 1989, IFCI was able to transfer to its reserves a sum Rs. 42.82 crores comprising General Reserve Fund, Benevolent Reserve Fund and Special Reserve Fund.

Dividend

2.91 In view of the satisfatory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 13% per annum as against 12% per annum declared last year.

Table 12 : Appropriations of Net Profit (Rs. Crores)

	This year (1988-89) (July-March)	Previous year (1987-88) (July-June)
(1)	(2)	(3)
Net Profit for the nine months	50·53	52·66
Appropriations		
Transferred to—		
(a) General Reserve Fund	27·53	17·93
(b) Benevolent Reserve Fund	1·00	2·00
(c) Special Reserve (under section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)	14·29	25·01
Allocation to the Staff Welfare Fund	0·50	0·25
Payment of Dividend (13% p.a.)	7·21	7·47
Total:	50·53	52·65

Working Results Trends

2.92 The working results of IFCI for five years inclusive of the period of nine months ended the 31st March 1989, are summarised in Table 13.

2.93 It would be observed from the above that based on the data for the nine months' period in the previous year on annualised basis—

— Interest Income from lending operations increased by 29.8% in 1988-89 (July-March).

Table 13: Working Results of IFCI for Five Years (Rs. Crores)

Particulars	Year ended the 30th June				Nine months periodended the 31st March
	1985 Rs.	1986 Rs.	1987 Rs.	1988 Rs.	1989 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest on lending	129·78	167·74	225·48	285·30	277·77
Less: Cost of Borrowing.	85·62	119·92	160·78	212·10	213·62
Net Interest Revenue	44·16	47·82	64·70	73·20	64·15
Other Income	5·22	9·40	8·00	9·36	11·26
Net Income	49·38	57·22	72·70	82·56	75·41
Expenditure:					
Personnel Expenses	4·44	4·85	6·55	6·12	5·02
Loss on Investments	0 19	0·37	0·18	0·02	0·31
Directors' and Committee Members' Feeders & Expenses	0·03	0·02	0·03	0 03	0·02
Other Expenses & Grants	2·29	2 67	3·14	4 51	3.70
Depreciation	0·34	0·50	1 18	3·00	5·81
Pre-tax profit	42·09	48 81	61 62	68·88	60 55
Taxation	12·78	14·63	18·14	16 22	10·02
Net profit	29·31	34 18	43·48	52·66	50·53
(Dividend Rate)	9·0%	10 0%	11·0%	12·0%	13 0%

— Increase in the 'Cost of Borrowings' was 34.3% in 1988-89 (July-March).

— Increase in the 'Net Income', 'Pre-tax Profit' and 'Net Profit' was 21.8%, 17.2% and 28% respectively.

— Cost of Borrowings which formed 74.3% of the 'Interest Income on Lendings' in 1987-88 was 76.9% in 1988-89 (July-March).

— Pre-tax Profit as percentage to Net Income was 80.3% in 1988-89 (July-March).

— Net Profit as percentage of Net Income was 67% in 1988-89 (July-March) as against 63.8% last year.

Financial Position

2.94 The financial position, as evidenced by the Balance Sheets of IFCI for the five years inclusive of the position of assets and liabilities as on the 31st March, 1989, is indicated in Table 14.

Table 14 : Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years (Rs. Crores)

Particulars	Year ended 30th June				As at the 31st March
	1985 Rs.	1986 Rs.	1987 Rs.	1988 Rs.	1989 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASSETS					
Cash & Bank Balance	142·13	208·88	137·00	193·38	140·93
Investments					
In Assisted Concerns	57·16	58·68	72·83	96·53	111·75
In other Institutions	0·21	0·21	2·81	6·50	20·10
Loans to Assisted concerns	1,307·31	1,649·11	2,117·10	2,733·21	3,372·53
Fixed & Other Assets	65·68	93·25	132·73	221·45	309·61
Customers, Liabilities for Acceptances	7·87	17·88	21·93	22·92	32·51
	1,580·36	2,028·01	2,484·40	3,273·99	3,987·43
LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S FUNDS					
Share Capital	35·00	45·00	57·50	70·00	82·50
Reserve & Reserves fund	114·32	144·88	182·17	225·62	270·94
Borrowings					
(a) Bonds	1,107·00	1,452·88	1,729·40	2,083·80	2,314·70
(b) From Govt. & IDBI	130·73	87·13	79·30	70·73	67·85
(c) In Foreign Currencies	88·22	163·25	285·78	611·15	988·60
Current Liabilities & Provisions	92·36	110·74	120·29	179·87	216·88
Earmarked Funds	4·86	6·25	8·03	9·90	13·45
Liability for Acceptances	7·87	17·88	21·93	22·92	32·51
	1,580·36	2,028·01	2,484·40	3,273·99	3,987·43
Debt:Equity	8·9:1	8·9:1	8·7:1	9·3:1	9·5:1
Net worth-Net profit	5·1:1	5·6:1	5·5:1	5·6:1	7·0:1

Audit Report

2.95 During the period under review, M/s. Gupta & Co., Chartered Accountants, Calcutta were appointed as Statutory Auditors by Industrial Development Bank of India (IDBI) in terms of Section 34(1) of the IFC Act, 1948 M/s. T. R. Chaddha & Co., Chartered Accountants, New Delhi, continued as the Auditors elected by the shareholders of IFCI (other than IDBI). The Report of the uditors in terms of Section 34(3) of the IFC Act, 1948 for the period of nine months ended the 31st March, 1989, is also given with the Accounts for the period in this Report. M/s. Thakur Vaidyanath Aiyer & Co., Chartered Accountants, New Delhi, were the Tax Auditors of IFCI for conducting its tax audit in terms of Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 for the period ended the 31st March, 1989.

CHAPTER 3

PROMOTIONAL SERVICES

Promotional Services—A Review

3.01 In its promotional and developmental role, it has been the endeavour of IFCI to identify the gaps in the institutional infrastructure, or extension services, and, to provide, as well as, stimulate the provision of non-financial inputs to the extent possible, consistent with its resources and capability. The philosophy that permeates IFCI's promotional services is to help and encourage the small and medium scale enterpreneurs and/or enterprises with such

supportive measures as can provide them 'growth' and 'stability'.

3.02 Some of the promotional services being rendered by IFCI are—

— Support to Village & Small Industries (VSI) sector through specially designed Promotional Schemes.

— Support for Consultancy Services through the instrumentality of Technical Consultancy Organisations (TCOs) set up all over the country.

— Support for entrepreneurship development through funding of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) and assisting specialist institutions set up for the purpose at the apex and State-level.

— Support for professionalisation of management and upgradation of managerial skills.

— Support for risk capital, venture capital and technology finance to technology-oriented projects.

— Support for financing tourism and tourism related activities, facilities and services.

— Support for development of securities market and investor protection.

— Support for Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs).

— Support for research in various disciplines and research-oriented activities.

3.03 During the nine months' period under report, the total amount utilised by IFCI in providing various promotional services was Rs. 572.93 lakhs which was higher by 41.4% over the utilisation in the corresponding period in the previous year on annualised basis. Cumulatively upto the 31st March 1989, IFCI had utilised Rs. 3,262.51 lakhs towards its various promotional services. Table 15 and 16 give the break-up of the amount utilised by IFCI on its promotional services and the sources through which the same had been funded.

Table 15 : Amount Utilised by IFCI on Promotional Services (Rs. Lakhs)

Nature of Services supported by IFCI	1988-89 (July-March) Amount Rs.		Cumulatively upto 31st March,1989 Amount Rs.	
(1)	(2)		(3)	
(i) Promotional Schemes				
Subsidy	35·00		306·76	
Loan assistance	—	35·00	23·50	330·26
(ii) Industrial Potential Surveys for development of backward areas including No-Industry districts		0·04		9 63
(iii) Support for Technical Consultancy Services				
Technical Consultancy Organisations	6·22		68·75	
Directory of Industrial Consultants	—	6·22	0·43	69·18
(iv) Support for Entrepreneurship Development				
Sharing of EDP costs	8·71		55·70	
Resources support to EDII	8·75		93·00	
Resources support to IFDs	2·81	20·27	15·06	163·76
(v) Support for Management Development activities of MDI		48·25		845·24
(vi) Support for Risk Capital Assistance through RCTC		325·31		1,575·23
(vii) Support for Securities and Exchange Board of India		125·00		125·00
(viii) Support to Science and Technology Entrepreneurs, Parks (STEPs)		—		15·91
(ix) Promotion of Research, etc.				
IFCI Chairs	1·79		29·15	
Special Research Studies	—		10·63	
Support to Indian Economic Journal	0 05	1·84	0 15	39·93
(x) Support for International Conferences and Seminars				
International Exposition of Rural Development (IERD)	—		1·00	
Research & Information Systems for Non-aligned & other Developing Countries	3·00		11·00	
World Economic Congress	—		4 00	
Indian Econometric Society	—	3 00	0 50	16 50
(xi) Support to special organisations				
New Hope Rural Leprory Trust, Muniguda, Orissa, for Deep Well project	—		0·21	
Centre for Multi-Disciplinary Development Research (CMDR) Dharwar (Karnataka)	5 00		5 00	
Policy Group (A non-profit Research organisation) at New Delhi	3 00	8 00	3·00	8·21
(xii) Orientation Programmes and Assistance to State-level Institutions		—		4·30
(xiii) Others				
(Utilised for direct financing of projects)		—		59·36
Total:		572 93		3,262·51

Table 16: Sources of Funds for IFCI's Promotional Services (Rs. Lakhs)

Fund	1988-89 (July-March) Amount Rs.	Cumulatively upto 31st March, 1989 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
Benevolent Reserve Fund (Created out of Profits of IFCI under Section 32B of IFC Act, 1948)	160·73	829·80
Interest Differential Funds (Representing monies received from the Government of India out of interest Paid by IFCI on KFW loans in terms of agreements amongst IFCI, Kreditansalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and Government of Federal Republic of Germany)	412·20	2,432·71
Total	572·93	3,262·51

Promotional Schemes

3.04 During the period under review, IFCI introduced two new Promotional Schemes as under :

— Scheme for Encouraging Entrepreneurship Development in Tourism and Tourism-related Activities.

— Scheme for Encouraging Self-Employment amongst Persons Rendered jobless due to Retrenchment or Rationalisation in Sick Industrial Units in the Organised Sector Undergoing a Process of Rehabilitation/ Revival.

To begin with, the first scheme was made applicable to the State of Goa and the second scheme was introduced, on an experimental basis, in the State of Madhya Pradesh only. Further, some of the existing Promotional Schemes were liberalised, largely, with a view to bringing uniformity in the approach, and, in the quantum of subsidy admissible under the Schemes.

3.05 The present position is that IFCI has fourteen Promotional Schemes, of which eight are consultancy fee subsidy schemes, four interest subsidy schemes and two entrepreneurship development schemes, as per details given below :

Consultancy Fee Subsidy Schemes

— Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for Meeting Cost of Feasibility Studies, etc.

— Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries relating to Animal Husbandry, Dairy Farming, Poultry Farming and Fishing.

— Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries based on or related to Agriculture, Horticulture, Sericulture and Pisciculture.

— Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries.

— Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting Cost of Market Research/Surveys

— Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units.

— Scheme of Subsidy for Consultancy on Use of Non-Conventional Sources of Energy and Energy Conservation Measures.

— Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Village nd Small Industries Sector.

Interest Subsidy Schemes

— Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons.

— Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs.

— Scheme of Interest Subsidy for Encouraging Quality Control Measures in Small Scale Sector.

— Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology.

Entrepreneurship Development Schemes

— Scheme for Encouraging Entrepreneurship Development in Tourism and Tourism-related Activities.

— Scheme for Encouraging Self-Employment amongst Persons Rendered Jobless due to Retrenchment or Rationalisation in a Sick Industrial Unit in the Organised Sector Undergoing a Process of Rehabilitation/Revival.

3.06 The Consultancy Fee Subsidy Schemes are aimed at providing subsidised consultancy services to industrial units, largely in Village and Small Industies (VSI) sector through Technical Consultancy Organisations (TCOs). The Interest Subsidy Shemes are intended to provide encouragement to self-development and self-employment to unemployed youths, women entrepreneurs, adoption of quality control measures, harnessing the indigenously available technology, etc. The Entrepreneurship Development Schemes envisage giving impetus to self-employment in tourism related activities in the small scale sector, and help in mitigating the sufferings of people, who have to face retrenchment due to implementation of modernisation, rehabilitation and revival plans in the case of potentially viable sick units, by a process of re-training or self-employment avenues.

Assistance by way of Subsidy and Loans Granted under Promotional Schemes

3.07 In nine months' period under report, IFCI disbursed under its Promotionl Schemes, subsidy amounting to Rs. 35 lakhs benefiting 1,224 projects, mostly in the village and small scale industries (including ancillary) sector. Table 17 gives the details of the subsidy disbursements made by IFCI under its various Promotional Schemes during the period of nine months under report and cumulatively upto the 31st March, 1989.

Table 17: Subsidy Disbursed by IFCI under its various Promotional Schemes (Rs. lakhs)

Names of the Promotional Schemes	1988-89 (July-March) Amount Rs.	Cumulatively upto 31st March, 1989 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny and Small Scale Sectors for Meeting Cost of Feasibility Studies etc.	23.40	207.61
Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Relating to Animal Husbandry Dairy Farming Poultry Farming & Fishing etc.	0.65	0.65
Scheme of Subsidy for Consultancy to Industries Based on or Related to Agriculture, Horticulture, Sericulture and Pisciculture etc.	1.64	1.64
Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Industries.	0.14	16.95
Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for Meeting Cost of Market Research/Surveys	3.07	12.60
Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Village and Small Industries Sector	0.15	0.15
Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units.	0.29	0.73
Scheme of Subsidy for revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors	2.87	13.59
Schemes of Subsidy for implementing the Modernisation Programme of Tiny, Small Scale and Ancillary Units	1.71	4.75
Scheme of Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons	0.10	0.42
Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs	0.98	2.32
Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology	--	45.35
Scheme of Assistance for Development of Technology through In-House R&D Efforts	--	23.50
Total:	35.00	330.26

Support for Technical Consultancy Services

(A) *Technical Consultancy Organisations*

3.08 Technical Consultancy Organisations (TCOs), sponsored by the all-India Financial Institutions, including IFCI, constitute an important instrumentality in providing promotional services on behalf of the sponsoring institutions. Presently, 18 TCOs—9 under the lead of IDBI, 5 under the lead of IFCI and 3 under the lead of ICICI and one sponsored by Government of Karnataka—are providing a wide spectrum of consultancy and extension services in enterprise setting, particularly in the rural, tiny, small and medium scale industrial sectors. These TCOs together, during nine months' period under report, had executed 2,985 assignments, and cumulative 30,415 assignments upto the 31st March, 1989 as per details given in Table 18.

Table 18: Summary of Operations of all Technical Consultancy Organisations (TCOs)

Nature of assignments	No of assignments completed: 1988-89 (July-March)	No of assignments completed: Since inception of each TCO and up to the 31st March, 1989
(1)	(2)	(3)
I. Pre-investment Consultancy Assignments		
- Feasibility, Pre-feasibility Studies/Project Reports, etc.	1,691	13,953
Industrial Potential/Area Development Surveys	19	484
- Market Surveys	62	611
- Project Profiles	551	8,701
- Preliminary Fact-Finding Studies	26	121
- Appraisal	23	1,029
Others	243	2,130
Sub-total (i)	2,615	27,029
II. Post-investment Consultancy Assignments		
- Diagnostic Studies	79	925
- Rehabilitation of Sick Units	42	484
Others	83	987
Sub-total (II)	204	2,396
III. Turnkey Assignments/Functional Industrial Complexes, etc.	3	63
IV. Entrepreneurship Development Programmes	163	927
Grand Total (I+II+III+IV)	2,985	30,415

3.09 IFCI's emphasis during the year continued to be on (a) improving the qualitative aspects of TCOs' services, (b) identification of thrust areas for diversification of their business-mix, (c) building up a nexus between training and placement in Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) where conducted by them, and, (d) providing consultancy support to industries, particularly in the Village and Small Industries (VSI) sector. The consultancy fee subsidy schemes of IFCI under its Promotional Schemes also helped in maintaining as well as creating desired thrust in those areas in which consultancy services, particularly for the VSI sector, were considered to be most desirable.

(B) Directory of Industrial Consultants

3.10 The all-India Financial Institutions under IDBI's lead continued to maintain a panel of industrial and technical consultants and list them in a Directory of Industrial Consultants.

During the period, 69 new consultants were empanelled and enlistment in additional areas was granted to 10 consultants already empanelled. With this, the total number of consultants empanelled by the Institutions upto the 31st March, 1989, stood at 817.

Support for the Development of Entrepreneurship

3.11 Institutions have recognised that mere availability of finance, raw materials and other infrastructure facilities can not make a perceptible impact, unless the human resources are re-oriented towards self-development and self-employment. The objective is being sought to be achieved by giving appropriate thrust and funds support to entrepreneurship development movement by IFCI in collaboration with other participating institutions.

3.12 During the nine months' period under report, IFCI alongwith IDBI and ICICI, supported 276 Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) which included 64 EDPs for Science & Technology (S&T) entrepreneurs. The EDP conducting agencies included the Technical consultancy Organisations (TCOs), sponsored by the all-India Financial Institutions, the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), the State-level Institute of Entrepreneurship Development (IEDs) the entrepreneurship and Management Development Organisations, the Regional Engineering Colleges, the Technology Institutes and various other technology-oriented organisations. With this, upto the end of March, 1989, IFCI, alongwith IDBI and ICICI, had provided/agreed to provide funds support to 1,206 EDPs benefiting 24,880 potential entrepreneurs.

3.13 The funds support provided by IFCI towards sharing of EDPs cost upto the 31st March, 1989, aggregated Rs. 59.70 lakhs, of which a sum of Rs. 8.71 lakhs related to nine months period under report.

Support to Institutional Infrastructure for Entrepreneurship Development

3.14 In the area of creation of institutional infrastructure for entrepreneurship development, the first step of all-India Financial Institutions including IFCI was the establishment of Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) in March, 1983, at Ahmedabad as a resource organisation at the national level. The Central Government also established in 1983 the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) at New Delhi, with the objective of co-ordinating activities related to entrepreneurship and small business development. Both these organisations are working hand in hand for giving a fillip to the entrepreneurship development movement.

3.15 For institutionalising the entrepreneurship development activities at the State-level, Institutes of Entrepreneurship Development (IEDs) in Uttar Pradesh, Bihar and Orissa have already come into existence with the support of all-India Financial Institutions, concerned State Governments and Banks, and are carrying on their activities on a full-fledged basis. During the period under review, a Centre for Entrepreneurship Development (CED) was registered in Madhya Pradesh on the 17th November, 1988, the lead responsibility for which has now been taken by IFCI. An Institute for Entrepreneurship Development has also been agreed to be set up at Goa under the lead of IDBI on the same pattern as adopted in case of other IEDs. A proposal to set up an IED for North-Eastern Region is also under consideration of the North Eastern Council. A few State Governments like Government of Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan, etc., have also expressed the desire to set up Centre for Entrepreneurship Development in their respective States. The proposals of these State Governments are likely to be considered on their merits by the Financial Institutions in due course.

3.16 IFCI upto the end of March, 1989 had provided resource support to EDII of the order of Rs. 93 lakhs, of which a sum of Rs. 8.75 lakhs was made available in 1988-89. The resource support to State-level IEDs upto the end of March, 1989 had been of the order of Rs. 15.06 lakhs, of which Rs. 2.81 lakhs was provided during the period under review. This apart, in the case of IEDUP, IFCI had also agreed to contribute by way of grant a sum of Rs. 54.50 lakhs towards the campus construction and creation of a corpus fund, over and above the grant for capital budget and recurring expenditure agreed to be met by the Institutions together on an agreed basis upto a period of five years since inception. IFCI has also agreed to participate on sharing basis in the establishment of other State-level Institutes/Centres for Entrepreneurship Development, particularly, where these are being sponsored by the Financial Institutions in comparatively less developed States.

3.17 While the focus of the national level organisations like EDII, NIESBUD, etc., continued to be on (a) institutionalising entrepreneurship activities, (b) generating, sharpening and sharing knowledge through research documentation and publication, (c) creating and developing a cadre of professionals in the body of knowledge, which can now be rightly called as discipline of 'entrepreneurship', (d) sensitising and improving environment for entrepreneurship to emerge and flourish, and (e) developing new products, market segments for carrying the entrepreneurship development movement in priority areas and sections of the people, the State-level Institutes/Centres for Entrepreneurship Development endeavoured to carry out Entrepreneurship Development Programmes at the grass-root level and to provide the human resources support to various State and district level organisations engaged in the entrepreneurship development work. The State-level organisations also continued to provide industrial extension motivation services, business opportunities guidance, project counselling, etc., and helped in initiating entrepreneurisation at school level in the career planning of the youths of the country. In fulfilment of their support and sustaining role, these organisations conducted, during the period under review, a number of workshops, seminars, conferences and brought out publications, based on research, and, as aids for training of entrepreneurs. The organisations also produced a number of video films as audio-visual aids for training the entrepreneurs and motivating them towards enterprise setting and operating the same on sound and healthier lines.

Support for Professionalisation of Management and Upgradation of Management Skills

3.18 For developing and improving the quality of day-to-day management, which so crucial for the success of any industrial venture, as also, with a view to encouraging professionalisation in management, IFCI, sponsored in 1973, the Management Development Institute (MDI) at Gurgaon (Haryana) near Delhi. MDI is now a cornucopia of management training, research and consultancy, its prime goal being to improve managerial effectiveness in 'Industry', 'Government' and 'Banking' sectors of the economy. Research studies undertaken by MDI are in both macro areas of economic and industrial development as also in micro areas relevant to a specific industry or economic activity.

3.19 A mention was made in the last year's Annual Report about MDI having been chosen by the Government of India, Department of Personnel and Training as an agency for conducting the first ever intensive 15 months National Management Programme (NMP) for Government Officers belonging to IAS/Group 'A' Services as well as executives from public and private sector organisations having potential to acquire top positions. During the period under review the first NMP was started with effect from the 1st July 1988 in co-operation with the Indian

Institutes of Management at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and Lucknow and Xavier Labour Relations Institute (XLRI), Jamshedpur.

3.20 During the calendar year 1988 and, thereafter, during three months' period ended the 31st March, 1989, MDI had conducted 103 Management Development Programmes in various disciplines from which a total of 1,857 participants had benefited. These programmes included, *inter-alia* programmes for officers of Indian Economic Service (IES), Indian Administrative Service (IAS) and for the executives of a number of public sector, undertakings, like Oil & Natural Gas Commission (ONGC), Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL), Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO), Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC), Bureau of Indian Standards (BIS), Hindustan Zinc Ltd. (HZL), Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT), Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (IDPL), Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd. (UPSIDC), Madhya Pradesh Financial Corporation (MPFC), etc.

3.21 MDI also conducted in Karnataka a programme on 'Identification, Promotion and Implementation of Industrial Projects' (IPIIP) specially catering to the needs of officers of District Industries Centres (DICs) and State-level Promotional and Financial Institutions and Commercial Banks, etc. In addition, a number of programmes, particularly, in the area of strategic planning, marketing of new products, strengthening of co-operative short-term credit system, marketing and sales, management consultancy, development banking, labour-management relations, human resources development, small industries financing, performance evaluation, role of directors, merchant banking, leasing, working capital financing, technology transfer, management, documentation and recovery practices of Development Financing Institutions, etc., were carried out by MDI and its Development Banking Centre (DBC). As many as 23 workshops were conducted by MDI under Planning Commission/International Labour Organisation/United Nations Development Programme, In-house Management Consultancy Development Project (Phase-II). Cumulatively, upto 31st March, 1989, MDI had conducted 928 Management Development Programmes benefiting 21,944 participants, of whom 539 were from other developing countries.

3.22 A major effort was made by MDI during the period under report in the area of consultancy and research. The focus was not only on developing management consultancy through training programmes and workshops but also undertaking process consultancy assignments in large complex organisations and directing efforts to develop in-house management consultancy teams in public utilities. The Consultancy and Research Wings of MDI have done extensive work in areas like corporate planning, evaluation of appraisal systems, feasibility studies, job structuring, management information systems, manpower planning, marketing appraisal, capital markets, off-shore banking, inter-firm comparison, seed capital, technology—its relevance, assessment and diffusion, etc.

3.23 MDI also had its Foundation Day Lecture delivered by Shri Vasant Sathe, Hon'ble Union Minister of Energy, Government of India, on the 19th November, 1988 on the subject of "Management of Public Sector".

3.24 IFCI's financial support to MDI in 1988-89 was of the order of Rs. 48.25 lakhs, exclusive of yearly contribution of Rs. 5 lakhs from IFCI's General Funds. Cumulatively, upto the 31st March, 1989, IFCI had provided financial support to MDI out of Benevolent Reserve Fund (BRF) and Interest Differential Funds (IDFs) to the extent of Rs. 845.24 lakhs and out of its General Funds Rs. 80 lakhs.

Support for Risk Capital, Venture Capital and Technology Finance

3.25 While the risk capital assistance has its own significance in broadening the entrepreneurial base in the country, the assistance in the form of venture capital and technology finance helps in improving the technology base of the Indian industry. The Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC), sponsored by IFCI, is perhaps, the only institution of its kind, which provides both the risk capital assistance and technology finance under one roof to the upcoming entrepreneurs and their technology-oriented ventures.

3.26 In the area of risk capital assistance, RCTC, which is the successor of the erstwhile Risk Capital Foundation (RCF), sanctioned, during 15 months' period commencing from January, 1988 and ending with March, 1989, assistance of the order of Rs. 641.50 lakhs to 70 promoters for their 43 medium-sized industrial projects. Cumulatively, since inception of RCF in 1976, and upto the 31st March, 1989, RCTC had sanctioned risk capital assistance of the order of Rs. 2,188.98 lakhs to 297 entrepreneurs for their 177 projects. The disbursements against these sanctions had been of the order of Rs. 1,735.73 lakhs for 247 promoters of their 148 projects.

3.27 In the area of technology finance, a beginning was made, during the period under review by sanctioning assistance aggregating Rs. 124.85 lakhs to five innovative technology-oriented projects. These projects covered a variety of technology-oriented fields such as development and manufacture of educational robots, development of LAN/WAN Systems Software, specialised software for expert systems for Hotels/Tourism/Medical Application, development and manufacture of digitised fonts relating to various Indian/Asian scripts, manufacture of direct compaction fuel making machines based on a new design concept and development of a totally newly designed-handloom for catering to the needs of handloom sector in rural areas.

3.28 Both in the area of Risk Capital Assistance and Technology Finance, RCTC's focus is on helping trailblazer technocrats/professionals taking on ventures with high risk and higher returns having regard to the distinctive features of their schemes, e.g., new technology (specially if developed domestically), new products, new markets, new usages and new specialised services. Emphasis is also on commercialisation of domestic technologies including initiation of steps entailing customers' acceptance, establishment of in-house R & D infrastructure, undertaking in-house research and development, application of newer technologies for energy conservation, control of environmental pollution, etc.

3.29 It is expected that in its newly emerging role, RCTC would not only continue to help broaden the entrepreneurial base in the country but also fulfil the wide gap between the development of technology and its commercial application.

3.30 So far, the funds support to RCTC has been totally provided by IFCI. Upto the 31st March, 1989, IFCI had disbursed a sum of Rs. 1,575.23 lakhs to RCTC besides subscribing to its share capital to the extent of Rs. 100 lakhs. IFCI had also agreed to subscribe to additional equity of RCTC to the extent of Rs. 400 lakhs during 1989-90 and to grant it interest-free and interest-bearing loans aggregating Rs. 325 lakhs.

Support for Providing Finance for Tourism and Tourism-related Activities, Facilities and Services

3.31 A significant development during the period was that IFCI was declared by the Government of India as nodal financial agency at the national level, for financing tourism and tourism-related activities within the country In the fulfilment of this role, and with a view to operating on, as large a canvas as possible, IFCI, alongwith other all-India Financial Institutions and banks sponsored a new organization, viz., the Tourism Finance Corporation of India Ltd. (TFCI). TFCI, which was incorporated as a public limited company on the 27th January, 1989 became operational with effect from the 1st February, 1989.

3.32 TFCI's main objective is to carry on the business of assisting enterprises—corporate bodies, partnership firms, trusts, individuals, other companies, howsoever constituted which are engaged or propose to engage themselves in setting up and/or development of tourism and tourism-related activities, facilities and services, such as, hostels, restaurants, cafeterias, flight kitchens, holiday resorts, lodging houses, hostels, comping sites, amusement parks, cinerama, auditoriums, museums, all means of tourist transports, travel agencies, tourist emporia, facilities for

water sports and other sports of tourists' interest, etc., by assisting in the creation, operation, expansion and modernisation of such enterprises and by encouraging and promoting private and public ownership and participation of capital in such enterprises.

3.33 The assistance from TFCI would be in the form of rupee and foreign currency loans, underwriting and/or direct subscription to shares/debentures, guarantee for deferred payments, equipment finance, equipment leasing, suppliers' credit, etc. TFCI is also expected to provide Merchant Banking and Advisory Services and carry on the activities of coordinating and formulating guidelines and policies relating to the financing of all projects in tourism industry and tourism-related activities, facilities and services. TFCI, however, is not expected to provide refinance assistance which would continue to be extended to State-level Institutions/Banks by IDBI.

3.34 To begin with, TFCI would provide financial assistance to project with capital cost of Rs. One crore and above. However, unique projects which are important from the tourism point of view and for which assistance from State-level institutions/banks is not available, can be considered on exceptional basis even though their capital cost might be below Rs. One crore. Projects with capital cost upto Rs. 3 crores would be financed by TFCI alongwith State-level Institutions/banks. However, projects with capital cost of Rs. 3 crores and above would be financed by TFCI on consortium basis with the all-India Financial Institutions like IFCI, IDBI and ICICI.

3.35 The authorised share capital of TFCI is Rs. 100 crores, out of which the initial paid-up share capital of Rs. 50 crores has been subscribed by IFCI, IDBI, ICICI, UTI, LIC, GIC, SBI, Canara Bank, and Bank of India. TFCI has also been authorised to issue bonds, which will be guaranteed by the Government of India for mobilising further resources. IFCI's contribution, so far, towards the equity capital of TFCI has been of the order of Rs. 12.50 crores.

Support for Development of Securities Market and Investor Protection

3.36 With a view to promoting orderly and healthy growth of the securities market and to provide adequate investor protection, the Government of India, pending the setting up of a Statutory Apex Board, had constituted on the 12th April, 1988, as an interim measure, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the overall administrative control of Ministry of Finance. To meet the initial fund requirements of the order of Rs. 30 crores, IFCI, alongwith LIC, GIC, UTI, IDBI, ICICI, SBI and other nationalised banks performing investment banking functions, contributed during the period under review Rs. 1.25 crores against its own share of Rs. 2.50 crores.

3.37 SEBI has been envisaged as an agency to promote an orderly and healthy growth of the securities market and to protect the investors' interest including preparation of comprehensive legislation for the regulation and development of securities markets.

Support for Science & Technology Entrepreneurs' Parks

3.38 With a view to developing an on-going interaction between Science & Technology Institutions and industry, promoting new class of Science & Technology entrepreneurs and creating a technology culture in industry, the all-India Financial Institutions have been supporting Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs) set up by well established Engineering Colleges and Technical/Research Institutes. IFCI has already participated in the funding of four STEPs, viz., Birla Institute of Technology STEP (BIT-STEP), Ranchi, Regional Engineering College STEP (REC-STEP), Tiruchirapalli, National Entrepreneurs' Chemical Park STEP (NECP-STEP), Bombay, Harcourt Butler Technological Institute STEP (HBTI-STEP), Kanpur.

3.39 BIT-STEP has developed a unique technology for automatic wire length measurement system and import substitutive stainless steel wedge wire screens, besides other technologies for industrial application. REC-STEP is developing technology for hi-tech paints for nuclear applications, besides other hi-tech and import substitutive products. Commercial production has already been started by 7 REC-STEP entrepreneurs. NECP is engaged in preparation of project profiles of selected imported drugs. Student entrepreneurs of HBTI-STEP are working on projects which include fibre reinforced concrete and plastic components.

3.40 During the period under review IFCI also agreed to the funding of two more STEPs, one sponsored by Shri Jayachamarajendra College of Engineering, Mysore (SJCE-STEP) and the other sponsored by Guru Nanak Engineering College, Ludhiana (GNEC-STEP). SJCE-STEP would be specialising mainly in the field of electronics and instrumentation in view of the expertise available with SJCE. GNEC-STEP would be specialising in machine tools accessories and machno-electronic controls.

3.41 As at the end of March, 1989, three more requests one each from University of Roorkee, Maulana Azad College of Technology, Bhopal and Jadavpur University, Calcutta, were pending consideration of the all-India Financial Institutions. The funds support provided by IFCI to the STEPs by way of grants upto the 31st March, 1989 was of the order of Rs. 15.91 lakhs.

Support for Research in Areas of Industrial Management and Development Banking

(A) IFCI Chairs

3.42 For promoting research in the field of industrial management, financial management, industrial finance, regional economics and development banking, IFCI has created six Chairs—one each at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) and at the Universities of Delhi, Bombay, Calcutta, Guwahati and Madras.

3.43 During the period under review, under the auspices of the aforesaid Chairs, the following Annual Public Lectures were delivered :

— Managing Productivity of Corporate Capital
—Prof. S. C. Kuchhal of IIMA

— Some Aspects of Development Banking and Policy in India.
—Dr. R. S. Sabnis, University of Bombay

— Development Banking in India—Performance and Expectations in North East India.
—Dr. P. C. Goswami, University of Guwahati

3.44 The working of the Chairs was reviewed by a Committee of the Board of Directors of IFCI at their meeting held on the 18th March, 1989 when the members of the Committee also had an opportunity to interact with IFCI Chair professors who had been invited specially for the purpose. The recommendations of the Committee were, thereafter, considered by the Board of Directors of IFCI, in terms of which the consensus evolved was as under :

(i) The Chairs should better confine to those areas of research which were relevant to the industry, finance, banking and economics. Determination of some sort of priority in research projects by Chair Professors in consultation with IFCI was necessary.

(ii) The Chairs should be subject to an on-going review mechanism based on which the continuance of the Chair and the amount granted by way of endowment could be reviewed by IFCI after a period of every five years.

(iii) It would be desirable to have the funding pattern of the Chairs on a one-time endowment basis.

(iv) Further creation of Chairs should be based on vigorous selectivity and the specificity should be built around the person occupying or identified to occupy the Chair.

(v) Where the research work done under the Chair was of outstanding nature, IFCI could have the work published either by giving some additional grant or meeting the cost of publication.

As at the close of the period, steps were under way to implement the aforesaid recommendations, by making changes, where necessary, in the amount of endowment, and, in the Memoranda of Understanding (MOU) with various Institutions/Universities.

3.45 IFCI's funds support in the form of endowment grant/annual grant to the existing Chairs upto the 31st March, 1989 aggregated Rs. 29.15 lakhs.

(B) Other Research Projects

3.46. For promotion of research-oriented activities IFCI made, during the period under review, a further contribution of Rs. 3 lakhs of Research and Information Systems for Non-Aligned and other Developing Countries, New Delhi. IFCI also contributed a sum of Rs. 3 lakhs out of Rs. 8 lakhs agreed towards the research project entitled "A Macho-Econometric Model of the Indian Economy" undertaken by a research organisation known as "The Policy Group" with its headquarters at New Delhi.

3.47 A voluntary organisation kown as "Professional Assistance for Development Action" (PRADAN), was extended funds support for its corpus by IDBI, IFCI and ICICI (IFCI's share being Rs. 10 lakhs) for building on a continuing basis a core of grass root professionals to assist low income groups in building self sustaining economic enterprises. Two programmes, one relating to Human Resources Development, consisting of a three months' associateship and a one year apprenticeship to 25 and 10 graduates respectively and one pilot project to enable promotion of non-traditional rural occupation are proposed to be taken up by PRADAN, on an yearly basis with the income accruing from the aforesaid corpus fund.

3.48 With a view to strengthening consumer movement in the country, as a part of its promotional role, IFCI also agreed during the period under review to provide funds support, to the extent of Rs. 73 lakhs towards capital outlay and Rs. 18 lakhs per annum for an intial period of five years towards recurring expenses, on sharing basis with other Financial Institutions, to Consumer Education and Research Centre (CERC), a non-profit-making and non-political voluntary agency, engaged in providing service to consumers in the field of consumer information, research and education. CERC has proposed to set up a Product Testing Laboratory (PTL) for testing the consumer products picked up from market in the field of food, drugs and pharmaceuticals, and domestic electrical appliances, so as to create better awareness amongst the manufacturers of the consumer products about their commitment to produce quality products on a continuing basis. In the larger interest of consumers' protection and safety, the institutional support to the establishment of product testing and rating organisations is considered to be a significant activity amongst the variegated nature of promotional services of the Financial Institutions.

CHAPTER 4

In House Matters

Meetings of the Board of Directors

4.01 During the nine months' period ended the 31st March, 1989, nine meetings of the Board of Directors were held—seven at New Delhi and one each at Calcutta and Madras.

Changes In the Board of Directors

4.02 There was no change in the Board of Directors, except, that Shri S. H. Khan, Executive Director, Industrial Development Bank of India, was nominated with effect from the 9th January, 1989 in place of Shri S. M. Palia. As at the close of the period, Shri S. K. Seth, an elected Director representing insurance companies, investment trusts and other like Financial Institutions, had also resigned from the Board of Director of IFCI, and his place is likely to be filled by election at the ensuing 41st Annual General Meeting scheduled for the 30th June, 1989.

4.03 The Board of Directors of IFCI place on record their high sense of appreciation for the very useful and valuable contribution made by Shri S. M. Palia and Shri S. K. Seth during the period of their association with IFCI as its Director

Meetings of Ad-hoc Group of Advisers

4.04 During the period, twelve meetings of the Ad-hoc Group of Advisers were held with a view to obtaining expert advice on proposals relating to hotels, hospitals, chemical process & allied industries, engineering and sugar industries.

Meetings of the State Advisory Committees

4.05 State Advisory Committees were constituted for the first time in the State of Goa and Haryana in terms of Section 15 of the IFC Act, 1948. Three meetings of State Advisory Committees were held during the period, one each in Goa, Haryana and Madhya Pradesh. IFCI now has in all, 18 State Advisory Committees functioning in various States.

Inter-Institutional Co-ordination

4.06 Inter-institutional co-ordination among the national level Financial Institutions continued to be maintained through the forum of Inter-Institutional Meetings (IIMs), Inter-Institutional Rehabilitation Meetings (IIRMs), Senior Executives Meetings (SEMs) and Regional Executives Meetings (REMs). During the nine months' period ended the 31st March, 1989, eight IIMs, two IIRMs, nineteen SEMs and sixteen REMs were held.

4.07 At the State level, IFCI continued to maintain co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional/Branch Offices in the meetings of the State-level Co-ordination Committees, State-level Guidance and Monitoring Committees and other State level fora.

Foreign Visits and Participation in the International Fora

4.08 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Financing Institutions (DFIs) abroad as also the international banks operating in the world market.

4.09 Shri D. N. Davar, Chairman, IFCI, accompanied by Shri V. P. Kamath, Dy. General Manager, visited Finland, Federal Republic of Germany, Switzerland and United Kingdom for signing the Loan Agreement with "Finnish Fund for Industrial Development Cooperation Ltd., discussing matters of mutual interest and credit lines with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) and carrying out negotiations with other eminent banks in Federal Republic of Germany, Switzerland and U.K.

4.10 Shri S. K. Rishi, Executive Director, visited Hong Kong and Singapore in connection with signing of agreement for Yen 20 billion with Merril Lynch at Hong Kong and for discussions with bankers at Singapore. Likewise, Shri F. M. Patnaik General Manager, accompanied by Shri K. P. Mukherjee, visited Switzerland and Federal Republic of Germany for signing Loan Agreement with Swiss Bank Corporation Investment Banking Ltd. in connection with US $ 100 million credit and holding discussions with the officials of KFW. So also, Shri V. S. R. K. Sastry, General Manager, represented the country at the meeting of the Expert Group Studies for Co-operation in the area of trade and industry held at Islamabad in Pakistan under South Asian Association of Regional Co-operation (SAARC) as a member of the Indian delegation team.

4.11 A number of foreign dignitaries also visited IFCI and held discussions about Indian financial system, investment opportunities in India and other matters of mutual interest.

XI IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture

4.12 IFCI had its XI Silver Jubilee Memorial Lecture delivered on the 5th December, 1988 by Tan Sri Dato' Jaffar Hussein, Governor, Bank Negara, Malaysia (Central Bank of Malaysia) on the subject of "Central Bank in an

Era of Change". The Lecture which was well attended was presided over by Shri R. N. Malhotra, Governor, Reserve Bank of India (RBI). The *'summum bonum'* of Tan Shri Dato' Jaffar Hussein's Lecture was that the success of a development country in managing development hinged critically on the effectiveness of its social, economic and financial institutions, and the responsiveness of these institutions to the process of change. Central Banks like Development Banks had to change themselves with the times or face the consequences of obsolescence. In a developing country, where foreign exchange trading skills were scarce, Tan Sri Dato' Jaffar Hussein was of the view that it was the duty of a Central Bank to be the provider of skilled manpower in the market, to be an educator of such technical skills and to be in the fore front of banking and computer technology. Bank Negara, Malaysia, Mr. Jaffar Hussein added, had invested heavily in modern dealing room technology and manpower skills, because it believed that "the highest retur non capital was in human capital".

4.13 On the occasion of the XI IFCI Silver Jubilee Memorial Lecture, Shri R. N. Malhotra, Governor, RBI also presented, on behalf of IFCI, silver plaques to the past Chief Executives/Chairmen of IFCI for their yeoman's services in making IFCI an institution of national pride in the country.

Jawaharlal Nehru Centenary Celebrations

4.14 On the 1st July, 1989, IFCI would be stepping into its 42nd year of service to the Indian industry. The year coincides with the Jawaharlal Nehru Centenary year. IFCI, therefore, has decided to celebrate the occasion in an appropriate manner. Quotations from Shri Nehru's writings and speeches have been superscribed on the letter-heads and other publications brought out by IFCI. Symposia have been planned for being organised at seven centres, viz., Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Guwahati, Kanpur and Madras during the centenary year on topics concerning Nehru's role in variegated form in building modern India.

4.15 As a part of Nehru Centenary celebrations, IFCI held a Nehru Bal Mela on the 25th February, 1989 at its Staff Colony, Paschim Vihar, New Delhi. Besides an impressive march past by about 160 children of employees in various dresses of Indian States, symbolising 'unity amongst diversity', competitions in drawing and painting and debates on topics related to the life and work of the first Prime Minister of Independent India, Shri Jawaharlal Nehru, were organised. The participants were awarded suitable prizes. An exhibition depicting the life and works of Shri Jawaharlal Nehru, was also organised.

Organisational Developments

4.16 On the expiry of his term of deputation, Shri R. Viswanathan, Executive Director, reverted to his parent organisation, viz., State Bank of India, from the 19th August, 1988. Shri S. P. Banerjee, General Manager, was elevated as Executive Director with effect from the 1st March, 1989.

4.17 Two Conferences of the Senior Officers of IFCI were held in the months of April and December, 1988 as a part of ongoing process of reviewing the performance, scanning the environment and building plans and programmes together with strategy for action for the period to follow.

Electronic Data Processing and Communication System

4.18 A mention was made in the last year's Annual Report about IFCI installing and operating a modern ICIM-6040 Main Frame Computer with required peripherals at Head office and one ICIM-Quattro Personal Computer (PC) at Delhi Regional Office of IFCI. During the period, the ICIM-Quattro PC was replaced by ICIM's latest machine in the mini/super micro range, i.e., DRS-300 system with UNIX operating system and the same was installed at Head Office to facilitate networking/communication in future between the ICIM Main Frame Computer and ESPL mini system working in UNIX environment, which are proposed to be installed in all Regional and Branch Offices.

4.19 The software developed/implemented on ICIM-6040 Main Frame Computer in key operational areas, viz., accounting and management information system in IFCI, continued to work satisfactorily. At the end of March, 1989, fresh user friendly systems were under development on ESPL's mini systems for revised system of financial ratio analysis, storing, maintaining, updating and retrieving data for brief particulars of assisted concerns, compilation of performance data of Regional and Branch Offices, and computerisation of the activities of Foreign Currency Resources and Operations Department. Besides strengthening of the professional staff for Electronic Data Processing Deptt., training continued to be imparted to officers and staff of user Departments/Divisions on computer appreciation, data documentation and computer discipline.

4.20 With a view to evolving a common approach, avoidance of duplication of efforts in the development of systems and integration of systems in future, an Inter-Institutional Electronic Data Processing Co-ordination Committee was formed by the Institutions under the aegis of IDBI. The Committee is also expected to take up the work of standardising the formats and manner in which the information can be exchanged in the area of maintenance of particulars of assisted concerns and project profiles.

Personnel

4.21 As at the end of March, 1989, IFCI had a complement of 1,136 employees (inclusive of staff strength at its Regional, Branch and Other Offices). It consisted of 392 officers, 530 supporting staff and 214 subordinate staff. The number of employees in the category of scheduled castes/scheduled tribes, ex-servicemen and physically handicapped persons was 160,37 and 17 respectively. The number of women employees in IFCI as at the end of March, 1989 was 181.

Human Resources Development

4.22 Rightful emphasis was laid, as in the past, on the development of human resources with systematic training for enhancing the employees' competence and creating a climate of positive attitude and ethos for conducive growth of the organisation. The focus on training programmes organised in IFCI was on equipping its human resources with necessary skills and developing in them an in-depth understanding of the changing business environment and the emerging role of Financial Institutions. Some of the thrust areas covered by in-house training programmes included, *inter-alia*, computer awareness, merchant banking, leasing, foreign currency loan operations, economic analysis of industrial projects, etc.

4.23 Twenty-seven training programmes were organised of varying durations for the benefit of IFCI's officers and staff during the nine months' period ended the 31st March, 1989, which were conducted at Training Centres at New Delhi, Patna, Hyderabad and Bombay. These training programmes covered in all 405 staff members at various levels from different offices.

4.24 To supplement in-house training, 50 staff members were deputed to external training programmes organised by other professional institutions in the country. In addition, 15 staff members were deputed to programmes conducted by the Management Development Institute (MDI)—an IFCI-sponsored organisation for management development. Two officers were sent to participate in the programmes sponsored by Economic Development Institute (EDI) of World Bank and Asian Development Bank (ADB). Special lectures from experts were also arranged for the benefit of officers and staff on the subjects relevant to IFCI's operations.

4.25 Under the Reserve Bank of India (RBI)'s Scheme for co-ordination between commercial banks and Financial Institutions for rehabilitation of sick units, IFCI extended during the period, on-the-job training facilities in its Rehabilitation Finance Department (RFD) to four executives of the commercial banks.

4.26 IFCI also continued to implement Government guidelines regarding reservations/concessions to be given to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees in IFCI's service. To prepare and enable the Scheduled Caste/

Scheduled Tribe candidates to show better results, 33 pre-recruitment familiarisation training programmes were conducted in which 234 Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates participated prior to taking written tests and interviews for various posts in IFCI.

4.27 Apart from intensive in-house, on-the-job and external training programmes, the members of staff were continually encouraged and motivated to give suggestions under the Staff Suggestions Scheme for improving the overall productivity of the organisation. A Staff Suggestions Committee evaluated each and every suggestion, and, in the event of the suggestion being accepted/taken up for implementation, the concerned staff members were given cash awards/commendation certificates.

Welfare Activities

4.28 The welfare of the employees of IFCI at all centres and at all levels continued to receive, as in the past, priority in the area of personnel management Social security, housing and medical facilities continued to be the main planks of IFCI's welfare activities. The Staff Welfare Fund continued to be the resource base for staff welfare activities of diversified nature.

Sports Meet

4.29 IFCI continued to promote sports and sportsmanship amongst its employees for the fourth year in succession. The Fourth all-India IFCI Sports Meet, 1989, was concluded at a function held at the Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi on the 19th February, 1989. The special features of this Sports Meet were (a) introduction of more athletic events, (b) active participation of both men and women athletic of IFCI in a large number, and (c) greater participation of the children of the employees of IFCI, at all levels.

Contribution to Relief Funds

4.30 IFCI contributed a sum of Rupees One lakh to the Chief Minister, Punjab's relief Fund for providing relief and succour to the person affected by floods and rains, which occurred in various parts of Punjab during the latter part of the year 1988. Modest contributions were also made for the Flag Day and All-India Sports Council of Deaf, New Delhi.

Progressive Use of Hindi

4.31 IFCI continued, as in the past, its endeavours to promote the use of Hindi in official work to the maximum extent. An all-India competitive examination in Hindi was conducted during the period ended the 31st March, 1989 in which cash prizes were awarded to successful competitors. A few Divisions/Departments were identified for transacting their entire work in Hindi both at Head Office as well as Regional/Branch Office located in Regions 'A' & 'B' and Hindi was introduced as medium of office work in these Divisions/Departments on 100% basis.

4.32 The Official Language Implementation Committees formed at each of the Regional/Branch Offices of IFCI, including the one at Head Office, continued to monitor the progressive use of Hindi and suggest ways and means for its promotion in their respective offices. Further, last Friday of each month was observed as Hindi Day. Again the first, and third Wednesday of each month was added as a day for maximising the originating correspondence in Hindi.

4.33 All Administration Circulars and Operational Circulars, Notifications, Advertisements and General Orders were issued in bilingual form. Most of the registers in use in IFCI offices were made bilingual. Staff members not possessing working knowledge of Hindi were deputed for training programmes in Hindi, Hindi typewriting and Hindi stenography under Hindi Teaching Scheme of the Government of India. The Internal Audit Department of IFCI was also entrusted with the duty of monitoring the achievement of targets set for progressive use of Hindi by the respective offices and

Publications

4.34 A number of publications were brought out by Public Relations Department of IFCI during the period. One of the year's prestigeous publication was a compendium of Chairman's Statements made at the Annual General Meetings of IFCI under the title "Industrial Finance Corporation of India—Growth and Development". Another significant publication was "IFCI—A Sagn of 40 years of Service to Industry".

Acknowledgements

4.35 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assstiansc, co-operation and support received from various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, Reserve Bank of India, the Industrial Development Bank of India, other sister all-India Financial Institutions, various State Governments, State-level financial and developmental organisations and merchant banking organisations.

4.36 The Board of Directors further acknowledge the continued co-operation received by IFCI from various Development Financing Institutions (DFIs) abroad, particularly the assistance received from the World Bank, the Economic Development Institute, the Asian Development Bank, the Association of Development Financing Institutions in Asia and Pacific (ADFIAP), the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of Federal Republic of Germany and a host of correspondent banks abroad and other members of international banking community.

4.37 The Board of Directors are also pleased to place on record their high appreciation of the very sincere and devoted services put in by all members of staff at all levels in IFCI during the period.

D. N. DAVAR
Chairman

Appendix—I

Statement showing the Installed Capacities' Production and Capacity Utilisation of Selected Industries in 1988–89

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1988-89					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and no. of units	Production 1988-89 (April-March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and no. of units	Production 1988-89 April-March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh tonnes	82.69 (392)	84.20*	101.8	12.40 (79)	16.90	136.3
2.	Cotton Yarn (mill sector)		28.09 Million spindles (1054)**	1296.90 Million Kgs.	---	5.81 Million spindles (159)	375.64 Million Kgs.	—

*Production is for the period from October 1988 to 7 May 1989.

**Includes 238 composite mills.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Cotton Cloth (mill sector)		1.99 Lakh Looms	2911 Million Metres	- -	0.51 Lakh Looms	904.33 Million Metres	—
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	16.86 (72)	13.88	82.3	0.77 (3)	0.62	80.5
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	29.85 (303)	17.20	57.6	8.71 (25)	6.74	77.3
6.	Rayon Pulp	Lakh tonnes	1.96 (5)	1.60	81.6	0.96 (3)	1.01	105.2
7.	Newsprint	Lakh tonnes	3.00 (5)	3.10	103.3	0.75 (1)	0.87	116.0
8.	Plywood	Million sq. metres	122.44 (61)	70.00	57.2	3.25 (2)	0.46	14.1
9.	Cement	Million tonnes	62.07	42.92	69.1	28.34 (61)	23.03	81.3
10.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	81.48 (47)	64.55	79.2	22.84 (17)	20.14	88.2
11.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	26.50 (19)	22.69	85.6	15.64 (10)	21.79	139.3
12.	Caustic soda	Lakh tonnes	11.03 (39)	8.60	77.9	3.24 (7)	2.69	83.0
13.	Soda ash	Lakh tonnes	14.60 (7)	11.00	75.3	0.66 (1)	0.57	86.4
14.	Calcium Carbide	Lakh tonnes	2.19 (7)	0.80	36.5	0.84 (3)	0.38	45.2
15.	Acetic Anhydride	Thousand tonnes	35.00 (11)	20.00	57.1	5.10 (1)	2.90	56.9
16.	Acetic acid	Lakh tonnes	1.05 (21)	0.80	76.2	0.07 (2)	0.07	100.0
17.	Carbon black	Lakh tonnes	1.75 (7)	1.20	68.6	0.17 (1)	0.12	70.6
18.	Liquid chlorine	Lakh tonnes	7.70 (29)	3.29	42.7	2.23 (6)	1.72	77.1
19.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	158.09 (22)	34.88	22.1	13.61 (3)	13.92	102.3
20.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	N.A.	N.A.	- -	8.00 (2)	8.89	111.1
21.	Polyester filament yarn	Thousand tonnes	158.09 (22)	140.67	89.0	29.40 (8)	42.04	143.0
22.	Polyester staple fibre	Thousand tonnes	176.06 (9)	100.28	56.9	103.00 (4)	73.65	71.5
23.	Viscose staple fibre	Thousand tonnes	89.00 (2)	125.03	140.5	78.00 (1)	89.92	115.3
24.	Auto tyres	Lakh nos.	182.28 (24)	160.00	87.7	45.60 (5)	30.30	66.4
25.	Auto tubes	Lakh nos.	193.73 (26)	145.00	74.8	43.35 (5)	32.08	74.0
26.	Rubber contraceptives	Million pieces	1033.00 (3)	890.00	86.2	808.00 (2)	544.33	67.4
27.	Reclaimed rubber	Thousand tonnes	36.58 (11)	24.00	65.6	4.80 (1)	2.36	49.2
28.	Finished leather from hides	Lakh pieces	120.37 (46)	62.00	51.5	3.70 (2)	2.62	70.8
29.	Finished leather from skins	Lakh pieces	614.94 (67)	330.00	53.7	19.40 (2)	3.89	20.00
30.	Sheet glass.	Million sq. mtrs.	40.79 (9)	42.00	102.9	14.70 (2)	17.10	116.3
31.	Fibre glass.	Thousand tonnes	5.29 (3)	4.65	87.9	2.00 (1)	1.91	95.5
32.	Glass bottles and misc. glassware	Lakh tonnes	6.53 (31)	5.95	91.1	0.24 (1)	0.12	50.0
33.	Synthetic detergents	Thousand tonnes	323.46 (21)	282.52	87.3	20.00 (2)	9.17	45.8
34.	Soaps	Thousand tonnes	365.40 (48)	368.00	100.7	33.50 (3)	6.29	18.8
35.	Fatty acid	Thousand tonnes	150.00 (18)	110.00	73.3	17.96 (3)	7.78	43.3
36.	Glycerine	Thousand tonnes	22.58 (19)	12.65	56.0	2.34 (2)	0.40	17.1
37.	Refractories	Lakh nos.	17.20 (71)	9.34	54.3	1.55 (5)	1.04	67.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38.	Ceramic Tiles	Lakh tonnes	2.13 (16)	1.30	61.0	0.36 (3)	0.21	58.3
39.	Explosives	Thousand tonnes	199.00 (15)	144.20	72.5	26.50 (3)	11.46	43.2
40.	Oxygen	MCM	205.38 (177)	129.00	62.8	21.65 (8)	14.05	64.9
41.	Watches	Million nos.	14.20 (13)	7.71	54.3	5.97 (2)	5.37	89.9
42.	Saleable steel (main plants)	Lakh tonnes	92.52 (6)	92.10	99.5	21.00 (1)	19.20	91.4
43.	Steel Ingots/billets	Lakh tonnes	52.40 (166)	33.00	63.00	6.81 (15)	4.35	63.9
44.	Steel forgings	Lakh tonnes	3.30 (75)	1.90	57.6	0.25 (3)	0.10	40.0
45.	Steel Castings	Lakh tonnes	2.05 (85)	1.00	48.8	1.05 (5)	0.62	59.0
46	Cold rolled steel strips	Lakh tonnes	15.00 (57)	3.88	25.9	0.90 (5)	0.58	64.4
47	Sponge Iron	Lakh tonnes	3.00 (3)	1.94	64.7	1.35 (1)	0.89	65.9
48.	Two wheelers	Lakh nos.	24.00 (24)	16.00	66.7	5.20 (5)	3.19	61.3
49.	Commercial vehicles	Lakh nos.	2.65 (13)	1.90	71.7	0.99 (5)	0.81	81.8
50.	Cars	Lakh nos.	1.71 (5)	1.60	93.6	0.35 (2)	0.20	57.1
51.	V belts	Lakh nos.	183.71 (16)	300.00	163.3	12.00 (1)	11.90	99.2
52.	Conveyor Belts	Thousand tonnes	8.91 (8)	11.45	128.5	2.38 (1)	2.54	106.7
53.	G.I.S. Lamps	Million nos.	343.00 (20)	250.00	72.9	76.10 (3)	53.57	70.4
54.	Fluorescent Tubes	Million nos.	46.20 (16)	50.00	108.2	9.50 (2)	10.15	106.8
55.	Power and distribution transformers	Million KVA	33.7 (33)	25.00	74.2	1.80 (1)	1.61	89.4
56.	Electrical fans	Lakh nos.	76.00 (17)	55.00	72.4	0.60 (1)	0.60	100.00
57.	Diesel Engine	Thousand nos.	336.00 (34)	198.00	58.9	4.80 (2)	3.51	73.1
58.	Tractors	Thousand nos.	122.30 (19)	101.00	82.6	37.00 (2)	27.00	73.0
59.	Power tillers	Thousand nos.	16.00 (5)	4.00	25.0	2.50 (1)	1.74	69.6
60.	Hotels	Lakh nos.@	135.05 (600)	91.56	67.8	7.51 (14)	4.92	65.5

@Figures in columns 4 & 7 and 5 & 6 refer to the number of lettable room days and the number of room days occupied respectively.

Appendix—II

Direct Economic Contribution of New, Expansion and Diversification Projects assisted by IFCI during 1988-89 (July-March)

(Rs. crores)

Industry	Projects (Nos.)	Total Capital Cost (Rs.)	Expected Direct Employment (Nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mining	3	37.89	1,021	32.94	28.08	Processing of 80,620 tonnes of low grade chrome ore, acquisition of 4 mobile drilling rigs and seismic survey of 3,200 km. lines of oil field for oil exploration.
Sugar	12	282.09	8,315	251.22	99.18	5.18 lakh tonnes of sugar.
Food Processing	8	91.00	1,137	162.69	58.57	Processing of 33,000 tonnes of wheat and 6,000 tonnes of rice, 4,680 tonnes of processed food 131.80 lakh litres of fruit juices, 2 lakh litres of mineral waters, 120 lakh litres of malt beverages, 106.42 lakh litres of soft drinks, 4,100 tonnes of processed chocolate and 20,000 tonnes of malt.
Textiles	16	153.53	4,721	176.96	55.49	1.66 lakh spindles, 10 lakh kgs. of texturised/twisted yarn and processing of 66 lakh metres of synthetic blended cloth.

1	2	3	4	5	6	7
Paper . . .	2	18.87	135	28.55	4.45	19,800 tonnes of newsprint and 750 tonnes of bagasse-based paper.
Fertilisers/Pesticides .	6	1,902.44	2,664	985.98	644.93	15.00 lakh tonnes of Urea fertiliser, 1.32 lakh tonnes of Single Super Phosphate (SSP), 1.00 lakh tonnes of methanol, 2.5 lakh tonnes of ammonia-nitrophosphate, 1,200 tonnes of rice herbicides.
Chemicals and Chemical Products . .	24	372.13	3,504	446.40	173.63	10,560 tonnes of chloromethane, 12,500 tonnes of oxo alcohol 7,000 tonnes of maleic anhydride, 7,200 tonnes of methyl ethyl ketone, 1,800 tonnes of Betanophthol, 1,800 tonnes of chlorobenzene, 1,500 tonnes of glyoxal, 1,300 tonnes of ethyl acetate, 200 tonnes of methyl/ethyl acrylate, 550 tonnes of ethyl hexyacrylate, 1,500 tonnes of sodium thiosulphate, 900 tonnes of red oxide/pigment, 9,900 tonnes of dextrose monohydrate, 2,775 tonnes of dextrose anhydrate, 1,650 tonnes of meltrodextrin, 58 tonnes of injectible sodium ampicilin, 8,350 tonnes of refined base lubestock, 250 tonnes of phenyle glycine chloride, 60 tonnes of danesalt, 345 tonnes of trimethoxy benzadehyde, 70 tonnes of ampicilin trihydrate, 30 tonnes of amoxycilin trihydrate, 30 tonnes of cephaxilin monohydrate, 10 tonnes of difexacilin sodinm 200 tonnes of magnetic oxide, 3,500 tonnes of alphaoletins, 184 tonnes of starch Powder, 1,28,750 tonnes of glucose syrup, 6,600 tonnes of fructose syrup, 1,000 tonnes of Powder paint, 441 million Nos. of tablets and hard and soft shell Capsules, 22,400 tonnes of anima] feed and distribution of 6 lakh m of helium gas.
Automobile tyres and tubes	3	14·80	573	26·83	7 38	11·65 lakh nos. of two wheeler/three wheeler tyres and 6·39 lakh nos. of tubes.
Synthetic Fibres . .	4	507 33	1,863	256·38	169 17	34,500 tonnes of Polyster filament yarn and 12,000 tonnes of acrylic staple fibre yarn.
Synthetic Resins and Plastic Products	21	1,075·95	3,890	741·12	401·78	20,000 tonnes of Polyols, 13·250 tonnes of Propylene-glycol, 1,000 tonnes of polybutanes, 12,000 tonnes of propylene oxide, 2,000 tonnes of polyvinyl alcohol, 10,00 tonnes of ethylene propylene copolymers and ethylene propylene Diene terpolymers, 6,000 tonnes of trichloro ethylene 9,000 tonnes of acrylonitirte butadine styrene, 60,000 tonnes of high density Polyethylene 60,0000 tonnes of monoethylene glycol, 1,00,000 tonnes of Polyvinyl chloride, 2,000 tonnes of BOPP films, 100 million, nos. of disposable needles 30 million nos. of disposable syringes, 6,600 tonnes of PVC rigid films/sheets, 670 tonnes of thermo-formed containers and PVC sheets, 1,080 tonnes of PVC doors/window Profiles, 3·96 lakhs nos. of HM-HDPE (L-ring barrels), 1,120 tonnes of adhesive tapes, 750 tonnes of pherolic foam, and 2,850 tonnes of wall covering material.
Cement . . .	9	208 06	1,403	114 16	39·26	13·14 lakh tonnes of Portland cement, 50,000 tonnes of white and coloured cement, and 75,000 nos. of spun cast concrete Poles.
Glass : Glass Products .	4	78 75	1,150	56 55	32·34	2·65 million metres of sheet glass, 32,700 tonnes of high weight glass bottles, 48,000 tonnes of ambre glass bottles and 600 tonnes of laboratory glass ware and borosilicate glass tubes.
Miscellaneous non-metalic mineral	7	46·23	917	51·69	23·22	86 million nos. of sand lime bricks, 4·01 milion square feet of agglomerated marbles and granite-slabs and tiles, 4 lakh square metres of wall and floor tiles, 12,000 tonnes of unglazed tiles, 9,000 tonnes of synthetic marbles, 24,000 spuar metres of granite monuments and slabs, 1,000 tonnes of bonded abrasives and 6,000 tonnes of mineral wool.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Iron & Steel	10	365·06	2,570	471·87	141·09	92,500 tonnes of cold rolled steel coils/strips, 61,250 tonnes of carbon and alloy seamless tubes, 64,000 tonnes of pre-coated cold rolled galvanised sheets, 25,000 tonnes of galvanised sheets, 1,600 tonnes of stainless steel condenser tubes, 3,750 tonnes of high speed steel, 90 000 tonnes of steel billets and 2·2 lakh tonnes of direct reduced iron.
Machinery & Accessories	10	154·46	2·827	226·92	94·18	1 05 lakh nos. of portable power tools, 12,000 nos. of industrial grade sockets, 1780 nos. of high Precision spindles for grinding and tool cutting, 280 nos. of barrels for single and twin screw extruders, 1,875 nos. of diesel engines and 25 web offset printing machines, 89 colour offset printing machines, 2 lakh nos. of micro-processor based washing machines, 7,000 nos. of laundry systems, 15,000 nos. of washing systems, 10,,000 dispensing systems, 120 nos. of air and gas compressors, 90 nos. of centrifuges, 30 nos. of liquid nitrogen Plants, 25 nos. of industrial refrigerators, 300 nos. of mixing process equipment and 15 nos. of fluid-bed dryers
Electric Machinery and apparatus	6	49·12	917	132·94	28·07	25,000 number of moulded case circuit breakers, 1,000 numbers of bushless alternators, 6 lakh nos. of heat sleeves type cable joining kits, 6,25 lakh conductor kilometres of polyethylene jelly filled telepone cables, 500 nos. of power systems, 100 nos. of charges/rectifiers , 200 nos. of solid stateline voltage regulators, 1,000 nos. of switch mode rectfiers.
Electronic equipment .	17	196·67	4,308	442·49	154·57	2·0 million nos. of black & white picture tubes, 112 5 milion nos. of rectified diodes, 1.5 million nos. of black & white and 3·7 lakh nos. of coloured television sets, 140 lakh nos. of electronic connectors, 4,100 million running metres (MRM) of video and audio tapes, 10 lakhs nos. of audio tapes deck mechanisms,) 6 lakh nos. of turners of transformers, 25 lakh nos. of other electronic components, 3,000 nos. of process control systems. 72 million nos. of aluminium electrolytic capacitors, 23,400 sq. metres of printed circuit boards, 650 tonnes of Professional/consumers grade soft ferrites, 15,000 lines of analgue subscriber and digital subscriber carrier systems and 23 computer main frames.
Transport equipment .	3	8·31	137	18 25	6·00	2·75 lakh nos. of switches and locks for two wheelers and four wheelers, 300 nos. of deluxe bus bodies, 1,09,000 nos. of fan blower motors, 34,000 nos. of ventilator motors, 17,300 nos. of magnetic CDI and magnetic coils.
Metal Products .	9	58·73	1,467	188·13	36·89	2 10 lakh nos. of pressure cookers, 1·05 lakh nos. of pressure pans, 2,00 lakh nos. of vaccum flasks, 250 tonnes of nickel and cobalt based cast alloy rods, 65,000 tonnes of plain and corrugated galvanised sheets, 1,500 tonnes of Poly-laminated aluminium foil tapes, 54,000 high Pressure seamless cylinders, 2,400 tonnes of industrial fasteners, and 11,250 tonnes of aluminium extruded products.
Wood Products .	4	61·03	604	41·41	22·23	26,390 tonnes of medium density particle boards and 30,000 tonnes of cement bonded particle boards.
Hotels . . .	10	121·15	2,331	65·22	46·45	1,289 rooms.
Hospitals . . .	6	133·05	3,096	83·46	51·52	1,732 beds.
Electricity and gas .	6	416·82	504	204·62	127·79	Generation of 289]MW electricity and distribution of 595 lakh NM 3 of natural gas.
Others . . .	14	58·87	1,388	141·62	45·23	
Total : .	214	6,412·34	51,442	5,348·40	2,491·30	

ACCOUNTS 1988-89 (JULY—MARCH)

REPORT OF THE AUDITORS

To the Shareholders of the Industrial Finance Corporation of India

We have audited the attached Balance Sheet of the Industrial Finance Corporation of India as at the 31st March, 1989, and also the Accounts of the Corporation for the period the 1st July, 1988 to the 31st March, 1989, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.
2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.
3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet, together with the Accounting Policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948, and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

GUPTA & CO.

T. R. CHADHA & CO.
Chartered Accountants

Place : New Delhi

Dated : 19th May, 1989

BALANCE SHEET AS AT THE 31ST MARCH, 1989

Description	Schedule	As at the 31st March, 1989 Rs. lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. lakhs
ASSETS			
Cash and Bank Balances	1	14,092·53	19,337·83
Investements in Assisted Concerns	2	11,175·28	9,653·38
Investements in other Institutions	—	2,010·02	650·00
Loans to Assisted Concerns	3	3,37,253·47	2,73,320·77
Fixed Assets	4	4,809·80	3,902·88
Other Assets	5	26,151·87	18,242·42
Customers' Liability for Acceptances		3,250·64	2,292·01
Total		3,98,743·61	3,27,399·29
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUND			
Share Capital	6	8,250·00	7,000·00
Reserves and Reserve Fund	7	27,094·32	22,561·85
Long Term Borrowings	8	3,37,115·35	2,76,568·24
Current liabilities and Provisions	9	21,688·10	17,987·54
Liability on Acceptances	—	3,250·64	2,292·01
Earmarked Funds.	10	1,345·20	989·65
Accouting Policies and Notes.	17	—	
Total		3,98,743·61	3,27,399·29

H. C. Sharma, General Manager; S. K. Rishi, Executive Director; D. N. Davar, Chairman; A. V. Ganesan, M. C. Satyawadi, S. H. Khan, V. R. Panchamukhi, S. S. Kadam, D. M. Patel, Directors

As per our report of even date

New Delhi ; 19 May, 1989

Gupta & Co.

T. R. Chadha & Co.
Chartered Accountants

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM 1ST JULY, 1988 to 31st MARCH, 1989

Description	Schedule	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	Year ended the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
(1)	(2)	(3)	(4)
Interest from loans, Advances, Deposits and Income from other Financial Assistance (less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	27,777·34	28,529·67
Cost of Borrowings	12	21,361·84	21,209 70
Net Interest Revenue		6,415·50	7,319·97
Income from other operations.	13	1,125·58	936·38
Total		7,541·08	8,256·35
Personal Expenses	14	501·85	612·23
Directors' and Committee Members' Fees, etc.	—	2·09	3·30
Rental, Maintenance and Depreciation	15	762.65	533·49
Other Expenses	16	213·95	214·26
Grant to Management Development Institute	—	5·00	5·00
Provision for Taxation	—	1,002·19	1,621·85
Total		2,487·73	2,990·13
Appropriated to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948.		2,753·54	1,792·52
Special Reserve Fund under Section 36(1) (vii) of the Income tax Act, 1961		1,429·11	2,500·01
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		100·00	200·00
Staff Welfare Fund		50·00	25·00
Dividend		720·70	747·87
		5,053·35	5,266·22

Accounting Policies and Notes

H. C. Sharma, General Manager
S. K. Rishi, Executive Director
D. N. Davar, Chairman
A. V. Ganesan, M. C. Satyawadi, S. H. Khan, V. R. Panchamukhi, S. S. Kadam, D. M. Patel, Directors

As per our Report of even date

Gupta & Co.
T. R. Chadha & Co.
Chartered Accountants

New Delhi: 19 May 1989

Schedule 1

Cash and Bank Balances

Annexed to and forming Part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	As at the 31st March, 1989 Rs. lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. lakhs
Cash and Bank Balances		
Cash in Hand	1·12	1·14
Cheques/Drafts in Hand and lodged for collection	4608·69	1,142·31
Balances with Banks in India		

(1)	(2)	(3)
In Current Accounts (See Note No. 7)	11,255·93	7,992·65
In Short Term Deposits	1,453·25	9,848·00
Balances with Banks outside India.		
In Current Accounts.	722·43	283·70
In Short Term Deposits	199·11	70·03
Total	14,092·53	19,337·83

Schedule 2

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Investments in Assited Concerns (At Cost)

Description	Under Section*			As at the 31 st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30th June 1988 Rs. Lakhs
	23 (d)	23 (f)	23 (i)		
(i) Equity Shares	5,184·13	2,691·90	1,985·89	9,861·92	8,807·15
(ii) Preference Shares	305·30	91·00	0·01	396·31	384·76
(iii) Debentures	32·92	439·30	218·67	690·89	425·68
(iv) Application money on Shares and Debentures	94·37	131·79	—	226 16	35·79
Total as at the 31st March, 1989	5,616·72	3,353·99	2,204·57	11,175·28	9,653·38
Total as at the 30th June, 1988	5,226·11	2,410·38	2,016·89	9,653·38	
Quoted					
Book Value				5,818·13	5,069·05
Marked Value				16,298·83	10,288·39
Investments for which quotations are not available.					
Book Value				5,130·99	5,548·54
Break-up value				3,104·83	3,328·64

*Relates to Industrial Finance Corporation Act, 1948.

Schedule 3

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March 89

Loans to Assisted Concerns (Less : Provision for bad & doubtful debts)

Description	Ast at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
(ii) In Indian Rupees.	2,75,576·76	2,25,840·72
(ii) In foreign Currencies	61,676·71	47,480·05
Total	3,37,253·47	2,73,320·77

Notes:

(i) Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	NIL	NIL
(ii) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors.	NIL	NIL
(iii) Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which in the Directors (other than nominees of the Corporation are interested as Directors.	NIL	NIL

Schedule 4

Fixed Assets

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st Mrch, 1989

Description	As at the 31st March 1989			Net Value
	Original Cost	Depreciation to date	As at the 31st March, 1989	As at he 30th June, 1988
	Rs. Lakhs	Rs. Lakhs	Rs. Lakhs	Rs. Lakhs.
Premises				
Freehold Land and Buildings .	775·18	141·07	634·11	562·85
Leasehold Land and Buildings .	810·73	143·20	667·53	388 80
Equipment				
Furniture and Fixtures .	129.22	51.11	78·11	58·20
Office Equipment . .	282·01	157·64	124·37	68·11
Electrical Instalation . .	26·32	20·06	6·26	5·00
Vehicles . . .	18·29	12·48	5·81	7·17
Leased Assets —Plant & Machinery .	2,268·77	640·99	1,627·78	1,310·98
Sub-Total	4,310·52	1,166·55	3,143·97	2,401·11
Advances against capital expenditure .	1,665·83	—	1,665·83	1,501·77
Total	5,976·35	1,166·55	4,809·80	1,902·88
As at the 30th June, 1988 . . .	4,476·92	574·04		

Schedule 5

Other Assets

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31s March, 1989

Description	As the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Interest accrued but not due	5,264·52	6,746·83
Advances to Machinery Suppliers, under Equipment leasing Scheme	4,409·33	
Advances to Machinery Suppliers under Equipment Procurement Scheme	61·66	
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd.	660·60	587·69
Advances to Employees	212·58	179·63
Deposits	59·86	100·65
Difference in Exchange Suspense Account.	3,814·47	2,465·90
Net Assets of Staff Welfare Fund	14·00	14·00
Advance Tax paid	6,612·06	4,943·44
Other Assets	5,042·79	1,204·28
Total	26,151·87	38,242·42

REVENUE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	Amount (Rs.)
INCOME	
Dividend and Interest	164·31
Profit on Sale of Investments (Net)	458·46
Other Income	
Total	622·77
EXPENDITURE	
Management Fees	16·10
Advisor Fees	27·46
Custodian Fees	6·94
Office & Administrative Expenses (Include Directors' Travelling Expenses of Rs. 1,20,857/-)	1.28
Stamp Fee and Bank Charges	42·41
Professional and Legal Fee	2·10
	96·29
Excess of Income over Expenditure Transferred to Revenue Appropriation Account	526.48
Total	622·77

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1989.

(Rupees in lakhs)

	Amount(Rs.)
Balance Transferred from Revenue Account	526·48
Total	526·48
Balance Carried Forward	526·48
Total	526·48

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989.

(Rupees in lakhs)

	Amount Rs.
SCHEDULE 'A'	
CAPITAL	
Unit Capital	4193·66
(41,93,658 Units of Rs. 100/- each includes 9,97,250 Units issued at the time of initial Transfer of Funds and 31,96,408 units issued on subsequent Transfer of Funds)	
Total	4193·66

Schedule 8

Long Term Borrowings — **Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March 1989**

Description	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948—Guaranteed by the Government of India)		
(a) 6-1/4% Bonds	—	3,501·54
(b) 6-1/2% Bonds	7,500·00	7,500·00
(c) 6-3/4% Bonds	7,810·00	7,810·00
(d) 7-1/4% Bonds	10,050·22	10,050·22
(e) 7-1/2% Bonds	10,995·00	10,995·00
(f) 8-1/4% Bonds	7,975·00	7,975·00
(g) 8-3/4% Bonds	8,004·80	8,004·80
(h) 9% Bonds	19,701·00	19,701·00
(i) 9.75% Bonds	32,269·13	32,269·13
(j) 11% Bonds	69,548·00	69,548·00
(k) 11·5% Bonds	39,802·00	15,000·00
(l) 7·6% Bonds (Yen Currency)	5,938·24	5,341·88
(m) 6.9% Bonds (Yen Currency)	5,938.24	5,341.88
(n) 6·3% Bonds (Yen Currency)	5,938·24	5,341·88
	2,31,469·87	2,08,380·33
Borrowings		
(a) From Industrial Development Bank of India under Section 21 (4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	5,765·00	6,185·00
(b) From Government of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	95·68	140·04
(c) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	924·66	747·67
(d) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue	1,247·66	1,159·87
(e) From Foreign Credit Institutions in Foreign Currencies (Including short term bridging loan of Rs. Nil) (Previous year Rs. 14,194·46 lakhs)	97,612·48	59,955·33
Total	3,37,115·35	2,76,568·24

Schedule 9

Current Liabilities and Provisions — **Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989**

Description	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
(1)	(2)	(3)
(A) Current Liabilities		
Sundry Creditors	4,168·21	5,884·81
Interest accrued but not due—		
(a) On Bonds	6,177·21	1,802.85
(b) On Borrowings from Government	4·38	17·75
(c) On Borrowings from Foreign Credit Institutions	1,788·75	764·06
(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others	457·47	262·36

(1)	(2)	(3)
Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	500·00	500·00
Advance receipts	38·30	24·58
Unclaimed Dividend	0·49	0·39
Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government of India out of interest on borrowings in Foreign Currency	1,287·94	1,154·28
(B) Provisions		
Amounts held in suspense—		
(a) Interest	295·00	305·79
(b) Commitment charges	0·05	0·05
(c) Incidental charges	2·38	2·38
Provision for taxation	6,247·22	6,520·37
Provision for dividend	720·70	747·87
Total (B) :	7,265·35	7,576·46
Total (A)+(B) :	21,688·10	17,987·54

Schedule 10

Earmarked Funds

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund	1,028·71	904·48
Special Jute Development Fund	180·10	—
Staff Welfare Fund	136·39	85·17
Total :	1,345·20	989·65

Schedule 11

Interest from Loans, Advances, Deposits & Income from other Financial Assistance

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	Year ended the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Interest Income (Including Rs. 0·81 lakh relating to prior period)	25,158·98	26,830·25
Interest on Short term deposits, etc.	1,838·70	1,250·40
Commitment Charges	460·81	429·84
Lease Rentals	318·05	19·18
Standing Charges	0·80	—
Total :	27,777·34	28,529·67

Schedule 12

Cost of Borrowings

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	Year ended the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Interest on Bonds and Borrowings	21,055·97	20,943·87
Commitment Charges on Foreign Currency loans availed	15·70	3·76
Cost of issue of Bonds (Net of credit Rs. 2·52 lakhs relating to prior period)	290·17	262·07
Total :	21,361·84	21,209·70

Schedule 13

Income from Other Sources

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	Year ended the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Business Service Fee	180·46	192·46
Dividend	280·97	289·23
Profit on Sale of Investments	605·60	333·26
Other Miscellaneous Income	58·55	121·43
Total :	1,125·58	936·38

Schedule 14

Personnel Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	Year ended the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Salary and Allowances	468·83	572·45
Staff Welfare Fund Expenses	2·38	4·08
Other Personnel Expenses	30·64	35·70
Total :	501·85	612·23

Schedule 15

Rental, Maintenance and Depreciation

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	Year ended the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Rent, Taxes, Insurance and Lighting (Including Rs. 1·94 lakhs relating to prior period)	153·59	193·65
Repairs & Maintenance (Includes Rs. 1·40 lakhs relating to prior period)	27·99	39·83
Depreciation (Includes Rs. 5·07 lakhs relating to prior period)	581·07	300·01
Total :	762·25	533·49

Schedule 16

Other Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	Period ended the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	Year ended the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
Audit Fees	1·25	1·25
Travelling and Halting Expenses	25·99	33·30
Communication Expenses	44·90	44·37
Printing, Stationery& Advertiseement	41.67	46.94
Loss on Investments	30.69	2.22
Other Expenses (including contribution to Prime Minister's Relief Fund-Rs. Nil (Previous year—Rs. 25 lakhs)	69·45	86·18
Total :	213·95	214·26

Schedule 17

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES (FORMING PART OF ACCOUNTS)

(A) *Significant Accounting Policies*

1. *Revenue Recognition*

(a) The Corporation does not account for Income by way of Interest, Commitment Charges, Commission, etc., in cases where the possibility of recovery is considered remote. Commitment Charges are accounted for as income only on conclusion of the loan agreements.

(b) Interest on those loans and advances, where Court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amount is received.

2. *Investments*

2.1 Valuation :

Aggregate market value/break-up value of investments is compared to Book Value thereof on a global valuation basis.

2.2 Transactions :

(a) Gains or losses on sale of investments are measured against the average cost of investments sold.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies in liquidation or sick companies which are proposed to be merged with other healthy companies, is accounted for when the final payment is received or the merger is complete.

3. *Exchange Transactions*

(a) The balances of—

(i) foreign currency loans availed of by the Corportion,

(ii) the loans granted to sub borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency account with banks, and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantees undertaken in foreign currency.

are all expressed in Indian Currency at TT selling rates prevailing at the Balance Sheet Date.

(b) Profit, if any, arising on account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions and the louns granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange difference relating to :

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans,

(ii) conversion of year-end foreign currency balances, and

(iii) operations in the foreign currency accounts with Banks.

are accounted for in Difference in Exchange Suspense Account. The contribution received from Central Government, in part reimbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

4. *Fixed Assets* :

(a) Leased assets are depreciated on the Straight Line Method over the primary period of lease of assets or the number of complete years determined with reference to the income tax depreciation rates relating to these assets, whichever is shorter.

(b) Other assets are depreciated by the Written Down Value Method at the rates prescribed by the Income Tax Act, 1961, and the Rules framed thereunder.

(c) The assets are stated at cost less depreciation.

(B) *Notes forming part of Accounts*
(Figures in brackets relate to the previous year)

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of :—

(a) Outstanding underwritting contracts (under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948) Rs. 305.00 lakhs (Rs. 739.00 lakhs),

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as Investment (under Section 20, Section 23 (d) and Section 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948), Rs. 216.32 lakhs (Rs. 13.73 lakhs), and

(c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts, Approx. Rs. 975.83 lakhs (Rs. 1,117.50 lakhs) (net of advances paid).

2. The Income Tax Department/the Corporation have gone in appeal/reference on certain matters in which the earlier orders have gone in favour of/against the Corporation. The disputed liability in this regard amounts to Rs. 55.39 lakhs (Rs. 55.39 lakhs) against which adequate provision exists in the Accounts.

3. Sundry Creditors include Rs. 1,365.61 lakhs (Rs. 2,505.56 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

4. Investments under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, include a sum of Rs. 127.27 lakhs (Rs. 131.69 lakhs) in the share capital of some companies which have either gone into liquidation or which are 'sick' and are proposed to be merged with healthy companies.

5. Up to the 31st March, 1989, a sum of Rs. 56.55 lakhs (Rs. 50.36 lakhs has been utilised partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy Organisations as part of the promotional activities of the Corporation. Hence, these investments have not been included in the 'investment' of the Corporation.

6. An aggregate amount of Rs. 1,626.78 lakhs (Rs. 1,849.55 lakhs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. Besides, a sum of Rs. 35.11 lakhs (Rs. 35.11 lakhs) is due on the Balance Sheet Date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

7. Balances with banks in India in Current Accounts include (a) Rs. 6,800.00 lakhs approx (Rs. 7,900.00 lakhs), invested by bankers in Central and/or State Government securities/units of Unit Trust of India with the concurrence of the Corporation, and (b) Rs. 2,100.00 lakhs (Rs. Nil) in bills under the Bills Rediscounting Scheme of Reserve Bank of India

8. In respect of some of the premises acquired by the Corporation, formalities regarding conveyancing are in the process of completion.

9. Provision for taxation for the year amounting to Rs. 1,002.19 lakhs has been made taking into account the entitlement to the deduction under Section 32AB of the Income Tax Act, 1961 and after taking credit of Rs. 291.18 lakhs in respect of earlier years no longer required. As per the Income Tax Act 1961 as amended the previous year of the Corporation relevant to the Assessment Year 1989-90, relates to the period from 1st July, 1987 to 31st March, 1989.

10. Consequent to the amendment of Income Tax Act, 1961, the accounting year of the Corporation has been changed from 30th June to 31st March. Accordingly, these accounts are for the period from 1st July, 1988 to 31st March, 1989 and as such figures are not comparable with those of the previous year. Previous year figures have been rearranged wherever necessary.

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheets of Unit Scheme 1964, Unit Scheme (ULIP) 1971, Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS) 1981, Capital Gains Unit Scheme (CGS) 1983, Children's Gift Growth Fund (CGGF) 1986, Parents' Gift Growth Fund (PGGF) 1987, Monthly Income Unit Scheme (MIS-POOL), Income Unit Scheme (IUS) 1985 and Growing Income Unit Scheme (GIUS-POOL) of the Unit Trust of India as at 30th June, 1989 and the Revenue Accounts of the respective schemes for the year/period ended on that date, annexed thereto and report that :—

Special attention is invited to the following notes in Schedule 'L' :

1. The Trust has, during the year, changed its method of computing the average cost in working out the profit/loss on sale of equity shares as detailed in note no. 10(I). As a result of the change, the excess of income over expenditure for the year is lower by Rs. 7.28 lakhs under Unit Scheme 1964 and is lower by Rs. 7.28 lakhs under Capital Gains Scheme, 1983 and the cost of investments is lower/higher by such amounts under the respective schemes.

2. Contracts for purchase of shares amounting to Rs. 70.35 lakhs remaining undelivered for over one year shown as investment, where status is unascertained, as stated in Note No. 10(II)-(ii) and (iii).

3. Note No. 11 regarding sizeable discrepancies between the records of the Trust and the holding certificates received from the custodians together with the securities physically held by the Trust which are not quantifiable for the last over many years. The Trust is not able to state the extent and status of investments which should by lying in the safe custody with each of the Custodian as also investments physically on hand with the Trust. Effective steps have not been taken by the Trust to ascertain the difference and reconcile the same with the records of the Trust. Investments lying in custody with the Trust at Calcutta were physically verified. When compared with what should have been with the Trust at Calcutta on the basis of Delivery Instructions for Purchase and Delivery Instructions for Sales advices of Calcutta, there is a marked discrepancy resulting in shortage whose value is Rs. 1001.13 lakhs. We are informed that this discrepancy is on account of investments either lying with the concerned companies for registration in favour of the Trust or on account of Investments in Transit to those companies for such transfers, but no confirmation or other supporting evidence thereof is produced to us. Hence, we are unable to express our opinion as to the existence of investments and impact of the above on the accounts of the Trust.

4. Note Nos. 13, 20, 21(b), 24(c), 25(c)(ii) regarding reconciliation and separation of unpaid dividends. The paid dividends are carried forward along with the figure of unclaimed income distribution. After reconciliation, when necessary entries are made, it will have the effect of increasing/reducing the figure shown as Unclaimed Income Distribution in the liabilities side and bank balances on the assets side. In the absence of all necessary entries for all paid dividend warrants, we are unable to state to what extent the income distribution liability as also the bank balance stand increased decreased.

5. Note No. 14 regarding non-reconciliation of Outstanding and Accrued Income between subsidiary/detailed records and the General Ledger Outstanding balance.

6. As stated in Note No. 16, reconciliation of bank accounts in almost all offices pertaining to income distribution and agency commission, in certain cases repurchase and collection accounts in respect of Open Ended and Closed Ended Schemes, reflecting in their respective books, have remained unreconciled for quite long period and are also not up-to-date. Hence, we are unable to comment as to their effect on the accounts of the Trust.

7. Note Nos. 18(a), 19(a), 22(a), 23(a) and 24(a) regarding reconciliation yet to be completed between the subsidiary records prepared Unit Holder-wise with the total figure shown as Unit Capital under Unit Scheme 1964, CGGF—1986 PGGF—1987 and GIUS(POOL) respectively and the figure of difference not ascertained.

8. The ownership of shares in a company shown at Rs. 35.52 lakhs (Market Value Rs. 460.70 lakhs) is in dispute in a litigation pending in the Court vide note No. 18(d).

9. Non-reconciliation of inter-office balances as state in Note Nos. 18(g)(iii), 19(d), 24(e), 25(e)(i) and 25(f).

10. Note No. 19(c)(i) regarding reconciliation yet to be completed between the subsidiary records with the total figure shown in Sundry Creditors in respect of ULIP 1971 and the quantum of difference not ascertained.

11. Note No. 21(a) regarding short provision of Rs. 3399.23 lakhs on account of depreciation in respect of quoted shares, debentures and bonds in CGS 1983 scheme. However, on a global basis the overall net depreciation on investments will be Rs. 2076.86 lakhs.

12. As stated in Note No. 19(c)(i), 24(b) and 25(c)(i), no provision has been made for :

(i) Income distribution on Units to be allotted for unidentified contributions of ULIP 1971 lying in Sundry Creditors.

(ii) Income distribution on amounts lying in application money under GIUS(POOL).

(iii) Pro-rata dividend payable to unit holders of MIS (POOL) for the period ended 30th June, 1989.

13. As stated in Note No. 24(d)(i), no reconciliation has been done in respect of Balance of Unit Capital, Unclaimed Income Distribution and Premium payable on conversion of I.U.S. 1982 to G.I.U.S. (POOL).

14. In our opinion, keeping in view the Trust's manifold growth in the spheres of activities the internal control systems and procedures and internal audit need to be streamlined, strengthened and improved so as to make the same commensurate with the size of the Trust and nature of its business, particularly, in the areas of investments, fixed assets and establishment.

15. Subject to our comments in paragraphs 1 to 14 above :

(a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit.

(b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Accounting Policies and notes as per Schedule "L" :

(i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;

(ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various schemes of the Trust mentioned above as at 30th June, 1989; and

(iii) the said Revenue Accounts of the respective schemes show a true and fair view of the excess of Income and Expenditure in case of the said schemes for the year/period ended on that date.

For K. K. SONI & CO.
Chartered Accountants

K. K. SONI
Partner

For V. SANKAR AIYAR & CO.
Chartered Accountants

S. VENKATARAMAN
Partner

Bombay
Dated : 11th October, 1989.

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Schedule	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Period
LIABILITIES													
Capital	'A'	447909.83	222710.27	34606.22	25918.31	9699.01	7132.14	89903.13	87498.02	21292.94	12891.88	1654.16	999.85
Reserves and Surplus	'B'	131791.41	56473.51	5566.06	4215.81	667.81	509.10	7610.75	5867.99	248.71	42.74	12.24	17.13
Divided Equalisation Reserve	'C'	9000.00	3500.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Development Reserve Fund	'D'	1241.65	863.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Development Reserve (Offshore Schemes) Fund	'E'	685.97	320.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Current Liabilities & Provisions	'F'	116525.69	66648.75	8849.67	7247.27	1520.83	1160.69	23322.32	12101.38	2442.76	1480.76	129.92	78.94
Total		707154.55	350516.46	49021.95	37381.39	11887.65	8801.93	120836.20	105467.39	23984.41	14415.28	1796.32	1095.92
ASSETS													
Investments	'G'	506618.57	299600.38	30324.46	18755.03	5081.71	4742.82	77576.06	39475.21	13059.79	6825.54	3.00	—
Deposits & Other Investments	'H'	150359.31	26919.96	15381.05	16157.00	5409.00	3699.00	42200.00	53061.00	9293.00	6691.00	1674.00	943.00
Current Assets	'I'	45307.21	20795.42	2419.67	1952.79	1396.94	360.11	1060.14	12931.18	1238.77	637.00	65.92	109.60
Fixed Assets	'J'	4869.46	3200.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred Revenue Expenditure	'K'	—	—	896.77	516.67	—	—	—	—	392.85	261.74	53.40	43.32
Total		707154.55	350516.46	49021.95	37381.39	11887.65	8801.93	120836.20	105467.39	23984.41	14415.28	1796.32	1095.92
Notes to Accounts	'L'												

As per our attached report of even date.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Period
INCOME												
Dividend and Interest	69046.26	35931.30	5597.02	4178.59	1355.12	1022.03	8184.37	9855.50	2626.67	1420.91	232.06	34.89
Profit on Sale/Redemption of Investments (Net)	24220.38	6547.63	1.17	99.73	—	—	1960.38	98.92	—	—	—	—
Committee Charges	135.78	80.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Underwriting Commission	141.63	358.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C.Y.	P.Y.										
Management Fees Received from if and IGF (Net)	334.97	175.88										
Less : Amount Transferred to Development Reserve (Offshore Schemes) Fund (Note 1.(b))	334.96	175.00	0.01	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—
Income Equaliser (Net)	3402.65	1396.00	457.44	343.52	163.00	126.20	359.44	357.03	—	—	—	—
Provision made in earlier years no longer required written back												
1. For Doubtful Income	—	—	36.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. For Depreciation in the Value of Investments	368.30	—	5.47	0.66	6.77	0.65	—	—	—	—	—	—
Other Income	47.20	11.92	—	—	—	—	0.04	0.16	0.12	0.09	—	—
'A'	97362.21	44326.75	6097.34	4622.50	1524.89	1148.88	10504.23	10311.61	2626.79	1421.00	232.06	34.89
Less : Provision For												
1. Depreciation in the value of investments	270.63	2317.49	120.20	3.76	—	—	588.48	896.24	—	—	—	—
2. Outstanding and Accrued Income considered doubtful	1766.98	1625.44	—	94.56	37.50	—	—	—	—	7.65	—	—
3. Maturity Bonus	—	—	716.22	481.30	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	2037.61	3942.93	836.42	579.62	37.50	—	588.48	896.24	—	7.65	—	—
Total ('A'-'B')	95324.60	40383.82	5260.92	4042.88	1487.39	1148.88	9915.75	9415.37	2626.79	1413.35	232.06	34.89

C.Y.—Current Year
P.Y.—Previous Year

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Period
EXPENDITURE												
Salaries, Allowances, Contribution to Provident Fund and Gratuity*	357.93	284.66	64.28	53.18	0.69	0.56	7.20	7.36	10.16	7.00	0.30	0.12
Office expenses**	843.06	548.07	151.59	138.23	2.24	2.94	16.09	69.16	44.73	48.97	0.53	4.25
Publicity Expenses	210.53	168.30	49.26	30.46	0.07	4.01	2.53	10.41	51.37	30.51	—	—
Commission to Agents	1493.91	655.09	89.13	45.95	12.66	5.58	24.28	23.05	—	—	—	—
Bank Charges	287.02	88.13	26.58	6.13	1.94	2.08	76.23	60.88	2.00	0.80	0.20	0.06
Auditor's Fees	2.50	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Deferred Revenue Expenses Written off	—	—	231.63	165.07	—	—	—	—	49.53	30.61	16.06	10.83
Depreciation of Fixed Assets	222.31	142.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3417.26	1889.16	612.47	439.02	17.60	15.17	126.33	170.86	157.79	117.89	17.09	15.26
Less : Amount Recovered on Sale of Units on Account of Management Expenses	2785.99	1718.63	390.03	268.78	13.06	11.61	108.44	98.96	—	—	—	—
	631.27	170.53	222.44	170.24	4.54	3.56	17.89	71.90	157.79	117.89	17.09	15.26
Excess of Income over Expenditure transferred to Revenue Appropriation Account	94693.33	40213.29	5038.48	3872.64	1482.85	1145.32	9897.86	9343.47	2469.00	1295.46	214.97	19.63
Total	95324.60	40383.82	5260.92	4042.88	1487.39	1148.88	9915.75	9415.37	2626.79	1413.35	232.06	34.89

*Includes Chairman's and Executive Trustee's Remuneration and Allowances of Rs. 2.45 lakhs (Previous Year Rs. 2.95 lakhs)

**Includes sitting fees of trustees Rs. 0.06 lakh (Previous Year Rs. 0.03 lakh) and Travelling and other expenses in connection with Board and Committee Meetings Rs. 1.29 lakhs (Previous Year Rs. 1.96 Lakhs).

ALLOCATION OF INCOME AND EXPENDITURE UNDER THE UNIT SCHEME 1964 BETWEEN INITIAL AND UNIT CAPITAL UNDER SECTION 24 AND 25 OF THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963

(Rupees in Lakhs)

	Current Year			Previous Year		
	Total	Initial Capital	Unit Capital	Total	Initial Capital	Unit Capital
Total Income as above	95324·60	106·41	95218·19	40383·82	90·66	40293·16
Less : Total Expenditure as above	631·27	0·71	630·56	170·53	0·39	170·14
Net Income	94693·33	105·70	94587·63	40213·29	90·27	40123·02

*Transferred to Initial Capital Appropriation Account.

** Transferred to Unit Capital Appropriation Account.

As per our attached report of even date.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Unit Scheme 1964				Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
	Initial Capital		Unit Capital		Unit Capital		Unit Capital		Unit Capital		Unit Capital		Unit Capital	
	Current Year	Previous Year	Current Year	previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Period
Balance carried forward from Previous Year	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17·13	—
Balance transferred from Revenue Account	105·70	90·27	94587·63	40123·02	5038·48	3872·64	1482·85	1145·32	9897·86	9343·47	2469·00	1295·46	214·97	19·36
Transferred from Development Reserve Fund (Note 22(b) 23(b))	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35·86	—	2·75	—
Transferred from General Reserve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47·14	—	—
Excess / (Short) Provision for Expenses in Prior Years (Net)	—	—	13·44	(3·85)	(9·96)	(14·60)	2·00	0·09	57·14	(14·87)	3·78	2·15	1·32	—
Total	105·70	90·27	94601·07	40119·17	5028·52	3858·04	1484·85	1145·41	9955·00	9328·60	2508·64	1344·75	236·17	19·63
Income Distribution for the year*	75·00	67·50	80533·77	36664·69	4758·36	3498·97	1454·85	1051·99	8720·60	8399·81	2303·36	1283·53	179·30	—
Income Distribution for Prior Years	—	—	1·89	0·06	37·91	29·00	0·13	0·02	(0·14)	(0·38)	(0·69)	44·77	44·63	—
Transferred to dividend equalisation reserve	—	—	5500·00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Transfered to development Reserve Fund	—	—	—	—	32·50	17·20	6·53	5·81	67·78	61·85	—	16·45	—	2·50
Transferred in General Reserve	30·70	22·77	8565·41	3454·42	199·75	312·87	23·34	87·59	1166·76	867·32	205·97	—	12·24	—
Balance carried to Balance Sheet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17·13
Total	105·70	90·27	94601·07	40119·17	5028·52	3858·04	1484·85	1145·41	9955·00	9328·67	2508·64	1344·75	236·17	19·63
*Rate of income distribution	15%	13·5%	18%	16·5%	13·75%	13·5%	15%	14·75%	9·7%	9·6%	12·5%	12·5%	12·5%	12·5%

As per our attached report of even date.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Period
SCHEDULE 'A'												
Capital												
Initial Capital												
1000 Certificates of Rs. 50000/- each	500.00	500.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unit Capital	447409.83	222210.27	34606.22	25918.31	9699.01	7132.14	89903.13	87498.02	21229.11	12866.77	1640.81	888.04
*(Note 18(a), 19(a), 22(a), 23(a))												
Application Money on Sale of Units	—	—	—	—	—	—	—	—	63.83	25.11	13.35	111.81
TOTAL	447909.83	222710.27	34606.22	25918.31	9699.01	7132.14	89903.13	87498.02	21292.94	12891.88	1654.16	999.85
*Number of Units (in Lakhs)	44740.98	22221.02	3460.62	2591.83	96.99	71.32	8990.31	8749.80	2122.91	1286.67	16.41	8.88
Face value of each Unit	(Rs. 10/-)		(Rs. 10/-)		(Rs. 100/-)		(Rs. 10/-)		(Rs. 10/-)		(Rs. 100/-)	
SCHEDULE 'B'												
RESERVES & SURPLUS												
Unit Premium Reserve (Notes 18 (b),(c), 19(b)												
Balance as per last Balance Sheet	47831.70	25870.30	2635.90	1783.74	167.77	67.52	2242.45	1884.62	—	—	—	
Add : Premium collected during the year (net)	66729.10	22247.78	1157.94	852.96	135.37	100.25	576.00	357.83	—	—	—	
Add : Cost of investments written Down/off in prior years written back	—	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Add : Provision towards doubtful investments and Deposits made in prior years written back	31.55	15.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	114592.35	48134.05	3793.84	2636.70	303.14	167.77	2818.45	2242.45	—	—	—	—
Less : Cost of shares written down/off during the year	38.86	254.12	7.44	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—
Less : Provision towards doubtful investments and deposits	—	48.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	114553.49	47831.70	3786.40	2635.90	303.14	167.77	2818.45	2242.45	—	—	—	—
GENERAL RESERVES												
Relating to Initial Capital												
Balance as per last Balance Sheet	234.56	211.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Transferred from Revenue appropriation account	30.70	22.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUB-TOTAL 'A'	265.26	234.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Currrent Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Pervious Petiod
Relating to Unit Capital												
Balance as per last Balance Sheet	8407.25	8452.82	1579.91	1267.04	341.33	253.74	3625.54	2758.22	42.74	89.88	—	—
Transferred from Revenue appropriation account	8565.41	3454.43	199.75	312.87	23.34	87.59	1166.76	867.32	205.97	—	12.24	—
Appropriation account (Surplus as per Revenue Account)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.13
	16972.66	11907.25	1779.66	1579.91	364.67	341.33	4792.30	3625.54	248.71	89.88	12.24	17.13
Less : (i) Transferred to revenue appropriation account	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.14	—	—
(ii) Transferred to dividend Equilisation reserve	—	3500.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUB-TOTAL 'B'	16972.66	8407.25	1779.66	1579.91	364.67	341.33	4792.30	3625.54	248.71	42.74	12.24	17.13
TOTAL ('A'+'B')	17237.92	8641.81	1779.66	1579.91	364.67	341.33	4792.30	3625.54	248.71	42.74	12.24	17.13
GRAND TOTAL	131791.41	56473.51	5566.06	4215.81	667.81	509.10	7610.75	5867.99	248.71	42.74	12.24	17.13
SCHEDULE 'C'												
Dividend Equalisation Reserve												
Balance as per last Balance Sheet	3500.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Transferred from general reserve	—	3500.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Transferred from revenue appropriation account	5500.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	3000.00	3500.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCHEDULED 'D'												
Development Reserve Fund (Note (a)												
Balance as per last balance sheet	863.73	525.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Add : (a) Contribution during the year	330.16	285.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(b) Interest Income	86.37	52.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1280.26	863.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Less : Transferred to CGGFS 1986 and PGGF 1987	38.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	1241.65	863.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Yeat	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Period
SCHEDULE 'E'												
Development reserve (Offshore Schemes) Fund												
Balance as per last balance sheeet . . .	320.20	132.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Add : (a) Transferred out of Management fees received from if and IGF . .	334.96	175.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(b) Interest Income	32.02	13.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	687.18	320.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Less : Utilisation during the year . . .	1.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	685.97	320.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCHEDULE 'F'												
Current Liabilities & Provisions . . .												
Current Lability												
Sundry Creditors	3987.61	13524.65	1455.47	1366.70	21.13	90.51	12445.88	1060.28	120.88	150.04	4.77	77.00
Contracts for Purchase of Investments . . .	14186.34	987.20	—	—	—	—	0.22	13.32	—	—	—	—
Bank Current Accounts overdrawn as per Books	2017.10	1471.88	210.14	627.67	4.35	7.78	627.08	1671.71	10.98	39.49	26.67	1.94
Unclaimed Income Distribution [Note 13, 20, 21 (b)]	504.08	419.42	—	—	1.68	1.32	25.98	42.18	—	—	—	—
Employees Provident Fund	240.91	191.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'A'	20936.04	16594.61	1665.61	1994.37	26.16	99.61	13099.16	2787.49	131.86	189.53	31.44	78.94
Provisions												
Provision for staff welfare	1.08	1.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provision for Gratuity (Includes Rs. 40.00 Lakhs Towards Erstwhile Employees of Reserve Bank of India)	136.50	115.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
'B'	137.58	116.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provision for Depreciation in the Value of Investments	7863.41	7961.08	272.42	157.69	2.32	9.09	1502.56	914.08	—	—	—	—
Provision for outstanding & Accrued Income Considered Doubtful	5248.53	3481.55	82.97	119.21	37.50	—	—	—	7.65	7.65	—	—
Provision for Doubtful Deposits/debentures/Bonds	1731.36	1762.91	51.50	51.50	—	—	—	—	—	—	—	—
'C'	14843.30	13205.54	406.89	328.40	39.82	9.09	1502.56	914.08	7.65	7.65	—	—

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30th JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C. R. T. S. 1981		C. G. S. 1983		C. G. G. F. S. 1986		P. G. G. F. 1987	
	Current year	Provious year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Provision for Maturity Bonus												
Balance as per Last Balance Sheet	—	—	1425.53	997.39	—	—	—	—	—	—	—	—
Less: Amount Paid During the Year	—	—	122.94	53.16	—	—	—	—	—	—	—	—
Sub Total	—	—	1302.59	944.23	—	—	—	—	—	—	—	—
Add: Amount Provided during the year	—	—	716.22	481.30	—	—	—	—	—	—	—	—
'D'	—	—	2018.81	1425.53	—	—	—	—	—	—	—	—
Income Distribution on : Initial Capital	75.00	67.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unit Capital	80533.77	36664.69	4758.36	3498.97	1454.85	1051.99	8720.60	8399.81	2303.25	1283.48	98.48	—
'E'	80608.77	36732.19	4758.36	3498.97	1454.85	1051.99	8720.60	8399.81	2303.25	1283.48	98.48	—
Total 'A' 'B' 'C' 'D' 'E'	116525.69	66648.75	8849.67	7247.27	1520.83	1160.69	23322.32	12101.38	2442.76	1480.66	129.92	78.94
SCHEDULE 'G'												
Investments (At Cost or at Written Down Cost)												
1. Central and State Government Securities	90621.33	3539.83	—	—	—	—	33000.00	33000.00	—	—	—	—
2. Debentures & Bonds	215133.43	181703.08	19863.08	18319.74	5066.57	4730.68	974.23	123.59	8056.79	6825.54	—	—
3. Preference Shares	1417.01	1201.13	68.65	70.72	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Equity Shares	155835.77	85873.97	392.73	364.57	15.14	12.14	43601.83	6351.62	3.00	—	3.00	—
5. Call paid in Advance	4.75	4.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Term Loans	43606.48	27277.62	10000.00	—	—	—	—	—	5000.00	—	—	—
Total	506618.57	299600.38	30324.46	18755.03	5081.71	4742.82	77576.06	39475.21	13059.79	6825.54	3.00	—
Quoted (At cost)	172061.02	105657.51	1094.30	815.05	12.14	77.10	43796.55	6351.62	—	—	—	—
Unquoted (At cost)	334557.55	193942.87	29230.16	17939.98	5069.57	4665.72	33779.51	33123.59	8109.79	6825.54	3.00	—
'A'	506618.57	299600.38	30324.46	18755.03	5081.71	4742.82	77576.06	39475.21	8109.79	6825.54	3.00	—
Quoted (Market value)	306339.35	166378.16	2721.36	1499.24	100.68	125.69	41719.69	5647.18	—	—	—	—
Unquoted (At Cost)	334557.55	193942.57	29230.16	17939.98	5069.57	4665.72	33779.51	33123.59	8109.79	6825.54	3.00	—
'B'	640896.30	360321.03	31951.52	19439.22	5170.25	4791.41	75499.20	38770.77	8109.79	6825.54	3.00	—
Appreciation/Depreciation in the Value of Quoted Investments ('B'—'A')	134278.33	60720.65	1627.06	684.19	88.54	48.59	(2,07.86)	(704.44)	—	—	—	—

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30th JUNE, 1989

(Rupees in Laksh)

	Unit Scheme 1964		Unit scheme 1971		C. R. T. S. 1981		C. G. S. 1983		C. G. G. F. S. 1986		P. G. G. F. 1987	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Period
SCHEDULE 'H'												
Deposits & other Investments												
With Scheduled Banks	85489.00	3265.39	14905.00	15357.00	1858.00	3373.00	32490.00	42081.00	4818.00	5831.00	244.00	543.00
With Companies/Institutions	63951.52	23172.50	375.00	800.00	3551.00	326.00	9710.00	10980.00	4475.00	860.00	1430.00	400.00
Funded Interest	918.79	482.07	101.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	150359.31	26919.96	15381.05	16157.00	5409.00	3699.00	42200.00	53061.00	9294.00	6691.00	1674.00	943.00
SCHEDULE 'I'												
Current Assets												
Balance with Banks in current Accounts	4130.09	3005.81	283.07	157.73	260.09	0.38	93.71	0.01	148.94	62.95	3.85	88.84
Cash on hand	0.06	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sunsdry Debtors	14383.41	1840.69	55.56	644.21	892.03	12.25	5.62	11988.93	32.45	47.57	16.19	7.31
Contracts for sale of Investments	2114.69	126.09	—	—	—	—	29.60	6.64	—	—	—	—
Outstanding & Accured Income	22146.37	15299.35	2081.04	1150.80	244.82	347.38	931.21	935.60	1057.38	526.48	45.88	13.45
Advances, Deposits, etc.	225.94	134.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Shares/Debentures Application money	1306.65	387.33	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Advance Towards Capital under Venture Capital unit Scheme	1000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	45307.21	20795.42	2419.67	952.79	1396.94	360.11	1060.14	12931.18	1238.77	637.00	65.92	109.60

SCHEDULE 'J'

FIXED ASSETS (Unit Scheme 1964)

(Rupees in Lakhs)

	Gross Block At Cost				Depreciation				Net Block	
	As on 30th June, 1988	Additions/Deductions/ Adjustments	Adjustments	Total to 30th June,89	As on 30th June, 1988	Deudcutions/ Adjustment	For the year 1988-89	Total to 30th June,89	As on 30th June, 1989	As on 30th June, 1988
(1) Land (Lease hold)	168.38	—	—	168.38	17.43	—	2.89	30·32	148.06	150.95
(2) Building	137.63	108.87	—	246.50	42.65	—	11.82	54.47	192.63	94.98
(3) Land (Freehold)	155.80	6.83	—	162.83	—	—	—	—	162.63	155.80
(4) Office Premises (Leasehold)	—	652.23	—	652.23	—	—	10.87	10.87	641.36	—
(5) Ownership Premises	1391.92	1105.58	0.15	2497.35	169.21	—	116.41	285.62	2211.73	1222.71
(6) Furniture & Fixture	221.28	47.63	4.01	264.90	58.36	0.49	20.70	78.57	186.33	162.92
(7) Office Equipments	230.09	53.51	7.31	276.29	77.82	3.72	30.43	104.53	171.76	152.27
(8) Motor Vehicles	17.92	7.26	0.21	24.97	6.69	0.21	3.70	10.18	14.79	11.23
(9) Computors	144.86	42.12	(10.98)	187.96	59.55	(0.97)	25.49	86.01	101.95	85.31
	2467.88	2024.03	10.70	4481.21	431.71	3.45	222.31	650.57	3830.64	2036.17
(10) Advance Towards Purchase of capital Assets	—	—	—	1038.52	—	—	—	—	1038.82	1164.52
Total	2467.88	2024.03	10.70	5520.03	431.71	3.45	222.31	65.057	4869.46	3200.69
Previous Year	1529.08	947.20	8.40	2467.88	290.72	1.95	142.94	431.71	2036.17	1238.36

NOTE (i) Pending Completion of Formalities, lease deed in respect of leasehold office Premise is yet to be Executed in favour of the trust.

(ii) Amoritsation of the lease premium in respect of the teleasehold land and Building Constructed thereon and leasehold office premises have been provided on straight line method over the period of lease.

(iii) (a) Ownership premises include investments represeting ownership of office premises and residential flats in cooperative societies. The shares in respet of five flats in Cooprative housing societies acquired during the year are yet to be received.

(b) Additions to ownership premises and building include Amounts paid forand possession taken in prespect of properties acquired at public auctions under the income tax act, 1961. Provisions on account of stamp duty for executing the necessary conveyance deeds/Agreements has been made and capitalised in the books on account.

(iv) Capital, committments as on 30th, June, 1989 in respect of purchase of fixed assets amount to Rs.1186.16 lakhs.

16—309 GI/89

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

FIXED Assets (Unit Scheme 1964)

(Rupees in lakhs)

	Unit Scheme 1964		Unit Scheme 1971		C.R.T.S. 1981		C.G.S. 1983		C.G.G.F.S. 1986		P.G.G.F. 1987	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous yeas	Current year	Previous year
SCHEDULE 'K'												
Deferred Revenue Expenditure (Note 2(a), (b), (c), (d))												
Balance as per last balance sheet	—	—	516.57	290.39	—	—	—	—	261.74	123.45	43.42	—
Add : Amount Deferred during the year	—	—	611.83	391.25	—	—	—	—	180.64	168.89	26.14	54.15
Less : Amount written off during the year	—	—	1128.40	681.64	—	—	—	—	442.38	292.34	69.46	54.15
	—	—	231.63	165.07	—	—	—	—	49.53	30.60	16.06	10.83
TOTAL	—	—	896.77	516.57	—	—	—	—	392.85	261.74	53.40	43.32

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	Schedule	I.U.S. 1985		G.I.U.S.—POOL		M.I.S.—POOL	
		Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
LIABILITIES							
Capital	'A'	6456.75	6256.22	68100.79	44926.30	167919.33	106877.46
Reserves & Surplus	'B'	377.85	297.69	1011.71	623.79	2857.05	1402.44
Income Distribution/Maturity Premium Equalisation Reserve	'C'	—	—	20.85	—	97.89	—
Current Liabilities & Provisions	'D'	493.80	447.34	5554.68	3730.94	10581.60	6389.26
TOTAL		7328.40	7001.25	74688.03	49281.03	181455.87	114669.16
ASSETS							
Investments	'E'	3590.37	3813.87	16013.37	15676.95	65488.39	73228.61
Deposits & Other investments	'F'	3475.00	2891.00	55364.00	31367.00	102349.26	32723.00
Current Assets	'G'	256.14	275.70	2524.53	1748.57	11935.67	7471.90
Deferred Revenue Expenditure	'H'	6.89	20.68	696.13	488.51	1682.55	1245.65
TOTAL		7328.40	7001.25	74688.03	49281.03	181455.87	114669.16

Notes to Accounts

AS per out attached Report of even date.

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

(REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rs. in lakhs)

	I.U.S. 1985		G I U.S.—Pool		M.I.S.—Pool	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
INCOME						
Dividend and Interest	938.17	902.45	7703.68	5579.72	17377.68	10017.75
Profit on sale of Investments	—	—	—	—	35.77	6.44
Provision for Depreciation in the value of investments made in earlier years no longer required written back	—	—	—	—	—	1.09
Provision for outstanding and accrued income considered doubtful, made in Earlier years no longer required written back	—	—	—	—	37.94	—
Other Income	—	—	0.38	0.01	1.73	—
'a'	938.17	902.45	7704.06	5579.73	17453.12	10025.28
Less : Provision for :						
1. Depreciation in the valuee of Investments	—	—	—	—	56.65	10.36
2. Outstanding and accrued income considered doubtful	—	—	50.82	9.84	—	45.00
'b'	—	—	50.82	9.84	56.65	55.36
TOTAL ('a'—'b')	938.17	902.45	7653.24	5569.89	17396.47	9969.92
EXPENDITURE						
Salaries, Allowances, Contribution to Provident Fund and Gratuity	1.03	1.13	11.27	9.51	13.80	9.11
Office Expenses	2.43	2.64	15.40	17.52	70.05	156.82
Bank Charges	0.36	0.04	7.90	1.50	16.60	14.73
Deferred Revenue Expenses Written off	13.79	13.78	146.49	106.61	346.52	188.68
	17.61	17.59	181.06	135.14	446.97	369.34
Excess of Income over expenditure transferred to revenue appropriation Account	920.56	884.86	7472.18	5434.75	16949.50	9600.58
TOTAL	938.17	902.45	7653.24	5569.89	17396.47	9969.92
Balance carried forward from previous year	—	—	—	—	314.97	199.60
Provision towards conversion expenditure no longer required now written back	—	—	—	29.00	—	—
Excess/(Short) Provision for Expenditure in prior years	(0.87)	(0.03)	(3.69)	(5.44)	28.42	(21.88)
Balance transferred from revenue account	920.56	884.86	7472.18	5434.75	16949.50	9600.58
Transferred from General Reserve	—	—	—	—	—	8.04
TOTAL	919.69	884.83	7468.49	5458.31	17292.89	9786.34
Income distribution for the year*	832.45	811.44	7001.42	5023.26	15182.23	8328.77
Income distribution for prior years	—	—	0.44	(0.16)	(0.32)	387.33
Transferred to development reserve fund	—	—	49.56	51.36	153.08	130.11
Transferred to income distribution/maturity premium equalisation reserve	—	—	20.85	—	97.89	—
Transferred to general reserve	87.24	73.39	396.22	383.85	1860.01	625.16
Balance carried to balance sheet	—	—	—	—	—	314.97
TOTAL	919.69	884.83	7468.49	5458.31	17292.89	9786.34
*Rate of ucome Distribution p.a.	13%	12%	12.5% 13%		12%	

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	U.S. 1985		G. I. U. S.—Pool		M. I. S.—Pool	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
SCHEDULE 'A'						
Capital						
Unit Capital	6456·75	6256·22	68011·33	44926·30	140856·26	83214·31
Application Money on sale of units	—	—	89·46	—	27063·07	23663·15
TOTAL	6456·75	6256·22	68100·79	44926·30	167919·33	106877·46
Number of Units (in lakhs)	64·57	62·56				
Face value of each Unit	(Rs. 100/-)				*	*

***SERIESWISE BREAK-UP OF GIUS—POOL**

Series		Current Year Amount	Current Year No. of Units	Previous Year Amount	Previous Year No. of Units	Face Value of Each Unit
GIUS 1986	—U.C	13484.38	134·84	12547.23	125.47	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
GIUS 1987 (1)	—U.C	12295·41	1229·54	11393·03	1139·30	Rs. 10/-
	—A.M	—	—	—	—	
GIUS 1987 (2)	—U.C	4756·07	47·56	4523·99	45·24	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
GIUS 1987 (3)	—U.C	17741·66	1774·17	16462·05	1646·20	Rs. 10/-
	—A.M	0·90	—	—	—	
GIUS 1989	—U.C	19733·81	1973·38	—	—	Rs. 10/-
	—A.M	88·56	—	—	—	
TOTAL U.C		68011·33	—	44926·30	—	
TOTAL A.M		89·46				
TOTAL		68100·79	—	44926·30	—	

****SERIESWISE BREAK-UP OF MIS—POOL**

Series		Current Year Amount	Current Year No. of Units	Previous Year Amount	Previous Year No. of Units	Face value of Each Unit
MIS. 1	—U.C			869.72	8.70	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
MIS. 2	—U.C			565·71	5·66	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
MIS. 3	—U.C	762·45	7·62	801·01	8·01	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
MIS. 4	—U.C	551·83	5·52	595·62	5·96	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
MIS. 5	—U.C	909·90	9·10	999·64	9·99	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
MIS. 6	—U.C	7375·13	73·75	7429·85	74·30	Rs. 100/-
	—A.M	—	—	—	—	
MIS. 7	—U.C	7625·81	76·26	7685·87	76·86	Rs. 100/-
	—A.M	0·60	—	—	—	
MIS. 8	—U.C	35679·22	356·79	35863·71	358·64	Rs. 100/-
	—A.M	17·73	—	21·27	—	
MIS. 9	—U.C	24811·14	248·11	24888·43	248·88	Rs. 100/-
	—A.M	0·43	—	16·84	—	
MIS. 10	—U·C	28934·40	2893·44	3514·75	351·47	Rs. 10/-
	—A.M	16·06	—	23625·04	—	
MIS. 11	—U.C	34206·38	3420·64	—	—	Rs. 10/-
	—A.M	89·48	—	—	—	
MIS. 12	—UC	—	—	—	—	Rs. 10/-
	—A.M	26938·77	—	—	—	
TOTAL	U.C.	140856·26	—	83214·31	—	
TOTAL	A. M.	27063·07	—	23663·15	—	
TOTAL		167919·33	—	106877·46	—	

U.C—Unit Capital

A.M—Application Money on Sale of Units.

(ESTABLISED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	I.U. S. 1985		G.I.U.S.—Pool		M.I.S.—Pool	
	Current year	Previous year	Current Year	Previous year	Current year	Previous year
SCHEDULE 'B'						
RESERVES & SURPLUS						
General Reserve*						
Balance as per last Balance Sheet	297·69	228·33	623·79	239·40	1087·47	476·50
Balance transferred from IUS 1982	—	—	—	0·54	—	—
Transferred from Revenue appropriation account (Note 5)	87·24	73·39	396·22	383·85	1860·01	625·16
	384·93	301·72	1020·01	623·79	2947·48	1101·66
Less : 1. Premium paid on conversion of Capital into MISG(8)	—	—	—	—	—	6·15
2. Premium paid on Repurchase	7·08	4·03	8·30	—	—	—
3. Premium paid on Maturity	—	—	—	—	90·43	—
4. Transfer to Revenue appropriation A/c	—	—	—	—	—	8·04
	7·08	4·03	8·30	—	90·43	14·19
	377·85	297·69	1011·71	623·79	2857·05	1087·47
Revenue appropriation Account (Surplus as per Revenue A/c)	—	—	—	—	—	314·97
TOTAL	377·85	297·69	1011·71	623·79	2857·05	1402·44

SERIESWISE BREAK-UP OF GIUS—POOL

Series	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Balance as on 30-06-1988	Transferred from Revenue Appropriation Account	Premium on Repurchase of Units	Balance as on 30-06-1989	Balance as on 30-06-1987	Transferred from Revenue Appropriation Account	Transferred from IUS 1982	Balance as on 30-06-1988
GIUS 1986	308·22	98·45	(8·30)	398·37	221·61	86·61	—	308·22
GIUS 1987 (I)	196·33	89·16	—	285·49	17·79	178·54	—	196·33
GIUS 1987 (II)	116·00	34·78	—	150·78	—	115·46	0·54	116·00
GIUS 1987 (III)	3·24	126·67	—	129·91	—	3·24	—	3·24
GIUS 1989	—	47·16	—	47·16	—	—	—	—
TOTAL	623·79	396·22	(8·30)	1011·71	239·40	383·85	0·54	623·79

SERIESWISE BREAKUP OF MIS—POOL

(Rupees in lakhs)

Series	CURRENT YEAR					PREVIOUS YEAR			
	Balance as on 30-06-1988	Transfer from Appropriation Account	Premium Paid on Maturity	Transferred from (To) General Reserve [(Note 25(b)]	Balance as on 30-06-1989	Balance as on 30-06-1987	Transfer from/ (To) Appropriation Account	Premium Paid on conversion to MIS 8	Balance as on 30-06-1988
MIS (1)—83 . .	87·08	—	(52·06)	(35·02)	·00	96·99	(8·04)	(1·87)	87·08
MIS 2)—83 . .	77·14	—	(38·37)	(38·77)	·00	59·04	19·33	(1·23)	77·14
MIS (3)—84 . .	102·06	12·66	—	—	114·72	75·88	27·72	(1·54)	102·06
MIS (4)—85 . .	50·41	8·83	—	—	59·24	37·94	13·44	(0·97)	50·41
MIS (5)—85 . .	83·64	14·55	—	—	98·19	72·74	11·44	(0·54)	83·64
MISG (6)—86 . .	181·56	110·67	—	—	292·23	98·16	83·40	—	181.56
MISG (7)—86 . .	161·54	114·06	—	—	275·60	35·75	125·79	—	161.54
MISG (8)—87 . .	260·11	526·61	—	73·79	860·51	—	260.11	—	260·11
MISG (9)—87 . .	83·93	364·61	—	—	448·54	—	83·93	—	83·93
MISG (10)—88 . .	—	424·00	—	—	424·00	—	—	—	—
MISG (11)—88 . .	—	251·14	—	—	251·14	—	—	—	—
MISG (12)—89 . .	—	32·88	—	—	32·88	—	—	—	—
TOTAL . .	1087·47	1860.01	(90·43)	—	2857·05	476·50	617·12	(6·15)	1087·47

	I.U.S. 1985		G.I.U.S.—Pool		M.I.S.—Pool	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
SCHEDULE 'C'						
Income Distribution/Maturity Premium Equalisation Reserve [(Note 25(d), 24(f)]						
Transferred from Revenue Appropriation A/c	—	—	20·85	—	97·89	—
TOTAL	—	—	20·85	—	97·89	
SCHEDULE 'D'						
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS						
Current Liabilities						
Sundry Creditors	43·60	23·26	591·72	562·61	1314·96	1960·44
Bank current accounts overdrawn as Per books	8·03	8·57	83·98	49·64	166·50	171·69
Unclaimed income distribution [Note 24(i), 25(i) (ii)]	22·48	8·86	717·61	342·12	8984·67	4160·37
'a'	74·11	40·69	1393·31	954·37	10466·13	6292·50

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA, ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	I.U.S. 1985		G.I.U.S.—Pool		M.I.S.—Pool	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Provisions						
Provision for depreciation in the value of investments	—	—	—	—	90·03	33·38
Provision for outstanding & accrued income considered doubtful	—	—	60·66	9·84	25·44	63·38
'b'	—	—	60·66	9·84	115·47	96·76
Income distribution on unit capital 'c'	419·69	406·65	4100·71	2766·73	—	—
TOTAL ('a'+'b'+'c')	493·80	447·34	5554·68	3730·94	10581 60	6389·26
SCHEDULE 'E'						
INVESTMENTS (AT COST)						
1. Debentures & Bonds	3590·37	3813·87	15403·37	15676 95	45486·39	46073·36
2. Equity Shares	—	—	—	—	2·00	—
3. Term Loans	—	—	700·00	—	20000·00	10000·00
4. Government Securities	—	—	—	—	—	17155·25
	3590·37	3813 87	16103·37	15676·95	65488·39	73228·61
Quoted (At Cost)	—	—	—	—	3382·88	19493·15
Unquoted (At Cost)	3590·37	3813·87	16103·37	15676·95	62105·51	53735·46
'a'	3590·37	3813 87	16103·37	15676·95	65488 39	73228·61
Quoted (Market Value)	—	—	—	—	3352·22	19627·59
Unquoted (At Cost)	3590·37	3813·87	16103·37	15676·95	62105·51	53735·46
'b'	3590·37	3813·87	16103 37	15676·95	65457·73	73363 05
Appreciaiton/(Depreciation) in value of Quoted Investments ('b'—'a')	—	—	—	—	(30·66)	134·44
SCHEDULE 'F'						
Deposits and Other Investments						
With Scheduled Banks	3475·00	2891·00	19079·00	21000·00	62296·00	21026 00
With Companies	—	—	36285 00	10367·00	39985·00	11697·00
Funded Interest	—	—	—	—	68·26	—
TOTAL	3475·00	2891 00	55364·00	31367 00	102349·26	32723 00

SCHEDULE 'G'

Current Assets

Balance with Banks in Current Accounts	9 89	11 44	1062 42	490 07	8455·14	3643·13
Sundry Debtors	0·30	—	8·25	210·42	279 47	782·57
Outstanding & Accrued Income	245·95	264·26	1453·86	1048·08	3201·06	3046·20
TOTAL	256·14	275·70	2524·53	1748·57	11935 67	7471·90

SCHEDULE 'H'

Deferred Revenue Expenditure

Balance as Per Last Balance Sheet	20·68	34·46	488·51	277·22	1245·65	509·54
Add : Amount Deferred during the year	—	—	354·11	317·90	890·07	924·79
	20·68	34·46	842 62	595·12	2135·72	1434·33
Less : Amount excess deferred in 1987-88 adjusted	—	—	—	—	106·65	—
Less : Amount written off during the year	13·79	13·78	146·49	106·61	346·52	188·68
TOTAL	6·89	20·68	696·13	488·51	1682·55	1245·65

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS AS AT 30TH JUNE, 1989

SCHEDULE 'L'

ACCOUNTING POLICIES

1. In accordance with the provisions of Section 25(B)(1) of the Unit Trust of India Act, 1963, the following funds have been created, which, though belonging to the Trust, are accounted for by the Unit Scheme 1964 as a matter of administrative convenience.

(a) *Development Reserve Fund*

The Fund is built up by income earned on its own resources and contributions made by the subsequent Schemes every year, based on the Unit Capital mobilised under those Schemes during the year. The Reserve Fund is to be utilised for Research, Promotional, Development and other related activities of the Trust.

(b) *Development Reserve (Offshore Scheme) Fund*

The Fund is built up by transferring Management Fees earned by the Trust for services rendered to the India Fund Unit Scheme, 1986, and the India Growth Fund Unit Scheme, 1988. The Reserve Fund is to be utilised for developmental and promotional expenses of overseas funds/offshore schemes.

2. *Deferred Revenue Expenditure*

(a) *Unit Scheme* 1971

(i) Out of the total amount of commission paid/payable to the individual agents on initial contributions, 40% has been charged to the current year's Revenue Account and the balance 60% is deferred over a period of 9 years/14 years, this being the remaining term of the Plans under the Scheme.

(ii) Commission paid/payable to individual agents, on renewal contributions is deferred over a period of 9 years/14 years, this being the remaining term of the Plans under the Scheme.

(iii) Commission to individual agents short provided in the earlier years included in excess/short provision account has been fully charged to the current year's Revenue Account.

(b) *Childrens Gift Growth Fund Unit Scheme* 1986 *(CGGF* 86)

Commission to individual agents is deferred over a period of 10 years. Accordingly, proportionate amount of total commission relating to current year has been written off to Revenue Account and the balance amount of Rs. 162.58 lakhs (Previous year Rs. 152.00 lakhs) has been carried forward under "Deferred Revenue Expenditure".

(c) *Parents Gift Growth Fund Unit Scheme* 1987 *(PGGF* 87)

The initial expenditure comprising of commission to Agents, publicity, etc. is being defered over a period of 5 years. Accordingly, an amount of Rs. 20.91 lakhs (Previous year Rs. 43.32 lakhs) has been carried forward under "Deferred Revenue Expenditure" after charging proportionate amount to the current year's Revenue Account.

(d) In accordance with the provisions of Section 25(3) of the Unit Trust of India Act, 1963, all initial direct expenses including commission to Agents, incurred by the closed ended schemes are written off over the duration of the respective schemes. The balance of expenditure remaining to be written off is being carried foward as "Deferred Revenue Expenditure".

3. *Allocation of Common Expenses.*—In accordance with the provisions of Section 25(4) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses incurred by the Unit Scheme 1964, have been identified as common expenses and allocated to the other schemes on certain basis as decided by the Trust. Accordingly, expenditure of each scheme includes the element of common expenses as allocated to it.

4. *Pool Accounting.*—The Trust has adopted the procedures of "Pool Accounting" for maintaining accounts of all Closed Ended Schemes with effect from 1st July 1988. Accordingly, accounts of all the series of Growing Income Unit Scheme (GIUS) and Monthly Income Scheme with Extra Growth (MISG) have been drawn up by pooling together their Investments, Income, Expenses, Assets and Liabilities under respective schemes.

5. *Distribution of Net Surplus of various series of Growing Income Unit Scheme and Monthly Income Unit Scheme.*—Consequent to the adoption of "Pool Accounting" procedure, as stated in 4 above, after appropriation of Income Distribution, transfers to Development Reserve Fund and Income Distribution/Maturity Premium Equalisation Reserve, the resultant net surplus has been allocated to each series under respective scheme in proportion to the total of Unit Capital and General Reserve, taking into account the period for which series remained in operation during the year. However, no surplus has been allocated to series which terminated during the year. The period for which sales were kept open with regard to new series launched during the year has also not been reckoned while allocating the net surplus.

6. Death/Accident claims to claimants under Unit Linked Insurance Plan (1971) are accounted for on actual payment basis.

7. Income has been accounted for as under :

(a) Dividend Income on the date of the Annual General Meeting.

(b) Miscellaneous Income and underwriting commission on actual receipt basis.

(c) All other income on accrual basis.

8. Investments also include money paid on application towards subscription for Rights Securities awaiting allotment.

9. *Depreciation in the value of Investments*

(i) Depreciation has not been provided on the Government Securities.

(ii) In case of Quoted Investments, if the security has not traded for a period of six months or more prior to the Balance Sheet date the same is treated as Unquoted Investment and Depreciation, if any, computed accordingly.

(iii) In respect of Debentures and Bonds, depreciation has been computed as under :

(a) In case of Quoted Debentures and Bonds, where the market value is less than the cost, difference between the cost and the market value.

(b) In case of unquoted debentures and bonds, the difference between the cost and marked-down cost calculated on the basis of the rate of normal yield. Normal yield is taken at the prevailing maximum rates of interest as at 30th June 1989, being 12.5% (Previous year 12.5%) for Convertible debentures/Bonds and 14% (Previous year 14%) for Non-Convertible Debentures/Bonds as stipulated in the guidelines issued by the Government of India.

(c) In case of Privately Placed Debentures and Bonds, where the yield is less than 14% (Previous year 14%), the difference between the cost and the marked-down cost calculated on the basis of the said rate of yield.

(iv) In respect of Equity and Preference Shares, Depreciation has been computed as under :

(a) In case of Quoted Equity and Preference shares, where the Market Value is less than the Cost, difference between the cost and market value.

(b) In case of Unquoted Equity Shares, where the intrinsic value is less than the Cost difference between the Cost and the Intrinsic value.

(c) In case of Unquoted Preference Shares, the difference between the Cost and Marked-down Cost calculated on the basis of the normal yield. Normal yield is taken at the prevailing maximum rate of interest as at 30th June 1989, being 14% (Previous year 14%) as stipulated in the guidelines issued by the Government of India.

NOTES

10. *Investments*

(I) The Trust has changed the method of computing the average cost in determining the profit/loss on sale of Equity Shares. The cost of the Rights shares and the shares received on conversion of debentures, which hithertofore were not considered while computing the average cost has been added to the cost of the purchased shares, as increased by the number of bonus shares and the aggregate cost is reckoned to arrive at the average cost for accounting profit/loss on sale of investments and also for effecting the cost of the balance shares in the Balance Sheet. Consequent to the above change, the excess of income over expenditure for the year is higher and cost of investments lower as follows :—

(a) Unit Scheme 1964 Rs. 844.23 lakhs.

(b) Capital Gains Scheme 1983 Rs. —7.28 lakhs.

(II) Investments include contracts awaiting completion for purchase of Shares, Debentures and Bonds :

	Current Year (Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)
(a) Unit Scheme 1964	14186.34	987.20
(b) Capital Gains Scheme 1983	0.23	13.32

Of the above :

(i) Contracts completed as at the Balance Sheet date but advised subsequently by the Bankers amount to :

	Current Year (Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)
Unit Scheme 1964	11417.78	400.85
Capital Gains Scheme, 1983	0.17	13.09

(ii) Contracts for which deliveries are outstanding for years awaiting settlement with parties amount to:

	Current Year (Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)
Unit Scheme 1964	70.12	26.17
Capital Gains Scheme, 1983	0.23	NIL

(iii) Investments include Rs. 255.98 lakhs on account of contracts for purchase of shares which remain undelivered for over two years for lack of necessary information from the bankers and brokers. Hence, their present status is unascertainable.

(III) Investments exclude contracts awaiting completion for sale of shares, debentures and bonds :

	Current Year (Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)
(a) Unit Scheme 1964	1158.40	61.30
(b) Capital Gains Scheme, 1983	30.10	5.59

The Profit (Net) on these sale contracts amounting to Rs. 956.28 lakhs and Rs. —0.50 lakhs pertaining to Unit Scheme 1964 and Capital Gains Scheme 1983 respectively, has been booked as Income under the head "Profit/Loss on Sale/Redemption of Investments".

11. The investments of the Trust are kept in safe custody with Bankers of the Trust, Industrial Investment Trust Ltd., Stock Holding Corporation of India Ltd. and on hand with the Trust. Holding Certificates received from these parties alongwith investments physically on hand with the Trust, when compared with the records of the Trust show sizeable differences. In most of the cases, investments as per the holding certificates are observed to be short, while in few cases the same are more, when compared with the Trust's records. In the opinion of the Trust, there are certain discrepencies in the Holding Certificates. As a result thereof and also in the absence of maintenance of custodianwise records by the Trust, exhibiting various investments to be actually held by each of the custodians separately, the discrepencies between the records of the Trust and the Holding Certificates alongwith the physical holding of the Trust are not quantifiable. Necessary steps are being taken to ascertain the difference and reconcile the same with the records of the Trust. Discrepancies if any, in respect of the above, on completion of reconciliation, will be to the account of Unit Scheme 1964.

12. The cost of investments include brokerage but does not include acquisition charges comprising stamp fee and bank charges, which have been booked as revenue expenditure under the Office Expenses on the basis of advices received from the custodians of the investment as follows :

	Current Year (Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)
(a) Unit Scheme 1964	471.74	174.17
(b) Capital Gains Scheme, 1983	0.11	5.02

13. *Unclaimed Income Distribution Account*

Necessary entries for all paid Dividend Warrants are not reflected in the books of accounts. In a large number of cases, reconciliation of Unpaid Dividend Warrants is pending. The requisite entries will be effected on completion of its reconciliation.

14. *Income Receivable Account*

The outstanding balance as per General Ledger under the head "Outstanding and accrued income" has not been reconciled with subsidiary/detailed records.

15. *Sundry Debtors/Creditors*

Sundry Debtors/Creditors include inter-scheme dues as under :

(Rs. in lakhs

No.	Scheme	Due to other Schemes (included in Creditors)		Due from other Schemes (included in Debtors)	
		Current year	Previous year	Current year	Previous year
1.	Unit Scheme 1964	2539·51	1386·96	13492·97	295·60
2.	Unit Scheme 1971 (ULIP)	352·13	163·47	0·01	604·63
3.	C.R.T.S. 1981	7·77	39·03	892·03	1·00
4.	C.G.S. 1983	12313·90	60·00	—	282·38
5.	C.G.G.F. 1986	18·22	12·75	26·43	4·04
6.	P.G.G.F. 1987	0·54	20·99	16·07	2·27
7.	M.I.S. (Pool)	190·73	107·53	188·55	372·43
8.	G.I.U.S. (Pool)	216·72	35·95	—	214·33
9.	I.U.S. 1985	2·42	—	—	—
10.	Mutual Fund	390·55	—	—	25·00
11.	India Fund	—	—	—	25·00
12.	VECAUS 1989	—	—	1416·43	
	Total	16032·49	1826·68	16032·49	1826·68

16. *Bank Reconciliation*

Reconciliation of bank accounts in almost all offices pertaining to payment of income distribution and agency commission, in certain cases repurchase accounts and collection accounts in respect of open-ended and closed-ended schemes, reflected in their respective books, remained unreconciled for quite long period and are also not up-to-date. The Trust has entrusted the job to some professional firms of Chartered Accountants to attend to all pending work connected with reconciliation of Bank Accounts, both for operative as well as at par accounts. Necessary adjustments will be carried out on completion of the above assignment, which is in progress.

17. *Previous year's figures*

Previous year's figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

18. UNIT SCHEME 1964

(a) *Reconciliation of Unit Capital*

Reconciliation of Unit Capital with subsidiary/detailed records is still in progress and adjustments, if any, will be made on completion of reconciliation.

(b) *Unit Premium Reserve Account*

(i) In respect of certain investment in companies, the cost of which was written off in earlier years, where such companies have subsequently improved their financial position by showing a positive net worth and have declared dividend during the year, a sum of Rs. NIL (Previous year Rs. 0.52 lakhs) has been written back to Unit Premium Reserve Account.

(ii) In respect of certain deposits in companies, the principal amount of which was provided in earlier years, where such companies have subsequently repaid the principal amount of deposit during the year, a sum of Rs. 31.55 lakhs (Previous year Rs. 15.45 lakhs) has been written back to Unit Premium Reserve Account.

(c) The following provisions towards doubtful investments and deposits have been charged to Unit Premium Reserve Account :

(i) In respect of Debentures and Bonds, net amount of Rs. NIL (Previous year Rs. 48.23 lakhs) towards principal amount.

(i) In respect of Unquoted shares in companies whose accumulated losses exceed their aggregate capital and reserve Rs. 38.86 lakhs (Previous year Rs. 254.12 lakhs) by writing down the value to Re. 1/-.

(d) *Investments*

Investment amounting to Rs. 35.52 lakhs (Market value Rs. 460.71 lakhs) in the shares of a Company are not registered in the name of the Trust on account of Stay granted by the Court since the ownership is disputed.

(e) The funds of Unit Trust of India Employees' Provident Fund stand invested alongwith other investments of the Trust and are vested in Unit Scheme 1964, on which the Scheme pays interest at the rate determined by the Trust

(f) *Sundry Debtors*

Include Rs. 3.20 lakhs (Previous year Rs. 2.95 lakhs) being income distribution representing excess payments made on basis of duplicate warrants and are recoverable from Unit Holders. The Trust is taking necessary steps for their recovery/adjustment.

(g) *Sundry Creditors*

Include :

(i) A sum of Rs. 5.47 lakhs (Previous year Rs. 6.79 lakhs) being the balance amount payable to Unit Holders of the Unit Scheme 1976, whose assets and liabilities have been taken over with effect from 1st July 1981 upon closure of that Scheme.

(ii) A sum of Rs. 34.24 lakhs (Previous year Rs. NIL) being the balance amount payable to the Unit Holders of the Growth and Income Unit Scheme, 1983, whose assets and liabilities have been taken over with effect from 1st July 1988, upon closure of that Scheme.

(iii) Include inter-office balances of Rs. 8.65 lakhs (Previous year Rs. 9.95 lakhs) which are still under reconciliation.

(h) *Contingent Liability*

(i) On account of Uncalled Liability on partly paid Shares and Debentures is Rs. 3683.44 lakhs (Previous year Rs. 199.43 lakhs).

(ii) In respect of unexpired underwriting contracts for Shares and Debentures is Rs. 3591.10 lakhs (Previous year Rs. 2385.01 lakhs).

19. UNIT SCHEME 1971

(a) *Reconciliation of Unit Capital*

Reconciliation of Unit Capital with subsidiary/detailed records is still in progress and adjustments if any will be made on completion of reconciliation.

(b) *Unit Premium Reserve Account*

An amount of Rs. 7.44 lakhs (Previous year Rs. 0.80 lakh) has been charged to Unit Premium Reserve Account on account of provision for doubtful investments and deposits.

Sundry creditors include :

(i) Rs. 703.68 lakhs (Previous year Rs. 444.37 lakhs) received from the year 1980-81 onwards on account of sale of units for which adjustments to the Unit Capital and Premium Accounts remain to be made pending security thereof. Necessary provision for Income Distribution thereon will be made on completion of such scrutiny. Of the above reconciliation with subsidiary records is pending in respect of Rs. 87.45 lakhs (Previous year Rs. 58.66 lakhs) being the Income Distribution to Ex-members, Rs. 30.85 lakhs (Previous year Rs. 20.68 lakhs) being the amount received under Salary Savings Scheme and Rs. 227.68 lakhs (Previous year Rs. 159.05 lakhs) being the amount received on account of sale of units, for which all the necessary particulars are not available.

(ii) Inter-Office balances of Rs. NIL (Previous year Rs. 0.18 lakh) which is pending reconciliation.

(d) *Sundry Debtors*

Include Inter-Office balances of Rs. 9.08 lakhs (Previous year Rs. 0.92 lakh) which is pending reconciliation.

(e) *Contingent Liability*

In respect of Uncalled Liability on partly paid shares and debentures is Rs. 13.98 lakhs (Previous year Rs. NIL).

20. UNIT SCHEME FOR CHARITABLE RELIGIOUS TRUSTS AND REGISTERED SOCIETIES 1981.

Unclaimed Income Distribution Account

Income Distribution Warrants for the year 1987-88 have been accounted for as paid in the books of the scheme on the basis of despatch of warrants. No entries for unpaid warrants are made in the books of account.

21. CAPITAL GAINS UNIT SCHEME, 1983

(a) *Depreciation in the value of investments*

In respect of investments in Quoted Shares, Debentures and Bonds where the market value is less than the cost, the depreciation in the value works out to Rs. 4901.79 lakhs (Previous year Rs. 914.08 lakhs). The depreciation already provided upto 30th June 1988 is Rs. 914.08 lakhs. Against the additional depreciation of Rs. 3987.87 lakhs required to be provided, an ad-hoc provision of Rs. 588.48 lakhs has been made during the year. However on a global basis the overall net depreciation on investments will be Rs. 2076.86 lakhs.

(b) *Unclaimed Income Distribution Account*

Income Distribution Warrants for the year 1987-88 have been accounted for as paid in the books of the Scheme on the basis of despatch of warrants. No entries for unpaid warrants are made in the books of account.

22. CHILDRENS GIFT GROWTH FUND UNIT SCHEME 1986 (CGGF 86)

(a) *Unit Capital*

Reconciliation in respect of Unit with subsidiary/detailed records is still in progress and adjustments, if any will be made on completion of reconciliation.

(b) *Contribution to Development Reserve Fund*

In terms of the decision taken at the Executive Committee Meeting held in June 1984, an amount equivalent to 0.25% of the funds mobilised for the years 1986-87 and 1987-88 was transferred to the Development Reserve Fund accounted for under Unit Scheme 1964. The Executive Committee at their meeting held on 7th July 1989, in supersession of the earlier decision, exempted the Scheme from making such contribution retrospectively. As a result of this, a sum of Rs. 35.86 lakhs has been credited to the Appropriation Account.

(c) *Sundry Debtors*

Include Inter-Office balances of Rs. NIL (Previous year Rs. 1.37 lakhs) pending reconciliation.

23. PARENTS GIFT GROWTH FUND UNIT SCHEME 1987 (PGGF 87)

(a) *Unit Capital*

Reconciliation in respect of Unit Capital with subsidiary/detailed records is still in progress and adjustments, if any, will be made on completion of reconciliation.

(b) *Contribution to Development Reserve Fund*

In terms of the decision taken at Executive Committee Meeting held in June 1984, an amount equivalent to 0.25% of the Funds mobilised for the year 1987-88 was transferred to the Development Reserve Fund accounted for under Unit Scheme 1964. The Executive Committee at their meeting held on 7th July 1989, in supersession of the earlier decision, exempted the Scheme from making such contribution retrospectively. As a result of this, a sum of Rs. 2.75 lakhs has been credited to the Appropriation Account.

24. GROWING INCOME UNIT SCHEME (POOL)

(a) *Unit Capital*

(i) Reconciliation of Unit Capital in respect of GIUS, 1987 (I), GIUS. 87 and (II) GIUS 1989 with subsidiary/detailed records is still in progress and adjustments, if any, will be made on completion of reconciliation.

(ii) Pending receipt/scrutiny of applications, the amount received on sale of units under various GIUS series has been kept in Application Money Account.

(b) *Income Distribution*

No provision has been made for income distribution for amounts received towards Unit and lying in application money.

(c) *Unclaimed Income Distribution*

Necessary entries for all paid dividend warrants are not reflected in the books of account. In a large number of cases, reconciliation of unpaid dividend warrants is pending. The requisite entries will be effected on completion of reconciliation.

(d) *Sundry Creditors*

Includes :

(i) The following payable to Unit Holders of Unit Scheme 1982 :

(A) Balance of Unit Capital Rs. 94.70 lakhs (Previous year Rs. 162.80 lakhs).

(B) Unclaimed Income Distribution Rs. 44.61 lakhs (Previous year Rs. 46.78 lakhs).

(C) Premium payable on conversion Rs. 3.79 lakhs (Previous year Rs. 6.65 lakhs).

Reconciliation of the above accounts with subsidiary/detailed recordes has not been conducted and hence adjustments, if any, will be made on completion of reconciliation.

(ii) Sundry creditors include Inter-Office balance of Rs. NIL lakhs (Previous year Rs. 2.72 lakhs) pending reconciliation.

(e) *Sundry Debtors*

Includes Inter-Office balance of Rs. 0.02 lakhs (Previous year Rs. 0.20 lakhs) pending reconciliation.

(f) *Income Distribution/Maturity Premium Equalisation Reserve*

During the year, an amount equivalent to 5% of the net surplus in Revenue Appropriation Account before allocating net surplus to the individual series has been transferred to "Income distribution Maturity Premium Equilisation Reserve".

25. MONTHLY INCOME UNIT SCHEME WITH EXTRA BONUS PLUS GROWTH (MISG) POOL

(a) *Capital*

Pending receipt/scrutiny of applications, the amount received on sale of units under various MISG series has been kept in Application Money Account.

(b) *General Reserve*

As most of the unitholders of MIS(1) and MIS(2) series have opted for conversion to MIS(8) series, the residual reserve under MIS(1) and MIS(2) series, after distribution to the unitholders of those series, have been transferred to the General Reserve of MIS(8).

(c) *Income Distribution*

(i) As per the provisions of the Scheme, pro-rata Income Distribution for the period upto the year ended 30th June 1989 is payable @ 12% p.a. to the unitholders of the scheme. An amount of Income Distribution in respect of the sale proceeds of units shown under application money will be accounted for at the time of capitalisation alongwith the Income Distribution for that year.

(ii) Post dated Monthly Income Distribution Warrants under all the MISG series despatched in advance are encashable on due dates. Necessary entries for paid warrants have not been fully reflected in the books of accounts. In a large number of cases, reconciliation of unpaid warrants is still in progress and entries will be made on completion of the same.

(d) *Income Distribution/Maturity Premium Equilisation Reserve*

An amount equivalent to 5% of the net surplus in Revenue Appropriation Account before allocating net surplus to the individuals series has been transferred to "Income Distribution/Maturity Premium Equivilisation Reserve" during the year.

(e) *Sundry Creditors*

Includes

(i) Inter-Office balance of Rs. 1.28 lakhs (Previous year Rs. 3.68 lakhs) pending reconciliation.

(ii) Rs. 114.49 lakhs (Previous year Rs. 182.60 lakhs) being unreconciled premium amount of MISG(8) due to unitholders for MIS(1) to MIS(5).

(f) *Sundry Debtors*

Includes Inter-Office balance of Rs. 3.59 lakhs (Previous year Rs. 22.50 lakhs) pending reconciliation.

AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

For V. SHANKAR AIYER & CO.
Chartered Accountants
A. P. KURIAN
(Executive Trustee)

For K. K. SONI & CO.
Chartered Accountants
S. VENKATARAMAN
(Partner)

K. N. ATMARAMANI
Chief General Manager
(Finance & Investments)

M. J. PHERWANI
Chairman

K. K. SONI
(Partner)

C. G. PAREKH
Joint General Manager
(Accounts)

J. S. VARSHNEYA, S. H. KHAN, B. K. JHAWAR, K. GANESAN & N. K. SHINKAR
Trustee

Bombay
Dated : 11th October 1989

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 (VECAUS-89) of the UNIT TRUST OF INDIA (hereinafter called the "Scheme") as at 30th June, 1989 and the Revenue Account of the said scheme for the period ended on that date, annexed thereto and report that :—

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us read together with notes to accounts as per Schedule 'F' :

(i) the said Balance Sheet is full and fair containing all the necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act 1963 and the Regulation framed thereunder :

(ii) the said Balance Sheet exhibits a true and fai view of the state of affairs of the VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 of the Trus as at 30th June, 1989;

(iii) the said Revenue Account of the Scheme show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the period ended or that date.

for K. K. SONI & CO.
Chartered Accountants

for V. SANKAR AIYAR & CO
Chartered Accountant

K. K. SONI
Partner

S. VENI
Parne

Bombay

Dated : October 11, 1989

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 (VECAUS 1989)

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rs. in lakhs)

	Schedule	Amount
Liabilities		
Capital	'A'	2,000 ·00
Reserves and Surplus	'B'	52 ·80
Current Liabilities and Provisions	'C'	0 ·48
Total		2,053 ·28
Assets		
Investments	'D'	496 ·33
Other Current Assets	'E'	1,556 ·95
Total		2,053 ·28

Notes to Accounts . . . 'F'

As per our attached Report of even date

REVENUE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rs. in lakhs)

	Amount
Income	
Interest	55 ·76
Total	55 ·76
Expenditure	
Management Fees	2 ·5[illegible]
Office and Administrative Expenses	0 ·1[illegible]
Legal and Processional charges	0 ·31
Total	2 ·9[illegible]

Excess of Income over Expenditure Transferred to Revenue Appropriation Account	52·80
Total	52·80

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rs. in Lakhs)

	Amount
Balance Transferred from Revenue Account	52·80
Transferred to General Reserve	52·80

As per out attached Report of even date

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rs. in Lakhs)

Schedule 'A'

	Amount
Capital	
Unit Capital Contributed by (See Note 2)	
ICICI	1,000·00
UTI	1,000·00
	2,000·00

Schedule 'B'

		Amount
Reserves and Surplus		
General Reserve		
Transferred from Revenue Appropriation Account		52·80
		52·80

Schedule 'C'

		Amount
Current Liabilities and Provisions		
Current Liabilities		
Sundry Creditors		0·15
	'A'	0·15
Provisions		
Provisions for Expenses		0·33
	'B'	0·33
	Total ('A'+'B')	0·48

Schedule 'D'

(Rs. in lakhs)

	Amount
Investments (See Notes 3 to 5)	
Equity shares (Unquoted at Cost)	37·58
Advance Towards Equity Subscription	66·45
Conditional Loans	372·30
Normal Loans	20·00
Total	496·33

Schedule 'E'

Other Current Assets	
Balance with Banks in Current Accounts	132·51
Sundry Debtors	1416·43
Prepaid Expenses	7·50
Accrued Income	0·51
Total	1556·95

Schedule 'F'

Notes to Accounts:

1. Venture Capital Unit Scheme 1989 (VECAUS '89) came into force on 28th March, 1989. The accounts have been drawn up for the period from 28th March, 1989 to 30th June, 1989 on accrual basis for all income and expenses.
2. a. In terms of clause 5 of VECAUS '89, Unit Capital includes contribution of Rs. 10·00 crores allocated to the Unit Capital being advance from Unit Scheme 1964.
   b. In terms of clause 4 of VECAUS '89 Unit Capital includes Rs. 10·00 crores subscribed by the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
3. Equity shares are held jointly in the name of the Unit Trust of India and Technology Development and Information Company of India Ltd. (TDICI).
4. No depreciation has been provided on unquoted equity shares held under this scheme.
5. In the opinion of the Trustees, the assistance in the form of Conditional and Normal Loans given to assisted concerns under the scheme have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet.
6. Sundry Debtors represent amount receivable from Unit Scheme 1964.
7. In terms of the agreement between the Trust and TDICI, TDICI is entitled to receive compensation by way of management fee for services rendered in managing the funds of VECAUS 1989 at Rs. 10·00 lakhs every year. Accordingly, provision has been made for management fee of Rs. 2·50 lakhs for the period for which the scheme's accounts are drawn up.

As per our attached Report of even date.

For V. SANKAR AIYAR & CO.
Chartered Accountants

S. VENKATRAMAN
Partner

For K. K. SONI & CO.
Chartered Accountants

K. K. SONI
Partner

K.N. ATMARAMANI
Chief General Manager
(Finance & Investment)

C.G. PAREKH
Joint General Manager
(Finance & Investment)

M.J. PHERWANI
Chairman

S.H. KHAN
K. GANESAN
N. K. SHINKAR
Trustees

A.P. KURIAN
Executive Trustee

J.S. VARSHNEYA
B.K. JHAWAR
Trustees

Bombay, Dated : 11th October, 1989

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of THE MUTUAL FUND (SUBSIDIARY) UNIT SCHEME, 1986 of the UNIT TRUST OF INDIA (hereinafter called the "Scheme" as at 30th June, 1989 and the Revenue Account of the said Scheme for the year ended on that date annexed thereto and report that :

1. The cost to be incurred for subscribing to Rights Entitlements to be exercised subsequent to 30th June, 1989 is provided for and shown as Rights Entitlement under "Investments".

2. In arriving at the market value of investments on Global Method, the following basis has been adopted.

(a) The market vlaue of the Rights Entitlements for shares is computed on the basis as if the equity shares have been allotted for the Rights Entitlements at the year end and taking prevailing market value of such shares, duly discounted for dividend element, if nay. The market vlaue of the convertible portion of the Rights Entitlements for the debentures have been computed on the basis as if they have been converted into equity shares at the year and taking the prevailing market value, duly discounted for dividend element, if any. The cost of the non-convertible portion of the Rights Entitlements for the debentures and bonds has been taken as its market value.

(b) In cases where market quotations for composite convertible debentures and bonds are not available, the market value of the convertible portion of debentures and bonds has been computed on the basis as if they have been converted into equity shares at the year end and taking the prevailing market value, duly discounted for dividend element, if any. The cost of the non-convertible portion of the debentures and bonds has been taken as its market value.

3. The amount subscribed/to be subscribed on Rights Entitlements for shares, if any, together with the cost of the existing shares is reckoned to arrive at he average cost for accounting profits on sale of investments and also for reflecting the cost of the balance shares in the balance sheet.

4. Attention is invited to the following notes in Schedule I—

(a) Note 4 & 5 regarding—

(i) Reconciliation yet to be completed between the subsidiary records prepared unit holderwise with the total figures shown as Unit Capital.

(ii) Reconciliation yet to be completed in respect of bank accounts relating to payment of dividend and agency commission.

(b) Contracts for purchase of shares of Rs. 18.01 lakhs and debentures of Rs. 0.42 lakhs remained undelivered for more than one year. In the absence of information we are unable to express an opinion on the status of these investments.

Subject to our comments in paragraphs 1 to 4 above :

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us read with the notes as per Schedule "I" :

(i) the said Balance Sheet is full and fair containing all the necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act 1963 and regulations framed thereunder :

(ii) the said Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of the MUTUAL FUND UNIT SCHEME 1986 of the Trust as at 30th June, 1989 and;

(iii) the said Revenue Account of the Scheme shows a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For V. SANKAR AIYAR & CO.
Chartered Accountants

S. VENKATRAMAN
Partner

For K. K. SONI & CO
Chartered Accountants

K. K. SONI
Partner

Bombay
Dated : October 11, 1989

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

THE MUTUAL FUND (SUBSIDIARY) UNIT SCHEME, 1986

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rs. in Lakhs)

	Schedule	Current Year	Previous Year
Liabilities			
Capital	'A'	23,327·40	15,042·93
Reserves and Surplus	'B'	11,245·04	1,488·92
Current Liabilities and Provisions	'C'	5,305·43	3,188·27
Total		39,877·87	19,720·12

(Rs. in Lakhs)

	Schedule	Current Year	Previous Year
Assets			
Investments	'D'	30,266·51	11,752·44
Deposits and other Investments	'E'	8,889·00	6,511·00
Other Current Assets	'F'	369·08	1,238·22
Fixed Assets	'G'	0·42	0·48
Deferred Revenue Expenditure	'H'	352·86	217·98
Total		39,877·87	19,720·12
Notes to Accounts	'I'		

As per our attached Report of even date

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rs. in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
Income		
Dividend and Interest	1,054·10	1,309·50
Profit on sale and Redemption of Investments (Net)	10,172·94	1,946·61
Other Income	1·77	—
Total	11,238·81	3,256·11
Expenditure		
Salaries and Allowances	10·90	10·99
Office Expenses	114·56	101·21
Publicity Expenses	2·93	5·16
Bank Charges	57·06	33·96
Deferred Revenue Expenditure written off	88·22	43·59
Depreciation on Fixed Assets	0·07	0·08
	273·74	194·99
Excess of Income over Expenditure transferred to Revenue Appropriation Account	10,965·07	3,061·12
Total	11,238·81	3,256·11

As per our attached Report of even date

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Current Year	Previous year
Balance Transferred from Revenue Account	10,965·07	3,061·12
Total	10,965·07	3,061·12
Short Provision for Expenses in prior years (Net)	2·43	—
Income Distribution for the year*	2,842·62	1,955·58
Transferred to Development Reserve Fund**	20·71	—
Transferred to General Reserve	8,099·31	1,105·54
Total	10,965·07	3,061·12
Rate of Income Distribution p.a.	18%	13%

**Fund is maintained by Unit Scheme 1964

As per our attached Report of even date.

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rs. in Lakhs)

		Current year	Previous year
Schedule 'A'			
Mastershare Capital			
(Mastershares of Rs. 10/- each)		23,327·40	15,042·93
	Total	23,327·40	15,042,·93
Number of Units (Face Value Rs. 10/-)		23,32,73,955	15,04,29,300
Schedule 'B'			
Reserves and Surplus			
General Reserve			
Balance as per last Balance Sheet		1,488·92	383·38
Transferred from Revenue Appropriation Account		8,099·31	1,105·54
	'A'	9,588·23	1,488·92
Mastershare Capital Premium Reserve	'B'	1,656·81	—
Total ('A'+'B')		11,245·04	1,488·92
Schedule 'C'			
Current Liabilities and Provisions			
Current Liabilities			
Sundry Creditors		489·92	337·99
Contracts for purchase of Investments		606·64	713·48
Bank Current Account Overdrawn as per books		1,025·74	0·11
Income received in advance		41·85	15·48
Unclaimed Income Distribution		36·98	10·18
Other Liabilities		261·68	155·45
	'A'	2,462·81	1,232·69
Provisions			
Income Distribution on :			
Mastershare Capial	'B'	2,842·62	1,955·58
Total ('A' + 'B')		5,305·43	3,188·27
Schedule 'D'			
Investments (At cost)			
Debentures and Bonds		2,680·18	1,074·32
Equity Shares		27,586·33	10,678·12
	Total	30,266·51	11,752·44
Quoted (At Cost)		28,242·62	11,438·96
Unquoted (At Cost)		2,023·89	313·48
	'A'	30,266·51	11,752·44

(Rs. in Lakhs)

	Schedule	Current Year	Previous Year
Quoted (Market Value) (Refer Note 3)		42,391·56	14,328·36
Unquoted (At Cost)		2,023·89	313·48
	'B'	44,415·45	14,641·84
Appreciation in the value of Quoted Investments ('B'—'A')		14,148·94	2,889·40
Schedule 'E'			
Deposits and Other Investments			
With Scheduled Banks		8,889·00	6,511·00
	Total	8,889·00	6,511·00
Schedule 'F'			
Other Current Assets			
Balance with Banks in Current Account		25·21	858·16
Sundry Debtors		47·07	263·79
Contracts for sale of Investments		7·05	7·05
Outstanding and Accrued Income		275·79	99·34
Advance payment of unallotted shares		13·96	9·88
Total		369·08	1,238·22

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

Schedule 'G'

Fixed Assets

(Rupees in Lakhs)

	Gross Block at cost				Depreciation				Net Block	
	As on 30th June, 1988	Additions Adjust-ments	Deduc-tions/ Adjust-ments	Total to 30th June 1989	As on 30th June 1988	Deduc-tions/ Adjust-ments	For the year 1988-89	Total to 30th June 1989	As on 30th June 1989	As on 30th June 1988
Office Equipment	0·51	—	—	0·51	0·10	—	0·06	0·16	0·35	0·41
Furniture & Fixture	0·09	—	—	0·09	0·01	—	0·01	0·02	0·07	0·08
Total	0·60	—	—	0·60	0·11	—	0·07	0·18	0·42	0·49

Schedule 'H'

(Rupees in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
Deferred Revenue Expenditure		
Balance as per last Balance Sheet	217·98	261·57
Add: Amount deferred during the year	223·10	—
	441·08	261·57
Less: Amount written off during the year	88·22	43·59
Total	352·86	217·98

UNIT TRUST OF INDIA

(Establishment under the Unit Trust of India Act, 1963)

THE MUTUAL FUND (SUBSIDIARY) UNIT SCHEME, 1986

Notes Annexed to and forming part of the Accounts as at 30th June, 1989

SCHEDULE-1

1. *Investments (At cost)*

(a) Investments include contracts awaiting completion for purchase of shares of Rs. 586.54 lakhs (previous year Rs. 711.84 lakhs) and Debentures and Bonds Rs. 20.10 lakhs (Previous year Rs. 1.64 lakhs). These include contracts for shares of Rs. 18.01 lakhs (Previous year Rs. 50.65 lakhs) and Debentures of Rs. 0.42 lakhs (Previous year NIL) outstanding for more than one year, which are awaiting settlement with parties.

(b) Investments exclude contracts awaiting completion for sale of shares of Rs. 4.66 lakhs (Previous year Rs. 7.05 lakhs). The profit (net) on these sale contracts amounting to Rs. 2.39 lakhs has been booked as income under the head 'Profit/loss on sale/redemption of Investments'.

(c) The investments of the Mutual Fund are held alongwith other investments of the Trust in the name of UTI, which in turn are kept in safe custody with Bankers of the Trust, Industrial Investment Trust, Stock Holding Corporation of India Ltd., and physically on hand with the Trust. As decided by the Trust, any discrepancy attributable to investments of this Fund is to be borne by the Unit Scheme 1964.

(d) Investments include Rs. 261.68 lakhs (Previous year Rs. 155.45) lakhs) being the cost to be incured for subscribing to rghts for shares, convertible debentures and bonds which the Scheme is entitled to exercise subsequent to the end of the year. These are accounted for because the investments were made at 'cum-rights' rates whereas the year-end quoted rates were on 'ex-right' basis.

(e) Investments include application money paid for right securities awaiting allotment.

2. The amount subscribed/to be subscribed on rights entitlements for shares, if any, together with the cost of the existing shares, is reckoned to arrive at the average cost of accounting profits on sale of investments and also for reflecting the cost of the balance shares in the Balance Sheet.

3. *Valuation of Investments* :

The market value of investments computed on the basis stated hercunder, have been considered on Globla Method whereby the aggregate market value of all investments have been compared with the aggregate cost of such investments and which results into the overall appreciation.

(a) Equity shares have been valued at year-end market rates, wherever available. These year-end market rates duly discounted for dividend element, if any, are taken as the market rates for valuing equity shares which are not pari passu with the existing shares and for which year-end market quotations are not available. Equity shares for which year-end market rates are not available are taken at cost.

(b) Debentures and Bonds which are partly or wholly convertible into equity shares subsequent to the year-end on the dates prescribed by the respective companies are valued as under :

(i) Composite convertible debentures and bonds (comprising of convertible and non-convertible portion) for which quotations are avilable, have been valued at year-end market rates;

(ii) In cases where market quotations for composite convertible debentures are bonds are not available, the market value of the convertible portion is taken at the year-end rates applicable to relevant equity shares, duly discounted for dividend element, if any, which works out to Rs. 3236.49 lakhs (Previous year Rs. 323.88 lakhs) as against the cost of Rs. 1770.46 lakhs. (Previous year Rs. 198.41 lakhs). The residual non-convertible portion of such debentures and bonds are taken at cost.

(iii) Non-convertible debentures and bonds have been valued at year end market rates wherever available. Non-convertible debentures and bonds which are not quoted or which are quoted but not traded during the last six months as at the Balance Sheet date have been valued at cost.

(c) The market value of the rights entitlements both for shares and convertible portion of debentures and bonds have been computed taking the year-end rates applicable to the shares, duly discounted for divided element, if any, and it works out to Rs. 307.38 lakhs (Previous year Rs. 297.42 lakhs) as against the cost of Rs. 158.03 lakhs (Previous year Rs. 155.45 lakhs). The residual non-convertible portion of debentures and bonds are taken at cost of Rs. 103.65 lakhs (Previous year NIL).

4. *Reconcilation of Unit Capital and Unclaimed Income Distribution Accounts* :

Reconciliation in respect of Unit Capital, Unclaimed Income Distribution Accounts with subsidiary/detailed records is in progress and adjustments, if any, will be made on completion of reconcillation.

5. *Bank Reconciliation*

Reconciliation of bank accounts pertaining to payment of dividend and agency commission have not been completed.

6. *Dlferred Revenue Expendlture*

In accordance with the provision of Section 25(3) of the Unit Trust of India Act, 1963, all initia direct expenses including commission to agents, incurred by the scheme during 1986-87 are deferred over a period of seven years as the Trust is not bound to redeem or repurchase the Mastershare at least for a period of seven years as per the terms of prospectus. Accordingly, all initial direct expenses incurred by the Scheme during the year on account of Rights Issue of capital have been deferred off over a period of 5 years. The balance of expenditure remaining to be written off is being carried forward as "Deferred Revenue Expenditure".

7. *Income*

(i) Income on Investment has been accounted for on acctual basis. The dividend income has been accrued and accounted for n the ex-dividend date.

(ii) Miscellaneous Income is accounted for on cash basis.

8. *Contlngent Liabillty*

Contingent liability on account of uncalled liability on partly paid shares and debentures is R. 281.09 lakhs (Previous year Rs. 50.08 lakhs).

9. *Inter Scheme Blance*

(i) Sundry Creditors include Rs. 390.55 lakhs (Previous year Rs. NIL) due to other Schemes.

(ii) Sundry Debtors include Rs. NIL (Previous year Rs. 25.00 lakhs) due from other schemes.

10. *Previous year's figures*

Previous year's figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE

For V. SANKAR AIYAR & CO. Chartered Accountants	K.N. ATMARAMANI Chief General Manager (Finance & Investment)	M.J. PHERWANI Chairman	A.P. KURIAN Executive Trustee
S. VENKATRAMAN Partner			
For K.K. SONI & CO. Chartered Accountants	C.G. PAREKH Joint General Manager (Finance & Investment)		J.S. VARSHNEYA
K. K. SONI Partner		S. H. KHAN	B.K. JHAWAR
		K. GANESAN N. K. SHINKAR Trustees	Trustees

Bombay, dated 11th October, 1989.

AUDITOR'S REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of THE INDIA FUND UNIT SCHEME, 1986 of THE UNIT TRUST OF INDIA (hereinafter called the Scheme) as at 30th June, 1989 and the Revenue Account of the said Scheme for the year ended on that date annexed thereto and report that :

1. The cost to be incurred for subscribing to Rights Entitlements to be exercised subsequent to 30th June, 1989 is provided for and shown as Rights Entitlement under "Investments".

2. In arriving at the market value of investments on Global Method, the following basis has been adopted :

(a) The market value of the Rights Entitlement for shares is computed on the basis as if the equity shares have been allotted for the Rights Entitlements at the year end and taking prevailing market value of such shares, duly discounted for dividend element, if any. The market value of the convertible portion of the Rights Entitlements for the debentures have been computed on the basis as if they have been converted into equity shares at the year end and taking the prevailing market value, duly discounted for dividend element, if any. The cost of the non-convertible portion of the Rights Entitlements for the debentures and bonds has been taken as its market value.

(b) In case where market quotations for composite convertible debentures and bonds are not avilable, the market value of the convertible portion of debentures and bonds has been computed on the basis as if they have been converted into equity shares at the year and taking the prevailing market value, duly discounted for dividend element, if any. The cost of the non-convertible portion of the debentures and bonds has been taken as its market value.

3. The above basis of computing the market value has also been adopted for the weekly Net Asset Value (NAV) and consequently for computing the management fee payable to the Unit Trust of India under the Scheme.

4 .The amount subcribed/to be subscribed on Rights Entitlements for shares, if any, togther with the cost of the existing shares is reckoned to arrive at the average cost for accounting profits on sale of investments and also for reflecting the cost of the balnce shares in the balance sheet.

Subject to our comments in paragraphs 1 to 4 above :

(a) We have obtained all the information and explanations which to the bond of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us read with the notes as per Schedule "G" :

(i) the said Balance Sheet is full and fair containing all the necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act 1963 and regulations framed thereunder;

(ii) the said Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of THE INDIA FUND UNIT SCHEME 1986 of the Trust as at 30th June, 1989; and

(iii) the said Revenue Account of the scheme shows a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For V. SANKAR AIYAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

S. VENKATRAMAN
PARTNER

For K. K. SONI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

K. K. SONI
PARTNER

BOMBAY
DATED : 11th October, 1989

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963

THE INDIA FUND UNIT SCHEME, 1986

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	Schedule	Current Year	Previous Year
LIABILITIES			
Capital	'A'	13,948·16	13,948·16
Reserves and surplus	'B'	13,081·11	1,971·54
Current liabilities and provisions	'C'	2,262·32	1,334·14
Total		29,291·59	17,253·84
ASSETS			
Investments	'D'	20,722·01	10,902·46
Deposits and other Investments	'E'	8,349·00	5,928·00
Other Current Assets	'F'	220·58	423·38
Total		29,291·59	17,253·84
Notes to Accounts	'G'		

As per our attached Report of even date

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
INCOME		
Dividend and Interest	1,004·52	969·55
Profit on sale and Redemption of Investments (Net)	11,332·59	1,361·61
Other Income	4·86	—
Total	12,341·97	2,331·16
EXPENDITURE		
Management Fee	318·87	187·60
Office and Administrative Expenses	12·23	7·69
Stamp Fee and Bank Charges	64·25	39·24
Professional and Legal Fee	0·16	0·53
	395·51	235·06
Excess of Income over expenditure Transferred to Revenue Appropriation Account	11,946·46	4,096·10
Total	12,341·97	2,331·16

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	Current Year	Previous Year
Balance Transferred from Revenue Account	11,946·46	2,096·10
Transferred from General Reserve	241·09	—
Total	12,187·55	2,096·10

(Rupees in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
Income Distribution for the year*	836·89	732·28
Transferred to General Reserve	11,350·66	1,363·82
Total	12,187·55	2,096·10
*Rate of Income Distribution p.a.	6%	5·25%

As per our attached Report of even date.

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Current Year	Pervious Year
SCHEDULE 'A'		
Capital		
Unit Capital		
(139, 48, 160 units of Rs. 100/- each)	13,948·16	13,948·16
Total	13,948·16	13,948·16
SCHEDULE 'B'		
RESERVE and Surplus		
GENERAL Reserve		
Balance as per last Balance Sheet	1,971·54	607·72
Transfer from Revenue Appropriation Account	11,350·66	1,363·82
Less: Transfer to Revenue Appropriation Account	(241·09)	—
Total	13,081·11	1,971·54
SCHEDULE 'C'		
CURRENT Liabilities and Provisions		
CURRENT Liabilities		
Sundry Creditors	182·17	77·81
Contracts for purchase of Investments	375·70	473·14
Bank Current Account Overdrawn as per books	822·07	—
Income received in advance	45·22	25·13
Other Liabilities	0·27	25·78
'A'	1,425·43	601·86
PROVISIONS		
Income Distribution on :		
Unit Capital 'B'	836·89	732·28
Total ('A'+'B')	2,262·32	1,334·14

THE INDIA FUND UNIT SCHEME, 1986

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 'D'		
Investments (At Cost)		
Debentures and Bonds	2,991·96	290·38
Equity Shares	17,559·03	10,557·20
Rights Entitlements (Refer Note 3,4 (c)	171·02	54·88
Total	20,722·01	10,902·46

(Rupees in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
Quoted (At Cost)	20,374·51	10,730·88
Unquoted (At Cost)	347·50	171·58
'A'	20,722·01	10,902·46
Quoted (Market Value) (Refer Note 4)	32,739·95	13,205·94
Unquoted (At Cost)	347·50	171·58
'B'	33,087·45	13,377·52
Appreciation in value of quoted Investments ('B'—'A')	12,365·44	2,475·06

SCHEDULE 'E'

Deposits and other invesetments		
With Scheduled Banks	8,349·00	5,928·00
Total	8,349·00	5,928·00

SCHEDULE 'F'

Other Current Assets		
Balance with Banks in Current Account	0·02	220 59
Sundry Debtors	2·16	59·34
Contracts for Sale of Investments	7·05	61·62
Outstanding and accrued Income	211·35	81·83
Total	220·58	423·38

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

THE INDIA FUND UNIT SCHEME 1986

Notes annexed to and forming part of the accounts as at 30th June, 1989

SCHEDULE "G"

1. *Books of Accounts*

The books of accounts of the Scheme are maintained in Indian Rupees and on Mercantile basis.

2. *Investment (At Cost)*

(a) Investments include contracts awaiting completion for purchase of shares of Rs. 375.70 lakhs (Previous Year Rs. 473.14 lakhs). These include contracts for shares of Rs. 4.20 lakhs (Previous Year Rs. 39.91 lakhs) outstanding for more than one year, which are awaiting settlement with parties.

(b) Investments exclude contracts awaiting completion for sale of shares of Rs. 7.05 lakhs (Previous Year Rs. 61.62 lakhs), of which Rs. 7.05 lakhs (Previous Year Rs. 0.36 lakhs) are outstanding for more than one year, awaiting settlement with parties.

(c) The investments of the Fund are kept in safe custody with Bankers of the Trust/Industrial Investment Trust Ltd./Stockholding Corporation of India Ltd.

(d) Investment include Rs. 171.02 lakhs (Previous Year Rs. 54.88 lakhs) being the cost to be incurred for subscribing to rights for shares, convertible debentures and bonds which the scheme is entitled to exercise subsequent to the end of the year. These are accounted for because the investments were made at cum-rights rates wheras the year end quoted rates were on ex-rights basis.

3. The amount subscribedfflto be subscribed on right entitlements for shares, if any, together with the cost of the existing shares is reckoned to arrive at the average cost for accounting profits on sale of investments and also for reflecting the cost of the balance shares in the Balance Sheet.

4. *Valuation of Investments*

The Market Value of Investments computed on the basis stated hereunder, have been considered on Global Method whereby the aggregate market value of all investments have been compared with the aggregate cost of such investments and which results into the overall appreciation. Further, such market value has been arrived at after deducting 1% to cover relevant charges payable on deemed realisation of investments as provided under the Scheme.

(a) Equity shares have been valued at year end market rates. These year end market rates duly discounted for dividend element, if any, are taken as the market rates for valuing equity shares which are not pari passu with the existing shares and for which year end market quotations are not available.

(b) Debenures and Bonds which are partly or wholly convertible into equity shares subsequent to the year end on the dates prescribed by the respective companies are valued as under :

(i) Composite convertible debentures and bonds (comprising of convertible and non-convertible portion) for which quotations are available have been valued at year end market rates.

(ii) In cases where market quotations for composite convertible debentures and bonds are not available, the market value of the convertible portion is taken at the year end rates applicable to relevant equity shares, duly discounted for dividend element, if any, which works out to Rs. 3881.03 lakhs (Previous year Rs. 147.04 lakhs) as against the cost of Rs. 2194.94 lakhs (Previous year Rs. 94.61 lakhs). The residual non-convertible portion of such debentures and bonds are taken at cost.

(c) The market value of the rights entitlements both for shares and convertible portion of debentures and bonds have been computed taking the year end rates applicable to the shares, duly discounted for dividend element, if any, and it works out to Rs. 188.76 lakhs (Previous year Rs. 100.78 lakhs) as aginst the cost of Rs. 97.59 lakhs (Previous year Rs. 54.88 lakhs). The residual non-convertible portion of debentures and bonds are taken at cost of Rs. 73.43 lakhs (Previous year Rs. NIL).

5. *Management Fees*

In terms of the agreement with the India Fund, UTI is entitled to receive compensation by way of Management Fees for the services rendered while managing the funds of India Fund. Accordingly, Management Fees at the annual rate of 1.1% of the Average Net Asset Value of the Investment has been calculated and paid on quarterly basis.

6. *Income*

(i) Income on investment has been accounted for an accrual basis. The dividend income has been accurred and accounted for on the ex-dividend date.

(ii) Miscellaneous Income is accounted for on cash basis.

7. *Income Distribution*

An amount of Rs. 596.98 lakhs, being interest earned on funds awaiting initial investment was transferred to General Reserve during the period ended 30th June, 1987, out of which Rs. 241.09 lakhs is drawn during the current year for distribution of income, in addition to current years' distributable income.

8. *Contingent Liability*

Contingent Liability on account of uncalled liability on partly paid shares and debentures is Rs. 180.07 lakhs (Previous year Rs. 66.81 lakhs).

9. *Regrouping of Previous Year's figures*

Previous year's figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

AS PER OUR ATTACHED REPORT OF EVEN DATE.

For V. SANKAR AIYAR & CO.
Chartered Accountants

S. VENKATRAMAN
Partner

For K. K. SONI & CO.
Chartered Accountants

K. K. SONI
Partner

C G. PARKEH
Joint General Manager
(Accounts)

K.N. ATMARAMANI
Chief General Manager
(Finance & Investment)

M.J. PHERWANI
Chairman

S. H. KHAN
Trustee

K. GANESAN
Trustee

N. K. SHINKAR
Trustee

A. P. KURIAN
Executive Trustee

J.S. VARSHNEYA

B.K. JHAWAR
Trustee

Bombay,
Dated: 11th October, 1989.

AUDITORS' REPORT

TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheet of THE INDIA GROWTH FUND UNIT SCHEME, 1988 of the UNIT TRUST OF INDIA (hereinafter called the Scheme) as at 30th June, 1989 and the Revenue Account of the said Scheme for the period ended on that date, annexed thereto, and report that :

1. The cost to be incurred for subscribing to Rights Entitlements to be exercised subsequent to 30th June, 1989 is provided for and shown as Rights Entitlements under "Investments".

2. In arriving at the market value of Investments on Global Method, the following basis has been adopted :

(a) In cases where market quotations for composite convertible debentures and bonds are not available, the market value of the convertible portion of debentures and bonds has been computed on the basis as if they have been converted into equity shares at the year end and taking their prevailing market value, duly discounted for dividend element, if any. The market down cost of the residual non-convertible portion of the debentures and bonds has been taken as its market value as stated in Note 5(b)(ii).

(b) The Market Value of the Rights Entitlements for shares is computed on the basis as if the equity shares have been allotted of the Rights Entitlements at the year end and taking prevailing market value of such shares, duly discounted for dividend element, if any. The market value of the convertible portion of the Rights Entitlements for debentures have been computed on the basis as if they have been converted into equity shares at the year end and taking their prevailing market value, duly discounted for dividend element, if any. The market

down cost of the residual non-convertible portion of the Rights Entitlements for debentures and bonds has been taken as its market value as stated in Note 5(c).

3. The above basis of computing the market value has also been adopted for computing the weekly Net Asset Value (NAV), and consequently for computing the Management Fee payable to the Unit Trust of India, and the custodianship fee payable to State Bank of India except that in respect of the residual non-convertible portion of the Rights Entitlements for debentures and bonds and the residual non-convertible portion of the composite convertible debentures and bonds, where cost has been taken as its market value.

4. The amount subscribed on fully paid rights entitlements for shares, together with shares contracted to be purchased and duly delivered after deducting therefrom shares contracted to be sold is reckoned to arrive at the average cost of accounting profit/loss on sale of investments.

7. In view of note number 7 to the accounts, we are unable to express an opinion as to the correctness of the provision for investment advisor's fees made in the accounts.

6. Attention is invited to Note number 8 regarding provision for custodianship fees. In our opinion the fee is to be computed based on the book value of the assets at the end of each week without deducting liabilities therefrom. Had provision been made in the accounts on the above basis, the excess of income over expenditure would be more by Rs. 0.52 lakhs with the consequential impact on the reserves.

Subject to our comments in paragraphs 1 to 6 above :

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us read with the Notes as per Schedule 'G':

(i) the said Balance Sheet is full and fair containing all the necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder;

(ii) the said Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of THE INDIAN GROWTH FUND UNIT SCHEME, 1988 of the Trust as at 30th June, 1989; and

(iii) the said Revenue Account of the Scheme shows a true and fair view of the excess of income over expenditure for the period ended on that date.

For K. K. SONI & CO.
Chartered Accountants

K. K. SONI
Partner

For V. SANKAR AIYAR & CO
Chartered Accountants

S. VENKATARAMAN
Partner

Dated : 11th October, 1989

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

THE INDIA GROWTH FUND UNIT SCHEME, 1988

THE INDIA GROWTH FUND UNIT SCHEME, 1988

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1989

(Rupees in lakhs)

	Schedule	Amount (Rs.)
LIABILITIES		
Capital	'A'	4193·66
Reserves and Surplus	'B'	2947·49
Current Liabilities and Provisions	'C'	1743·71
Total		8884·86
ASSETS		
Investments	'D'	7677·32
Deposits and Other Investments	'E'	975·36
Other Current Assets	'F'	232·18
Total		8884·86
Notes to Accounts	'G'	

Schedule 6

Share Capital

Annexured to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st Match, 1989.

Description	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30 th June, 1988 Rs. Lakhs.
Authorised		
2,00,000 shares of Rs. 5,000/-- each (Previous year 2,00,000)	10,000 ·00	10,000 ·00
Issued & Subscribed.		
1,75,000 Shares of Rs. 5,000/–each (Previous year 1,50,000)	8,750 ·00	7,500 ·00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948).		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	500 ·00	500 ·00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	200 ·00	200 ·00
(iii) 2,692 (Third Series shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134 ·60	134 ·60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165 ·40	165 ·40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500 ·00	500 ·0
(vi) 5,000 (Sixth Series) share of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250 ·00	250 ·00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250 ·00	250 ·00
(viii) 10,000 (Eighth Series) shares of Rs. 5,000 each fully paid-up	500 ·00	500 ·00
(ix) 10,000 (Ninth Series) Shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500 ·00	500 ·00
(x) 20,000 (Tenth Series) Shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000 ·00	1,000 ·00
(xi) 20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,000 ·00	1,000 ·00
(xii) 25,000 (Twelth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,250 ·00	1,250 ·00
(xiii) 25,000 (Thirteenth Series) shares of Rs. 5,000/– each fully paid-up	1,250 ·00	750 ·00 (Party Paid-up)
(xiv) 25,000 (Fourteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each (Rs. 3000/- per share called and paid-up)	750 ·00	
	8,250 ·00	7,000 ·00

Schedule 7

Reserves & Reserve Fund

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 31st March, 1989

Description	As at the 31st March, 1989 Rs. Lakhs	As at the 30th June, 1988 Rs. Lakhs
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	10,622 ·31	7,868 ·77
Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100 ·00	100 ·00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	232 ·20	292 ·93
Special Reserve Fund under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961	15,429 ·11	14,000 ·00
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	710 ·70	300 ·15
Total :	27,094 ·32	22,561 ·85

		AMOUNT RS.
SCHEDULE 'B'		
Reserves and Surplus		
Unit Premium Reserve		2421·01
Transfer from Revenue Appropriation Account		526·48
Total		2947·49
SCHEDULE 'C'		
Current Liabilities and Provisions		
Current Liabilities		
Sundry Creditors		43·25
Contracts for Purchase of Investments		1661·01
Other Liabilities		39·45
'A'		1743·71
Provisions		
Income Distribution on Unit Capital	'B'	
Total ('A' + 'B')		1743·71
	(Rupees in Lakhs)	
SCHEDULE 'D'		
Investment (At Cost)		
Debenture and Bonds		872·51
Equity Shares		6767·63
Rights Entitlements		37·18
Total		7677·32
Quoted (At Cost)		7460·48
Unquoted (At Cost)		216·84
'A'		7677·32
Quoted (Market Value)		10415·33
Unquoted (At Market Down Cost)		214·61
'B'		106·2994
Appreciation in value of Investments ('B'-'A')		2952·62
SCHEDULE 'E'		
Deposits and Other Investments		
With Scheduled Banks		957·00
Others		18·36
Total		975·36
SCHEDULE 'F'		
Other Current Assets		
Balance with Banks in Current Account		1·62
Contracts for Sale Investments		165·67
Outstanding and accrued Income		64·89
Total		232·18

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS AS AT 30TH JUNE 1989

SCHEDULE-G

1. Books of Accounts :-

The books of accounts of the Scheme are maintained in Indian Rupees and on Mercantile basis. The accounts have been drawn up from August 29, 1988 to June 30, 1989, this being the period for which the Scheme was in operation.

2. Unit Premium Reserve :—

Pursuant to the Unit Scheme Agreement between the Unit Trust of India and the India Growth Fund Inc., upon the initial transfer of funds, U.T.I. shall issue Units of the face value of Rs. 100/- each. Additional Units issued by U.T.I. in respect of subsequent transfer of funds shall be issued at the net assets value rate as most recently determined prior to such issue. Consequently, the excess of the net assets value rate over Rs. 100/- has been credited to Unit Premium Reserve Account.

3. Investments (at cost) :—

(a) Investments include contracts awaiting completion for purchase of shares of Rs. 1661.00 lakhs, and debentures and bonds Rs. Nil lakhs.

(b) Investments exclude contracts awaiting completion for sale of Shares amounting to Rs. 135.54 lakhs. The Profit (net) on these sale contracts amounting to Rs. 30.13 lakhs has been booked as Income under the head Profit (net) on sale of Investments.

(c) Rights Entitlements represent the cost to be incurred fors ubscribing to rights for shares, convertible debentures and bonds which the Scheme is entitled to exercise subsequent to the end of the year. These are accounted for because the investments were made at cum-rights rates whereas the year-end quoted rates were on ex-rights basis

4. The amount subscribed on fully-paid right entitlements for shares, together with shares contracted to be purchased and duly delivered after deducting therefrom shares contracted to be sold is reckoned to arrive at the average cost for accounting profit/loss on sale of investments.

5. Valuation of Investments :—

The Market Value of Investments computed on the basis hereunder stated have been considered on Global Method whereby the aggregate market value of all investments have been compared with the aggregate cost of such investments and which results into the overall appreciation.

(a) Equity Shares have been valued at year-end market rates. These year-end market rates, duly discounted for dividend element, if any, are taken as the market rates for valuing Equity Shares which are not pari-passu with the existing shares for which year-end market quotations are not available

(b) Debentures and Bonds which are partly or wholly convertible into Equity Shares subsequent to the year-end on the dates prescribed by the respective companies are valued as under :—

(i) Composite convertible debentures and bonds (comparising of convertible and non-convertible portion) for which quotations are available have been valued at year-end market rates.

(ii) In cases where market quotations for composite convertible debentures and bonds are not available, the market value of the convertible portion is taken at the year-end rates applicable to relevant equity shares, duly discounted for dividend element, if any, which works out to Rs. 1162.67 lakhs as against the cost of Rs. 679.25 lakhs. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds are value at marked down cost calculated on the basis of the rate of normal yield, Normal yield is taken at the prevailing maximum rate of interest as at 30th June 1989, being 14% for Non-convertible Debentures/Bonds as stipulated by the guide-lines issued by the Government of India.

(c) The market value of the rights entitlements both for shares and convertible portion of debentures and bonds have been computed taking the year-end rates applicable to the shares duly discounted for dividend element, if any, and it works out to Rs. 34.54 lakhs as against the cost of Rs. 16.10 lakhs. The residual non-convertible portion of debentures and bonds are valued at marked down cost calculated on the basis of the rate of normal yield. Normal yield is taken at the prevailing maximum rate of interest as at 30th June 1989, being 14% for Non-convertible Debentures/Bonds as stipulated by the guide-lines issued by the Government of India.

6. Management Fees :

In terms of agreement with the India Growth Fund Inc., Unit Trust of India is entitled to receive compensation for services rendered while managing the Funds of The India Growth Fund. Accordingly, management fees has been provided at the annual rate, on the slab basis of the average weekly net assets held under the Scheme.

7. Investment Adviser's Fees :—

In terms of the Investment Advisory Agreement between the India Growth Fund Inc., (the Fund) and the Unit Trust of India Investment Advisory Services Limited (U.T.I.I.A.S.), UTIIAS is entitled to receive compensation for Investment Advisory Services rendered to the Fund and for expenses incurred by it, based on the average weekly value of the Fund's net assets. Such compensation, to the account of the Scheme in respect of Fund's net assets held under the Scheme are payable in Indian Rupees out of the assets held in the Scheme. Due to non-receipt of information relating to the Fund's net assets not held in India, it is not possible to determine the liability in respect of the fees payable in Indian Rupees to the account of the Scheme. Therefore, provision has been made for the fee to the Account of the Scheme based on advice received from the Fund.

8. *Custodianship Fees* :

In terms of the Custody Agreement between the India Growth Fund Inc (the Fund), the Unit Trust of India and the State Bank of India, State Bank of India is entitled to receive the custodianship fee based on the average weekly value of the assets in the Unit Scheme. Such fees has been provided in the accounts based on the market value of the net assets in the Scheme.

9. *Income* ;

Income on investment has been accounted for on accrual basis. The dividend income has been accrued and accounted for on the ex-dividend date

10. Pursuant to the Unit Scheme Agreement between India Growth Fund Inc. (Fund) and Unit Trust of India (UTI), the Unit Scheme is to distribute all of its investment income at the request of the Fund. As no such request for distribution has been received for the period, no provision has been made for Income Disribution.

For V. SANKAR AIYAR & CO.
Chartered Accountants

S. VENKATRAMAN
Partner

For K.K. SONI & CO.
Chartered Accountants

(K.N. ATMARAMAI)
Chief General Manager
(Finance & Investment)

(M. M. KARUR)
Joint General Manager
(Finance & Investment)

M.J. PHERWANI
Chairman

A.P. KURIAN
Executive Trustee

Trustee

Trustee

J.S. VARSHNEYA
Trustee

Trustee

S.H. KHAN
Trustee

B.K. JHAWAR
Trustee

K. GANESAN
Trustee

Trustee

N.K. SHINKAR
Trustee

Bombay, dated 11th October, 1989.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989